चतुर्थ माला, खण्ड 38, अंक 23 बुधवार, 25 मार्च, 1970/4 चैत्र, 1892 (शक)
Fourth Series, Vol. XXXVIII, No. 23 Wednesday, March 25, 1970/Chaitra 4, 1892 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र]

Tenth Session

सत्यमेव जयते

[खण्ड 38 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XXXVIII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is Translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. In English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—23, बुधवार, 25 मार्च, 1970/4 चैत्र, 1892 (शक)
No.—23, Wednesday, March 25, 1970/Chaitra 4, 1892 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	Subject	
602.	भारत द्वारा जेद्दाह सम्मेलन में भाग लेने की स्थिति में पाकिस्तान द्वारा उस का बहिष्कार किये जाने की धमकी	Pakistan's threat to Boycott Jeddah Meet on India's Participation	1 –5
603.	आई०एन०ए० के शहीदों के स्मारक को पुनः बनाने के लिये सिंगापुर सरकार के साथ बातचीत	Negotiation with Singapore Government for rebuildings INA Martyr's Memorial	5—8
604.	अफ्रीकी देशों में भारतीय दूतावासों के प्रधानों की बैठक	Meeting of Heads of Indian Missions in African Countries	3 –15
606.	पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में स्थापित काश्मीर कमांडो यूनिट	Kashmir Commando Unit Set up in Pakistan Occupied Kashmir	15

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

अतारां - सूचना पत्र

(i)

Short notice Question
Shortage of small Coins in Indore, Ujjain, Ratlam and Dewas districts

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
601. भूतपूर्व सैनिकों को नेफा में बसाये जाने के बारे में प्रस्ताव	Proposal for Settlement of Ex-Servicemen in NEFA	19
605. विकास शील क्षेत्रों में अधिक उत्पादन दर के बारे में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें	Recommendations of Expert Committee under United Nations Economic and Social Council Re. Higher Growth Rate for Developing Areas	19—20
607. आयुध कारखानों में बनी वस्तुओं का निर्यात	Export of Items Manufactured in Ordinance Factories	20
608. गन्डक परियोजना नहर का सारन (बिहार) तक विस्तार	Extension of Gandak Project Canal upto Saran, Bihar	20
609. राज्य सरकार निगम द्वारा सीरिया के साथ दोषपूर्ण इस्पात करार	Defective Steel Contract with Syria by STC	21
610. भारत के विरुद्ध पाकिस्तान की युद्ध की तैयारियां	Pakistan's War Preparations against India	21
611. उत्तरी वियतनाम द्वारा विद्रोही नागाओं का तथा-कथित प्रशिक्षण	Alleged Training of Hostile Nagas by North Vietnam	22
612. आयात विनियमों में छूट	Relaxation of Import Regulations	22
613. मध्य प्रदेश के दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ तथा सरगुजा जिलों में सूखा	Draught in Durg, Bilaspur, Raigarh and Sarguja Districts of Madhya Pradesh	22
614. भारतीय दूतावासों द्वारा मनोरंजन पर व्यय	Expenses on Entertainment by Indian Embassies	23
615. उगांडा भारतीयों को ब्रिटेन में बसाना	Settlement of Uganda Indians in U. K.	23—24

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
616. लाओस में उत्तरी वियतनाम के आक्रमण को रोकने के लिये भारत की पहल	Indian Initiative to Stop Aggression by North Vietnamese in Laos	24
617 काश्मीर में छापामार युद्ध शुरू करना	Organising of Guerilla Type Warfare in Kashmir	24—25
618. भारत पाकिस्तान सर्वेक्षण सम्मेलन में मतभेद	Differences in Indo-Pakistan Survey Conference	25
619. अन्य देशों के साथ पटसन तथा सूती वस्त्र के बारे में बातचीत	Talks with other Countries on Jute and Cotton Textiles	25—26
620. भारत और चैकोस्लोवाकिया के उत्पादों को अन्य देशों में संयुक्त रूप से बेचने के लिये भारत द्वारा चैकोस्लोवाकिया को दिया गया सुझाव	Suggestion given by India to Czechoslovakia for Joint Marketing of Products in Third Countries	26
621. भारत का जेद्दाह सम्मेलन में भाग लेना	India's Participation in Jeddah Meet	26—27
622. दस्तकारी की वस्तुओं के निर्यात में जापान से प्रतिस्पर्धा	Competition from Japan in the Exports of Handicrafts	27—29
623. मलयेशिया में भारतीयों के लिये कार्य परमिट	Work Permits for Indians in Malaysia	29
624. मैक्स मुलर भवनों का बन्द किया जाना	Closure of Max Muller Bhavans	29 - 30
625. केलों का निर्यात	Export of Bananas	30
626. डा० धर्मतेजा और उनकी पत्नी को भारत वापस लाना	Extradition of Dr. Dharma Teja and his Wife	31
627. हथकरघा बुनकरों का उत्थान	Uplift of Handloom Weavers	31—32
628. पाकिस्तान द्वारा वापदा बांध काटने के कारण भारतीय गांवों में बाढ़ का आना	Flood caused in Indian Villages by Pakistan cutting open Wapda Bund	32

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
629. चीन को फ्रांसीसी लड़ाकू बमबार विमानों का बेचा जाना	Sale of French Fighter Bombers to China	32—33
630. मध्य प्रदेश को पार्वती जलमार्ग से पानी की सप्लाई	Water Supply to Madhya Pradesh at Parvati Aqueduct	33—34

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos.

3970. मध्य प्रदेश की बिजली सम्बन्धी आवश्यकताओं का अनुमान	Assessment of requirements of Electricity of Madhya Pradesh	34
3971. उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में परियोजनाओं को प्राथमिकता	Priority to Projects in Backward Areas of U. P.	34—35
3972. उत्तर प्रदेश को कुमाऊं तथा उत्तराखंड के गांवों में बिजली लगाने के लिये सहायता	Aid to U. P. for Rural Electrification of Kumaun and Uttarkhand	35—36
3973. आयुध कारखानों की उत्पादन क्षमता का उपयोग	Utilisation of production capacity of Ordnance Factories	36
3974. हांगकांग में भारतीय लोग	Indians in Hongkong	37
3975. दूतावासों के अधिकारियों की नियुक्ति	Posting of Officials in Embassies	37—38
3976. चलचित्र फिल्में तैयार करने में प्रयोग में आने वाले "मैटोल" की कमी	Shortage of "Metol" in the processing of Cine Films	38—39
3977. नागपुरी सन्तरों का निर्यात	Export of Nagpuri Oranges	39
3978. राज्य व्यापार निगम द्वारा स्कूटरों की नीलामी	Auction of Scooters by S. T. C.	39—40
3979. हिमाचल प्रदेश में डलहौजी और बकलोह छावनियों का पुनर्निर्माण	Rebuilding of Dalhousie and Bakloh Cantonment in Himachal Pradesh	40

अ.ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3980. छावनियों में मकानों को खाली कराना	Dehiring of Houses in Cantonment	40
3981. धन देकर गणतन्त्र दिवस परेड देखना	Witnessing of Republic Day parade on Payment	41
3982. वैदेशिक सांस्कृतिक संस्थाओं से राज्य सरकारों के सम्बन्ध	Association of State Governments with Foreign Cultural Societies	41
3983. खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा दिल्ली तथा कलकत्ता में अपने कार्यालय भवनों के लिये दिया गया किराया	Rent paid by MMTC for its Office Buildings in Delhi and Calcutta	41
3984. भारत तथा श्रीलंका में विद्युत शक्ति का प्रति व्यक्ति उत्पादन	Per Capita Production of Electricity in India and Ceylon	42
3985. ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य में प्रगति	Progress in Rural Electrification	42—43
3986. राज्यों में कानून तथा व्यवस्था को बनाये रखने के लिये सेना का उपयोग	Use of Army in States for maintaining Law and Order	43—44
3987. अन्दमान को अवाध व्यापार पतन बनाने का प्रस्ताव	Proposal to make Andaman as a Free Port	44—45
3988. दिल्ली के देहाती क्षेत्रों से देसु के ट्रांसफार्मरों की चोरी	DESU Transformers stolen from Rural Areas, Delhi	45
3989. हंगरी से व्यापार करार	Trade Agreement with Hungary	45—46
3990. राष्ट्रीय विकास परिषद् की कार्यसंचालन सम्बन्धी प्रक्रियाओं में परिवर्तन के सुझाव	Suggestions for Changes in Operational Procedures of National Development Council	46
3991. लौकटाक परियोजना का बोरक नदी के जल की निकासी पर प्रभाव	Effect of Loktak Project on Water Discharge of Borak River	47

तारां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3992. रेयन फिलामेंट स्टैपल फाइबर उद्योग के विस्तार पर लगे प्रतिबन्ध का हटाया जाना	Lifting of the Ban on the Expansion of the Rayon Filament Staple Fibre Industry	
3993. मिश्र में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Egypt	43
3995. सूती कपड़ा उद्योग के उत्पादन में कमी	Decline in Production in Textile Industry	48
3996. जगतपुर में पटसन मिल स्थापित करने के लिये लाइसेंस	Licence for setting up a Jute Mill at Jagatpur	49
3997. सेवा-मुक्त आपात कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारियों को रोजगार देने के लिये आयोग की नियुक्ति	Appointment of a Commission for the Settlement of released Emergency Commissioned Officers	49
3998. इंगलैण्ड में भारतीय दूतावास की एक महिला की हत्या	Murder of Women Employee of Indian Embassy in U. K.	50
3999. द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् सेवा मुक्त हुए आपात कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारी	Emergency Commissioned Officers released after Second World War	50--51
4000. उत्तर प्रदेश में चौकाघाट रेलवे स्टेशन के निकट बमों का पाया जाना	Bombs found near Chaukaghat Railway Station in U. P.	51
4001. नेपाल से भारतीय सैनिक सम्पर्क ग्रुप की वापसी से उप्पन्न स्थिति	Situation arising out of withdrawal of Indian Military Liaison Group from Nepal	51
4002. यूरोपीय बाजारों को भेजने के लिये इंजीनियरी माल की मांगों का सर्वेषण	Survey of Demands of Engineering Goods for Export to European Market	52
4003. रूस को भारतीय माल का निर्यात	India's Exports to USSR	52--53
4004. भारतीय वैदेशिक व्यापार दल द्वारा बर्मा का दौरा	Indian Foreign Trade Team to Burma	53

ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4005. रूई की गांठों तथा लम्बे रेशे वाले धागे का आयात	Import of Bales of Cotton and Staple Fibre	53—54
4006. विदेशों से नेताजी सम्बन्धी दस्तावेजों का वापस लाना	Bringing back Documents on Netaji from Foreign Countries	54
4007. सिंगापुर में नेताजी के निवास स्थान का राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षण	Preservation of Residence of Netaji in Singapore as a National Monument	54—
4008. भारतीय दूतावासों में नेताजी के चित्रों का लगाया जाना	Display of Netaji's Photographs in Indian Embassies	55
4009. अफगानिस्तान और रूस में नेताजी की मूर्तियों वाले फलक	Netaji Plaques in Afghanistan and USSR	55—56
4010. कुन्नूर (दक्षिण भारत) में कल्याण एवं सम्पर्क अधिकारी का पद का भरा जाना	Filling up of Post of Welfare Liaison Officer at Coonoor (South)	56
4011. पख्तूनों का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाना	Raising of Pakhtoon issue in U. N.	56
4012. आन्ध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली देने की योजना	Scheme for Rural Electrification of Andhra Pradesh	57
4013. विद्रोही नागा जनरल अंगमी पर मुकदमा	Rebel Naga General Angami's Trial	58
4015. भारतीय निर्यात संगठन संघ के सदस्यों द्वारा अफ्रीकी देशों का दौरा	Visit by Members of the Federation of Indian Export Organisation to African Countries	58
4016. आयुध कारखानों में प्रशिक्षित बेरोजगार शिशिक्षु	Apprentices trained in Ordnance Factories without jobs	58—59
4017. विभिन्न प्रतिरक्षा संस्थाओं के सरकारी कर्मचारीयों के रूप में घोषित न किये गये कैंटीन स्टोर्स कर्मचारी	Canteen Stores Employees of Various Defence establishments not declared as Government Servants	59

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. O. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4018. अमरीका तथा यूरोप में भारत विरोधी प्रचार का खंडन	Countering Anti India Propaganda in USA and Europe	57—60
4019. बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था करना	Extension of Electicity to Rural Areas of Bihar	60
4020. प्राथमिकता वाले क्षेत्र में गंडक नहर सम्बन्धी कार्य में प्रगति	Progress of Gandak Canal in Priority Zone	61
4021. बिहार के चम्पारन जिले में सड़कों का विकास	Development of Roads in District Champaran in Bihar	61
4022. राज्य व्यापार निगम में एक अधिकारी को ऊंचा वेतन दिया जाना	High Salary given to an Officer in State Trading Corporation	62
4023. राज्य व्यापार निगम में हाल में नियुक्त किये गये व्यक्तियों को दिये गये अधिक वेतन	Higher Salary granted to the persons newly recruited in STC	62—63
4024. केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठनों में इनवैस्टिगेटरों के पद भरना	Filling up of posts of Investigators in Central Statistical Organisation	63—64
4025. बंगाल की खाडी में रूसी अनुसंधान पोत	Soviet Research Ship in Bay of Bengal	64
4026. रूसी दूतावास द्वारा लैनिन की मूर्ति का आयात	Import of a Statue of Lenin by Soviet Embassy	64
4027. चाय बोर्ड को सरकारी क्षेत्र में चाय विपणन निगम के रूप में बदलना	Conversion of the Tea Board into a Public Sector Tea Marketing Corporation	65
4028. अम्मान में नया कार्यकारी राजदूत	New Charge 'D' Affairs to Amman	65
4029. पाकिस्तान द्वारा चण्डीगढ़ के बारे में पंजाब को भड़काया जाना	Pakistan Instigation to Punjab on Chanigarh Issue	65
4030. नागाओं से चीनी गोला बारूद का बरामद होना	Ammunition with Chinese Markings recovered from Nagas	66

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4031. सूती कपड़े का मूल्य	Price of Cotton Cloth	66—67
4032. अमरीका को टाटा का निर्यात	Export of Hessian to USA	67
4033. पश्चिम बंगाल में कंगसावती परियोजना की अनुमानित लागत	Estimated Cost of Kangsabati Project in West Bengal	67—68
4034. चाय बोर्ड के कोचीन स्थित कार्यालय	Cochin Office of Tea Board	68—69
4035. काफी-चाय बोर्ड कर्मचारियों को बोनस देना	Grant of Bonus to Coffee/Tea Board Employees	69
4036. जम्मू तथा काश्मीर के लिये यथापूर्व स्थिति	Status Quo for Jammu and Kashmir	69
4037. पाकिस्तान के लिये फ्रांसीसी हथियार	French Arms for Pakistan	70
4038. भारतीयों को विदेशी पुरस्कार	Foreign Awards to Indians	70
4039. मध्य प्रदेश में हस्दो नदी पर एत्मा बांगों बांध	Etma Bango Dam on River Hasdo in Madhya Pradesh	70
4040. गत तीन वर्षों में काश्तकारों तथा मध्य आय वर्ग के तथा धनी व्यक्तियों सहित गैर काश्तकारों की आय में हुई कमी बेशी	Income Behaviours of Agriculturists and Non Agriculturists Including Middl Income Group and the Rich during Last Three Years	71
4041. भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों के प्रश्न पर विदेशों द्वारा प्रतिकारात्मक कार्यवाही	Retaliatory Action by Foreign Countries on Indian Cultural Mission Closure Issue	71
4042. ब्रिटिश जहाजों में पाकिस्तान के लिये फ्रांसीसी हथियार लाया जाना	French Arms for Pakistan in British Vessels	72
4043. जापान को लौह अयस्क की सप्लाई	Supply of Iron ore to Japan	72

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subjects	पृष्ठ Pages
4044. सिंगापुर में होने वाली राष्ट्रमंडल के प्रधान मंत्रियों की बैठक	Commonwealth Prime Minister's Meeting to be Held at Singapore	72—73
4046. अणु शक्ति विभाग द्वारा विदेश यात्रा पर व्यय की गई धन राशि	Expenditure Incurred by the Department of Atomic Energy on Visits Abroad	73
4047. क्लेरऐरफेनिकोल का आयात	Import of Chloramphenicol	73—74
4048. पंजाब में भटिंडा परियोजना की स्वीकृति	Sanction of Bhatinda Project for Punjab	74
4049. ऊनी हौजरी तथा ऊनी वस्त्र के निर्यात के लिये समान प्रक्रिया	Uniform Procedure Regarding Export of Woollen Fabrics of Hosiery	75
4050. चीन द्वारा अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रों का परीक्षण किया जाना	Testing of Inter-Continental Ballistic Missile by China	75
4051. मध्य प्रदेश से केलों का निर्यात	Export of Bananas from M. P.	75—76
4052. मध्य प्रदेश से आमों का निर्यात	Export of Mangoes from M. P.	76
4053. मध्य प्रदेश में कपड़ा मिलों में तालाबन्दियों तथा हड़तालों के कारण हानि	Loss due to Lock Outs and Strikes in Textile Mills in Madhya Pradesh	76
4055. आयुध कारखानों में बनने वाली कुछ वस्तुओं का गैर सरकारी क्षेत्र में बनाया जाना	Diversion of a Part of Production of Ordinance Factories to Private Sector	77
4056. हथकरघा क्षेत्र में रंगीन साड़ियों का उत्पादन	Production of Coloured Sarees by Hand-looms	77
4057. पूर्वी जर्मनी स्थित भारतीय वाणिज्य कार्यालय का दर्जा बढ़ाना	Upgrading of Indian Trade Office in German Democratic Republic	78
4058. दिल्ली विद्युत सम्भरण उपक्रम के कर्मचारियों की मांगें	Demands of Employees of Delhi Electric Supply Undertaking	78

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4059. मनीपुर में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध करने के लिये निर्धारित धन-राशि	Funds Earmarked for Irrigation Facilities of Manipur	79
4060. मनीपुर के काकचिंग पलेल में फालतू हवाई अड्डे का समाप्त किया जाना	Disposal of Surplus Air Field at Kakching Palel of Manipur	79
4061. मनीपुर में ग्रामीण विद्युतीकरण	Rural Electrification in Manipur	79—80
4062. इम्फाल के निकट तुलीहाल हवाई अड्डे का निर्माण	Construction of Tulihal Airport near Imphal	80
4063. भाभा आणविक अनुसंधान केन्द्र द्वारा इलैक्ट्रोन बीम से बेल्डिंग करने के एकक का डिजायन बनाना	Electron Beam Welding Unit Designed by Bhabha Atomic Research Centre, Trombay	81
4064. गार्ड प्रशिक्षण केन्द्र के शिक्षकों को रोजगार दिया जाना	Absorption of Teachers of Guards Training Centre, Kota	81
4065. गार्ड प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा	Guards Training Centre, Kota	81—82
4068. भारत जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य सहयोग पर विचार गोष्ठी	Seminar on Indo-German Democratic Republic Corporation	82
4069. हथकरघा तथा खादी और ग्रामोद्योग को एक पृथक मंत्री के अधीन लाने का प्रस्ताव	Proposal to Place Handloom and Khadi and Village Industries under a Separate Minister	82—83
4070. अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड को एक सांविधिक बोर्ड में बदलना	Conversion of All India Handloom Board into a Statutory Board	83
4071. त्यौहार के समय कच्चाटीवू द्वीप में श्रीलंका की पुलिस	Ceylonese Police in Kachchativu Island during Festival	83
4072. खेल के समान का निर्यात	Export of Sports Goods	84
4073. ब्रिटेन की एक फर्म द्वारा निर्मित एक छोटे विमान आइलैंडर की खरीद	Purchase of Small Aircraft Islander Manufactured by a British Firm	84

ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4074. हिमाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड तथा जम्मू काश्मीर में जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करना	Setting up of Hydro Electric Projects in Himachal Pradesh, Assam, Nagaland and Jammu Kashmir	85
4075. दक्षिण पूर्व एशिया सांझा बाजार की स्थापना	Establishment of South East Asia Common Market	85
4076. गोयबल की डायरियों में नेताजी के सम्बन्ध में उल्लेख	Reference about Netaji in Goebbel's Diaries	85—86
4077. विमान वाहक जहाज की उपयोगिता के बारे में विचार	Views on Role of Aircraft Carrier	86
4078. अणुशक्ति का शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिये प्रयोग	Use of Atomic Energy for Peaceful Purposes	86
4079. एच०एफ० 24 विमान	Aircraft HF—24	87
4080. ब्रिटेन द्वारा सूती कपड़ों पर शुल्क लगाया जाना	Imposition of Duty by U. K. on Cotton Textiles	87
4081. रुपयों में भुगतान सम्बन्धी व्यापार प्रणाली का दुरुपयोग	Misuse of Rupee Pattern Trade	87—88
4083. विभिन्न राज्यों से केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने वाले अधिकारियों की संख्या	Number of Officers in Central Water and Power Commission on Deputation from Various States	88—89
4084. चम्बल नहर से सिंचित क्षेत्र	Area Irrigated by Chambal Canal	89
4085. नागपुर के निकट को राडी परियोजना	Koradi Project near Nagpur	90
4086. बन्दरदारा बांध का पूर्ण होना	Completion of Bandaradara Dam	90—91
4087. तेजपुर में भारतीय वायु सेना के अधिकारी की मृत्यु	Death of an IAF Officer in Tezpur	91

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subjects	पृष्ठ Pages
4088. भारत में चीनी तथा पाकिस्तानी दूतावासों द्वारा भारत विरोधी प्रचार	Anti India Propaganda by Chinese and Pakistan Embassies in India	92
4089. वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास में चोरी	Burglary in Indian Embassy in Washington	92
4090. श्रीलंका में भारत मूलक व्यक्तियों द्वारा नागरिकता के लिये आवेदन करने की समय सीमा बढ़ाना	Extension of Time for Citizenship Applications for Persons of Indian Origin in Ceylon	92—93
4091. राष्ट्रमंडल को अधिक उपयोगी बनाने के लिये सुझाव	Suggestion to make Commonwealth more Meaningful	93
4092. पूर्वी पाकिस्तान-पश्चिम बंगाल सीमा का सीमांकन	East Pakistan West Bengal Border Demarcation	93
4093. राणा प्रताप सागर बांध का पुरा होना	Completion of Rana Pratap Sagar Dam	94
4094. उधमपुर (जम्मू तथा काश्मीर) में क्षेत्रीय सेवा रियायतें समाप्त करना	Withdrawal of Field Service Concessions in Udhampur (J. and K.)	94
4095. रूई का आयात	Import of Cotton	94—95
4096. भारत तथा श्रीलंका द्वारा संयुक्त चाय सार्थ संघ का बनाया जाना	Establishment of Joint Tea Consortium by India and Ceylon	95—96
4097. अमरीका को भारतीय माल के निर्यात में कमी	Decline in Indian Exports to USA	96—97
4098. अमरीका स्थित जनरल मोटर्स कम्पनी द्वारा भारतीय दूतावास के माध्यम से चीन के साथ व्यापार सम्बन्धी बातचीत किया जाना	General Motors Company in USA Negotiating Trade with China through Indian Embassy	97
4099. रूई का आयात	Import of Cotton	97—98
4100. दूतावासों में हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति	Posting of Hindi Officers in Embassies	98

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4101. इंडोनेशिया के साथ व्यापार करार	Trade Agreement with Indonesia	98—99
4102. अमरीकी सांस्कृतिक केन्द्रों को चलाने के वैकल्पिक प्रबन्ध के लिये अमरीका का अनुरोध	US Request for Alternative Arrangement to Run American Cultural Centres	99
4103. भारत तथा नेपाल के बीच व्यापार करार का नवीकरण	Renewal of Trade Pact between India and Nepal	99—100
4104. विद्युत पैदा करने के लिये केन्द्रीय बन अनुसंधान संस्था का सुझाव	Suggestion by Central Forest Research Institute for Power Generation	100
4105. वियतनाम में बड़े पैमाने पर हुई हत्याओं के प्रश्न को मानव अधिकार आयोग में उठाना	Raising of Issue of Mass Killing in Vietnam in Human Rights Commission	100—101
4106. "रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस" द्वारा कांग्रेस (ओ) के नेताओं की आलोचना	Radio Peace and Progress Criticism about Congress (O) Leaders	101
4107. रूस तथा अन्य यूरोपीय देशों को इस्पात का निर्यात	Export of Steel to USSR and other European Countries	101—102
4108. पश्चिम कोसी नहर का पूरा होना	Completion of Western Kosi Canal	102
4109. प्रधान मंत्री के सचिवालय में हिन्दी में प्राप्त पत्र	Letters Received in Hindi in Prime Minister's Secretariat	103
4110. उत्तर वियतनाम के विरुद्ध युद्ध में लाओस के पक्ष में अमरीका द्वारा सहयोग दिया जाना	American Participation on the Side of Laotian Government against North Vietnamese Forces	103
4111. राष्ट्रमंडल के नागरिकों पर ब्रिटेन आने पर प्रतिबन्ध	Curb on Commonwealth Citizens to Enter Britain	103—104
4112. तारापुर परमाणु शक्ति परियोजना में लोटोनियम की उत्पादन लागत	Cost of Production of Lotanium in Tarapur Atomic Power Project	104

तारा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4113. नाभिकीय विद्युत संयंत्र की लागत	Cost of Nuclear Power Plant	104—105
4114. दिल्ली में सेना मुख्यालय के आयुध निदेशालय में निर्धारित सेवावधि के बाद तक कार्य करने वाले कर्मचारी	Employees Working in Ordinance Directorate of Army Headquarters in Delhi Beyond their Tenure	105—106
4115. विद्युत चालित करघा उद्योग को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Powerloom Industry	106—107
4116. सैनिक स्कूलों से प्रतिवर्ष उत्तीर्ण होने वाले लड़के	Boys Passing out of Sainik Schools Annually	107—108
4117. अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को नियमित अधिकारियों के रूप में रखने के लिये अनुपयुक्त पाया जाना	Short Service Commissioned Officers Found Unsuitable for Retention as Regular Officers	108
4118. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा भारतीय सेना अकादमी के माध्यम से प्रतिवर्ष अफसरों का लिया जाना	Annual Intake of Officers through NDA and IMA	108—109
4119. नई दिल्ली नाँगल राया गांव की भूमि पर प्रतिरक्षा मंत्रालय का अवैध कब्जा	Land in Illegal Possession of Ministry of Defence in Village Nangal Ruya New Delhi	109—110
4120. यूनिट कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेंट (इंडिया) से अर्जित लाभ का सेनाओं के कल्याण के लिये उपयोग	Utilization of Profits Earned from Unit Canteen Store Department (India) for Welfare of Troops	110
4121. 18 पंजाब रेजीमेंट के दैनिक रूटीन आर्डर में 'रम' देने सम्बन्धी समाचार को प्रकाशित न करना	Non-Publishing of Issue of Rum in Daily Routine Order of 18 Punjab Regiment	110—111
4122. जापान में आयोजित होने वाली एक्सपो—70 प्रदर्शनी में भाग लेना	Participation in Expo—70 to be Held in Japan	111

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4123. हिन्दी संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकीय भाषा के रूप में	Hindi as Official Language of UNO	111—112
4124. पूर्वी क्षेत्रों में संयंत्रों तथा मशीनों के लिये घटिया किस्म के ईंधन का इस्तेमाल	Use of Inferior Type of Fuel for Plants and Machines in the Eastern Region	112—113
4125. गुजरात के मुख्य मंत्री द्वारा प्रधान मंत्री को दिया गया ज्ञापन	Memorandum Presented by the Chief Minister of Gujarat to the Prime Minister	113
भूकम्प पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति	Sympathy for Earthquake Victims	114
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	114
गुजरात में अंकलेश्वर तेल क्षेत्र के निकट भूकम्प	Earthquake in Gujarat near Ankleshwar Oil Fields	114—117
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	118—119
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	119
उच्चतम न्यायालय (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का परिवर्तन) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में	Supreme Court (Enlargement of Criminal Appallete Jurisdiction) Bill—As returned by Rajya Sabha	119
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	119
110 वां प्रतिवेदन	Hundred and Tenth Report	119
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	120
94 वां और 97 वां प्रतिवेदन	Ninety-Fourth and Ninety Seventh Reports	120
अनुदानों के लिये अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1969-70	Demands for Supplementary Grants (General) 1969-70	120—144
श्री श्रद्धाकार सूपकार	Shri Sradhakar Supakar	124
श्री एस० कंडप्पन	Shri S. Kandappan	124—126
श्री देवराव पाटिल	Shri Deorao Patil	126
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	126—127

तारांकित प्रश्न संख्या 3475 के उत्तर में हुई त्रुटि के बारे में वक्तव्य

Corrected Statement to Unstarred Question No 3475 dated

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्रीमती इलापाल चौधरी	Shrimati Ila Palchoudhri	128
श्री प० गोपालन	Shri P. Gopalan	128—129
श्री मीठालाल मीना	Shri Meethalal Meena	129
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	129
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiv Chandra Jha	131—132
श्री स० कुन्दू	Shri S. Kundu	132—133
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bohra	133—134
श्री दत्तात्रेय कुन्ते	Shri Dattatraya Kunte	134—135
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	135—136
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi	136—140
विनियोग विधेयक 1970	Appropriations Bill 1970	144—148
(पुरःस्थापित तथा पारित)	Introduced and Passed	144
गुजरात में आये भूकम्प के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Gujarat Earthquake	148
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	148
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (मनीपुर)	Demands for Supplementary Grants (Manipur) 1969-70 and	149
1969-70 और मनीपुर बजट 1970-71—सामान्य चर्चा और अनुदानों की मांगें	Manipur Budget, 1970-71—General Discussion and Demands for Grants	149
डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh	149—150
श्री रंगा	Shri Ranga	150—151
श्री बलराज मधोक	Shri Balraj Madhok	151
श्री धीरेश्वर कलिता	Shri Dhireswar Kalita	152
श्री भगवान दास	Shri Bhagwan Das	152
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiv Chandra Jha	152—153
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	153
श्री स० कुन्दू	Shri S. Kundu	153—154
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	154

विषय	Subjects	पृष्ठ Pages
श्री जी विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	154—155
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi	155—160
मनीपुर विनियोग विधेयक, 1970	Manipur Appropriation Bill, 1970	160
पुरःस्थापित और पारित	Introduced and Passed	160—161
मनीपुर विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1970	Manipur Appropriation (No. 2) Bill 1970	160
पुरःस्थापित और पारित	Introduced and Passed	160—161
अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1970-71	Demads for Grants (Railways) 1970-71	161—234
श्री नन्दा	Shri Nanda	230
श्री श्रद्धाकार सूपकार	Shri Sradhakar Supakar	230—231
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida	231—233
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	233—234

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 25 मार्च, 1970/4 चैत्र, 1892 (शक)
Wednesday, March 25, 1970/Chaitra 4, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारत द्वारा जेद्दाह सम्मेलन में भाग लेने की स्थिति में पाकिस्तान द्वारा उसका बहिष्कार किये जाने की धमकी

+

*602. श्री नि० रं० लास्कर :
श्री सामिनाथन :
श्री शारदा नन्द :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 फरवरी, 1970 को समाचार पत्रों में छपे इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों को सूचित किया है कि वह नहीं चाहता कि भारत जेद्दाह में मुस्लिम मंत्रियों की 23 मार्च 1970 की बैठक में भाग ले ;

(ख) क्या पाकिस्तान ने यह धमकी भी दी है कि यदि भारत प्रेक्षक के रूप में भी भाग लेगा, तो भी वह उसका बहिष्कार करेगा ; और

(ग) यदि हां, तो क्या भारत को निमन्त्रण प्राप्त हो चुका है और यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). सरकार ने इस आशय की अखबारी खबरें देखी है ।

(ग) भारत ने कोई निमंत्रण प्राप्त नहीं किया है ।

श्री पीलु मोदी : क्या उन्हें कभी निमन्त्रित भी किया जाता है ?

श्री नि० रं० लास्कर : मैं इस सम्मेलन के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता था, परन्तु मंत्री महोदय ने इस बारे में उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि सरकार ने समाचार पत्रों में समाचार देखा है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस सम्मेलन के प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया है।

श्री दिनेश सिंह : प्रश्न इसी बारे में है कि पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों को सूचित किया है कि वह नहीं चाहता कि 23 मार्च, 1970 को होने वाले सम्मेलन में भारत भाग ले। इस प्रकार के सम्मेलनों के प्रति पाकिस्तान के रवैये से सभी अवगत हैं, पाकिस्तान राजनैतिक उद्देश्यों के लिए धर्म को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है और वह चाहता है कि संगठनों का निर्माण राजनैतिक आधार पर हो, जिससे कि पाकिस्तान के हितों की पूर्ति हो सके और रबात में भी यह पूर्णतया स्पष्ट हो गया था, जहां कि वह इस उद्देश्य के लिए सम्मेलन का प्रयोग कर रहा था। इसलिये, अगर पाकिस्तान रबात वाले रवैये को दुहराता है, तो उससे हमें आश्चर्य नही होना चाहिए। पाकिस्तान का यही रवैया रहा है और हमने रबात में भी इसे देखा।

श्री नि० रं० लास्कर : क्या सरकार को पता है कि हमारे भारतीय संवाददाताओं को भी इस सम्मेलन में उपस्थित होने की अनुमति नहीं है और यदि हाँ, तो क्या वह इस मामले पर इस सम्मेलन के आयोजकों से चर्चा करेगी ?

श्री दिनेश सिंह : हमने समाचार पत्रों में खबर देखी है कि जेद्दाह जाने के लिए भारतीयों को वीसा नहीं दिया जा रहा है। हमने इस मामले पर सऊदी अरब के दूतावास से चर्चा की और उन्होंने इसका खण्डन किया है। वे कहते हैं कि यह सही नहीं है कि वीसा जारी नहीं किये जा रहे हैं। वास्तव में, उन्होंने वीसा जारी किये हैं और भारतीयों को वीसा दिये जाने पर कोई रोक नहीं है।

श्री बलराज मधोक : ये दुहरी नीति अपनाते हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, this Government received a severe set back at Rabat and the country was insulted. Now they are philosophising that incident and say that guilty countries are now repenting, but it is obvious from the latest position that Jeddah conference is a follow-up action of that Summit. This Government was not invited to attend the previous conference. Not only that, creation of Pan-Islamic Block at the instance of Pakistan on religions basis may prove to be a danger to the country and they can work against the interests of our country. In this situation, our policy towards West Asia and Arab countries has failed miserably. Our Government's policy would adversely affect our relations with Arab countries and would create tension. They asked Afghanistan to send their officers to non-aligned countries, but they replied that they were busy with Jeddah Conference and were unable to sent their officers. U. A. R. also rejected India's proposal regarding Secretariat. Do the Government approve all what happened at Jeddah and also the attitute of U. A R., Afghanistan and other countries towards us ? What is Government's reaction thereto ? Would the Government reconsider their whole policy in respect of Arab countries ?

Shri Dinesh Singh : Mr. Speaker, the Question hour is meant for furnishing information and, as Hon'ble Member knows there are other methods for having detailed discussion on policy matters. In this short time, I would like to say that I am happy that Hon'ble Member has mentioned that when organisations based on religion would step into political field, it would be against the interests of our country. From the very beginning, we are trying to stop it. We think that attempt of misusing religion for political ends is wrong and we are opposed to it. Poliltical matters should be settled through political methods only...

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, Han'ble Minister has not replied to my question. I had asked about happening at Jeddah. The journaliste are not being allowed to attend that conference and we have not been invited to participate. What is Government's reaction to all these matters ? Do they approve all this and would they reconsider their policy ?

Shri Dinesh Singh : Mr. Speaker, you also listened to the hon'ble Member's question. He has mixed up Jeddah, Afghanistan and Non-alligned-all matter in the question and I was trying to reply to all of them. When I have all thsse matters and reply to the question, Hon'ble Member does not want the reply. Hon'ble Member has asked about our reaction to the conference. In reply to the previous question asked by the Hon'ble Member, I had said that we were opposed to the misuse of religion for political ends. For solving political matters, a political conference should be concerned. We have clarified our policy in detail that we should attend only political conferences, and not religions ones.

In so far as he has stated that our journalists are not allowed to go there, I have already replied that Saudi Arabian Embassy has informed us that there is no ban on general Visa and they are issuing visas to the people.

श्री चेंगलराया नायडू : सम्मेलन के नाम से ही पता चलता है कि यह एक साम्प्रदायिक सम्मेलन है । इसे मुस्लिम राष्ट्रों का सम्मेलन कहा गया है । वे इसे मध्य-पूर्व सम्मेलन या इसी प्रकार का अन्य कोई नाम नहीं देते । यदि विदेश मन्त्रालय में जरा सी भी समझदारी है, तो उसे अभी तक इस बात का पता लग जाना चाहिये था ।

पिछली बार, अनुनय-विनय के परिणामस्वरूप, सरकार निमन्त्रण पाने में सफल हो गई थी । मुझे विदेश मन्त्री के साथ वास्तव में सहानुभूति है, क्योंकि एक ऐसा निर्णय जिसके लिये वह जिम्मेदार नहीं थे, उनके माथे मढ़ दिया गया और हमारे माननीय मन्त्री श्री फखरुद्दीन अली अहमद को जो वहां गये थे, एक जोरदार ठोकर भी लगी ।

यह शिक्षा मिलने के बाद भी सरकार ने न तो इसे समझो और न ही सचेत हुई । इस घटना के बावजूद भी सरकार ने निमन्त्रण प्राप्त करने के लिए कुछ देशों पर जोर डालने का प्रयास क्यों किया ? क्या यह सत्य है कि यद्यपि उन देशों ने कहा था कि हमारे प्रेस-प्रतिनिधियों को वीसे के साथ अनुमति दी जायेगी परन्तु पाकिस्तान द्वारा हस्तक्षेप के कारण उन्हें सम्मेलन में जाने की अनुमति नहीं दी गई ? इस प्रकार पाकिस्तान हमारे निमन्त्रण के बीच में या हमारे प्रेस-प्रतिनिधियों के सम्मेलन जाने की अनुमति के बीच में रोड़ा बना । अब सभी मुस्लिम देश भारत का वहिष्कार करने के लिए इकट्टे हो गये हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सारे मुस्लिम देश नहीं ।

श्री चेंगलराया नायडू : अधिकांश मुस्लिम देश मिल गये हैं। क्या सरकार उन मुस्लिम देशों को, जिन्होंने भारत को निमन्त्रण मिलने में बाधा डाली, शिक्षा देने के लिए कोई कार्रवाई करेगी ? क्या सरकार इस बात पर सहमत है कि देश की लाज को बचाने के लिए भारत को साम्प्रदायिक सम्मेलनों के बीच नहीं घसीटा जायेगा ? क्या यह लज्जाहीन मंत्रालय कम से कम इन तथ्यों को महसूस करेगा ?

श्री दिनेश सिंह : मैं नहीं समझ सका कि माननीय महोदय का विशेष प्रश्न क्या है। जो बातें वे सब कह रहे हैं वे उन्होंने पहली भी की थीं और इस विषय पर पूर्ण वाद-विवाद हो चुका है और हमने उसका उत्तर भी दे दिया था।

श्री चेंगलराया नायडू : क्या वे अपने राजदूतों को बुलाकर डांटेंगे।

श्री हेम बरुआ : पाकिस्तान ने केवल सम्मेलन में भारत के औपचारिक प्रतिनिधित्व का ही विरोध नहीं किया बल्कि उसने भारतीय पर्यवेक्षक दल के वहां जाने में भी रुकावट डाली। पाकिस्तान ने सम्मेलन में भारतीय पत्रकारों की उपस्थिति में भी बाधा डाली। दस दिनों के लिए किसी भी भारतीय को जेद्दाह जाने की अनुमति नही दी गई। इस सम्बन्ध में क्या किसी मित्र देश ने जो सम्मेलन में भाग ले रहे थे, पाकिस्तान के इस मत का विरोध किया कि भारत को निमन्त्रण न भेजा जाय ?

श्री दिनेश सिंह : मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमने नई दिल्ली स्थित सऊदी अरब के दूतावास से जांच पड़ताल की है और उन्होंने स्पष्ट बताया है कि उन भारतीयों को, जो सऊदी अरब जाना चाहते थे, वीसे देने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था।

श्री हेम बरुआ : पाकिस्तान रेडियो में समाचार प्रसारित किया गया था।

श्री दिनेश सिंह : भारतीयों को अनुमति न देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। इसी प्रकार पर्यवेक्षकों के जाने में भी कोई रोक नहीं थी। जहां तक मुझे पता है किसी पर्यवेक्षक को निमन्त्रित नहीं किया गया। हमने प्रतिनिधि-मंडल अथवा पर्यवेक्षकों के लिए निमन्त्रण पाने का प्रयत्न नहीं किया।

माननीय सदस्य ने रेडियो पाकिस्तान के जिस प्रसारण का हवाला दिया है, सदन को भलीभांति अत्याधिक गैर-जिम्मेदार प्रचार का पता ही है जो पाकिस्तान रेडियो से प्रसारित होता है। मुझे इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

श्री हेम बरुआ : मैं इसके लिए उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहरा रहा, मैं तो केवल कहना चाहता हूं कि क्या उन्होंने प्रसारण के बारे में कुछ सुना है ?

श्री रा० बरुआ : उनके उत्तर से स्पष्ट है कि पाकिस्तान ने भारत का कड़ा विरोध किया है। क्या उनका ध्यान नरेश फीज़ल के भाषण की ओर दिलाया गया है जो हमारे हित में नहीं है। प्रश्न संख्या 621 के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है कि धार्मिक सम्मेलनों में सरकारी प्रतिनिधि-मंडल नहीं भेजे जाते हैं। उसी समय वे यह भी कहते हैं कि अगर कोई निमन्त्रण आता है तो उसका मूल्यांकन किया जाता है और सरकार विचार कर सकती है कि क्या

प्रतिनिधि मंडल को भेजना उचित होगा या नहीं। अतः क्या मंत्री महोदय इन दो विभिन्न विचारों का, जो उन्होंने प्रकट किये हैं, समाधान करेंगे ?

श्री दिनेश सिंह : हम उस प्रश्न पर नहीं आए हैं। मुझे स्पष्ट नहीं हुआ कि क्या आपने दोनों प्रश्न मिला दिये हैं ? जहां तक सम्मेलन में भाग लेने का प्रश्न है, इसका विवेचन विस्तार-पूर्वक सदन में हो चुका है। हमने पहले ही बता दिया है कि हम सम्मेलनों में धार्मिक और राजनीतिक समस्याओं को मिलाने के विरुद्ध हैं, और अगर उसे सम्मेलन को उस समय धार्मिक सम्मेलन मान लिया जाता है और हमें निमन्त्रित किया जाता है तो हम उन विषयों को जिनकी चर्चा सम्मेलन में होनी है, तथा अपनी लाभ-हानि को ध्यान में रखकर ही निर्णय करेंगे। हमारे लिए यह बहुत कठिन होगा कि हम सम्मेलन में भाग लेने की स्वीकृति पहले से ही दे दें। जब सम्मेलन बुलाया जाता तो हमें निमन्त्रण मिलता है और वही सोचने का समय होता है कि हमें सम्मेलन में भाग लेना चाहिए या नहीं ? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारी प्रथा रही है कि हम सरकारी स्तर पर किसी भी धार्मिक सम्मेलन में भाग नहीं लेते और इस प्रथा को बदलने का हमारा कोई विचार नहीं।

Shri Jageshwar Yadav : The Reception Committee, Jeddah invited India and if another Nation objects to that invitation, is it not the responsibility of the Reception Committee to take strict action against that nation ? Similarly during the last conference Muslim nations objected to the invitation, can there be no objection from Reception Committee that India should not be insulted again and again ? Those natians say nothing about Pakistan.

Shri Dinesh Singh : So far as Rabat Conferenc is concerned the matter has been discussed in detail in Parliament. No invitation has yet been received so far as this conference is concerned. We do not know even about the invitation which caused insult unto India. I do not think that any matter has arisen about the invitation to India.

श्री फ० गो० सेन : मन्त्री महोदय ने कहा है कि सम्मेलन में भाग लेने पर किसी पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। क्या मैं जान सकता हूँ कि सम्मेलन में भाग लेने के लिए सरकार किसी प्रतिनिधि को बुलाने का सुझाव दे रही है ?

श्री दिनेश सिंह : नहीं, महोदय। हम किसी के नाम का सुझाव नहीं दे रहे हैं।

आई० एन० ए० के शहीदों के स्मारक को पुनः बनाने के लिए सिंगापुर सरकार के साथ बातचीत

*603. **श्री समर गुह** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सिंगापुर की यात्रा कर रहे भारतीय संसद् दल द्वारा आई०एन०ए० के शहीदों के उस स्मारक को दुबारा बनाने के प्रयत्नों की ओर दिलाया गया है जिसे ब्रिटिश सेना ने गिरा दिया था ;

(ख) क्या दल ने सिंगापुर के विदेश मन्त्री से आई० एन० ए० के स्मारक को दुबारा बनाने के बारे में पहल करने का निवेदन किया था ;

(ग) क्या सिंगापुर के विदेश मन्त्री सिंगापुर सरकार के साथ इस मामले को उठाने के लिए सहमत थे ; और

(घ) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय सम्मान को बनाये रखने के लिए आई० एन० ए० के स्मारक को दुबारा बनाने के कार्य के सम्बन्ध में सिंगापुर की सरकार से बातचीत की गई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). 4 फरवरी, 1970 को सिंगापुर के विदेश मन्त्री के साथ संसद् सदस्यों के सद्भावना मिशन की बैठक जब खत्म होने को थी तो, बताया जाता है कि एक सदस्य ने यह पूछा था कि सिंगापुर सरकार द्वारा आजाद हिन्द फौज शहीद स्मारक के पुनर्निर्माण की क्या सम्भावना है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री समर गुह : 1945 में, किसी अज्ञात मंजिल की ओर जाने से पहले नेताजी ने सिंगापुर में आई०एन०ए० स्मारक बनाया । मैंने बर्मा, मलेशिया, कम्बोडिया, इंडोनेशिया आदि प्रायः सभी दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की यात्रा की है और प्रायः सभी देशों के नेताओं से मिला हूँ तथा सभी ने सर्वसम्मति से कहा है कि नेता जी से उनको प्रेरणा मिली है और वे मानते हैं कि एशियन क्रांति के लीडर नेता जी हैं । नेता जी द्वारा दिये गये स्वातन्त्र्य भाषण के बारे में उन्होंने मुझे याद दिलाया ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न कीजिए । प्रश्न पूछने सम्बन्धी प्रक्रिया को विकृत मत कीजिए ।

श्री समर गुह : मैं विषय पर आऊंगा परन्तु यह प्रश्न केवल भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के बारे में ही नहीं है अपितु समस्त एशिया के स्वतन्त्रता संघर्ष का सवाल है । जापान में 1943 में आयोजित दक्षिण-पूर्व एशिया सह-समृद्धि सम्मेलन में नेता जी के ऐतिहासिक भाषण की ओर उन्होंने मेरा ध्यान दिलाया । एशियाई प्रतिनिधियों को कठपुतली के समान निश्चेष्ट समझा जाता था लेकिन सम्मेलन के पश्चात् उन्होंने कहा कि वे अनुभव करते हैं कि वे प्रधान थे । उस सम्मेलन में नेता जी ने कहा :

> "यह सम्मेलन विजेताओं के बीच लूट के धन को बांटने के लिए नहीं बुलाया गया है.....अपितु यह तो एशियाई देशों में एशियाई भावनाओं को विकसित करने तथा एशियाई क्रांति के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने का मामला है ।"

इसलिये, मेरे विचार से आजाद हिन्द शहीद स्मारक का नेता जी द्वारा बनाया जाना केवल भारतीय स्वाधीनता संघर्ष का प्रतीक ही नहीं है अपितु दक्षिण-पूर्व एशियाई क्राँति का भी प्रतीक है । सिंगापुर पर कब्जा करने के पश्चात् यह मोउंटबेटन द्वारा गिरा दिया गया था । मेरा प्रश्न यह है कि नेता जी द्वारा बनाए गए आई० एन० ए० स्मारक और शहीदों के स्मारक को पुनः बनाने के लिए क्या सरकार सिंगापुर सरकार के सहयोग से कार्यवाही करेगी ?

श्री दिनेश सिंह : हमारे देश की स्वाधीनता के लिये शौर्यमय संघर्ष में नेताजी की भूमिका और एशिया में इस क्रांति का प्रभाव इतिहास का अंग है जो तब तक जीवित रहेगा जब तक इन आन्दोलनों का रिकार्ड रहेगा। यह बिल्कुल ठीक है जब माननीय सदस्य कहते हैं कि नेता जी का योगदान भारत तक ही सीमित नहीं रहा था अपितु समस्त एशिया में फैला हुआ था।

मैं तो यह भी कहूँगा कि वस्तुत: उन्होंने क्रांतिकारी आन्दोलनों को सम्पूर्ण विश्व में फैलाया। जिस प्रश्न पर यहां विचार किया जा रहा है, वह सीमित है वह प्रश्न है जो स्मारक गिरा दिया गया है उसको बनाने के बारे में यह नया विषय नहीं है। इस प्रश्न पर सदन में हमने कई बार विचार-विमर्श किया है और सरकार का यह रुख रहा है कि वे इस प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और सम्बन्धित देश में इस विषय में किये गये कार्य और उस सरकार की प्रतिक्रिया तथा अन्य बातों की ओर ध्यान देगी। इसको हम ध्यान में रखेंगे और यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो इस प्रयास में निश्चित ही हम सहयोग देंगे।

श्री समर गुह : यह विदित है कि नेता जी के दो निवास थे, एक सिंगापुर में और और दूसरा बर्मा में और आजाद हिन्द सरकार का प्रधान कार्यालय भी सिंगापुर में ही था। दक्षिण वियतनाम की सरकार ने हाल में ही सैगोन में उस स्थान पर स्मृतिफलक बनाया जहां नेता जी ठहरा करते थे। इन सभी तथ्यों को देखते हुए मैं सरकार से जानना चाहूँगा कि क्या सम्बन्धित सरकार की मदद से रंगून और सिंगापुर में बनी इमारतों को और आजाद हिन्द सरकार द्वारा प्रयोग में लाये गये मुख्य कार्यालय को अभिग्रहण करने अथवा खरीदने का वे प्रयास करेगी ? और केथी होटल पर स्मृतिफलक बनाया जाएगा जहां नेता जी ने स्वाधीनता की उद्घोषणा की और आजाद हिन्द आन्दोलन को चलाया था ?

श्री दिनेश सिंह : हमारे समक्ष इस समय कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है। सामान्यतया हमारे विशिष्ट नागरिकों के ये स्मारक विभिन्न समितियों को सौंपे गये हैं और यदि किसी स्रोत से कोई विचार रखा जाता है, तो इस पर उनको सहायता देने के लिए हम अवश्य ही पूर्ण प्रयत्न करेंगे।

Shri Hukam Chand Kachwai : If any person or Government is ready to publish big volume on the life of Netaji and the different countries that he had travelled, and in this connection if any person is willing to go to any foreign country for research work then what facility the Government will give to him.

Mr. Speaker : The question which is being discussed here relates to INA Martyrs' Monument in Singapore, with which the question of any person publishing a volume on the life of Netaji and conducting travel for that purpose is not connected.

Shri Hukam Chand Kachwai : To throw light on the life of Netaji and to travel for writing a volume on his life is connected with the same question.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The question has extended a little bit.

Mr. Speaker : The hon. Member, as I have already said has brought in a number of things which are extraneous to the present question.

Shri A. S. Saigal : He had talks with the Singapore authorities in which he had stressed that Netaji Subhash Bose was a prominent leader of our country. What were the difficulties felt by him, during the course of his said talks, in rebuilding the INA martyrs memorial in Singapore which was demolished by the British Army ?

Shri Dinesh Singh : That talk was held by an honourable member of this House who will be knowing in details about this. We came to know only this that much anxiety was not shown from the other side.

Shri Prakash Vir Shastri : Fortunately I was a member of that delegation which had a talk about this with the foreign Minister of Singapore. It is a fact that this was the last item which was discussed that the Government of Singapore should accord permission for rebuilding the INA memorial which was built by Netaji Subhash Chander Bose, but the foreign Minister of Singapore had expressed his ignorance about this matter. He was very much surprised and said that he never knew about the information and background regarding the construction of memorial I have brought two photos also from there which show the condition of the memorial of INA when it was there and when Lord Mountbatten demolished it. I have brought both the photos. The point which I want to know is that it appeared from the discussion with the foreign Minister that the Government of India had had no talks of any kind with the Government of Singapore regarding rebuilding the memorial of INA. I want to know clearly that if he has not written to the Government of Singapore about this so far, then will he write now that the INA Memorial in Singapore which is a great memorial of Indian Freedom struggle may he rebuilt ? On the basis of the treatment of the Government of Singapore I assure you that they have such friendship towards India that if our Government request them then perhaps they will not find any difficulty in rebuilding that memorial. Why the Government do not insist on this and if the Government has insisted then what reply has been received from the Government of Singapore ?

Shri Dinesh Singh : As I have already mentioned, this issue has been there for a long time. We have gathered the impression that the Government of Singapore is not so anxious about it. The honourable member has himself stated that this matter was taken up with them at the last moment. If this matter was to be taken up with them then we should have also been informed before hand here or they should have been informed about this before hand and then the matter could be discussed methodically and the position clarified. So far as the question of our taking up the matter is concerned, we can discuss with them at an appropriate time but perhaps it will not be proper then to discuss that in detail here.

अफ्रीकी देशों में भारतीय दूतावासों के प्रधानों की बैठक

*604. **श्री मीठालाल मीना :** **श्री महेन्द्र माझी :**
श्री गु० च० नायक : **श्री सी० मुत्तुस्वामी :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हाल में अफ्रीकी देशों में भारतीय दूतावासों के प्रधानों की एक बैठक बुलायी थी ;

(ख) यदि हां, तो अफ्रीका में भारतीय नीतियों के सम्बन्ध में हमारे राजनयिकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या दूतावासों के प्रधानों से प्राप्त रिपोर्टों तथा दिल्ली में हुए विचार-विमर्श को दृष्टि में रखते हुए, सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन करना वांछनीय समझती है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क), (ख), (ग) और (घ). दिसम्बर 1969 में अफ्रीका में भारतीय मिशनों के प्रमुखों का एक सम्मेलन हुआ था। सामान्य रूप से यह महसूस किया गया कि आर्थिक तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से अफ्रीकी देशों के साथ हमारे वर्तमान मित्रतापूर्ण और सौहार्दपूर्ण सम्बंध और भी सुदृढ़ किए जाएं, जिससे अफ्रीका के प्रति हमारी नीति और अधिक सार्थक सिद्ध हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

Shri Meetha Lal Meena : Mr. Speaker, Indian export and import trade during the last four years amounted to about Rs. 70 crores. Our import figure has increase to Rs. 150 crores whereas export figure is still the same *i.e.* Rs. 7[illegible] crores Are the Government taking note of the problem that our imports are increasing and there is no increase in our exports ? Has this issue been ever discussed by our ambassadors ? If so, how do the Government propose to increase the export ?

Shri Surendra Pal Singh : All these issues were discussed at the Conference and it was decided that as far as possible our envoys should exert to increase trade and commerce. They have given their findings to us end we hope that our trade and commerce will increase.

श्री रंगा : मन्त्री महोदय सामान्य उत्तर दे रहे हैं। वास्तविक प्रश्न तो यह था कि क्या हमारा आयात बढ़ रहा है और निर्यात कम होता चला जा रहा है ? वह इसका सीधा उत्तर क्यों नहीं देते ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : यदि माननीय सदस्य इसका स्पष्ट उत्तर चाहते थे तो उन्हें यह प्रश्न सीधे वैदेशिक-व्यापार मंत्री से करना चाहिए था जो उन्हें आयात निर्यात के आंकड़े भी दे देते। माननीय आचार्य जी इस बात की पुष्टि करेंगे कि जब एक सामान्य प्रश्न पूछा जाता है तो उसके ठीक ठीक आंकड़े देना बहुत कठिन होता है।

Shri Meetha Lal Meena : It is claimed by our foreign Minister and other officers that we are maintaining cordial relations with African countries and they are abiding by our policies. But when the African countries are visited by our Ministries or delegations, they are neither treated properly nor the Ministers of African countries spare time to meet them. So I would like to know whether they are readily abiding by our policies, as said by honourable Minister ? In case they ane not doing so, will the Government change its policies in such a way that in future we may get a better treatment from African countries ?

Shri Dinesh Singh : When the question of our policy comes up, we will call for the views of honourable Member. But so far as policy of strengthening our firendship, Co-operation and trade is cancerned, I think it is proving useful to us. There are certain problems which are lingering since long. We are trying to sort them out in such a way that people who are residing in these countries may face minimum problems. Many times the House has discussed all these problems in detail and we are trying to solve the problems of Indians people who have settled there. We are trying that even if they are to leave, we should create such conditions, in which they may not face any difficulty.

Shri Meetha Lal Meena : It is said in the House that so many things are being done. How long, we will go on doing it ? What will as a result of all this, their attitude towards us be improved within six or seven months ?

श्री महेन्द्र माझी : क्या यह सत्य है कि पूर्वी अफ्रीका की सरकारें इस सम्बंध में कोई समझौता करने को तैयार नहीं हैं कि एशिया के उन लोगों का भविष्य क्या होगा जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हैं ? क्या मिशन-अध्यक्षों के सम्मेलन में इस विषय पर विचार-विमर्श किया गया था ? यदि हां, तो इस संबंध में उन की क्या प्रतिक्रिया थी ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : ब्रिटिश पासपोर्ट वाले भारत मूलक आदिवासी लोगों की इस समस्या पर भी इस बैठक में विचार विमर्श किया गया था । अधिकांश लोगों का यह मत था कि नीति के विषय में जो निर्णय किया गया है वह सन्तोषजनक है और वह लागू रहना चाहिए ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : समाचारपत्रों में निरन्तर यह समाचार प्रकाशित हो रहा है कि अफ्रीका के अधिकांश लोग यह समझते हैं कि भारत अफ्रीका में पुर्तगाली अधिकार के उपनिवेषों, रोडेशिया, दक्षिणी अफ्रीका, अंगोला और माजाम्ब्यू के मुक्ति आन्दोलनों के लिए विश्व परिषदों में उचित प्रयास नहीं कर रहा है मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सम्मेलन में समस्या के इस पहलू पर मिशन—अध्यक्षों के प्रतिवेदनों के आधार पर कोई विचार किया गया था और अफ्रीका के बहुमत की इस धारणा के प्रति भारत की प्रतिक्रिया क्या हुई और भारत का उपनिवेषवाद से मुक्ति पाने वाले प्रथम राष्ट्र के नाते जो सम्मान है, अफ्रीकी लोगों के समक्ष भी उसे बनाये रखने के लिए क्या भारत और अधिक सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए तत्पर है ?

श्री दिनेश सिंह : मैं इस सन्दर्भ में यही कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने इस विषय पर गलत साहित्य पढ़ लिया है । अफ्रीका के मुक्ति आन्दोलन में कहां तक भारत के योगदान का सम्बन्ध है मेरे विचार से तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में या अन्य इसी प्रकार के निकायों में स्वतन्त्रता के लिए लोगों के लिए जो ढील प्रयत्न किये हैं उन की काफी सराहना की गई है । सदन को यह मालूम ही है कि हम ने इन देशों के बहुत ऐसे विद्यार्थियों को आन्दोलन प्रशिक्षण दिया हैं जो यहां पढ़ने के लिए या प्रशिक्षण के लिए आये थे । हमने समय-समय पर उन्हें डाक्टरी सहायता के साथ-साथ अन्य सहायता भी प्रदान की । जहां तक मैं समझता हूँ हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों को बनाने और उन्हें क्रियान्वित कराने का जो कार्य किया है । उसकी सराहना की गई है । समस्या यह नहीं है कि हम अपना दायित्व पूर्ण नहीं निभा रहे हैं । वरन् वास्तविक समस्या यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जिन राष्ट्रों की भूमिका द्वारा स्थिति में विशेष परिवर्तन आ सकता है वह इस के प्रस्तावों की पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं । यदि इन प्रस्तावों को पूर्ण बल से क्रियान्वित किया जाये तो इससे स्वतन्त्रा के लिए संघर्षशील लोगों को बहुत सहायता हो सकेगी और वह लोग रंग भेद मुक्त स्वतंत्र समाज में रह सकेंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने सीधा प्रश्न पूछा था जिसका कोई उत्तर नहीं दिया गया । मैं अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर सामान्य वार्तालाप नहीं चाहता । मैं तो यह जानना चाहता था कि मिशन-अध्यक्षों के इस सम्मेलन में अफ्रीकी लोगों द्वारा भारत के प्रति इस रवैये के बारे में प्रतिवेदनों की दृष्टि से कोई विचार किया गया ? यदि विचार किया गया तो क्या उसके आधार पर स्थिति का पुनरीक्षण किया गया ?

श्री दिनेश सिंह : मैं पहले ही कह चुका हूं कि कोई ऐसा समाचार नहीं है जिससे कि भारत की स्थिति को गलत समझा गया हो या ऐसा अनुभव किया गया हो कि भारत ने अपनी

प्रमुख भूमिका नहीं निभाई । अपितु दूसरी ओर लोगों की यह धारणा है कि भारत से इन राष्ट्रों की जितनी सहायता हो सकती थी, उसने की है ।

श्री रंगा : भारतीय लोगों के विभिन्न वर्ग यथा भारत मूलक लोग जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, वे भारतीय जिन्होंने स्थानीय नागरिकता स्वीकार कर ली है, वे भारतीय जो अभी भारतीय नागरिकता को ही स्वीकार किए हुए हैं जो विभिन्न देशों विशेषता कोनिया, उगांडा और नयासालैंड आदि में हैं उन्हें हमारे वाणिज्य बोर्ड, औद्योगिक विकास वित्त और विदेशी मामलों के मन्त्रालयों के साथ व्यवहार करते समय कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । क्या सरकार ने विभिन्न मन्त्रालयों के सचिवों और मन्त्रिमण्डल की ऐसी उप-समिति बनाने की सम्भावना पर विचार किया है या विचार करने की सम्भावना है जिसकी समय समय पर बैठक हो और वह उन कठिनाईयों पर विचार करे जो इस सदन की जानकारी में लाई गई हों या सम्बद्ध मन्त्रालयों की जानकारी में लाई गई हों । अभी पिछले ही दिन मेरे माननीय मित्र अमीन और कुछ अन्य सदस्यों ने इस ओर ध्यान दिलाया था कि कोई ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिस के द्वारा इन लोगों की अपनी पूंजी यहां लाने के लिए ब्रिटिश सरकार और अफ्रीका की सरकारों से कुछ छूट दिलाई जा सके । क्या सरकार इस दिशा में कोई प्रयत्न करेगी कि अफ्रीकी देशों में बसे विभिन्न भारतीय वर्गों के लोगों को कोई छूट दी जा सके या उन्हें अन्य सहायता दी जा सके ?

श्री दिनेश सिंह : उन भारत मूलक लोगों को जो कि भारत में आना और भारत में ही बसना चाहते हैं कौन सी सुविधायें दी जा रही है इसके बारे में सदन को पहले ही बताया जा चुका है । विभिन्न सम्बद्ध मन्त्रालयों में उन पर विचार-विमर्श भी हो चुका है और इस योजना को लागू करने में मुख्यत: कोई रूकावट नहीं आई । यदि माननीय सदस्य कोई और विशेष बात कहना चाहते हों तो निश्चय ही उस पर विचार किया जा सकता है । जहां तक अधिकृत धन से अधिक पूंजी लाने का प्रश्न है इसे सम्बद्ध देशों के साथ तय किया जा चुका है ।

श्री रंगा : सीमा को समाप्त करना होगा । इस पर किसी प्रकार की सीमा नहीं होनी चाहिये ।

श्री दिनेश सिंह : जो योजनायें बनाई जा रही हैं उनके बारे में कुछ चर्चा हो रही है । मुझे ठीक से याद नहीं है कि इस प्रकार की कोई योजना हमारे सामने आई हो, परन्तु यह एक ऐसा विषय है जिस के विषय में हम सम्बद्ध सरकारों के निरन्तर सम्पर्क बनाए हुये हैं कि भारत यह देखने के लिये आने वाले लोगों को किन सुविधाओं की आवश्यकता है और उन्हें कौन कौन सी सुविधायें दी जा सकती हैं ।

श्री रंगा : मेरा सुझाव पूर्णतया स्पष्ट था । मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय उस पर विचार करें ।

श्री दिनेश सिंह : मैं कह चुका हूँ कि मैं विचार करूंगा, परन्तु वह सुझाव है कहां ? मेरे पास तो अभी कोई योजना नहीं भेजी गई है ।

श्री रंगा : आप या तो मंत्रिमण्डल की एक उपसमिति बना लो या अपने सचिवों की ही ऐसी समिति बना लो जो समय समय पर मिलकर इन बातों पर विचार करती रहें और आप का कार्य भार कुछ कम हो जाये ।

श्री दिनेश सिंह : मैंने भी तो यही बात कही है। जब हमारे पास निश्चित योजना होगी तो आवश्यकतानुसार निश्चय ही हम उसे किसी समिति को सौंप देंगे।

डा० रेनन सिंह : अंगोला मोजम्बिकू दक्षिणी अफ्रीका और अफ्रीका के अन्य देशों में जातिगत प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष जारी है और अफ्रीका में साम्राज्यवादी पुनः सत्ता छीनने के लिए प्रत्यनशील हैं। क्या आप यह बतायेंगे कि भारतीय राजदूतों के सम्मेलन में इन प्रश्नों पर विचार किया गया था ? यदि हां तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई दिशा निर्देश दिया कि अफ्रीका के ऐसे अन्दोलनों की किस प्रकार सहायता की जाये ?

श्री दिनेश सिंह : मैं एक प्रश्न के उत्तर में भी यह स्पष्ट कर चुका हूं कि भारत संयुक्त राष्ट्र में या अन्य देशों में सदा ही इस प्रकार के अन्दोलनों की सहायता करता रहा है इन देशों के लोग यहां शिक्षण और प्रक्षिशण पाते रहे हैं और जहां तक हो सकेगा हम इन देशों की सहायता करते रहेंगे।

डा० रेनन सेन : मेरा प्रश्न दूसरा था। मैं तो यह जानना चाहता था कि क्या भारत सरकार ने इस राजदूत सम्मेलन में क्या इस प्रकार का कोई निर्देश दिया कि अफ्रीका के जो लोग मुक्ति आन्दोलन के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनकी क्या सहायता की जा सकती है या उनसे कैसे सहानुभूति प्रकट की जा सकती है ?

श्री दिनेश सिंह : मैं नहीं समझता कि स्वतन्त्र देशों के राजनयिकों को निर्देश देने से माननीय सदस्य का क्या तात्पर्य हो सकता है ? माननीय सदस्य को सम्भावतः मालूम नहीं है कि राजदूत स्वतन्त्र देशों से होते हैं और स्वतन्त्रता संघर्ष उन देशों में हो रहा है जिन्होंने अभी स्वतन्त्रता प्राप्त करनी है। इसीलिए उन संघर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य सम्बद्ध स्थलों में ही रहा है। जहाँ तक उन्हें सहायता देने की हमारी नीति का सम्बन्ध है उस पर निश्चय ही विचार-विमर्श किया गया था।

Shri Suraj Bhan : I would like to know whether this issue was taken up in the conference that when a goodwill mission of ten members of Parliament visited Egypt, President Nassar failed to spare some time to see them despite the best efforts of our Ambassador...

अध्यक्ष महोदय : इसका प्रश्न विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Suraj Bhan Singh : Whereas he could share time to see Krishna Mennon who visited that country in an individual capacity.

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I know why you do not allow this question ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न अफ्रीका में भारतीय राजनीति की प्रतिक्रिया के ब्यौरे के सम्बन्ध में है न कि किसी व्यक्ति विशेष को राष्ट्रपति से मिलने देने या अन्य व्यक्तियों को न मिलने देने के सम्बन्ध में। क्षमा कीजिये, मैं इस की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री धीचंद गोयल : इस से इन के रवैये का पता चलता है...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : उस ने सूचना भी दी और साथ यह भी पूछा कि क्या मन्त्री महोदय इस से अवगत हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्हें निश्चय ही इस का पता होगा ।

श्री बलराज मधोक : उन्हें पूछताछ करने दीजिये । क्या प्रतिनिधि मण्डल की अपेक्षा कृष्णमेनन अधिक महत्व पूर्ण व्यक्ति हैं ?...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : मैं इस की अनुमति नहीं देता क्योंकि इस का कोई परिणाम नहीं निकलेगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसका अपना महत्व है नहीं तो आप एक अलग प्रश्न की अनुमति दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह स्वीकार है और मैं अनुमति दे दूंगा ।

श्री मनुभाई पटेल : यह सत्य है कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो सक्रिय कार्य किया गया था उस के प्रति अफ्रीका के लोगों में भारत के प्रति बहुत सद्भावना है । मैं नहीं जानता कि क्या यह सद्भावना आज भी बनी हुई है । मैं समझता हूं कि हम बहुत तीव्रता से इसे खो रहे हैं । विशेषतया पूर्वी अफ्रीका के देशों के भारतीय लागों में यह भावना दृष्टिगोचर होती है कि हम उन लोगों की कठिनाईयों की ओर कोई ध्यान नही देना चाहते । ब्रिटिशवासी निम्न कोटि के नागरिक थे, परन्तु ब्रिटिश सरकार ने कीनिया सरकार को ऋण देते समय ऐसी नीतियां अपनाई जिन के अन्तर्गत यह निश्चय किया गया कि ब्रिटिशवासियों को कीनियां छोड़ने के लिए बाध्य किया जायेगा, सरकार उन्हें उनकी सम्पत्ति का उचित मुआवजा देगी । भारतवासियों ने भी अपनी वहां की सम्पत्ति पर बहुत पूँजी लगा रखी है वे यहां आना चाहते हैं परन्तु वह अपनी भूमि सम्पति वहां नहीं छोड़ सकते । क्या आप यह बतायेंगे कि क्या मिशन-अध्यक्षों की बैठक में किसी इस से सम्बद्ध इस प्रकार की योजना पर विचार-विमर्श किया गया था । माननीय मन्त्री महोदय ने अभी कहा कि उनके साथियों ने इस प्रकार की कोई योजना प्रस्तुत नही की है । क्या आप अपने साथियों द्वारा योजना लाने की प्रतीक्षा करेंगे या सरकार स्वयं ही कोई योजना बना कर उन भारतियों को कुछ सहायता देगी ?

श्री दिनेश सिंह : हमें सम्पूर्ण भारतीयों के हित की दृष्टि से विचार करना है । माननीय सदस्य ने मेरे साथ इसी विषय पर बातचीत की थी । सदन में भी उन्होंने इस का उल्लेख किया । संसद के अन्य सदस्य भी जो प्रतिनिधि मण्डल के साथ थे, विभिन्न धारणायें बना वापिस लौट चुके हैं । अब हमें इस से उत्पन्न होने वाली सभी भलाईयों को देखना होगा ? क्या धन लाने की मांग पर जोर देना उन के हित में होगा ? यह देखना भी उन्हीं के हित में होगा कि वे कब तक वहां रह सकते हैं, और किस प्रकार वे अपने जीवन को देश की राष्ट्रीय जीवन धारा में समाहिक कर सकते हैं । हमें यह देखना है कि अफ्रीका में भारत मूलक लोगों के बारे मे कोई विशेष धारणा न बन जाये । इसलिए हमें समस्या पर विभिन्न दृष्टियों से विचार करना होगा । अतः किसी विशेष सुझाव पर विचार करते समय हमें समस्या के सभी पहलुओं पर दृष्टि रखनी पड़ती है ।

अध्यक्ष महोदय : जो सद्भावना मिशन अलग से वहां गया था क्या आप उसे मिले हैं या केवल इन की बातों का उत्तर देने के लिए यह कह रहे हैं । मेरा विचार है कि उन्हें अलग से आप को मिलकर अपने सुझाव दे देने चाहिए थे ।

श्री दिनेश सिंह : इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जब मिशन ग अध्यक्षों की बैठक हुई थी तो इन सभी विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा सुझाव है कि आप उस शिष्टमंडल से मिलें और उनसे इस विषय पर चर्चा करे ।

श्री स० कुण्डू : मुझे ज्ञात नहीं कि क्या मंत्री महोदय यह जानते हैं कि अफ्रीकी देशों में चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है । मुझे सूचित किया गया है कि चीन अब तक लगभग 200 सांस्कृतिक शिष्टमंडल इन देशों को भेज चुका है और उन्हें पर्याप्त औद्योगिक तथा सांस्कृतिक सहायता दे रहा है । क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्री महोदय अफ्रीका में चीन के प्रभाव से अवगत हैं ? उन देशों से भारत को दूर रखने का यह भी एक कारण है । क्या दूतावासों के अध्यक्षों की बैठक में इस पर विचार-विमर्श हुआ था ? मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार अफ्रीका में भारत के दृष्टिकोण को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने के लिए कार्य कर रही है ?

श्री नाथ पाई : अधिक आकर्षक ढंग से ।

श्री दिनेश सिंह : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है अधिक आकर्षक ढंग से ।

श्री स० कुण्डू : क्या इन्होंने समस्या को समझा है ? क्या किसी मंत्री द्वारा इस प्रकार उत्तर दिया जाना चाहिये ?

श्री नाथ पाई : सभी वक्ताओं ने यह कहा है कि अफ्रीकी देशों में हमारे लिए बहुत सद्-भावना थी । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने अफ्रीकी राष्ट्रों द्वारा स्ततंत्रता के लिये किये गये संघर्ष का पूर्ण समर्थन किया । अफ्रीकी देशों में हमारी परम्परा और गांधी जी के कारण हमारे लिए बहुत सद्भावना थी । अब सामान्य धारणा यह है कि इस सद्भावना का धीरे-धीरे विलोप हो रहा है । हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार अफ्रीकी जनता और देशों में भारत को एक स्थायी मित्र के रूप में प्रस्तुत करने के लिए क्या पग उठा रही है ? यही प्रश्न महत्वपूर्ण है ।

श्री स० कुण्डू : यह कितना आश्चर्य प्रद है ? यह एक महत्वपूर्ण समस्या है । वह इसे यों ही उड़ाये दे रहे हैं । हमारे सभी दूतावास वहाँ सो रहे हैं । इस क्षेत्र में प्रति वर्ष हमारी तस्वीर धुंधली पड़ती जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया इनकी बात सुनिये ?

श्री दिनेश सिंह : मेरी कठिनाई यह है कि मैं इस धारणा से सहमत नहीं हो पा रहा कि हमारी स्थिति कमजोर होती जा रही हैं । अफ्रीकी देशों से हमारा सहयोग निरन्तर दृढ़ होता जा रहा है यह प्रश्न...(**व्यवधान**)

श्री नाथ पाई : आत्म संतुष्टि नहीं ।

श्री स० कुण्डू : चीन की तुलना में हमारी स्थिति कमजोर होती जा रही है । मैं चुनौती देता हूँ । अफ्रीका में हमें एक शिष्टमंडल भेज कर देख लेना चाहिये ।

श्री दिनेश सिंह : यदि माननीय सदस्य उत्तर सुनना चाहते हैं तो मैं उत्तर देने का प्रयत्न करूं किन्तु यदि वह यही कहना चाहते हैं कि हमारी स्थिति कमजोर होती जा रही है तब बात दूसरी हैं । दे अपना वक्तव्य दे चुके हैं और मैंने उसका उत्तर भी दे दिया है । अतः यह मामला यहीं समाप्त हो जाता है । प्रश्न यह था कि अफ्रीका में स्ततंत्रता के लिए संघर्ष चल रहा हैं । विश्व समाज में संयुक्त राष्ट्र संघ में तथा अन्य मंचों पर जहां भी इन देशों को स्वतंत्रता दिलाने का प्रयत्न किया गया हमने पूर्ण सहयोग दिया । वह चरण अब पूर्ण हो चुका है । हम वहाँ यह झंडा नही गाड़ सकते क्योंकि हमने आपकी सहायता की थी हमारा स्थान हमेशा के लिए यहां बना रहेगा । सम्बन्ध बनाने की यह कोई अच्छी पद्धति नहीं है । प्रश्न सम्बन्धों में विकास लाने का है । अब उन्हें किस बात की आवश्यकता है ? क्या उन्हें सांस्कृतिक शिष्टमण्डल की आवश्यकता है ? उन्हें सांस्कृतिक शिष्टमंडल नहीं चाहिए । उन्हें आर्थिक मामलों में सहयोग की आवश्यकता है और माननीय सदस्य सांस्कृतिक शिष्टमंडलों की बात कर रहे हैं । क्या आप हमसे नटों की टोली भेजने की अपेक्षा रखते हैं । यह ठीक नहीं है...(**व्यवधान**)

मैं यह कहने का प्रयत्न कर रहा हूं कि हम उनसे आर्थिक मामलों में सहयोग कर रहे हैं । संयुक्त परियोजनाएं बनाई जा रही हैं । अफ्रीकी देशों के साथ हमारा व्यापार बढ़ रहा है । इन देशों के आर्थिक विकास में अधिक से अधिक सहयोग हो रहा है । यही ठोस सहायता और सहयोग काम आयेंगे न कि केवल सांस्कृतिक शिष्टमंडल ।

श्री स० कुण्डू : महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । क्या इसकी चर्चा हुई थी कि... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कुण्डू महोदय, कृपया आप बैठ जाये । उन्होंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है ।

श्री स० कुण्डू : क्या उन्होंने उत्तर दिया है । उन्होंने कुछ और ही उत्तर दिया है ।

पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में स्थापित "काश्मीर कमांडों यूनिट"

*606. **श्री रामकिशन गुप्त** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 फरवरी, 1970 के ट्रिब्यून में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि "पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में काश्मीर कमांडों मूवमेंट" नामक एक सशस्त्र कमांडों यूनिट स्थापित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). जी हां । जम्मू तथा काश्मीर में तोड़-फोड़ और ध्वंसक गतिविधियों के लिए "अलबर्क" नाम के एक संघठन की विरहना के संबंध में सरकार को रिपोर्ट प्राप्त हुई है । जैसे कि सदन को ज्ञात है, पाकिस्तान मुजाहिदों नाम

की अनियमित सेनाओं की एक भारी संख्या और अन्य पैरामिलिट्री सेनाओं को पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में सशस्त्र कर रहा है तथा गुरिल्ला युद्ध, तोड़-फोड़ तथा अन्य विध्वंसक कार्यों में प्रशिक्षण दे रहा है। इस सम्बन्ध में संवर्धनों के प्रति सतर्कता बरती जा रही है, और उनका अपनी ध्यान रखा जा रहा है।

Shri Ram Kishan Gupta : May I know whether I have been made to find out the strength of the Institution known as Al Burq and where from the Institution gets arms and how the members of this Institution are trained ?

Shri Swaran Singh : Yer, Sir, we have tried to inquire into this matter. At present it is a private institution but Pakistan Government are strongly supporting the institution and they may help it and utilise it at some appropriate time.

Shri Ram Kishan Gupta : How far it is true that the members of this institution approached the Chinese Officers in Pakistan for providing arms and training facilities and the Chinese officers are giving them training in a full-fledged form ?

Shri Swaran Singh : It is true that Chinese officers are giving them training in Guiralla warfare in West and East Pakistan. We have got no direct and definite information regarding assistance sought by Al Burq or about the talks held between the institution and China.

Shri Balraj Madhok : Is it a fact that not only people from Pakistan occupied area but from our territory go to Al Burq and its campus there and they are given training there and after giving them training they sent to our territory and these persons are making cells in different parts of the country ? Jammu and Kashmir Government have some information in this connection I would like to know what steps are being taken to prevent them from making such cells ?

Shri Swaran Singh : It is not true that some persons from India or Jammu Kashmir go there for training and return. We have no such information that this is going on a large scale. It is very difficulty to find out if a person does it in a secret way. But it is true that a number of persons want to create disturbances in Jammu-Kashmir. They want to indulge in such activities which may create unrest and put people in trouble. It is their object. We have to deal with them. It is true that a number of persons, while sitting in their homes prepare some plan but when they come out, only then they will be cut to their size ?

Shri Balraj Madhok : Can the hon. Minister deny that a number of persons are receiving training in Rajouri area ?

Shri Swaran Singh : How can I deny this ? Some may be receiving.

श्री न० कु० सांघी : राजस्थान क्षेत्र में एक मंदिर के पास पाकिस्तानी रेंजर का एक सैनिक कोट मिला था और सैनिक क्षेत्र में कुछ जासूस मिले थे।

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न प्रासंगिक नहीं है। यह प्रश्न केवल जम्मू-काश्मीर स्थित 'अल वर्क' से सम्बन्धित है।

डा० राम सुभग सिंह : समाचार-पत्रों में प्रकाशित इन समाचारों में क्या कोई सत्य है कि पाकिस्तान को तुर्की के माध्यम से बहुत बड़ी मात्रा में अमरीकी टैंक दिए जाने वाले हैं तथा चीन भी पाकिस्तान को टैंक दे रहा है जिनका प्रयोग जम्मू तथा काश्मीर में किया जा सकता है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं नहीं कह सकता कि यह प्रश्न प्रासंगिक है। महत्वपूर्ण विषय होने के नाते जितनी भी जानकारी मेरे पास है उसे देने का प्रयत्न करूंगा। क्या उनका अभिप्राय तुर्की से है ?

डा० राम सुभग सिंह : तुर्की और चीन दोनों से।

श्री स्वर्ण सिंह : जहां तक चीन का सम्बन्ध है, यह सत्य है और मैं सदन में इस बारे में वक्तव्य दे चुका हूँ कि चीन समय-समय पर पाकिस्तान को टैंक देता रहा है अब तक वह कितने टैंक दे चुका है, इसकी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जो तुर्की टैंक उत्तर अतलांतिक संधि संगठन के पास आवश्यकता से अधिक है, उन्हें पाकिस्तान को देने का विचार किया गया था, उसके बारे में पूरी जानकारी हमारे पास है और इस मामला में हमने तुर्की सरकार एवं अमरीकी सरकार से बात की है। हमें सरकारी सूत्रों से जो अन्तिम जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अनुसार मामला अभी पूरी तरह तय नहीं हुआ है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Is it a fact that in several areas counts of ten paise and five-paise denominations are being used to make artificial ornaments and also for manufacturing steel wares ? Have the Government received any such information ? If so, what action has been taken by Government ? Is it also a fact that eight annas and four annas coins with the inscription of lion are not accepted in Madhya Pardesh ? Even the Post and Telegraph Department and all other Government departments do not accept these coins. Are the Government aware of it ?

Shri P. C. Sethi : Mr. Speaker, I have no aulhentic information in this regard but reports have been received about five-paise coins and two paise coins that they are melted and used to manufacture steel utensils as the metal of the cupro nickle based coins is more costly. Therefore as far as coins of small denominations are concerned these have been converted into Aluminium Magnesium based coins with effect from 1964-65. So far as four anna coins and eight anna coins are concerned, actually there are of three types. The coins issued after 1946 were having the picture of King George inscribed on the face and a lion on the reverse. The coins issued in 1956-57 were having the emblem of Ashoka Piller on the front. The circulation of silver coins, which were in circulated before 1956-57, was stopped in 1968 and publicity was also made. The coins which came in circulation in 1957-58 are legal tender and are accepted bv banks. If there is any misunderstanding, should be removed. There are legal tenders and therefore there should not be any objection in accepting them.

Shri Hukam Chand Kachwai : The coins issued by the Government are of very inferior quality. Metal of very inferior quality is used. I have got two three and five paise coins which are so light in weight that I can blow them off with my breath. Not only this, the paper used in currency notes is of inferior quality that if by mistake a note remains lying in the pocket and if it is socked in water. The printing on it is washed away. May I know whether Government propose to change the paper and also not to print such notes in future ? I have got four notes in worst condition, will the Government exchange these notes.

Shri P. C. Sethi : As I have already stated about the two-paise, three-paise, and five-paise coins, the cost of metal has gone up that the old two-paise coin costs more than four paise and five-paise coin costs more than six and a half paise. That is why it was decided that instead of cupro-nickle based, coins Aluminium Magnesium based coins have been put in circulation and that is the reason that they are light in weight. The metal is light in weight and therefore coin is also light in weight but it does not mean that there is any defect in it. So far as fading the printing on the currency note is concerned, no

complaint has yet been received. If the hon. Member give me his notes, I would look into the matter.

Shri Madhu Limaye : May, I know whether the coins are being given on 10 to 15 per cent commission in Indore Division ? May I also know whether nickle, copper and brass based coins are being melted their intransic value is higher than their face value ? If so, will the Government use such a metal which may maintain a certain difference between intransic value and face value, so that the coins may not be misused ?

Shri P. C. Sethi : It is not clear from the question of the hon. Member that who give coins on commission. If the allegation of hon. Member is this that banks are involved in this (*Interruption*)

Shri Madhu Limaye : Not banks, but persons who have such coins, adopt such practice in the tribal areas because most of the Indore Division is a tribal area.

Shri P. C. Sethi : As far as the circulation of old coins is concerned, I have stated that due to cupro-nickle based coins, their intransic value is higher than the face value. Now the difficulty is this that the melting of coins is not banned by law. - No punishment can be given.

श्री नाथ पाई : क्यों न इसके लिए कोई अध्यादेश जारी किया जाए ?

Shri P. C. Sethi : In 1964-65 the price of metal increased and therefore cupro-nickle based coins have been replaced by Aluminium Magnesium. For this we can say "why not demonetise the old coins" but it cannot solve the problem because melted coins cannot be brought into former shape. So efforts are being made to withdraw these coins from the circulation and we exchange them when we receive them.

Shri Meetha Lal Meena : Mr. Speaker, the Government of India have issued a ten rupee coin and its transaction is cofined to State Bank of India, State Bank of Bikaner and Jaipur and other banks. The employees of these banks are selling these coins for rupees 12 or 13 per coins in the black market. They are doing this because these coins are very small in number. What is the reaction of the Government in this regard ?

Mr. Speaker : This question is regarding the small denomination coins.

श्री प्र० चं० सेठी : मुझे 10 रुपये के सिक्के के बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्रश्न कम मूल्य के सिक्कों के बारे में था।

Shri Meetha Lal Meena : It is a question regarding coins. Ten rupees coins are being sold in black market openly.

Mr. Speaker : I have already told that this question is not relevent.

श्री फ० गो० सेन : क्या मंत्री महोदय ने 'हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड' में प्रकाशित इस समाचार की ओर ध्यान दिया है जिसमें 2 पैसे एवं 5 पैसे के सिक्कों की फोटोस्टेट प्रति दी गई है। क्या उन्होंने गौर किया है कि 5 पैसे का सिक्का दो पैसे की तरह दिया गया है ? अगर हां, तो इस भ्रम को दूर करने के लिए मंत्री महोदय क्या कार्यवाही करने का विचार कर रहे हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैंने ऐसी कोई खबर नही देखी है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : ग्रेशम के नियम के अनुसार खराब एवं घिसी मुद्रा अच्छी मुद्रा को कभी प्रचलन में नहीं आने देती। राजनीति के बारे में भी यही बात लागू होती है। छोटे

मूल्य के सिक्कों की कमी होने का क्या एक कारण यह भी है ? इस कठिनाई से छुटकारा पाने के लिए क्या मंत्री महोदय चांदी के 4 आने एवं 8 आने के सिक्कों को वापिस लेने पर विचार करेंगे ?

श्री पी० सी० सेठी : मेरे विचार में यह सब गलतफहमी का परिणाम है। यह एक अलग प्रश्न है। मूल प्रश्न 5 पैसे एवं 2 पैसे के छोटे सिक्कों के बारे में था, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उन्हें पिघला कर अधिक मूल्यों पर बेचा जाता है। जहां तक 1946 एवं 1957-58 में जारी किये गये चार आने एवं आठ आने का सिक्कों का सम्बन्ध है, ये कानूनी रूप से प्रचलन में रहेंगे। उनको वापिस लेने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जहां तक 1946 के पहले के चांदी के पुराने सिक्कों का सम्बन्ध है, उनका प्रचलन पहले ही बन्द कर दिया गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Proposal for Settlement of Ex-Servicemen in Nefa

*601. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether Government propose to settle ex-Servicemen in NEFA in view of the increasing threat and anti-India propoganda by China in that area ;

(b) if so, the progress made so far in this respect ; and

(c) the number of the ex-Servicemen Government propose to settle there ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) Government have a scheme to settle ex-servicemen in NEFA with a view to rehabilitable them and to develop the areas which are lying unused and unoccupied.

(b) 54 ex-servicemen families have been settled on land at Seijosa during 1969 and they have made good progress in cultivation of land.

(c) About 650 during the Fourth Plan period.

विकासशील क्षेत्रों में अधिक उत्पादन-दर के बारे में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें

*605. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :**

श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् के अधीन विशेषज्ञ समिति ने विकासशील क्षेत्रों में उत्पादन-दर को बढ़ाने पर जोर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna)

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) समिति का विचार है कि 1970 के दशक में विकासशील देशों के लिए समग्र रूप में सम्पूर्ण कुल उत्पादन में लगभग 6 से लेकर 7 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से तथा प्रति व्यक्ति 3.5 से लेकर 4.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि सम्भव होनी चाहिए।

(ग) समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखने के साथ-साथ सरकार को दीर्घकालीन आयोजन की आवश्यकता का भी ध्यान है तथा इसके विचारों को चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में दर्शाया गया है।

आयुध कारखानों में बनी वस्तुओं का निर्यात

*607. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुध कारखानों में निर्मित कुछ वस्तुओं का विदेशों को निर्यात किये जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन देशों को उनका निर्यात किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). सेवाओं की आवश्यकतायें पूरी करने के बाद, आयुधों और गोलाबारूद की कुछ मदें, फालतू पुर्जों की कई श्रेणियां और व्यापक स्टोरों की मदें सीमित राशियों में कई मित्र देशों को निर्यात की जाती हैं। अधिक विस्तार देना लोकहित में नहीं है।

Extension of Gandak Project Canal upto Saran, Bihar

*608. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the amount asked for by Government of Bihar during the current year to accelerate the pace of work relating to Gandak Project and the amount proposed to be allocated by the Central Government as grant of loan ;

(b) whether Government consider the said allocation adequate for the extension of the Gandak Canal under the said project upto saran District of Bihar ;

(c) if not, the additional allocations proposed to be made by Government for extension of Gandak Canal upto Saran District ; and

(d) if so, the details in this regard ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) The Government of Bihar sought an additional outlay of Rs. 6 crores during 1969-70 on the Gandak Project works, beyond the outlay of Rs. 12.00 crores approved by the Planning Commission. This request was examined in consultation with the State Government and an additional outlay of Rs. 5 crores was approved, out of which, the Government of India have agreed to provide Rs. 2 crores as non-Plan loan assistance and Rs. 3 crores will be met from the State resources.

(b) to (d). Consequently, work on Saran Canal, which had been slowed down since 1967 on account of paucity of funds, has also been speeded up.

राज्य व्यापार निगम द्वारा सीरिया के साथ दोषपूर्ण इस्पात करार

*609. **डा० प० मण्डल :**

श्री स० चं० सामन्त :

क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भर्ती किये गये एक मध्य स्तरीय मैनेजर ने, जिसे सीरिया भेजा गया था, भारत के राज्य व्यापार निगम की ओर से इस्पात के निर्यात के लिए एक करार किया जिससे निगम को लगभग 30 लाख रुपये का घाटा हुआ है ;

(ख) उतार-चढ़ाव सम्बन्धी खण्ड के बिना दोषपूर्ण करार करने के क्या कारण थे विशेष कर ऐसी स्थिति में जब कि विश्व मण्डी में इस्पात के दाम बहुत ऊंचे थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि राज्य व्यापार निगम सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाल रहा है वह इस प्रकार से हुई हानि को पूरा करने के लिए निर्यात सहायता दे ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि न केवल उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है, बल्कि उसे ऐसे सौदे करने के लिए जिनके लिए वह तकनीकी दृष्टि से योग्य नहीं है, बार-बार विदेशों में भेजा जा रहा है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) इस्पात जैसे मध्यवर्ती उत्पादों की पूर्ति से सम्बन्धित अल्पावधि संविदाओं के मामले में मूल्य वृद्धि खण्ड को शामिल करने की सामान्य वाणिज्यिक प्रथा नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत के विरुद्ध पाकिस्तान की युद्ध की तैयारियां

*610. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **प्रतिरक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान भारत के विरुद्ध युद्ध की तैयारियां कर रहा है ;

(ख) पाकिस्तान ताशकंद करार की भावना और शब्दों का उल्लंघन कर रहा है तथा हमारे देश के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपना रहा है ; और

(ग) सरकार ने इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). सभा को समय-समय पर पाकिस्तान की सशस्त्र तैयारी तथा सैनिक कार्यवाहियों को ढंग के बारे में सूचित किया जाता रहा है । सरकार स्थिति के बारे में सजग है और अपने देश की अखंडता तथा सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था की जा रही है ।

(ख) जी हां ।

उत्तरी वियतनाम द्वारा विद्रोही नागाओं का तथाकथित प्रशिक्षण

*611. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री 25 फरवरी, 1970 के आरांकित प्रश्न संख्या 61 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पुस्तिका में प्रकाशित हुए इस वितरण की, कि विद्रोही नागाओं को उत्तर वियतनाम में छापामार युद्ध प्रणाली में प्रशिक्षण दिया गया था, सत्यता अथवा असत्यता के बारे में जांच कर ली गई है।

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : इस प्रकार की खबरों की पुष्टि नहीं हुई है कि उत्तर वियतनाम में विद्रोही नागाओं को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया है।

Relaxation of Import Regulations

*612. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to relax the import-regulations consequent to easing of the foreign exchange situation ; and

(b) if so, the details of the liberalised import policy ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) and (b). The import policy is under review and the details of the policy for the year 1970-71 will be announced on 31-3-1970.

Drought in Durg, Bilaspur, Raigarh and Sarguja Districts of Madhya Pradesh

*613. **Shri Lakhan Lal Gupta** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Raipur, Bastar, Durg, Bilaspur, Raigarh and Surguja districts of Chhattisgarh areas of Madhya Pradesh were affected by drought due to less rains during 1969-70 ; and

(b) if so, whether Government of Madhya Pradesh have made a demand to Central Government for financial aid to meet the situation arising out of drought ;

(c) if so, the amount given by the Centre ; and

(d) in case no financial assistance has been given the reasons therefor ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) The Government of Madhya Pradesh have intimated that the districts of Rajpur, Durg, Bilaspur, Raigarh of Chhattisgarh and Shahdol, Chhattarpur, Sidhi and Tikamgarh districts of Rewa Division, have been affected due to unsatisfactory rains during 1969.

(b) Yes, Sir.

(c) A ceiling of expenditure of Rs. 2.15 crores has been fixed for purposes of Central assistance during 1969-70. A loan of Rs. 50 lakhs has so far been given to the State Government. Further assistance, if any, will be released on the basis of progress of expenditure called for from the State Government.

(d) Does not arise.

भारतीय दूतावासों द्वारा मनोरंजन पर व्यय

*614. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी भी भारतीय दूतावास में मनोरंजन पर कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है ;

(ख) ब्रिटेन, फ्रांस, अमरीका, रूस तथा पश्चिम जर्मनी में स्थित भारतीय दूतावासों के मनोरंजन व्यय के पिछले तीन वर्षों के आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार मनोरंजन व्यय में कटौती करने का है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय मे उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) 3.1 प्रतिशत ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें प्रदत्त प्रतिनिधिक अनुदान दिखाया गया है ।

(ग) प्रत्येक वर्ग के राजनयिक अधिकारियों के प्रतिनिधिक अनुदान का निश्चय सभी संगत बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है जिसमें अधिकारियों के कार्यालय प्रकृति और स्थानीय रहन-सहन का स्तर भी शामिल है । विदेश सेवा के निरीक्षक स्थित मिशनों/केन्द्रों की जांच करते समय प्रतिनिधिक अधिकारियों की कार्य-कुशलता के संदर्भ में प्रतिनिधिक अनुदान की उपयुक्तता और अन्य बातों की ही जांच करते हैं ।

विवरण

	1967-68	1968-69	1969-70
	(रुपए लाखों में)		
भारत का हाई कमीशन, लंदन	1.47	1.26	1.66
भारत का राजदूतावास, पेरिस	0.69	0.97	0.88
भारत का राजदूतावास, वाशिंगटन	1.50	1.43	1.54
भारत का राजदूतावास, मास्को	1.51	1.55	1.82
भारत का राजदूतावास, बोन्न	0.61	0.68	0.66

उगांडा भारतीयों को ब्रिटेन में बसाना

*615. **श्री वेद व्रत वरुआ** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि ब्रिटिश पास पोर्ट वाले हजारों भारत मूलक लोगों का उगांडा से निष्कासन अब निश्चित है ;

(ख) क्या उन्हें नियमित रूप से ब्रिटेन में बसाने के लिए ब्रिटेन सरकार के साथ कोई प्रबन्ध किये गये हैं ; और

(ग) क्या कोई अन्य कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) उगांडा के व्यापार लाइसेंस एवं आप्रवास अधिनियम की क्रियान्वित से ब्रिटिश पासपोर्टधारी भारतीय मूल के बहुत-से व्यक्तियों को उगांडा छोड़ना पड़ जाएगा।

(ख) और (ग). इस बारे में भारत सरकार ने अपने विचार ब्रिटिश सरकार को स्पष्ट बता दिए हैं और इस बात पर जोर दिया है कि इस स्थिति का समाधान आवश्यक है। भारत सरकार मानवीय आधारों पर यथा सम्भव सहायता प्रदान करती रहेगी।

लाओस में उत्तरी वियतनाम के आक्रमण को रोकने के लिये भारत की पहल

*616. **श्री बलराज मधोक :** **श्री देविन्दर सिंह :**
श्री रामावतार शर्मा : **श्री न० कु० सांधी :**

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाओस पर उत्तर वियतनाम का आक्रमण बिना रोकटोक बढ़ रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि लाओस सरकार ने भारत तथा अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के सह अध्यक्ष को इस आक्रमण को रोकने हेतु पहल करने के लिए कहा है ; और

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार ने इस सम्बन्ध अब तक क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) इस सम्बन्ध में 25 फरवरी, 1970 को लोकसभा में विदेश मंत्री ने एक वक्तव्य दिया।

(ख) लाओस की शाही सरकार के प्रतिनिधियों ने भारत के साथ इस स्थिति पर बात-चीत की है। लाओस के प्रधान मंत्री सुवन्न फूमा ने जेनेवा सम्मेलन के सहाध्यक्ष, यथा, यू० के० और यू० एस० एस० आर० को लिखा है। परन्तु लाओस की शाही सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग से प्रस्ताव नहीं किया है।

(ग) भारत सरकार ने सम्बद्ध पक्षों के साथ विचार विनिमय किया है और वियतनाम में अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग के अध्यक्ष से भी यह कहा है कि वह दो अन्य पर्यवेक्षी शक्तियों के प्रतिनिधियों से इस बात का परामर्श करे कि वर्तमान स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग द्वारा किसी प्रकार की पहल करना सम्भव है या नहीं। समझा जाता है कि एन० एस० एच० एस० के प्रस्ताव शाही सरकार के विचाराधीन हैं।

काश्मीर में छापा मार युद्ध शुरू करना

*617. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनका ध्यान काश्मीर में छापामार युद्ध का आयोजन करने के बारे में पाकिस्तान में दिये जा रहे भड़काने वाले वक्तव्यों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या उनको इस तथ्य का पता है कि काश्मीर में तोड़फोड़ की गतिविधियों के लिए रावलपिंडी में 'अल बर्क' नामक एक संगठन बनाया गया है ; और

(ग) क्या तोड़-फोड़ की इन गतिविधियों को शुरू होने से पूर्व ही दबा देने के लिए अग्रिम रूप से कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). ध्यान आज उत्तर दिये गए तारांकित प्रश्न संख्या 606 के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है।

भारत-पाकिस्तान सर्वेक्षण सम्मेलन में मतभेद

*618. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1970 के अंतिम सप्ताह में हुए भारत और पाकिस्तान के सर्वेक्षण अधिकारियों के सम्मेलन को दोनों प्रतिनिधिमण्डलों में गम्भीर मतभेद हो जाने के कारण स्थगित करना पड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो दोनों प्रतिनिधिमंडलों में मतभेद उत्पन्न होने के कारणों का ब्यौरा है ; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यधाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). भारत-पूर्वी पाकिस्तान सीमा के माल्दा-राजशाही क्षेत्र के सीमांकन के सम्बन्ध में कुछ तकनीकी मतभेदों के कारण, पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल के भूमि, रिकार्ड और सर्वेक्षण निदेशकों का 93 वां सम्मेलन स्थगित कर दिया गया। यह दूसरे दिन फिर से शुरू हुआ। अगले सम्मेलन में ये तकनीकी मतभेद दूर हो जाने की आशा है।

अन्य देशों के साथ पटसन तथा सूती वस्त्र के बारे में बातचीत

*619. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका और भारत तथा भारत और अन्य विकसित देशों के बीच पटसन तथा सूती वस्त्र के बारे में कोई बातचीत हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). सं० रा० अमरीका पटसन के आयात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाता है। फिर भी, जनवरी, 1970 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की सं० रा० अमरीका की यात्रा के दौरान सं० रा० अमरीका को हमारे पटसन के समान के निर्यात बनाने के लिए अपेक्षित उपायों पर बातचीत हुई थी। इस सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है। जहां तक यूरोपीय आर्थिक समुदाय का सम्बन्ध है, भारत

और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच एक करार पर 27 नवम्बर, 1969 को हस्ताक्षर हो चुके हैं और उसकी एक प्रति 4 मार्च, 1970 को पूछे गए तारांकित प्रश्न सं 214 के उत्तर में सभा-पटल पर रख दी गई थी। टैरिफ तथा टैरिफ इतर मामलों पर आगे बातचीत शीघ्र ही होने की आशा है। वर्ष 1970-71 में ब्रिटेन में आयात किए जाने वाले पटसन के समान के कोटे के स्तर के सम्बन्ध में ब्रिटेन के साथ भी बातचीत हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने यह एलान कर दिया है कि कोटे का स्तर वही होगा जो वर्ष 1969-70 में था।

सं० रा० अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय और ब्रिटेन के साथ भारतीय सूती वस्त्रों के व्यापार के विनियमन के प्रश्न पर विपक्षीय बातचीत शुरू हो गई है। यह बातचीत वस्त्र हेतु जेनेवा दीर्घावधि करार व्यवस्था तथा अंकटाड की अविमान सम्बन्धी व्यापक योजना के अंतर्गत विकसित देशों द्वारा दिए गए आफरों के क्षेत्र के अंतर्गत है। इन चर्चाओं का स्वरूप विभिन्न प्रकार का है और इनमें वे सारी समस्यायें आ जायेगी जिनका भारत को प्रत्येक बाजार में सामना करना पड़ा है, यथा, 1 जनवरी, 1972 से राष्ट्रीय मण्डलीय देशों से किए जाने वाले आयातों पर 15 प्र० श० शुल्क लगाने का ब्रिटिश प्रस्ताव, अविमान सम्बन्धी व्यापक योजना के अंतर्गत अन्य बाजारों में टैरिफ व्यवहार आदि।

भारत और चकोस्लोवाकिया के उत्पादों को अन्य देशों में संयुक्त रूप से बेचने के लिए भारत द्वारा टेकोस्लोवाकिया को दिया गया सुझाव

*620. **श्री अदिचन :** क्या **वैदेशिक व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चेकोस्लोवाकिया को सुझाव दिया है कि भारत और चेकोस्लोवाकिया के उत्पाद अन्य देशों में संयुक्त रूप से बेचे जायें ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर चेकोस्लोवाकिया सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). आर्थिक, व्यापार तथा तकनीकी सहयोग पर भारत चेकोस्लोवाकिया की संयुक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों में से एक है कि दोनों में से किसी भी देश में बने उत्पादों की अन्य देशों में संयुक्त ब्रिक्री की जाये। दोनों देशों के विदेशी व्यापार संगठन ऐसी संभावनाओं पर विचार करते रहे हैं, यद्यपि वास्तविक निर्यातों के रूप में अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकले हैं।

India's Participation in Jeddah Meet

*621. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Conference of the Foreign Ministers of the Islamic countries was held in Jeddah on the 23rd March, 1970 ;

(b) the names of the countries who participated in it and the subjects discussed ; and

(c) the Government of India's reaction in the matter and the policy decision taken in regard to India's participation in such communal conference in future ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) to (c). A statement is placed on the Table of the House.

STATEMENT

According to a press statement of the Government of Saudi Arabia, the following 24 countries had accepted the invitation to attend the Conference :

1. Afghanistan
2. Algeria
3. Cameroun
4. Gambia
5. Guinea
6. Indonesia
7. Iran
8. Jordan
9. Kuwait
10. Lebanon
11. Libya
12. Malaysia
13. Mauritania
14. Morocco
15. Niger
16. Pakistan
17. Saudi Arabia
18. Senegal
19. Somalia
20. Sudan
21. Tunisia
22. Turkey
23. U. A. R.
24. Yemen Arab Republic

The precise Agenda of the Conference is not yet known.

The policy of the Government of India in the matter has been previously stated in the House. Government are opposed to the exploitation of religion for political purposes. Government delegations are not sent to religious conferences. However, if India is invited to a conference bearing a religious label but discussing political issues we take into account the nature of the conference and the subjects to be discussed. Decision to attend or not to attend depends upon the assessment of usefulness of the conference and our interests involved.

दस्तकारी की वस्तुओं के निर्यात में जापान से प्रतिस्पर्धा

*622. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से दस्तकारी की वस्तुओं के निर्यात में भारत को जापान से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या यह प्रतिस्पर्धा मूल्य से सम्बन्धित है या उन वस्तुओं के गुण-दोष से संबंधित है ; और

(ग) भारत का इस चुनौती का किस प्रकार सामना करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हाँ ।

(ख) भारत से निर्यातित दस्तकारी की वस्तुओं को, जापान से मूल्य तथा गुण दोनों के सम्बन्ध में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है ।

(ग) जापान से प्रतिस्पर्धा होने के बावजूद, हाल के कुछ वर्षों में भारत से किए गए दस्तकारी सम्बन्धी निर्यातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई । दस्तकारी सम्बन्धी कुल निर्यात, जिसमें

हीरे जवाहरात भी शामिल हैं, वर्ष 1966-67 में 40.4 करोड़ रु० के थे और वर्ष 1967-68 में बढ़ कर 54.8 करोड़ रु० तथा वर्ष 1968-69 में 76.5 करोड़ रु० के हो गए। ये निर्यात, वर्ष 1969-70 (अप्रैल नवम्बर, 69) के प्रथम आठ महीनों में ही 64.5 करोड़ रु० तक पहुँच गए हैं। दस्तकारी के निर्यात को बढ़ाने और भारतीय दस्तकारी की वस्तुओं को विश्व बाजार में प्रतियोगी बनाने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं। ये उपाय संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

विवरण

(1) पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों की मंजूरी के लिए व्यवस्था की गई है ;

(2) दस्तकारी में निर्यात अभिमुख नए डिजाइनों के विकास के लिए तथा युवक शिल्पियों को प्रशिक्षण देने के लिए देश के कई स्थानों पर अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के अधीन डिजाइन केन्द्र स्थापित किए गए हैं ;

(3) शिल्पियों को औजार तथा उपकरण देने की एक योजना लागू है ;

(4) दस्तकारों को भंडारों के माध्यम से कच्चे माल के लिए उधार की सुविधाएं दी जाती हैं ;

(5) दस्तकारी वस्तुओं के संवर्धन तथा प्रचार के लिए भारत तथा विदेशों में प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं ;

(6) विदेशों में होने वाले व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना ;

(7) विदेशों में प्रदर्शन कक्ष तथा दुकानें खोली गई हैं ;

(8) भारतीय निर्यातकों तथा विदेशी आयातकों द्वारा की गई व्यापारिक पूछ-ताछों के उत्तर दिए जाते हैं और उनको अपेक्षित जानकारी दी जाती है ;

(9) बैंकों द्वारा अब दस्तकारों के लिए भी ऋण सुविधायें दी जाती हैं ; और

(10) भारतीय निर्यातकों को निर्यात ऋण प्राप्त करने में सहायता दी जाती है ?

आज तक किए गए उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त, भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुओं के लिए और अधिक बाजार प्राप्त करने के लिए निकट भविष्य में निम्नोक्त कदम उठाने का भी विचार है :—

(1) हस्तशिल्प की वस्तुओं के लिए विदेशों में बाजार सर्वेक्षण करना ;

(2) विदेशों में हस्तशिल्प की वस्तुओं के प्रचार के लिए रंगीन वृत्त चित्रों का निर्माण तथा प्रदर्शन ;

(3) विभिन्न कलाओं के अध्ययन तथा बिक्री दलों को विदेशों में भेजना ;

(4) पुस्तिकाओं, विज्ञापनों और चलचित्रों द्वारा विदेशों में प्रचार-माध्यमों का प्रसार करना ; और

(5) खरीद करने वाली विदेशी फर्मों को भारत के हस्तकला केन्द्रों में यात्रा को प्रोत्साहन देना

यह आशा की जाती है कि इस उपायों से भारतीय उद्योग को हस्तकला सामग्री के निर्यात में बढ़ावा मिलेगा और वह जापान से प्रतियोगिता कर सकेगा ।

मलेशिया में भारतीयों के लिए 'कार्य परमिट'

*623. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलेशिया सरकार ने वहां रहने वाले भारतीयों को 'कार्य परमिट' देने के प्रश्न में उदारता की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मुख्य रूप से स्थानीय लोगों द्वारा वन क्षेत्रों के ऊपरी भागों में कार्य करने को तैयार न होने के कारण किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह रियायत ऐसे भारतीयों के लिए जो ऐसी कठिन जीवन वाली परिस्थितियों में काम करने के लिए तैयार हैं ; और

(घ) क्या इस रियायत का छोटे बड़े व्यापारियों, सरकारी कर्मचारी जैसे अन्य भारतीयों पर कुप्रभाव पड़ता है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेंद्रपाल सिंह) : (क) से (घ). सरकार को यह बात मालूम है कि जनवरी 1970 के आखिर तक मलेशिया सरकार ने करीब 22,000 गैर-नागरिक लोगों को तीन महीने के जो कार्य परमिट जारी किये थे वे उसने नवीकृत कर दिये हैं। भारतीय मूल के व्यक्तियों के आंकड़े अलग से सुलभ नहीं है । मलेशियाई सरकार ने छह महीने के कार्य परमिट नवीकृत करने के पूरे आंकड़े अभी जारी नहीं किये हैं । अभी तक करीब 4,000 व्यक्तियों के 6-महीने वाले कार्य परमिट नवीकृत किये गये हैं । मलेशिया की सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि इन समस्या के प्रति वे मानवीय रवैया अपनायेंगे ।

मैक्स मूलर भवनों का बन्द किया जाना

*624. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारत में विदेशी सरकारों द्वारा चलाये जाने वाले कई सूचना और सांस्कृतिक केन्द्रों को इस आधार पर बंद करने के आदेश जारी किये हैं कि ये केन्द्र ऐसे स्थानों पर हैं, जहां सम्बन्धित सरकार का कोई दूतावास अथवा वाणिज्यिक कार्यालय नहीं है ;

(ख) क्या संयुक्त राज्य सूचना सेवा (यू० एस० आई० एस०) द्वारा भारत में चलाये जाने वाले अनेक केन्द्रों को उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत बन्द किया जायेगा ;

(ग) क्या यह सच है कि इस आदेश का भारत में काम करने वाले मैक्स मूलर भवनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त आदेश के प्रभाव से मैक्स मूलर भवनों को मुक्त रखने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां । 26 फरवरी 1970 को इस विषय पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में सरकार का निर्णय सदन में बताया जा चुका है ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) सरकार का निर्णय उन संस्थाओं पर लागू होता है जो कि विदेशी मिशनों द्वारा सीधे ही चलाये जाते हैं । मैक्स मूलर भवनों के भावी संचालन के प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं ।

केलों का निर्यात

*625. **डा० रानेन सेन** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में केलों के निर्यात में कोई वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ;

(ग) केलों के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ;

(घ) क्या यह सच है कि नौवहन केन्द्रों को भेजने में काफी केले खराब हो जाते हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या केलों के उचित परिक्षण के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) नौवहन केन्द्रों में केलों को भेजते समय उनके उचित परिरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु रेलवे द्वारा पहले से ही लकड़ी के ढांचे तथा लकड़ी की छत वाले डिब्बे दिये जाते हैं ।

विवरण

गत पांच वर्षों में केलों के निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहे :—

	मे० टन (हजार में)	मूल्य (लाख रुपये में)
1964-65	8	30
1965-66	9.1	38
1966-67	12	63
1967-68	3.8	20
1968-69	10.2	51
1969-70 (अप्रैल-दिसम्बर)	4.4	22

डा० धर्म तेजा और उनकी पत्नी को भारत वापस लाना

*626. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० धर्म तेजा और उनकी पत्नी को भारत वापस लाने के लिए कोई और प्रयत्न किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो लोक सभा में पिछली बार इस मामले पर हुई चर्चा के पश्चात् सरकार द्वारा क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). अगस्त 1969 में, डा० धर्म तेजा और उनकी पत्नी की वापसी के लिए, अपने राजदूत के माध्यम से भारत सरकार ने कोस्टारिका की सरकार को फिर एक प्रतिवेदन भेजा ; यह अभी भी सरकार के विचाराधीन है । इस वर्ष फरवरी में, अपने प्रतिवेदन के सम्बन्ध में पूछताछ करने के लिए, कोस्टारिका स्थित हमारे राजदूत, कोस्टारिका के अधिकारियों से मिले, और उन्हें यह सूचित किया गया कि एक मंत्रिमंडल उप समिति को अपनी सिफारिश सूत्रबद्ध करने का अनुदेश दे दिया गया था और 15 मार्च तक कोई निर्णय किया जायेगा । अपने राजदूत से इस पर आगे कार्रवाई करने के लिए कहा गया है ।

हथकरघा बुनकरों का उत्थान

*627. **श्री न० रा० देवधरे :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों को प्राथमिकता देने के लिए नई प्रक्रिया आरम्भ करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या हथकरघे बुनकरों के, जिनकी देश में काफी संख्या है, उत्थान के लिए कोई विशेष प्रक्रिया सरकार के विचाराधीन है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है ।

विवरण

हथकरघा उद्योग के विकास हेतु ऋणों तथा अनुदानों के रूप में पहले ही सहायता प्रदान की जा रही है । यह सहायता विभिन्न प्रयोजनों के लिए होती है जिनमें हथकरघा सहकारिताओं तथा सहकारी बुनाई कारखानों को सहायता, उपकरणों की पूर्ति, रंगाई घरों तथा परिष्करण

संयत्रों की स्थापना, मोटर गाड़ियों, बिक्री भण्डारों तथा उत्पादन सोसाइटियों पर होने वाले व्यय शामिल हैं। हथकरघा वस्त्रों की बिक्री पर 5 पैसे प्रति रु० की दर से रियायत के रूप में भी सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष के दौरान अल्पावधियों के लिए 5 पैसे प्रति रु० की अतिरिक्त रियायत भी दी जाती है।

पाकिस्तान द्वारा बांध काटने के कारण भारतीय गांवों में बाढ़ का आना

*628. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान सरकार ने जान बूझ कर बांध काट कर अपने फालतू जल से छुटकारा पाने के लिए लगभग दो दर्जन भारतीय गांवों को जिनमें 10,000 एकड़ भूमि में फसल खड़ी हुई थी, जलमग्न कर दिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल के राहत कार्य मन्त्री ने इन बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण किया था और भारत सरकार को सारे मामले की सूचना दी थी ;

(ग) इन गांवों के जलमग्न हो जाने के कारण कितनी हानि हुई ;

(घ) क्या सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान सरकार से इस बारे में विरोध प्रकट किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार ने बताया है कि पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में भारतीय सीमा पार पाकिस्तान द्वारा एक बांध काट देने के परिणामस्वरूप आई बाढ़ की वजह से 16 गांवों पर इसका असर हुआ था।

(ग) अनुमानित क्षति नीचे लिखे अनुसार है :

(i) धान, जिसका 22,49,000/-रु० ठहराया गया है।

(ii) 414 मकान, जिनका मूल्य 82,000/-रु० ठहराया गया है।

(घ) जी हां।

(ङ) पाकिस्तान सरकार ने इस बात को मानने से इन्कार किया है कि उनकी ओर से पानी के तेज बहाव के कारण भारतीय प्रदेश में बाढ़ आई।

चीन को फ्रांसीसी लड़ाकू बमबार विमानों का बेचा जाना

*629. **श्री रा० रा० सिंह देव** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 मार्च, 1970 के इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि फ्रांस ने चीन को गुप्त रूप से 48 सुपरसानिक मीराज लड़ाकू विमान बेचे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इन्जिनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और

(ख). सरकार ने इस मामले पर प्रेस रिपोर्ट देखी है। सरकार ने एक प्रेस रिपोर्ट यह भी देखी है जिसमें फ्राँस सरकार ने समाचार पत्र की रिपोर्ट के "शुद्ध हवाई कल्पना" बताया है।

मध्य प्रदेश को पार्वती जलमार्ग से पानी की सप्लाई

*630. **श्री हुकमचंद कछवाय** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 नवम्बर, 1969 को गांधी सागर में हुई बैठक में मध्य प्रदेश को मार्च, 1970 तक पार्वती जलमार्ग से 2000 क्यूसेक पानी सप्लाई करने का निर्णय किया गया था ;

(ख) क्या पानी की सप्लाई, जिस पर सहमति हो गई है, नवम्बर और दिसम्बर, 1969 की अवधि में, जबकि इसकी अत्यधिक आवश्यकता होती है, की गई थी ;

(ग) यदि नहीं, तो इन दो महीनों के दौरान प्रत्येक दिन वास्तव में कितना पानी सप्लाई किया गया ;

(घ) कम पानी सप्लाई किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) भविष्य में स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपचारी कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि मध्य प्रदेश को पानी की पूरी सप्लाई नहीं हो सकी है जिसके निम्नलिखित कारण हैं :—

(1) **अत्यधिक मात्रा में घास-फूस का पैदा होना**
इस घास-फूस की सफाई के लिए नहर बन्द न की जा सकी।

(2) गहरी काट वाली पहुंचों में नहर के तल पर कीचड़ का जमा हो जाना।

(3) जवाहर सागर बांध स्थल पर कापर बांध की मरम्मतों के कारण राणाप्रताप सागर बांध से पानी की कम सप्लाई।

(4) सांभी वाहक नाली के रामपुरा ताल के निकास-नलों की खराबी ;
मध्य प्रदेश को पार्वती जलमार्ग के दायें तट की नहर से नवम्बर-दिसम्बर, 1969 में पानी की निम्नलिखित सप्लाई की गई :—

नवम्बर 1969	दस दिनों का औसत दैनिक प्रवाह
1-10	1852 क्यूसेक
11-20	1814 क्यूसेक
21-30	1369 क्यूसेक
दिसम्बर 1969	
1-10	815 क्यूसेक
11-20	1105 क्यूसेक
21-31	1706 क्यूसेक

(ङ) राजस्थान सरकार दायें तट की नहर पर, जब वह 10 अप्रैल, 1970 से 10 जून, 1970 तक की अवधि के दौरान बन्द रहेगी, आवश्यक निर्माण कार्य करने का विचार कर रही है। दायें तट की नहर से संबंधित समस्याओं की जांच करने और प्रतिकारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक विशेष समिति भी नियुक्ति की गई है।

Assessment of Requirements of Electricity of Madhya Pradesh

3970. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the requirements of electricity of Madhya Pradesh have recently been assessed ;

(b) if so, the present estimated requirements of the said State ;

(c) the quantity of electricity likely to be required and that which is likely to be supplied during the Fourth Five Year Plan : and

(d) the steps proposed to be taken to meet the difference between the two, if any ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) The present requirement is estimated at 415 MW.

(c) By end of Fourth Plan, the, requirement is anticipated to be 794 MW. As against this availability of firm power is expected to be 612 MW.

(d) For meeting the anticipated deficit, the State Government has been considering a proposal for extension of one of the existing thermal stations in the State.

Priority to Projects in Backward Areas of U. P.

3971. **Shri J. B. S. Bist** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government would liberally sanction the establishment of small Hydro-electric projects in hilly areas of Uttar Pradesh ;

(b) if so, the names of project and priority by which they are proposed to be established in district Almora in Fourth Five Year Plan ;

(c) whether Government would accord special priority to the projects in backward regions ;

(d) if so, the progress made so far for expansion of Bageshwar Hydro-electric project setting up of the proposed hydro-electric projects for Taragtal and Favia villages and providing electricity from Ranikhet to Mansi ;

(e) the parts of Dampur, Gewar-Dwarahat and Chowkot (Almora) area, which will be benefited by the said projects ; and

(f) whether Government would implement the schemes for the expansion of the existing projects and setting up new projects keeping in view the backwardness of this area ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Small hydro-electric schemes in the hilly areas Uttar Pradesh have been executed and fresh schemes are under investigation.

(b) The names of projects already executed and those proposed to be executed in Almora District are given below :—

	Name	Installed capacity	Year of completion
	Schemes Already Executed		
1.	Bageshwar	1×18.4 KW 1×50 KW	1953 1966
2.	Champawat	2×100 KW	1965
3.	Garur	1×25 KW	1966
	Schemes investigated and project report prepared		
1.	Kapkot	50 KW	
	Schemes under investigation		
1.	Kotabadangarh	25 KW	
2.	Gular Nayarh	50 KW	
3.	Kulgarh	5 KW	
4.	Kanalgarh	200 KW	

The priority for execution of the schems will depend on the results of investigation.

(c) Yes, Sir.

(d) to (f). Bageswar hydro-electric scheme has already been completed. Taragtal hydro-electric scheme has been investigated by the Uttar Pradesh State Electricity Board and the scheme has not been found to be technically feasible. Uttar Pradesh State Electricity Board has been requested to investigate the Khatron hydro-electric scheme near Phania village. As regards providing electricity from Ranikhet to Masi, a 37.5 kV transmission line from Ranikhet to Masi via Bhikiasen and 11 kV lines from Masi to Chaukhutia and from Ranikhet to Dwarahat are under construction. This scheme is expected to meet the power requirements of the area.

Aid to U. P. for Rural Electrification of Kumaun and Uttarakhand

3972. **Shri J. B. S. Bist** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government of Uttar Pradesh have urged upon Central Government to grant them special aid for rural electrification and generating hydro-electricity in Kumaun-Uttarakhand divisions and also to contribute towards the deficit ;

(b) if so, the decision taken by Government in regard thereto ;

(c) whether Central Government would take interest in the economic progress and solving the problems of irrigation, drinking water, etc. of the hill district by granting liberal economic aid for the schemes for generating hydro-electricity in these districts ;

(d) if so, whether some special provision would be made in the Fourth Five Year Plan for this purpose ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The Uttar Pradesh Government had requested for subsidy from the Central Governmennt for micro hydel schemes to be taken up in the hilly regions of Uttar Pradesh.

(b) The State Government has been informed that since the initial small losses from the operation of micro hydel schemes would be balanced by eventual returns from the optimum utilisation of these schemes, the investment in this regard could be adjusted within the State Plan outlays inclusive of overall Central Assistance.

(c) Arising from the recommendation of the Conference of State Ministers of Irrigation and Power held at Nainital in May, 1969, a Committee has been constituted under the chairmanship of the Chief Minister of Himachal Pradesh for reviewing existing programmes and recommending measures, including special financing, for supply of drinking water, irrigation and electricity to hilly regions.

(d) and (e). The Fourth Five Year Plan is under finalisation.

आयुध कारखानों की उत्पादन क्षमता का उपयोग

3973. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **प्रति रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों की उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग किया जा रहा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो अप्रयुक्त क्षमता कितनी है और उसको उपयोग में लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). सिवाए आर्डनेंस वस्त्र और पैराशूट फैक्टरियों के सभी अन्य वर्तमान आर्डनेंस फैक्टरियों की क्षमता का, मशीनों के फेल हो जाने और द्रव्यों में अस्थायी कमी इत्यादि के कारण ऊंच-नीच के अनुसार, पूरा प्रयोग किया जा रहा है। तदपि आयोजना प्रावस्था में फैक्टरियों समेत नई फैक्टरियों की हालत में वास्तव उत्पादन अभी उन के पूर्ण उत्पादन तक बढ़ना है।

वस्त्र मदों में सेवाओं की मांग में कमी के कारण आर्डनेंस वस्त्र और पैराशूट फैक्टरियों की वर्तमान क्षमता का पूर्णतः इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, और इन फैक्टरियों में कुछ फालतू क्षमता विद्यमान रही है।

इन फैक्टरियों में प्राप्त फालतू क्षमता का प्रयोग करने के लिए निम्न पग उठाए गए हैं :—

सेवाओं के लिए तम्बुओं, दरियों इत्यादि जैसी मदों का निर्माण हस्तगत करके उत्पादन का विभिन्नीकरण किया गया है। अन्य केन्द्रीय सरकार के विभागों और राजकीय क्षेत्र के उपकरणों से वस्त्रों/सिलीसिलाई मदों के लिए कुछ सफलता सहित आर्डर प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं, और इस दिशा में अन्य प्रयास जारी हैं। देश में विक्रय तथा निर्यात के लिए सिलेसिलाए वस्त्रों का निर्माण हस्तगत करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

हांगकांग में भारतीय लोग

3974. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हांगकांग में भारतीय नागरिकों अथवा भारत मूलक व्यक्तियों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि हांगकांग में भारतीयों के बसने पर प्रतिबन्ध लगा है, यदि हां, तो प्रतिबन्ध की मुख्य बातें क्या हैं और यह कब से लागू है ;

(ग) उन भारतीय निवासियों को जो व्यापार के लिए हांगकांग से बाहर चले गये थे हाल ही में हांगकांग में पुनः आने न देने के क्या कारण हैं और इस रोक से कितने व्यक्तियों पर बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) क्या हमारी सरकार ने हांगकांग अधिकारियों से कोई विरोध प्रकट किया है, यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) ऐसा अनुमान है कि भारतीय मूल के लोगों की संख्या लगभग 4000 है। इनमें करीब 50 प्रतिशत भारतीय नागरिक हैं जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हैं।

(ख) 8 सितम्बर 1969 से हांगकांग की सरकार ने हांगकांग में राष्ट्रमंडल देशों के नागरिकों के प्रवेश से संबद्ध आप्रवास कानून लागू कर दिया है। इस नए कानून के अन्तर्गत युनाइटेड किंगडम को छोड़कर बाकी दूसरे राष्ट्रमंडल देशों के नागरिकों को हांगकांग में प्रवेश करने के लिए मगर उनके निवास की अवधि तीन महीने से ज्यादा हो और/अथवा उनका उद्देश्य रोजगार ढूंढना वहां निवास करना या फिर व्यवसाय करना हो तो उन्हें बीजा लेना होगा।

पर्यटकों और थोड़े समय के लिए जाने वालों को बीजा लेने की जरूरत नहीं होती जिसमें तीन महीने तक की अल्पावधि की व्यापारिक यात्रा भी शामिल है।

(ग) और (घ). इस स्थानीय आप्रवास कानून का बुरा असर पड़ने की किसी भारतीय राष्ट्रिक से कोई शिकायत सरकार को नहीं मिली है।

दूतावासों के अधिकारियों की नियुक्ति

3975. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में किसी एक भारतीय दूतावास में पांच वर्ष अथवा इससे अधिक समय तक नियुक्ति रहे अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा उनकी उपलब्धियां क्या हैं और वे किन-किन देश में है और उनके एक ही स्थान पर इतनी लम्बी अवधि तक रहने के क्या कारण हैं ;

(ख) कौन से दूतावास 'कठिन' और कौन से अन्य प्रकार के समझे जाते हैं ;

(ग) एक स्थान पर एक अधिकारी के रहने की सामान्य अवधि कितनी है और किन आधारों पर स्थानान्तरण किये जाते हैं ; और

(घ) लंदन, वाशिंगटन और मास्को में दूतावासों में सबसे प्रमुख प्रभारी अधिकारियों के वार्षिक वेतन तथा उपलब्धियां कितनी हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) विदेश स्थित किसी एक ही भारतीय मिशन में पिछले पांच वर्ष या उससे अधिक समय से काम करने वाले अधिकारियों से संबद्ध आवश्यक सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखी गयी**। देखिए संख्या एल० टी० 2978/70]।

(ख) विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों को ए, बी और सी, तीन वर्गों में बांटा गया है 'सी' वर्ग के स्थानों को कठिन स्थान समझा जाता है।

(ग) 'अ' और 'ब' वर्ग के स्थानों पर नियुक्ति की सामान्य अवधि तीन वर्ष है। 'सी' वर्ग के स्थानों पर राजनयिक अधिकारियों का सामान्य कार्यकाल तीन वर्ष और अगले के लिए दो वर्ष है। अधिकारियों द्वारा अपनी सामान्य अवधि पूरी कर लेने पर साधारणतः उन्हें स्थानान्तरित कर दिया जाता है।

(घ) वाशिंगटन और मास्को के हमारे राजदूतों को तथा लंदन के हमारे हाई कमिश्नर को नीचे लिखे अनुसार वार्षिक वेतन और परिलब्धियां दी जाती हैं :—

	वेतन रुपये	भत्ते रुपये
वाशिंगटन	42,000	2,06,520
मास्को	42,000	1,63,560
लंदन	42,000	1,22,220

चलचित्र फिल्में तैयार करने में प्रयोग में आने वाले "मैंटोल की कमी"

3976. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चलचित्र फिल्में तैयार करने के लिए प्रयोग में आने वाले "मैंटोल" नामक रसायन की कमी होने के कारण भारतीय चलचित्र-प्रयोगशालाओं के बन्द हो जाने का खतरा पैदा हो गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य व्यापार निगम उक्त प्रयोगशालाओं को यह रसायन सप्लाई करता था और उसने धीरे-धीरे यह सप्लाई कम करके गत दो मास से बिल्कुल ही बन्द कर दी है, यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ;

(ग) भारतीय चलचित्र प्रयोगशालाओं को प्रति वर्ष कुल कितनी मात्रा में "मैंटोल" की आवश्यकता होती है तथा उसका मूल्य क्या है ;

(घ) यदि उन प्रयोगशालाओं को विवश होकर बन्द होना पड़ा तो लगभग कितने रुपये की हानि होगी ; और

(ङ) इस रसायन की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). जी नहीं। राज्य व्यापार निगम ने जनवरी-मार्च, 19 0 में भारतीय चलचित्र प्रयोगशालाओं को 2,100 किग्रा० मैंटोल का बंटन किया है।

(ग) देश की चलचित्र प्रयोगशालाओं और अन्य उपभोक्ताओं की वार्षिक आवश्यकता अनुमानत: 9,000 किग्रा० है और इसकी लागत बीमा भाड़ा मूल्य अनुमानत: 2.5 लाख रुपये है।

(घ) और (ङ). चलचित्र प्रयोगशालाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त परिमाण में मैंटोल का आयात करने के उपाय किये जा रहे हैं अत: उनके बन्द होने और फलत: हानि होने का प्रश्न नहीं उठता।

नागपुरी संतरों का निर्यात

3977. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में नागपुरी सन्तरों के निर्यात से विदेशी मुद्रा की कितनी राशि अर्जित की गयी है ;

(ख) किन देशों को इन सन्तरों का निर्यात किया जाता है ; और

(ग) सन्तरों का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक): (क) किस्मवार निर्यात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु विगत तीन वर्षों में निर्यात किये गये सभी प्रकार के सन्तरों के मूल्य निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	मूल्य (हजार रु० में)
1966-67	278
1967-68	298
1968-69	154

(ख) सन्तरों का निर्यात प्रधानत: बहरीन द्वीप समूह, नेपाल, कतार, मस्कत, कुवैत, तथा इंडोनेशिया को किया जाता है।

(ग) अधिक परिमाण में निर्यात योग्य अधिशेष की व्यवस्था करने के उद्देश्य से सन्तरों का उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

राज्य व्यापार निगम द्वारा स्कूटरों की नीलामी

3978. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा वर्ष 1969 में कितने विदेशी स्कूटरों की नीलामी की गई है ; और

(ख) उससे कितना लाभ कमाया गया ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) वर्ष 1968-69 में 16 की ।

(ख) 18,013 रुपये ।

हिमाचल प्रदेश में डलहौजी और बकलोह छावनियों का पुर्ननिर्माण

3979. **श्री विक्रम चंद महाजन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डलहौजी और बकलोह छावनियों (हिमाचल प्रदेश) को गिरा कर पुनः बनाया जायेगा ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) कितने वर्ग फुट निर्मित रिहायशी क्षेत्र को गिराया जायेगा और कितने वर्ग फुट भूमि पर पुनः निर्माण किया जायेगा ; और

(ग) प्रति वर्ग फुट निर्माण लागत क्या होगी और इन छावनियों के पुर्ननिर्माण की लागत क्या होगी ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). डलहौजी और बकलोह छावनियों को तोड़कर फिर से बनाने का कोई अभिप्राय नहीं है । अपना उपयोगी अस्तित्व समाप्त कर देने वाले भवनों के बदले या स्टेशन में कमियों को पूरा करने के लिए/या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रासारणों और तब्दीलियों के लिए नए निर्माण समय-समय पर विभिन्न सक्षम प्राधिकरणों द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं । डलहौजी और बकलोह में गिराये जाने के लिए प्रस्तावित भवन क्षेत्र का लगभग क्षेत्रफल क्रमशः 32270 और 68082 वर्ग-फुट है, जबकि इन दोनों स्थानों में विवाहित वास्य भवनों के लिए प्रस्तावित नया निर्माण क्रमशः 110930 और 159693 वर्ग फुट है । निर्माण की लागत निर्माण के गुणरूप और समय तथा स्थिति के अनुसार विभिन्न होती है । विवाहित वास्य भवनों के लिये बाह्य सेवाओं को छोड़कर प्रति वर्गफुट औसतन निर्माण लागत डलहौजी में 30 रुपये से 32 रुपये तक विभिन्न है और बकलोह में 3 रुपये से 27 रुपये तक विभिन्न । इन दोनों स्थानों में वास्य भवनों के नए निर्माण की कुल लागत पर लगभग 112 लाख रुपये खर्च उठाना होगा ।

छावनियों में मकानों को खाली कराना

3980. **डा० करणी सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1967 से अब तक अम्बाला, लखनऊ, मेरठ, पूना और सिकन्दराबाद छावनियों में खाली कराये गये प्रत्येक मकान के सम्बन्ध में (एक) सरकार द्वारा किराये पर देने, (दो) वर्तमान एकक द्वारा खरीदे जाते और (तीन) खाली कराने की तारीखें क्या हैं ; और

(ख) छावनियों में सशस्त्र सेनाओं के सेवानिवृत अधिकारियों द्वारा अपना कब्जा करने के लिए अपने मकानों को खाली कराने के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं परन्तु जिन्हें सरकार ने आज तक स्वीकार नहीं किया है, (एक से अधिक मान रखने वाले अधिकारियों को इस सूची में सम्मिलित न किया जाये) ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

धन देकर गणतंत्र दिवस परेड देखना

3981. **श्री विक्रम चन्द महाजन** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडिया गेट के पास बैठकर गणतन्त्र दिवस परेड देखने के लिए जो जगह है वहां से कुछ धन लेकर लोगों को परेड देखने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). गणतन्त्र दिवस परेड के अवसर पर राजपथ के दोनों ओर जनपथ से मानसिंह रोड के बीच राजपथ के मैदान में बैठने के बार्डों में प्रवेश की व्यवस्था निमन्त्रण पत्रों के द्वारा की जाती है। राजपथ के दोनों ओर का शेष स्थान जनता के लिए खुला रहता है। कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि वर्तमान व्यवस्था को समग्र तौर पर संतोषजनक पाया गया है ।

वैदेशिक सांस्कृतिक संस्थाओं से राज्य सरकारों के सम्बन्ध

3982. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैदेशिक सांस्कृतिक संस्थाओं से सम्बन्ध स्थापित करने के बारे में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धांत बताये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इन पर राज्य सरकारों की यदि कोई प्रतिक्रिया हुई है तो क्या ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). जी हां। अंतर्राष्ट्रीय मित्र संघों के साथ, जिनमें भारत स्थित विदेशी मिशनों द्वारा संचालित सांस्कृतिक संघ भी शामिल हैं, संबंध जोड़ने के बारे में राज्य सरकारों की कुछ दिशा निर्देश दिये गये हैं। ये दिशा निर्देश सरकार में काम करने वाले व्यक्तियों की इस वांछनीयता पर बल देते हैं कि वे इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय संघों के साथ सम्बन्ध न जोड़े।

(ग) किसी भी राज्य सरकार की ओर से उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ।

Rent Paid by M. M. T. C. for its Office Buildings in Delhi and Calcutta

3983. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) the amount being paid annually by the Minerals and Metals Trading Corporation for the buildings rented by it for its offices in Delhi and Calcutta ; and

(b) the reasons for which the said Corporation has not constructed its own buildings in both of the said places but are paying huge rent every year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) Rs. 14.52 lakhs.

(b) The M. M. T. C. is purchasing land for construction of its office in New Delhi. Construction of office building in Calcutta is however, not envisaged by the M. M. T. C. as much of the work of the Corporation is likely to shift from Calcutta on the completion of the Port under construction at Haldia.

भारत तथा श्रीलंका में विद्युत शक्ति का प्रति व्यक्ति उत्पादन

3984. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत की तुलना में श्रीलंका में विद्युत का प्रति व्यक्ति उत्पादन कितना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : अनुमान है कि श्रीलंका में 1968-69 के दौरान बिजली का प्रति व्यक्ति उत्पादन 64 यूनिट था जब कि भारत में यह 99 यूनिट है।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य में प्रगति

3985. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य में सभी राज्यों में एक समान प्रगति नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं किया है, तथा इस कार्य में उन्हें क्या-क्या कठिनाइयां हुई ;

(ग) इस सम्बन्ध में चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं तथा इस बारे में राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी केन्द्रीय सहायता देनी स्वीकार की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). जहां पर ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति अखिल भारतीय औसत से नीचे है, उन राज्यों के नाम ये हैं— असम, बिहार, जम्मू व काश्मीर मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल। ग्रामीण क्षेत्रों में पारेषण और वितरण जाल बिछाने के विकास एवं विस्तार कार्य में तेजी लाने के लिए वित्तीय संसाधनों की तंगी मुख्य कठिनाई है। चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें कृषि उत्पादन की वृद्धि के लिए, पम्प-सैटों के ऊर्जन की ओर झुकाव के साथ, चालू रहेंगी। चौथी पंचवर्षीय योजना मसौदे में नलकूपों/पम्प सैटों के ऊर्जन के लिए राज्यवार निर्धारित लक्ष्य विवरण में दिये गये हैं।

चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए कोई पृथक-रहित केन्द्रीय सहायता नहीं दी जायेगी और इस सम्बन्ध में परिव्यय राज्य सरकारों के योजना संसाधनों में से उपलब्ध कराया जायेगा जिसमें उनको दी गई समग्र केन्द्रीय सहायता शामिल है। ग्राम विद्युतीकरण निगम राज्य योजनाओं से बाहर केन्द्रीय सैक्टर में 150 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों पर धन लगाने के उद्देश्य से, सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया गया है।

विवरण

चौथी योजना प्रारूप के अनुसार चौथी पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त पम्प-सैटों के ऊर्जन के लिये लक्ष्य

राज्य	चौथी योजना के दौरान ऊर्जित किये जाने वाले संभावित अतिरिक्त पम्पों की संख्या
आंध्र प्रदेश	37000
असम	10000
बिहार	100000
गुजरात	27500
हरियाणा	17500
जम्मू और काश्मीर	1700
केरल	11250
मध्य प्रदेश	33000
महाराष्ट्र	75000
मैसूर	60000
उड़ीसा	8300
पंजाब	50000
राजस्थान	15000
तमिलनाडू	100000
उत्तर प्रदेश	175000
पश्चिम बंगाल	16600
कुल :	737850

राज्यों में कानून तथा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सेना का उपयोग

3986. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्षवार तथा राज्यवार गत तीन वर्षों में कानून तथा व्यवस्था को बनाये रखने के लिये कितनी बार सेना को बुलाया गया है ; और

(ख) क्या उनका मंत्रालय ऐसे कार्यों के लिए सेना का कम से कम उपयोग करने के बारे में राज्य सरकारों को अनुदेश जारी करने के बारे में विचार कर रहा है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) विवरण संलग्न है ।

(ख) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 129 में वह परिस्थितियां दी गई हैं जिनके अन्तर्गत अवैध जमाव को तितर बितर करने के लिए सेना का प्रयोग किया जा सकता है। इस विषय पर सरकार का विचार है कि संघ के दूसरे सशस्त्र बलों का जैसे कि सी० आर० पी० और बी० एस० एफ० का जनता में व्यवस्था बनाये रखने के लिए पूरी तरह प्रयोग करना चाहिए किन्तु सेना को केवल विशिष्ट परिस्थितियों में बुलाना चाहिए।

विवरण

राज्य	1-4-1967 से 31-3-1968	1-4-1968 से 31-3-1969	1-4-1969 से 20-3-1970
आंध्र प्रदेश	—	1	1
असम	2	—	—
बिहार	1	—	—
दिल्ली	1	—	—
गुजरात	—	—	1
हरियाना	—	—	1
जम्मू व काश्मीर	2	—	—
मध्य प्रदेश	1	2	1
मद्रास	—	1	—
महाराष्ट्र	1	—	1
मनीपुर	—	—	2
नेफा	—	—	1
राजस्थान	1	—	1
उत्तर प्रदेश	1	1	—
पश्चिम बंगाल	4	—	3

अंदमान को अबाध व्यापार पत्तन बनाने का प्रस्ताव

3987. **श्री के० आर० गणेश** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान तथा निकोबार द्वीह समूह की आर्थिक क्षमताओं से निर्यात-प्रधान अर्थव्यस्था का संकेत मिलता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा लिटल अन्दमान को अबाध व्यापार पत्तन बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया गया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह की निर्यात क्षमता का अभी तक पूर्णतः पता नहीं लगाया गया है।

(ख) जी नहीं।

दिल्ली के देहाती क्षेत्रों से देसु के ट्रांस्फार्मरों की चोरी

3988. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत सम्भरण उपक्रम के ट्रांस्फार्मर दिल्ली के देहाती क्षेत्रों से बार-बार चोरी चले जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों में कितने ट्रांस्फार्मर चोरी किये गये हैं तथा उनकी लागत कितनी है ; और

(ग) क्या ऐसे मामलों में किन्हीं व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) दिल्ली बिजली सम्भरण उपक्रम में ट्रांस्फार्मरों की चोरियां बढ़ती ही जा रही है। 1968 में 19 और 1969 में 24 चोरियां हुई थी।

(ख) गत छः महीनों में ट्रांस्फार्मरों की 10 चोरियां हो चुकी है। और चुराए गए माल की कीमत 48,000 रुपये होने का अनुमान है।

(ग) इन चोरियों के सम्बन्ध में पुलिस को रिपोर्ट कर दी गई है और वे इनकी जाँच कर रही है।

हंगरी से व्यापार करार

3989. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी के साथ हाल में एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं जिसके अन्तर्गत भारत द्वारा हंगरी को रेलवे के माल-डिब्बे, एस्बैस्टस कंक्रीट उत्पाद, तारों के रस्से (वायर रोप्स), मोटर-गाड़ियों के सहायक पुर्जे, इस्पात की ट्यूबें और कलपुर्जे तथा सूती कपड़ों का निर्यात किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो करार की विशिष्ट शर्तें क्या हैं और इस करार के अन्तर्गत हंगरी को प्रत्येक मद का कितना-कितना निर्यात किया जायेगा तथा उसका मूल्य कितना होगा ;

(ग) इस करार के अन्तर्गत हंगरी से 1970 में आयात की जाने वाली मदों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) 1969 में हंगरी के साथ अनुमानतः व्यापार सन्तुलन क्या था और उक्त करार की क्रियान्विति से व्यापार सन्तुलन किस हद तक भारत के पक्ष में हो जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). हंगरी के साथ हाल में किसी व्यापार करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं। तथापि 14 जनवरी, 1970 को भारत सरकार तथा हंगरी जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच एक व्यापार संलेख पर हस्ताक्षर किये गये थे, जिसके अन्तर्गत 1970 के लिये दोनों देशों के बीच 59.2 करोड़ रुपये मूल्य के इस व्यापार की व्यवस्था है। परन्तु वास्तविक निर्यातों तथा आयातों की मदों के सम्बन्ध में दोनों देशों के निर्यातकों तथा आयातकों के बीच बात-चीत की जानी बाकी है।

(घ) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जनवरी-नवम्बर 1969 की अवधि में भारत का हंगरी के साथ 9.7 करोड़ रुपये तक का प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन था। 1968 की उसी अवधि में हंगरी के साथ भारत का व्यापार सन्तुलन 50 लाख रुपये तक भारत के अनुकूल था। 1970 में निर्यातों के, विशेषतया अपरम्परागत क्षेत्र में, बढ़ने की सम्भावना है, और इस लिए व्यापार सन्तुलन में लगातार सुधार होने की आशा है।

राष्ट्रीय विकास परिषद् की कार्य संचालन सम्बंधी प्रक्रियाओं में परिवर्तन के सुझाव

3990. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के मुख्य मंत्री ने राष्ट्रीय विकास परिषद् की कार्य-संचालन सम्बन्धी प्रक्रियाओं में आमूल परिवर्तन करने का केन्द्रीय सरकार के अनुरोध किया है।

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन मुख्य बातों का सुझाव दिया है ;

(ग) क्या सरकार ने उनके सुझावों पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो सुझाव को किस हद तक स्वीकार किया गया है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). पंजाब के मुख्य मन्त्री ने सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय विकास परिषद् को सहायता देने के लिए केन्द्र, राज्य और योजना आयोग के सरकारी सलाहकारों की एक स्थायी सलाहकार समिति होनी चाहिए, ताकि परिषद् के पास जाने वाले विषयों की पहले यह समिति पड़ताल कर ले और इसके निष्कर्षों पर बाद में परिषद् की पूरी बैठक में विचार किया जाए।

(ग) और (घ). इस सुझाव पर सावधानी पूर्वक विचार किया गया।

राष्ट्रीय आयोजन सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयों को राष्ट्रीय विकास परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत करने से पूर्व उनपर, पृथक-पृथक मुख्य मन्त्रियों के साथ योजना आयोग की बैठकों में विचार करने के अलावा, उनपर सरकारी स्तर पर राज्य सरकारों के साथ पर्याप्त विचार विनिमय किया जाता है। अतएव यह अनुभव किया गया कि राष्ट्रीय विकास परिषद् तथा योजना आयोग के मध्य अधिकारियों की स्थाई समिति को मध्यवर्ती बनाने से कोई लाभ नहीं होगा। तदनुसार पंजाब के मुख्य मन्त्री को सूचित कर दिया गया था।

लोकटाक परियोजना का बोरक नदी के जल की निकासी पर प्रभाव

3991. **श्रीमती ज्योत्स्ना चंदा :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोरक परियोजना की स्थिति क्या है तथा क्या लोकटाक परियोजना का बोरक नदी की जल की निकासी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). 18 जून, 1969 को शिलांग में असम और मणिपुर के मुख्य मन्त्रियों ने बोरक घाटी में नारायण-धलु पर एक बांध के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया था । मणिपुर के मुख्य मन्त्री ने बांध के निर्माण में अपनी हार्दिक समर्थन प्रदान करते हुए महसूस किया कि वर्तमान प्रस्तावित जगह पर बांध के निर्माण से बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित होंगे तथा धान उद्योग वाले क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा और नव-निर्मित कछार सड़क के कुछ हिस्से भी जलमग्न हो जाएंगे । अतः उन्होंने सुझाव दिया कि बांध बनाने के लिए वैकल्पिक स्थान की सम्भाव्यतायें ढूंढ़ी जायें । यह निर्णय किया गया कि बाढ़ ऋतु के बाद दोनों राज्यों के सम्बन्धित मन्त्री और अधिकारी वास्तविक स्थल का दौरा करके प्रस्ताव की जांच करें । इस मामले में आगे कोई प्रगति नहीं हुई है । परियोजना के निर्माण के प्रश्न पर आगे तभी विचार किया जा सकता है जबकि असम और मणिपुर राज्यों के बीच कोई समझौता हो जाए ।

बोरक नदी के जल-निस्सार पर लोकतक परियोजना के प्रभाव की जांच हो रही है ।

रेयन फिलामैंट स्टैपल फाइबर उद्योग के विस्तार पर लगे प्रतिबन्ध का हटाया जाना

3992. **श्री दे० अमात :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मानव द्वारा बनाए गए कपड़ों सम्बन्धी विकास परिषद् ने रेयन फिलामैंट स्टैपल फाइबर उद्योग के अग्रेतर विस्तार पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) रेयन फिलामैंट धागे तथा विस्कोस स्टैपल रेशे के लिए अग्रेतर औद्योगिक लाइसेंस देने पर लगे प्रतिबन्ध को हटा दिया गया है ।

Setting up of Industries in Egypt

3993. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Atam Das :

Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India proposed to set up industries in Egypt in collaboration with that country ;

(b) whether it is also a fact that in the beginning this collaboration would be offered to set up an industry for manufacturing railway wagons ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak): (a) and (b). A working group was set up in the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs to examine the scope for industrial Cooperation under the Tripartite Agreement between India, the UAR and Yugoslavia. The working group has tentatively identified certain industries as suitable for industrial collaboration between the three countries but it does not include manufacture of railway wagons. Prospects for industrial cooperation in the fields so identified are at present under discussion.

(c) Does not arise.

Decline in Production in Textile Industry

3995. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the production in textile industry has been declining and the per-unit production cost has been increasing ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps being taken by Government to remove the difficulties being faced by the said industry ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak): (a) There has been a slight fall in production and a small rise in the cost of production during the year 1969.

(b) The fall in production is due to uneconomic working of some mills, strikes, lock outs, disturbed conditions for some days in certain areas and power cut in certain areas.

The increase in the cost of production is due to rise in the prices of raw material and increase in wages.

(c) It is expected that with the return of normal conditions the level of production will rise. Government is constantly keeping the situation under review, and assisting in measures for improving efficiency in the running costs by modernisation of the industry and ensuring adequate supplies of raw cotton.

जगतपुर में पटसन मिल स्थापित करने के लिए लाइसेंस

3996. **श्री श्री निवास मिश्र :**
श्री रवि राय :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जूट मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड दानपुर, जिला कटक (उड़ीसा) से जगतपुर में पटसन मिल की स्थापना के लिए लाइसेंस दिये जाने के हेतु कोई आवेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि कलकत्ता के बड़े व्यापारिक संस्थानों के हित में उक्त लाइसेंस नहीं दिया गया ; और

(ग) यदि सरकार का विचार लाइसेंस देने का ही है, तो कब और किन शर्तों पर ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जूट मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड दानपुर ने किसी प-सन मिल की स्थापना के लिये कोई आवेदन-पत्र नहीं दिया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

Appointment of a Commission for the Settlement of Released Emergency Commissioned Officers

3997. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri T. P. Shah :
Shri Sharda Nand :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether Government appointed some Commission or Committee at the time of the release of the Emergency Commissioned Officers or before their release to find out some solution for the Problem of their settlement ;

(b) if not, whether Government propose to appoint such commission or committee now ;

(c) if so, the time by which it is likely to be appointed ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) All measures, which should be taken to achieve speedy rehabilitation of the released Emergency Commissioned Officers have been initiated. The setting up of a Commission or Committee for this purpose is not necessary.

Murder of Woman Emp'oyee of Indian Embassy in U. K.

3998. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri T. P. Shah :
Shri Sharda Nand :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a woman of Indian origin who was working in the Indian Embassy at London had been murdered ;

(b) wheter Government have collected the requisite information about her death or murder from the Indian Embassy at London ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c). Details are given in the attached note.

The Jury which held an inquest into the death of Mrs. Ne gesh Keen could not establish the cause or manner of her death and accordingly returned an open verdict. No charge of murder was brougnt in. [*Placed in Library. See* No. LT-2979/70].

Emergency Commissioned Officers Released after Second World War

3999. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri T. P. Shah :
Shri Sharda Nand :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the facilities which were provided by the then Government to the Emergency Commissioned Officers released after the Second World War ;

(b) whether it is a fact that one of the facilities they got was that they were allowed to avail of 3 chances to appear before the qualifying Sesvice Selection Board ;

(c) whether it is also a fact that Government of India have given only one such chance to the released Emergency Commissioned Officers of 1962 ;

(d) if so, the action Government propose to take to give them more chances ; and

(e) the action Government propose to take to provide all those facilities to the present released officers, which were provided by the then Government to the Emergency Commissioned Officers released after Second World War ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna) : (a) The following main facilities were provided for released Emergency Commissioned Officers of Second World war :

(i) Certain vacancies in the Central Government jobs were reserved for eligible Emergency Commissioned Officers.

(ii) Under the War Reconstruction Committee, funds were made available to the State Governments for rehabilitation of released officers.

(iii) State Governments reserved certain jobs in Class I and Class II categories for released officers.

(iv) Gratuity at prescribed rates was given for service rendered while holding Emergency Cammission.

(b) to (d). In the system which was followed after the 2nd World War, Emergency Commissioned Officers who appeared before the Service Selection Board for the grant of Permanent Commissions, if assessed as "not yet fit", were given further chances to appear before the Selection Board until a final assessment was made. Under the present system, a final assessment of an Emergency Commissioned Officer's fitness for Permanent Commission, is made within 4 days by the Services Selection Board by which time the condidates are tried out completely. There have been some variations in this procedure in respect of selection of Emergency Commissioned Officers for Permanent Commissions in the Army Remounts and Veterinary Corps and the Army Medical Corps to suit the requirements of these Services. The system which is now being followed, is considered adequate and no change is proposed.

(e) The facilities given now compare favourably with these given to the Emergency Commissioned Officers of Second World War.

Bombs Found near Chukaghat Railway Station in U.P.

4000. **Shri Om Parkash Tyagi :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that three boxes full of bombs, used in the bomber aircraft were found near the Chaukaghat Railway Station in Uttar Pradesh :

(b) if so, the place wherefrom the said boxes were brought and the person by whom they were brought ; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) to (c). It is understood from the Ministry of Railways that Chetganj Civil Police recovered three cases lying in a bush near the railway track at Chaukaghat Station. Two of the cases were empty and the third one contained ammunition. Further details are being ascertained.

Situation Arising out of Withdrawal of Indian Military Liaison Group from Nepal

4001. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether Government have tried to know the reasons for which Government of Nepal demanded withdrawal of the Indian Military Liaison Group from Nepal ;

(b) if so, the outcome thereof ;

(c) the steps being taken by Government to meet the situation arising out of the withdrawal of their Military Liaison Group from Nepal from Military point of view ; and

(d) in case no steps are being taken, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The Indian Military Liaison Group had been sent to Nepal at the request of the Government of Nepal. The Nepalese authorities had suggested that we should change the states of the Indian Military Liaison Group. They have been informed that the Government of India have no objection, in principle, to acceding to their request.

(b) The matter was discussed at the official level talks between the two Governments held in New Delhi from 29 August to 4 September, 1969 and joint recommendations made to the two Governments are under study.

(c) and (d). Do not arise.

यूरोपीय बाजारों को भेजने के लिए इंजीनियरी माल की मांगों का सर्वेक्षण

4002. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री मयावन :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रा० कृ० बिड़ला :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय राजकीय व्यापार निगम के एक प्रतिनिधि मण्डल ने यूरोप के कुछ देशों का दौरा किया था और वहां भारतीय इंजीनियरी माल के लिये अच्छी मण्डी देखी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि फ्रांस की एक बड़ी मोटरगाड़ी फर्म के एक तकनीकी दल ने भारत से आयात की जाने वाली वस्तुओं के विशिष्ट विवरणों और गुण-प्रकार के बारे में बातचीत करने के लिए भारत की यात्रा की थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस बारे में ब्रिटेन, स्वीडन और पश्चिम जर्मनी के ऐसे प्रतिनिधि-मण्डल भारत आये थे ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम करार किया गया है ; और यदि हां, तो किन वस्तुओं के बारे में ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). यूरोप तथा ब्रिटेन से तकनीकी विशेषज्ञों के एक दल के, आगामी तीन महीनों में आने की आशा है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

रूस को भारतीय माल का निर्यात

4003. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री सामिनाथन :
श्री मायावन :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1975 तक रूस को भारतीय माल का निर्यात 325 करोड़ रुपये तक बढ़ जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो रूस को चालू वर्ष की निर्यात सम्बन्धी योजना क्या है ;

(ग) इस वर्ष भारत से रूस को कुल कितनी राशि के माल का निर्यात किया गया ; और

(घ) क्या अमरीका तथा ब्रिटेन की तुलना में रूस के साथ निर्यात व्यापार कम है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) सोवियत संघ को भारत से वर्तमान निर्यातों के आधार पर, 1975 तक निर्यातों के परियोजित अनुमान लगभग 325 करोड़ के आसपास है ।

(ख) 1970 में सोवियत संघ को भारत से लगभग 200 करोड़ रुपये मूल्य के निर्यात होने की सम्भावना है ;

(ग) 1969 में सोवियत संघ को भारत से 166 करोड़ रुपये मूल्य से कुल निर्यात हुए ।

(घ) 1969 में रूस को हुआ निर्यात, हमारे विश्व व्यापार का लगभग 12.1 प्रतिशत है, जबकि अमरीका तथा ब्रिटेन को हुए निर्यात क्रमशः 17.7 तथा 11.7 प्रतिशत थे ।

भारतीय वैदेशिक व्यापार दल द्वारा बर्मा का दौरा

4004. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री मयावन : **श्री मधु लिमये :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वैदेशिक व्यापार दल बर्मा गया था ;

(ख) यदि हां, तो वहां पर किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था ;

(ग) क्या दोनों सरकारों के बीच कोई समझौता हुआ है ;

(घ) यदि हां, तो 1970 में दोनों देशों के बीच समूचे व्यापार में कितनी वृद्धि होगी ; और

(ङ) क्या बर्मा सरकार रंगून में राज्य व्यापार निगम का कार्यालय खोलने के भारतीय प्रस्ताव से सहमत हो गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) हाल में भारत से कोई सरकारी वैदेशिक व्यापार दल रंगून नहीं गया है ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

(ङ) रंगून में राज्य व्यापार निगम का कार्यालय खोलने का अभी कोई निश्चय नहीं हुआ है ।

रुई की गांठों तथा लम्बे रेशे वाले धागे का आयात

4005. **श्री सुशीला नैयर :** **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में रुई की गांठों तथा लम्बे रेशे वाले धागे का आयात किन देशों से किया जायेगा ; और

(ख) इस आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होने की संभावना है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) रुई का आयात सं० रा० अमरीका से पी० एल० 480 के अन्तर्गत और सूडान तथा संयुक्त अरब गणराज्य से विपक्षीय व्यापार करारों के अन्तर्गत होता है। इसकी कुछ मात्रा की किसी भी अन्य देश से आयात करने की अनुमति दी जाती है। साधारणतः आयात, पूर्व अफ्रीकी देशों, अदन तथा पीरू से किए जाते हैं। इस वर्ष रुई की अधिक आवश्यकताओं पूर्ति के लिए स्टेपल रेशे के आयात का प्रबन्ध, संयुक्त राज्य अमरीका तथा ब्रिटेन से किया जा रहा है।

(ख) पी० एल० 480 के अन्तर्गत रुई के आयातों के अतिरिक्त, विश्व भर से लगभग 54 करोड़ रु० लागत की रुई के आयात होने की संभावना है। स्टेपल रेशे के आयात का प्रबन्ध कुल 10.8 करोड़ रुपये के उधारों के आधार पर किया जा रहा है।

विदेशों से नेताजी संबंधी दस्तावेजों का वापस लाना

4006. **श्री समर गुह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और आजाद दि फौज से संबंधित बहुत से दस्तावेज और सामगी पूवी जर्मनी तथा पश्चिम जर्मनी, रूस, जापान, फारमोसा, बर्मा, मलयेशिया, सिंगापुर, इंग्लैंड और रूस आदि देशों में अभिलेखागारों में पड़ी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनको भारत में लाने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सरकार विदेशों से इस तरह की सामग्री भारत में लाने या लाने के कार्य में मदद करने की हर तरह से कोशिश करती रही है। उदाहरण के लिए भारत सरकार ने शंघाई और सिंगापुर में "इंडिया इन्डेपैन्डेंस लीग" के रिकार्ड हासिल करने के लिए, 1933-1942 के बीच मध्य यूरोप में नेताजी की गतिविधियों से सम्बद्ध कुछ सामग्री वियना-स्थित अपने राजदूतावास के माध्यम से हासिल करने में और आयरलैंड से श्रीमती ए० वुड के साथ नेताजी बोस के पत्राचार को हासिल करने के लिए कोशिश की है।

सिंगापुर में नेताजी के निवास स्थान का राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षण

4007. **श्री समर गुह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंगापुर में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के रिहायशी क्वार्टर तथा आजाद हिन्द सरकार के मुख्यालय और रंगून में एडवांस्ड आजाद हिंद मुख्यालय को सरकार द्वारा हमारे देश में स्वतन्त्रता आन्दोलन के संबंध में ऐतिहासिक महत्व के स्थान समझा गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन इमारतों को खरीदेंगी और उन्हें राष्ट्रीय स्मारकों के रूप में संरक्षण देगी ;

(ग) क्या सरकार बर्मा, मलयेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, कम्बोडिया, वियतनाम, फारमोसा, फिलिपाइन, इंडोनेशिया और जापान में नेताजी के आजाद हिंद संग्राम से सम्बद्ध महत्वपूर्ण स्थानों में प्लाक (फ्लक) लगाने के लिए कार्यवाही करेगी ; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां :

(ख) और (ग). जी नहीं । लेकिन, अगर वहां इस उद्देश्य से पहल की जाए तो वह सहर्ष सहयोग देगी ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय दूतावासों में नेताजी के चित्रों का लगाया जाना

4008. **श्री समर गुह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा, मलाया, सिंगापुर, थाईलैंड, कम्बोडिया, वियतनाम, फिलीपीन और जापान के भारतीय राजनयिक दूतावासों में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के चित्र को उनके दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष की स्मृति में लगाया जायेगा ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार इन क्षेत्रों के राजनयिक मिशनों में नेताजी के चित्र को लगाने के बारे में कोई कार्यवाही करेगी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

अफगानिस्तान और रूस में नेताजी की मूर्तियों वाले फ्लक

4009. **श्री समर गुह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अफगानिस्तान के उन महत्वपूर्ण स्थानों पर जहां नेताजी सुभाष चन्द्र बोस छिप कर जर्मनी जाते समय ठहरे थे, उनकी मूर्तियों वाले फ्लक लगायेगी ;

(ख) क्या सरकार रूसी सरकार से प्रार्थना करेगी कि अफगानिस्तान से इटली जाते समय जिस स्थान पर नेताजी ने रूस में प्रवेश किया था, उस स्थान पर फ्लक लगाने की अनुमति दे दी जाये ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) विदेशों के महान व्यक्तियों के स्मारकों का निर्माण करने की शाही अफगान सरकार की अनिच्छा को ध्यान में रखते हुए, ऐसा करने का प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग). सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी ।

कुन्नूर (दक्षिण भारत) में कल्याण एवं सम्पर्क अधिकारी का पद का भरा जाना

4010. **श्री नम्बियार** :
श्री चक्रपाणि :
श्री ई० के० नायनार :
श्री उमानाथ :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुन्नूर (दक्षिण भारत) में कल्याण एवं सम्पर्क अधिकारी का पद गत कई वर्षों से खाली पड़ा है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस पद को अभी तक क्यों नहीं भरा गया ; और

(ग) क्या चाय बोर्ड को शीघ्र ही इस पद को भरने के लिए निर्देश दिया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) पद को अस्थगित रखा गया है क्योंकि वर्तमान कार्य को देखते हुए पद को भरना न्यायोचित नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पख्तूनों का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाना

4011. **श्री दे० अयात** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ में पख्तूनों के मामले को उठाने के बारे में सरकार की वर्तमान नीति क्या है ; और

(ख) पख्तून नेता खान अब्दुल गफ्फार खां के हाल के कुछ महीनों के भारत दौरे से यह नीति कहां तक प्रभावित हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) पखतून प्रश्न के संबंध में सरकार की उस नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जो कि 13 नवम्बर 1968 को लोकसभा में श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा उठाई गई आधे घण्टे की बहस के दौरान उप-विदेश मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में बताई गई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली देने की योजना

4012. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था करने के लिए ऐसी कितनी योजनायें केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की हैं जिनके लिए ग्राम-विद्युतीकरण निगम द्वारा धन दिया जायेगा और उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). आंध्र प्रदेश राज्य ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा धन लगाये जाने के लिए निम्नलिखित ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमें प्रस्तुत की हैं :—

	कुल लागत (लाख रुपयों में)
1. भोंगीर तालूक	62.030
2. जनगांव तालुक	69.940
3. मारकापुर तालुक	69.000
4. नन्दीगाम विजया-तरुवर नुजविद तालुक	64.004
5. ताडपत्री तालुक	32.477
6. कादिरी तालुक	46.760
7. पालामेनेर और कुप्पम तालुक	39.420
8. माम्मरेड्डी तालुक	52.400
9. बंदार तालुक	32.649
10. मधिरा तालुक	27.900
11. पैड्डापल्ली तालुक	33.288
12. पुल्लीवेंडोला और कमालापुरम तालुक	71.350
13. पथीकोंडा तालुक	46.660
14. ओंगोल तालुक	52.091
15. करीम नगर तालुक	61.920
16. इब्राहीम पटनम तालुक	38.170
17. हिंदपुर तालुक	39.440
18. पालनाड और विनुकोंडा तालुक	38.000
19. पुत्तर तालुक	31.260
20. पालनाड तालुक	38.610
कुल	947.369

निगम द्वारा अपनाए गए मापदण्ड के अनुसार धन के लिए निगम के विचारार्थ इन स्कीमों कार्रवाई की जा रही है ।

विद्रोही नागा जनरल अंगमी पर मुकदमा

4013. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्रोही नागा "जनरल" भौवू अंगमी पर हथियार लाने तथा भारत के विरुद्ध युद्ध करने के लिए मुकदमा किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). श्री भावू अंगामी नौगाँव की विशेष जेल में बन्दी हैं और एक मुकदमें के अन्तर्गत उनकी सुनवाई चल रही है, यह मुकदमा उनके अतिरिक्त 133 अन्य व्यक्तियों पर भी कोहिमा में चलाया जा रहा है । दूसरी बातों के अलावा, इस बात का भी उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने तथा दूसरे आदमियों ने, एक अपराधिक षड़यंत्र को पूरा करने के सिलसिले में, बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के हथियार और गोला बारूद लेने के प्रयोजन से चीन का दौरा किया जिससे कि नागालैंड को भारत से अलग किया जा सके । इस बारे में तहकीकात चल रही है ।

भारतीय निर्यात संगठन संघ के सदस्यों द्वारा अफ्रीकी देशों का दौरा

4013. **श्री मीठालाल मीना :** **श्री महेन्द्र माझी :**
श्री गु० च० नायक : **श्री सी० मुत्तुस्वामी :**
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्यात संगठन संघ के सदस्यों ने हाल ही में कई अफ्रीकी देशों का दौरा किया था ;

(ख) क्या वापस आने पर उन्होंने भारतीय उत्पादों के लिए अफ्रीकी बाजार में मांग के बारे में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

आयुध कारखानों में प्रशिक्षित बेरोजगार शिशिक्षु

4016. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुध कारखानों में कारीगरों के रूप में प्रशिक्षित किए गये 5000 हजार से अधिक शिशिक्षु बिना रोजगार के हैं ;

(ख) यदि हां, तो 1968-69 में कितने शिशिक्षुओं को रोजगार दिया गया ; और

(ग) कितने शिशिक्षु अभी भी बेरोजगार हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी नहीं। 5595 व्यवसाय शिशिक्षुओं में से जिन्होंने प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया था, 3245 को या तो आर्डनेन्स कारखानों में सीधे रोजगार के लिए लगा लिया गया या फिर वे आर्डनेन्स कारखानों में अगला प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

1968-69 के दौरान क्रमशः 902 और 790 व्यवसाय शिशिक्षुओं को आर्डनेन्स कारखानों में नौकरी दी गई।

(ग) लगभग 2350 व्यवसाय शिशिक्षुओं को जिन्हें आर्डनेंस कारखानों में प्रशिक्षण दिया गया था, उन्हें प्रशिक्षण के उपरान्त आर्डनेन्स कारखानों में समाहत नहीं किया जा सका। यह कहा जा सकता है कि 1961 के शिशिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत आर्डनेन्स कारखानों पर सर्व प्रशिक्षणार्थियों को नौकरी का प्रस्ताव करने का कोई दायित्व नहीं है। शिशिक्षुओं का समाहत होना समय समय पर होने वाले स्थानों पर निर्भर करता है।

विभिन्न प्रतिरक्षा संस्थाओं के सरकारी कर्मचारी के रूप में घोषित न किए गए कैंटीन स्टोर्स कर्मचारी

4017. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न प्रतिरक्षा संस्थाओं के कैंटीन स्टोर्स विभाग कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के रूप में घोषित नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कब तक कोई निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) रक्षा स्थापनाओं के कैन्टीन कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी केवल तभी माना जाता है जब सरकार के द्वारा उनकी भर्ती की जाती है तथा उन्हें सरकारी निधि से वेतन दिया जाता है।

(ख) और (ग). रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत औद्योगिक स्थापनाओं में कैंटीनों के कर्मचारियों के प्रश्न पर कि उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाय या नहीं कुछ समय पूर्व सरकार ने इस प्रश्न पर निर्णय किया था कि कैंटीन कर्मचारियों के सरकारी कर्मचारी होने या न होने का प्रश्न उसकी सेवा की संविदा पर निर्भर करता है कि यदि कर्मचारियों की भर्ती सरकार के द्वारा की गई हो तथा उन्हें सरकारी निधि से वेतन मिलता हो तब वह सरकारी कर्मचारी समझे जायेंगे अन्यथा नहीं।

अमरीका तथा यूरोप में भारत विरोधी प्रचार का खंडन

4018. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका तथा कुछ अन्य पश्चिमी देशों में हो रहे भारत विरोधी प्रचार का खण्डन करने के लिए अग्रेतर कार्यवाही क्या की गई है ;

(ख) क्या भारत में अमरीकी सहायता से चल रहे कुछ सांस्कृतिक केन्द्रों को बंद कर देने के भारत सरकार के निर्णय के पश्चात इस प्रचार को तेज किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) विदेशों में भारत का समुचित चित्र प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सरकार भारत के विदेश प्रचार की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं पर बराबर निगाह रखती है और, जब जरूरत होती है, गलतफहमियों को दूर करती है। हाल के महीनों में इस दिशा में अपने सामान्य प्रयत्नों को तेज करने अथवा उनमें वृद्धि करने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ी है।

(ख) इस निर्णय की संयुक्त राज्य अमरीका और दूसरे देशों में रिपोर्टिंग तो हुई है लेकिन इस संदर्भ में कोई विशेष भारत-विरोधी प्रचार हमारे देखने में नहीं आया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Extension of Electricity to Rural Areas of Bihar

4019. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the amount provided by Government to Bihar Electricity Board and other institutions for the extension of electricity to the rural areas of Bihar and the direction given in respect of the manner in which the said amounts should be spent ; and

(b) the details of the amounts given by Government and the progress made in respect of the work for which the said amount was provided ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). Earmarked Central assistance was provided to the Bihar State Government, and other state Governments, from 1966-67 to 1968-69 for rural electrification schemes with a bias towards energisation of pump-sets for increasing agricultural production. The assistance given to the Government of Bihar during this period and the progress in respect of energisation of pump-sets are as follows :

	Central assistance	Number of pump-sets energised
	(Rs. in lakhs)	
1966-67	875.00	14082
1967-68	575.00	16009
1968-69	350.00	8624

Since the beginning of the Fourth Plan, no such earmarked assistance is being provided to the Bihar State Government and other State Governments and the outlays in this regard are made from the plan resources of the State Governments inclusive of the overall Central assistance provided to them. An outlay of Rs. 2.9 crores has been adjusted within the State plan ceiling of Bihar for rural electrification schemes in 1969-70. The number of pump-set energised from 1.4.69 to 31.12.69 is 5,017.

Progress of Gandak Canal in Priority Zone

4020. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the reason for the slow progress in the works of Gandak canal in Priority Zone during this year is the delay in design works at Patna as a result of which the work of some higher officers of Muzaffarpur is hampered ;

(b) if not, the details of the progress made in the priority zone during this year ;

(c) in case of slow progress, whether Government propose to take any step in this connection ;

(d) if so, the details thereof ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The Government of Bihar have reported that there is no delay in the design works at Patna, and that the progress in the execution of works of the Gandak Canal in the Priority Zone during this year is also not slow.

(b) The Government of Bihar have reported that the designs of all the structures on Don Canal, Nepal Eastern Canal and Tirhut Canal, and the branches of the Tirhut Canal included in the Priority Zone of 1970 have already been finalised and the approved drawings have been sent to the field Engineers. Work on all these structures is progressing satisfactorily. To expedite design and drawing of smaller structures on sub-distributaries and minors, design cells at the Headquarters of different circles in the field have also been set up and adequate staff posted.

(c) to (e). Do not arise.

Development of Roads in District Champaran in Bihar

4021. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government feel that it is necessary to construct new roads and develop those roads of District Champaran in Bihar, which touch the Northern border from country's security point of view ;

(b) whether the road from Motihari to Sitamarhi *via* Madhubani Ghat and Madhuban Shivhar and the road leading to Muzaffarpur are important from the said point of view ;

(c) if so, whether the dilapidated conditions of these roads is likely to be improved ; and

(d) if so, the action Government propose to take in this regard ?

The Minister of Dfence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) to (d). The existing road communications in the area are considered adequate from the defence point of view.

राज्य व्यापार निगम में एक अधिकारी को ऊंचा वेतन दिया जाना

4022. **डा० प० मण्डल :**

श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री राज्य व्यापार निगम में फालतू कर्मचारियों के बारे में 17 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4222 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विवरण में क्रमांक संख्या 11 में दिखाये गये कर्मचारी को, इस बात का पता लगाये बिना कि उसे संगठन में, जहां वह पहले नियुक्त था, कितना मूल वेतन व भत्ते मिलते थे, 1300-1600 के वेतन भाग में 1480 रुपये मूल वेतन पर नियुक्त करने के क्या कारण थे ;

(ख) क्या इस अधिकारी के चयन में राज्य व्यापार निगम के एक निदेशक द्वारा विशेष रूप से अनुचित पक्षपात किया गया था विशेषकर जब कि इस अधिकारी को प्रारम्भिक चयन में शामिल नहीं किया गया था ;

(ग) क्या इतना ऊंचा वेतन देना किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में भर्ती के सामान्य नियम और विनियमों के विपरीत है ; और

(घ) क्या राज्य व्यापार निगम में कर्मचारियों तथा अधिकारियों के भर्ती और पदोन्नति के नियमों और विनियमों की एक पूरी सूची (नवीनतम) सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) उस अधिकारी का मूल, वेतन, राज्य व्यापार निगम के प्रवरण बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी की आयु, उसके अनुभव, अर्हताओं और इस तथ्य पर विचार करने के पश्चात् निश्चित किया गया था कि बोनस के अतिरिक्त आवभगत तथा यात्रा भत्तों जैसे अनुषंगी लाभों को छोड़कर भी पहिले पद पर उसके द्वारा ली जाने वाली परिलब्धियां 1250 रुपये मासिक थी ।

(ख) और (ग). जी नहीं ।

(घ) राज्य व्यापार निगम के अमले और अधिकारियों की भर्ती और पदोन्नति के नियामक नियमों और विनियमों का एक प्रति 7 मई, 1969 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 8789 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए 21 नवम्बर, 1969 को सभा-पटल पर पहले ही रखी जा चुकी है ।

राज्य व्यापार निगम में हाल में नियुक्त किये गये व्यक्तियों को दिये गये अधिक वेतन

4023. **डा० प० मण्डल :**

श्री चं० सामन्त :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री राज्य व्यापार निगम में फालतू कर्मचारियों के बारे में 17 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4222 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारियों को देय मकान किराया भत्ते को विवरण में शामिल न किये जाने के

क्या कारण हैं तथा उक्त विवरण में उल्लिखित कर्मचारियों को देय मकान-किराया भत्ते का ब्यौरा क्या है ;

(ख) राज्य व्यापार निगम के मुख्य वित्त प्रबन्धक जिसे 1 अप्रैल,, 1969 से 1800 रुपये मासिक वेतन पर राज्य व्यापार निगम में नियुक्त कर लिया गया था, की नियुक्ति से संबंधित ब्यौरे को उक्त विवरण में शामिल न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) राज्य व्यापार निगम के मुख्य वित्त प्रबन्धक के मूल वेतन में लगभग 600 रुपये की वृद्धि करने का क्या औचित्य है ;

(घ) क्या राज्य व्यापार निगम सामान्यता सभी मामलों में वेतन में इतनी भारी वृद्धि करता है ; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य व्यापार निगम में ऐसे व्यक्तियों के नाम तथा ब्यौरा क्या है जिनके मूल वेतन में जुलाई 1968 के पश्चात् 300 से 600 रुपये प्रतिमास की वृद्धि की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) राज्य व्यापार निगम द्वारा जुलाई, 1968 से भर्ती किये गए व्यक्तियों की परिलब्धियों में आवास भर्ती शामिल नहीं किया गया था क्योंकि यह भत्ता, इन व्यक्तियों द्वारा किराये पर मकान लेने के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में है । इस विवरण (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखा जाता है । जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गयी है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०—2980/70]

(ख) निगम द्वारा मुख्य वित्त प्रबन्धक की नियुक्ति जुलाई, 1968 के पश्चात् नहीं की गयी थी ।

(ग) आयकर विभाग में 22 वर्ष का अनुभव, प्रमुख वित्त प्रबन्धक के पद हेतु उपयुक्तता जो निगम में उनके कार्य के आधार पर निश्चित की गयी है, प्रतिनियुक्त अधिकारी के रूप में उनका 1440 रु० मासिक वेतन, और उनके मूल विभाग में 1100-1600 रु० के वेतनमान में उनकी पात्रता ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

Filling up of Posts of Investigators in Central Statistical Organisation

4024. **Shri Molahu Prashad :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that five reserved permanent posts of Senior Investigators were unfilled while making appointments to such posts in August 1962 in the Central Statistical Organisation (Statistical Wing) as no candidate belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes was available at that time and that recruitment against the said reserved posts was made through the Union Public Service Commission the same year ;

(b) whether it is also a fact that the Senior Investigating belong to Scheduled Castes who were appointed against permanent posts in 1962 in the Statistics Wing have not so far been declared permanent ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) While making confirmations against vacancies in permanent posts of Senior Investigators in the Central Statistical Organisation in August 1962, only one confirmation could be made against six posts reserved for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes as suitable candidates belonging to the Scheduled Castes were not available for confirmation against the remaining five reserved posts.

(b) Recruitment was made in 1962 against ten *temporary* posts of Senior Investigators and out of the ten candidates appointed on the recommendation of the Union Public Service Commission three candidates belonged to Scheduled Castes/Scheduled Tribes. No recruitment was made against *permanent* posts in 1962.

(c) Does not arise.

बंगाल की खाड़ी में रूसी अनुसंधान पोत

4025. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान "हिन्दुस्तान टाइम्स" के 26 फरवरी 1970 के अंक में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि रूसी अनुसंधान पोत पाकिस्तान सरकार की प्रार्थना पर बंगाल की खाड़ी में है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में सरकार को पूर्व सूचना दी गई थी ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार को समाचार पत्रों की इस रिपोर्ट का ज्ञान है कि एक सोवियत अनुसंधान पोत बंगाल की खाड़ी में मूंगफली उद्योग के विकास से सहायता के लिए गहन जंगलों में पवृत्त है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी वैज्ञानिक जांच कर रहे सोवियत अनुसंधान करने वालों की सहायता कर रहे हैं।

(ख) कोई पूर्व सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। विदेशी पोत अन्तर्राष्ट्रीय पानियों में विचरने के लिए स्वतन्त्र है।

रूसी दूतावास द्वारा लेनिन की मूर्ति का आयात

4026. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री जनेश्वर मिश्र :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी दूतावास ने बिना शुल्क लेनिन की एक मूर्ति भारत में आयात करने की अनुमति मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चाय बोर्ड को सरकारी क्षेत्र में चाय विपणन निगम के रूप में बदलना

4027. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चाय बोर्ड को सरकारी क्षेत्र में चाय विपणन निगम के रूप में बदलने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) (क) और (ख). विदेशी व्यापार मन्त्रालय हेतु संसद् की परामर्शदात्री समिति की उप-समिति ने, जिसका गठन पैकेज बन्द चाय के निर्यात सम्बन्धी तथा प्रोत्साहन के लिए सिफारिशें करने के लिए किया गया था, अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में, अन्य विषयों के साथ साथ, सरकारी क्षेत्र में एक निगम स्थापित करने की सिफारिश की है। उप समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि चाय बोर्ड को पैकेज बन्द चाय का निर्यात करने के लिए उक्त निगम के रूप में परिवर्तित कर देना चाहिए। अन्तरिम प्रतिवेदन इस समय विचाराधीन है।

अम्मान में नया कार्यकारी राजदूत

4028. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत अम्मान में भारतीय दूत का कार्यभार सम्भालने के लिये नया कार्यकारी राजदूत भेज रहा है ;

(ख) क्या मोरक्को सरकार ने भारत से अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिये अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में नवीन स्थिति क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). ये मामले भारत सरकार के विचाराधीन हैं।

पाकिस्तान द्वारा चण्डीगढ़ के बारे में पंजाब को भड़काया जाना

4029. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता लगा है कि चण्डीगढ़ आन्दोलन के दौरान पाकिस्तान यह प्रचार कर रहा था कि सरकार चण्डीगढ़ के बारे में पंजाब के न्यायोचित दावे को पूरा नहीं कर रही है ;

(ख) क्या ऐसा हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि पश्चिम पाकिस्तान में गुरुद्वारों की यात्रा करने वाले पंजाबी तीर्थयात्रियों का राजकीय समारोह-पूर्व स्वागत किया गया था ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्दपाल सिंह) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) पाकिस्तानी अधिकारी हमारे तीर्थयात्रियों के लिए जो प्रबन्ध करते हैं कि वे सामान्य रूप से संतोषजनक रहते हैं, हालाँकि कभी-कभी शिकायतें मिलती हैं।

नागाओं से चीनी गोला बारूद का बरामद होना

4030. **श्री श्रीचंद गोयल** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागाओं से चीनी गोला बारूद बरामद हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में ; और

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). चीन से लोटे भूगर्भवत नागाओं से विभिन्न किस्म के चीनी गोला बारूद की लगभग 70000 गोलियाँ पकड़ी गई थीं ।

(ग) पकड़े गए व्यक्तियों से पूछताछ से चला है कि भारी अशान्ति, और नागालैंड में वैदेय सरकार के पतन के उद्देश्य से चीनियों द्वारा गोलाबारूद और आयुध दिए गए थे ।

सूती कपड़े का मूल्य

4031. **श्री ज्योतिमय बसु** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 से 1969-70 तक, वर्षवार, आन्तरिक खपत तथा निर्यात के लिये सूती कपड़े की प्रत्येक किस्म के औसत नियंत्रित मूल्य क्या रहे ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में उपभोक्ताओं को नियंत्रित मूल्यों से अधिक मूल्य देने पड़ते हैं, यदि हां, तो कपड़े की नियंत्रित तथा अनियंत्रित किस्मों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) वर्ष 1967-68 से 1969-70 तक वर्षवार तथा राज्य वार अनियंत्रित कपड़े की किस्मों के औसत मूल्य क्या रहे ;

(घ) क्या भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ ने हाल ही में सरकार से कपड़े की नियंत्रित किस्मों के मूल्यों में वृद्धि करने का अनुरोध किया है ;

(ङ) यदि हां, तो इस अनुरोध का आधार क्या है ; और

(च) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) खुदरा स्तर पर नियंत्रित कपड़े के सांविधिक मूल्यों के प्रवर्तन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और यदि छपे हुए मूल्यों से अधिक मूल्यों पर बिक्री की कोई सूचना, खुदरा वस्त्र बाजारों के अवधिक सर्वेक्षण के दौरान वस्त्र-आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्त होती है तो आप यह कार्यवाही हेतु, राज्य सरकारों को उससे अवगत करा दिया जाता है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) भारतीय सूती मिल संघ ने नियंत्रित कपड़े के मूल्यों में वृद्धि करने की मांग इस आधार पर की है कि रुई, मजूरी भंडारों, बिजली, ईंधन, कोयले रंजक और रसायनों के मूल्य बढ़ गये हैं तथा ब्याज की दर और ऊपरी खर्च में भी वृद्धि हुई है।

(च) मामला विचाराधीन है।

अमरीका को टाट का निर्यात

4032. **श्री ज्योतिमय बसु :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 से 1969-70 तक वर्षवार अमरीका को कितना तथा कितने मूल्य के टाट का निर्यात किया गया ; और

(ख) क्या अमरीका में हाल में मोटे टाट की खपत में कमी, म्यूटीबाल पेपर को ट्यूबिंग मशीन जैसी बोरा बनाने वाली मशीन का सफलतापूर्वक विकास होने के कारण हुई है जिससे बोरे बनाने का कार्य बहुत तेजी से होता ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) सं० रा० अमरीका में मोटे टाट की खपत में कमी विभिन्न कारणों से हुई है, जैसे इसके ऊंचे मूल्य भारत से रुक-रुक कर माल जाना ऊंची श्रम-लागत के कारण लदान-उतरान की विधियों में परिवर्तन, संश्लिष्टों से तथा कागज के लिफाफों से कड़ी प्रतियोगिता आदि।

विवरण

सं० रा० अमरीका को हेसियन के निर्यात का परिमाण तथा मूल्य

वर्ष	परिमाण	मूल्य
	(हजार मे० टन)	(करोड़ रु० में)
1966-67	150.5	52.19
1967-68	145.1	43.37
1968-69	114.8	35.72
1969-70	51.4	16.23*

*आंकड़े अप्रैल-नवम्बर, 69 तक के हैं।

पश्चिम बंगाल में कंगसावती परियोजना की अनुमानित लागत

4033. **श्री ज्योतिमय बसु :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में कंगसावती परियोजना पर मूलतः 25 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान था, अब समय गुजरने के साथ-साथ इस लागत का अनुमान बढ़ कर 48 करोड़ रुपया हो गया है ;

(ख) क्या इस लागत में वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना को अन्तिम रूप से अपनी स्वीकृति देने में बहुत समय लिया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस अनुमानित लागत में इतनी अधिक वृद्धि के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या इस परियोजना का कार्य वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण गत 13 वर्ष से बड़ी ही धीमी गति से चल रहा है जैसा कि पश्चिम बंगाल सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा है ; और

(ङ) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस परियोजना के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिये अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने हेतु प्रधान मंत्री को एक अभ्यावेदन पेश किया है और यदि हां, तो यदि इस अभ्यावेदन पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इस अवधि में कीमतों में चढ़ाव और दीर्घ निर्माणावधि के कारण ।

(घ) सिंचाई परियोजनाएं राज्य की योजनाओं का एक अंग हैं और उन्हें ही विकास क्रियाकलापों के लिए अपने आवंटनों में से इन के लिए धन का प्रबंध करना है ।

(ङ) स्कीम की कार्यगति में तेजी लाने के लिए 1968-69 के दौरान 1.3 करोड़ रुपये की विशेष सहायता दी गई थी । 1969-70 के लिए 2 करोड़ रुपये के विशेष ऋण को भी स्वीकार कर लिया गया है जो कि योजना के लिए स्वीकृत राशि से अलग होगा ।

चाय-बोर्ड के कोचीन स्थित कार्यालय

4034. **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री पी० पी० एस्थोस:
श्री क० अनिरुद्धन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **वैदेशिक व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय बोर्ड के कोचीन स्थिति कार्यालय में "स्वीकृत पदों" की संख्या क्या है तथा उसके बारे में श्रेणीवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सभी "स्वीकृत पदों' की नियुक्ति कर ली गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) रिक्त पड़े पदों का श्रेणीवार ब्योरा क्या है ; और

(ङ) प्रत्येक पद किस तारीख से रिक्त पड़ा है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें चाय-बोर्ड के कोचीन स्थित कार्यालय के अमले की वर्गवार स्थिति दर्शायी गयी है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०—2981/70] ।

(ग) और (घ). कोचीन स्थित कार्यालय में अमले की आवश्यकता की अपेक्षा तथा कार्यभार के अनुसार पूरा किया जाता था। नवम्बर, 1961 में निर्यात कोटा पद्धति समाप्त हो जाने के फलस्वरूप बोर्ड के कोचीन स्थित लाइसेंस-कार्यालय में कार्यभार काफी कम हो गया जिसके फलस्वरूप विद्यमान अमला बेशी हो गया। अतः स्वीकृत पदों का और स्थित पदों को भरने का प्रश्न नहीं उठता। बेशी हो गये अमले को शनैः-शनैः अन्यत्र खपाया जा रहा है और कोचीन स्थित कार्यालय में वस्तुतः कोई पद रिक्त नहीं है।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

काफी-चाय बोर्ड कर्मचारियों को बोनस देना

4035. **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री के० रमानी :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री प० गोपालन :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफ़ी बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस बोनस की दर क्या है तथा यह किस अवधि के लिए स्वीकृत किया गया है ;

(ग) यदि चाय बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया जाता तो, उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, हां।

(ख) 1-4-1964 से 31-3-1969 की अवधि के लिए न्यूनतम दर (4 प्र० श०) पर।

(ग) बोनस देने के सम्बन्ध में बोनस अधिनियम के उपबन्ध चाय बोर्ड के कर्मचारियों पर लागू नहीं होते।

जम्मू तथा काश्मीर के लिए यथापूर्व स्थिति

4036. **श्री वंश नारायण सिंह :**
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जनरल अयूबखां भारत के साथ युद्ध न करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने तथा संयुक्त प्रतिरक्षा पर विचार विमर्श करने और जम्मू तथा कश्मीर पर दोनों देशों के वर्तमान कब्जे को स्थायी बंटवारे का रूप देने के लिए सहमत हो गये थे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : भारत के साथ 'युद्ध नहीं संधि' पर हस्ताक्षर करने के लिए पाकिस्तान कभी सहमत नहीं हुआ, हालांकि इस सम्बन्ध में भारत ने 1949 से अनेक प्रस्ताव किए हैं, और न राष्ट्रपति अयूब खां ने 'युद्ध नहीं संधि' का कभी प्रस्ताव किया है। 1959 में अयूबखां ने भारत के साथ संयुक्त सुरक्षा का जो प्रस्ताव रखा था, उसमें काश्मीर के सम्बन्ध में पाकिस्तान की मांगों को मान लेने जैसी अस्वीकार्य शर्तें रखी गई थीं, अतः इसे अस्वीकार कर दिया गया। पाकिस्तान ने कभी यह प्रस्ताव नहीं रखा कि भारत या पाकिस्तान जम्मू और काश्मीर में अपने अधिकृत क्षेत्रों का प्रशासन करे।

French Arms for Pakistan

4037. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whetheg France has recently supplied a large quantity of armaments to Pakistan ;

(b) if so, the types of weapons supplied ;

(c) whether Government have sent a protest note to France in this regard ; and

(d) whether it is a fact that Saudi Arabia made available the necessary foreign exchange to Pakistan for purchasing the said armaments ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) to (c). Government are aware of the supplies of military equipment, including Mirage aircraft and submarines by France to Pakistan. Government have also received a report that a British ship left a French port a few weeks ago carrying some military supplies for Pakistan. Confirmed information regarding the nature of arms being carried in it is not available. Government's views regarding the supplies of arms to Pakistan have been made known to all friendly Governments, including the Government of France.

(d) Government have no authentic information on this.

भारतीयों को विदेशी पुरस्कार

4038. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री भारतीयों को विदेशी पुरस्कारों के बारे में 26 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1414 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूछी गई जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). सूचना अभी भी इकट्ठी की जा रही है ।

मध्य प्रदेश में हस्दो नदी पर एल्मा बांगो बांध

4039. **श्री लखन लाल गुप्ता :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने मध्य प्रदेश में हस्दो नदी पर एल्मा बांगों का निर्माण करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना पर कितना व्यय होने की सम्भावना है, तथा इस परियोजना पर सम्भवत: कब तक कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). योजना आयोग ने मध्य प्रदेश में चतुर्थ योजना के दौरान हाथ में ली जाने वाली नई बृहत् सिंचाई परियोजनाओं की सूची को अभी तैयार नहीं किया है ।

'गत तीन वर्षों में काश्तकारों तथा मध्य आय वर्ग के तथा धनी व्यक्तियों सहित गैर-काश्तकारों की आय में हुई कमी वेशी'

4040. **श्री देवकी नंदन पाटोदिया** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में हरित क्रान्ति से केवल काश्तकार ही समृद्ध हुए हैं किन्तु मध्य आय वर्ग के तथा धनी व्यक्तियों सहित गैर-काश्तकारों को इससे इतना लाभ नहीं हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास गत तीन वर्षों में उपरोक्त वर्गों की आय में हुई कमी-वेशी दर्शाने वाले आंकड़े हैं और प्रत्येक वर्ग की आय की दर में हुई कमी-वेशी के क्या कारण हैं और इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) यह माना गया है कि प्रश्न में व्यक्त 'हरित क्रान्ति' का तात्पर्य उच्च उत्पादन वाली किस्मों से संबन्धित कार्यक्रम के प्रवर्तन से है । इस कार्यक्रम में केवल कुछ क्षेत्र तथा किसानों के कुछ वर्ग एवं कुछ विशिष्ट फसलें आती हैं । परन्तु इससे खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि तथा उपभोग के लिए अपेक्षाकृत अधिक खाद्यान्नों की उपलब्धि हुई है तथा कुछ सीमा तक इससे सामान्य मूल्य का स्थिरीकरण हुआ है जिससे सभी वर्गों को लाभ हुआ है । उच्च उत्पादन वाली किस्मों से सम्बन्धित कार्यक्रम का धीरे-धीरे विस्तार भी किया जा रहा है ताकि इसके अन्तर्गत और अधिक क्षेत्र तथा किसान आ जाएं ।

(ख) 'हरित क्रान्ति' के फलस्वरूप विभिन्न वर्गों की आय पर क्या प्रभाव पड़ा इसके सम्बन्ध में अभी तक कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है ।

भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों के प्रश्न पर विदेशों द्वारा प्रतिकारात्मक कार्यवाही

4041. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विदेशी सांस्कृतिक केन्द्रों को बन्द करने के आदेश को प्रतिक्रिया स्वरूप किसी देश ने विदेशों में हमारे किसी सांस्कृतिक केन्द्र को बन्द करसे का आदेश निकाला है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों में हमारे सांस्कृतिक केन्द्रों को बन्द करने को कहा गया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ब्रिटिश जहाजों में पाकिस्तान के लिए फ्रांसिसी हथियार लाया जाना

4042. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री मणिभाई जे० पटेल ,

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान को फ्रांसिसी हथियार ब्रिटिश जहाजों में भेजे जा रहे हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने ब्रिटिश तथा फ्रांस सरकारों से पता किया है कि किस प्रकार के हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). सरकार को ज्ञान है कि पाकिस्तान के लिए कुछ सैनिक सप्लाईयां लेकर एक ब्रिटिश पोत कुछ सप्ताह हुए एक फ्राँसिसी बन्दरगाह से चला था । इसमें ले जाए जाने वाले आयुधों के गुण रूप के सम्बन्ध में पुष्ट सूचना प्राप्त नहीं है । साधारणतः विदेशी सम्बन्धित सरकार से लिखा-पढ़ी द्वारा ऐसे सौदों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती । तदपि पाकिस्तान को आयुधों और गोला बारूद की सप्लाई के विषय पर सरकार के विचार फ्रांस की सरकार सहित सभी भिन्न देशों को जता दिए गए हैं ।

जापान को लौह अयस्क की सप्लाई

4043. **श्री देवकी नंदन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत से जापान को लौह अयस्क सप्लाई करने के सम्बन्ध में जापान के साथ हाल में हुए करार की शर्तें तथा ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : हाल में भारतीय राज्य व्यापार निगम ने 1970-75 में लगभग 42.67 करोड़ रु० मूल्य के विभिन्न ग्रेड के 69.5 लाख टन लौह अयस्क की पूर्ति के लिए जापानी इस्पात मिलों के साथ संविदाएं की हैं । पोत-लदान जहाज पर मूल्यों के आधार पर होंगे और कुल बिक्री मूल्य अमरीकी डालरों में प्राप्त होगा ।

सिंगापुर में होने वाली राष्ट्रमण्डल के प्रधान मन्त्रियों की बैठक

4044. **श्री बलराज मधोक** :
श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रमण्डल के प्रधान मन्त्रियों की आगामी बैठक सिंगापुर में होगी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत सरकार यह चाहती थी कि यह सम्मेलन दिल्ली में हो ; और

(ग) यदि हां, तो भारत के इस सम्मेलन को आयोजित करने के दावे की अवहेलना क्यों की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अणु शक्ति विभाग द्वारा विदेश यात्रा पर व्यय की गई धन राशि

4046. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी से दिसम्बर, 1969 तक की अवधि में अणु शक्ति विभाग द्वारा विदेशों की यात्राओं पर 13.11 लाख रुपये व्यय किये गये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि फ्रांस की आठ यात्राऐं 1969 में कालक्कम में मद्रास आणविक विद्युत केन्द्र के लिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के निर्माण के बारे में कमिसरियटल इनर्जिक एटामिक के साथ सहयोग/करार के सम्बन्ध में विचार विमर्श के लिए की गई थी ; और

(ग) क्या उक्त सभी यात्राऐं और उन पर किया गया व्यय अनिवार्य था और यदि हां, तो उन यात्राओं के औचित्य का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं, इस विभाग के अधिकारियों द्वारा जनवरी से नबम्बर, 1969 तक की अवधि में किये गये दौरों पर लगभग 4.08 लाख रुपये खर्च हुए ।

(ख) जनवरी से नवम्बर, 1969 की अवधि में विभाग के दो अधिकारी सयुक्त राष्ट्र संघ/अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु शक्ति एजन्सी की बैठकों में भाग लेकर वापस आते समय फास्ट ब्रीडर टेस्ट रियेक्टर से सम्बन्धित मामलों पर कमसरियटल इनजिक एटामिक, फ्रांस के साथ विचार विमर्श करने के लिये, तीन अवसरों पर फ्रांस रुके थे ।

(ग) जी हां, अनेक तकनीकी मामलों पर फ्रांसीसी विशेषज्ञों और भारतीय फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के विस्तृत डिजाइन के लिये फ्रांस में कार्य कर रहे भारतीय परमाणु शक्ति आयोग के दल से विचार विमर्श करके निर्णय किया जाता है ।

क्लोरमफेनिकोल का आयात

4047. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि राज्य व्यापार निगम को 1969 में छ मे० टन क्लोरमफेनिकोल का आयात करने के लिए कहा गया था क्योंकि देश के उत्पादकों ने उक्त औषधि का पर्याप्त मात्रा में निर्माण करने में कठिनाई अनुभव की थी ;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम ने उस औषधि को लगभग 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद कर 700-800 रुपये पर प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया था जबकि स्थानीय भाव 410 रुपए प्रति किलोग्राम था ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो क्या यह मामला राज्य व्यापार निगम द्वारा मुनाफा और वह भी एक अत्यावश्यक प्रतिजीवाणु औषधि पर, कमाने का स्पष्ट उदाहरण नहीं है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां। राज्य व्यापार निगम से 1969 में 10 मे० टन क्लोरमफेनिकोल चूर्ण तथा 7 मे० टन क्लोरमफेनिकोल पाल्मिटेट के आयात का प्रबन्ध करने के लिए कहा गया था।

(ख) इन औषधियों की आयात लागत और खुदरा मूल्य इस प्रकार थे :

	आयात दर (लागत बीमा भाड़ा मूल्य तथा आयात शुल्क) रु० प्रति कि० ग्राम	खुदरा मूल्य रु० प्रति कि० ग्राम
क्लोरमफेनिकोल चूर्ण	145.20	400.00
क्लोरमफेनिकोल पाल्मिटेट	157.20	183.50

(ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा क्लोरमफेनिकोल चूर्ण के खुदरा मूल्य सरकार के अनुरोध पर उच्च स्तर पर निर्धारित किए गए थे ताकि इस औषध के स्वदेशी उत्पादन को संरक्षण मिल सके। क्लोरमफेनिकोल पाल्मिटेट पर होने वाला लाभ केवल 6 प्रतिशत था।

पंजाब में भटिंडा परियोजना की स्वीकृति

4048. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग तथा केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय ने पंजाब में भटिंडा परियोजना को स्वीकृति देने से इंकार कर दिया है ;

(ख) क्या पंजाब ने फिर भी इस परियोजना को आरम्भ कर दिया है ; और

(ग) यदि उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो राज्य सरकार द्वारा केन्द्र पर इस प्रकार अपनी इच्छा लादे जाने जाने के बारे में उनका क्या कार्यवाही का विचार है।

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं। भटिंडा ताप बिजली केन्द्र परियोजना कार्यान्वयनार्थ स्वीकृत हो चुकी है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

ऊनी हौजरी तथा ऊनी वस्त्र के निर्यात के लिए समान प्रक्रिया

4049. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊनी हौजरी का निर्यात राजकीय व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है जबकि ऊनी कपड़े का निर्यात सीधे किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कारण है कि दो भिन्न प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं ; और

(ग) निर्यात किये जाने वाले दोनों प्रकार के माल के लिए समान प्रक्रिया अपनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). होजरी तथा निट किये हुए माल के निर्यात को मार्गीकृत करना, इस क्षेत्र के असंगठित स्वरुप तथा इकाई मूल्य को संरक्षित करने की दृष्टि से, उचित समझा गया था ।

चीन द्वारा अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रों का परीक्षण किया जाना

4050. **श्री हरदयाल देवगुण** : **श्री यज्ञदत्त शर्मा** :
श्री जय सिंह :

क्या प्रति रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है, कि चीन अगले वर्ष स्व-निर्मित जेट लड़ाकू विमानों का मालिक हो जायेगा और उसने अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रों का भी पूरी तरह परीक्षण करके तैयार हो जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार देश की रक्षा के लिए आवश्यक उपाय कर रही है ।

Export of Bananas from M.P.

4051. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) the value of bananas exported from Madhya Pradesh during the year 1965-66, 1966-67 and 1968-69, year-wise ;

(b) whether it is a fact that the export thereof is declining ; and

(c) if so, the percentage thereof and the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) Statewise export figures are not maintained and as such information about export of bananas

from Madhya Pradesh is not available. The value of bananas exported from the country as a whole during the year 1965-66, 1966-67 and 1968-69 was as follows :

Year	Value
	(Rs. in lakhs)
1965-66	38
1966-67	63
1968-69	51

(b) and (d). During the years mentioned in part (a) of the Question there has not been significant decline in export of bananas.

Export of Mangoes from M.P.

4052. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the year-wise export of mangoes from Madhya Pradesh during 1966-67, 1967-68 1968-69 and the percentage of increase or decline in the export thereof during the year 1968-69 over the year 1967-68 ; and

(b) the targets fixed for their production and export separately in the Fourth Five-Year Plan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) Statewise export figures are not maintained. However, export of mangoes from the country as a whole during the year 1966-67 to 1968-69 was as follows :

Year	Quantity	Value
	Tonnes	'000' of Rs.
1966-67	810	1430
1967-68	1075	1819
1968-69	1204	2457

The percentage of increase during the year 1968-69 over the year 1967-68 was about 17.6%.

(b) No separate information for Madhya Pradesh is available. However, a Centrally Sponsored Scheme for production of fruits has been formulated to be implemented during the 4th Plan period. According to this Scheme, it is proposed to bring an additional area of 18,400 hectares under mangoes which would result in additional yield of 20,000 tonnes at the end of the 4th Plan out of which 7500 tonnes are envisaged for export annually.

Loss due to Lock-outs and Strikes in Textile Mills in Madhya Pradesh

4053. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether any estimate regarding the loss suffered by the owners due to lock-outs and strikes in the textile mills in Madhya Pradesh during the last 3 years has been made ;

(b) whether Government have also estimated the loss of the foreign exchange suffered due to the lock-outs in the said textile mills ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) and (b). No, Sir.

(c) Does not arise,

आयुध कारखानों में बनने वाली कुछ वस्तुओं का गैर-सरकारी क्षेत्र में बनाया जाना

4055. **श्री अदिचन** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध फैक्ट्रियों में बनने वाली कुछ वस्तुओं का गैर-सरकारी क्षेत्र में बनाने का कोई प्रस्ताव है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उन मदों को गैर-सरकारी क्षेत्र में बनवाने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). आर्डनेंस में उत्पादन की अनुपूर्ति के लिए जहां आवश्यक होता निजी क्षेत्र की सहायता ग्रहण की जाती है। मुख्यतः उन संघटकों और औजारों की सप्लाई के लिए निजी क्षेत्र पर भरोसा किया जाता है, कि जिनके लिए आर्डनेंस फैक्टरियों में क्षमता या तो है ही नहीं, या क्षमता पर्याप्त नहीं है ।

इसके अतिरिक्त रक्षा सप्लाई विभाग अब तक आयात की गई रक्षा मदों के देशीय निर्माण की स्थापना का अनुसरण करता रहा है ।

हथकरघा क्षेत्र में रंगीन साड़ियों का उत्पादन

4056. **श्री अदिचन** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रंगीन साड़ियों के उत्पादन का हथकरघा क्षेत्र में सीमित रखने के सरकार के निर्णय के विरुद्ध सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) सरकार, हथकरघों के लिए उत्पादन के कतिपय क्षेत्रों के आरक्षण की विद्यमान नीति में कोई परिवर्तन करने पर विचार नहीं कर रही है ।

विवरण

सरकार को प्राप्त हुए अभ्यावेदनों सार निम्नलिखित है :—

(1) देश के कुल शक्ति-चालित करघों में से 80 प्रतिशत महाराष्ट्र में हैं और रंगीन साड़ियों का उत्पादन भी प्रधानतः महाराष्ट्र राज्य में होता है ।

(2) शक्ति-चालित करघा राज्य में विकेन्द्रीकृत लघु उद्योग है ।

(3) उद्योग में कार्यरत व्यक्ति अधिकांशतः अपना काम करते हैं जो बेरोजगार हो जायेंगे ।

(4) हथकरघों से बनी रंगीन साड़ियों का निर्यात भी किया जाता है और विदेशी मुद्रा की आय की हानि नहीं होनी चाहिये ।

पूर्वी जर्मनी स्थित भारतीय वाणिज्य कार्यालय का दर्जा बढ़ाया

4057. **श्री चेंगल राया नायडू** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत सरकार ने भारतीय वाणिज्य कार्यालय का दर्जा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में कितनी सत्यता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस समाचार का खण्डन किया ;

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्दपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय व्यापार प्रतिनिधि को अब कुछ कोंसली कार्य का अधिकार भी दे दिया गिया है ।

(ग) सरकार ने उस स्थिति को स्पष्ट कर दिया है ।

Demands of Employees of Delhi Electric Supply Undertaking

4058. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the employees of the Delhi Electric Supply Uudertaking have been agitating for a very long time in support of their demands ;

(a) if so, the details of their demands ; and

(c) the action taken by Government to redress their grievances ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). In their notice for a strike from 1st March, 1970, the Delhi State Electricity Workers Union have referred to three categories of demands :—

(i) 6 demands concerning awards which have not been implemented, relating mainly to permanent appointment of work-charged khlasis, appointment of meter reader inspectors, payment of ex-gratia and provision of free housing accommodation for staff posted in rural areas.

(ii) 26 demands stated to be agreed to by the Management but which have not been implemented relating mainly to confirmation of staff, conversion of temporary posts into permanent ones, supply of uniforms, raincoats, pugress, provision of medical and other facilities.

(iii) 48 demands to be discussed and settled.

Negotiations have been resumed by the Delhi Electric Supply Undertaking with the Delhi State Electricity Workers Union and in this regard the assistance of the Ministry of Irrigation and Power is being availed of. The following is the progress—Out of the six demands in the first category, the Management have reported that five have been implemented fully and that the remaining one relating to provision of housing is an award which is for implementation on a long-term basis. In respect of the second category of demands, the Management have reported that 15 have been agreed to by the Management for implementation. The third category of demands as well as other demand including those in the first and second categories are being discussed by the Management with the Union. As a result of these negotiations which are in progress, the proposed strike on 1st March, 1970, did not materialise.

मनीपुर में सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध करने के लिए निर्धारित धनराशि

4059. **श्री एम० मेघचन्द** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में मनीपुर की सिंचाई योजनाओं के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ;

(ख) इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनके पूरा हो जाने के बाद कुल कितने क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी ;

(ग) क्या यह सच है कि सप्लाई की कमी के कारण मनीपुर में अनाज की दो फसलें नहीं बोई जा सकती ; और

(घ) यदि हां तो क्या सरकार सिंचाई सम्बन्धी कार्य के लिए अधिक राशि नियत करेगी और अधिक ध्यान देगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). चतुर्थ योजना के मसौदे में मणिपुर में बृहत् तथा मध्यम सिंचाई स्कीमों के लिए 10 लाख रुपये का प्रबन्ध किया गया है। मणिपुर प्रशासन इस समय लोकतक झील से उठाऊ सिंचाई करने की स्कीम की जांच कर रहा है।

मनीपुर के काकचिंग पलेल में फाल्तू हवाई अड्डे का समाप्त किया जाना

4060. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के काकचिंग पलेल स्थित फाल्तू हवाई अड्डे को समाप्त करने का काम रोक दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसे कब तक समाप्त किया जायेगा ;

(ग) क्या वहां पर बसने की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र उनके मंत्रालय द्वारा लिए गए हैं ; और

(घ) यदि हां, उन पर अब तक क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). यह निश्चय किया गया है कि भूमि को रक्षा कार्यों के लिए रखा जाय।

(ग) जी हां।

(घ) मामला विचाराधीन है।

मनीपुर में ग्रामीण विद्युतीकरण

4061. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के पहाड़ी तथा देहाती क्षेत्रों में बिजली लगाने का काम आरम्भ कर दिया गया है ;

(ख) क्या इम्फाल दीमापुर रोड में ताइवी के निकट स्थित देहातों के स्थानीय लोगों ने ताइवी से पौमाता केन्द्र तक बिजली की सप्लाई बढ़ाने के बारे में मनीपुर सरकार से प्रार्थना की थी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उस पर कोई कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 31 दिसम्बर, 1969 तक मणिपुर में 125 इलाके, जिनमें से 29 पहाड़ी क्षेत्रों में है, विद्युतिकृत हो चुके हैं, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए मणिपुर में 81 ग्रामों को विद्युतीकृत करने की स्कीम सितम्बर, 1969 में स्वीकृत हो चुकी है। ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों के अन्तर्गत चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पहाड़ी क्षेत्रों में 40 इलाके विद्युतीकृत हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त चतुर्थ योजना के दौरान असम से थोक बिजली सप्लाई के समुपयोजन संबंधी स्कीम के अन्तर्गत पहाड़ी क्षेत्रों में 60 इलाके और विद्युतीकृत हो जायेंगे।

(ख) और (ग). मणिपुर सरकार ने सूचित किया है कि तडूबी के निकटवर्ती ग्रामों के स्थानीय लोगों से तडूबी से पौमाटा केन्द्र को बिजली सप्लाई विस्तार के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी यह विस्तार-कार्य असम से थोक बिजली सप्लाई के समुपयोजन संबंधी स्कीम के अन्तर्गत प्रारम्भ किया जा रहा है।

इम्फाल के निकट तुलीहाल हवाई अड्डे का निर्माण

4062. **श्री एम० मेघचंद्र** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इम्फाल के निकट तुलीहाल हवाई अड्डे के निर्माण के लिए कितनी राशि मंजूर की गई थी और अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ;

(ख) ठेकेदार का नाम क्या है ;

(ग) निर्माण कार्य पर कौन श्रमिक लगाए गए हैं और पुरुष तथा महिला श्रमिकों की दैनिक मंज़ूरी कितनी है ;

(घ) 1969 में स्थानीय गैर-स्थानीय रूप में औसतन कितने श्रमिक लगाए गए ; और

(ङ) क्या मजदूरों को नियमत रूप से भुगतान किया जाता है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) यह सूचना देना वांछनीय नहीं होगा, क्योंकि इससे हवाई अड्डे के ब्यौरों और क्षमता का पता चल जायेगा।

(ख) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है, और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

भाभा आणविक अनुसंधान केंद्र द्वारा इलेक्ट्रोन बीम से बेल्डिंग करने के एकक का डिजायन बनाना

4063. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा आणविक अनुसंधान केन्द्र, ट्राँम्बे ने इलेक्ट्रॉन बीम से बेल्डिंग करने वाले एकक का डिजायन बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत क्या है और उस उपकरण का किन कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा और उसके फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) इस एक पर 1,25,000 लागत आई है । यह एकक आवणिक रिएक्टरों के लिए ईधन पदार्थों का उत्पादन करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा । इस एकक को भारतीय सामग्री से तैयार करने में कल पुर्जों पर 15,000 रुपये की विदेशी मुद्रा का खर्च होगा ;

Absorption of Teachers of Guards Training Centre, Kota

4064. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government have absorbed all the teachers retrenched from the Guards Training Centre, Kota on the same pay-scales ;

(b) if not, the reasons therefore ; and

(c) the places where they have been absorbed and their pay-scales ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) Yes.

(b) Does not arise.

(c) They have been absorbed in C. O. Ds Allahabad, Agra, Kanpur, Chheoki, Dehu CAFVD, Kirkee in the pay scale Rs. 110-3-131-4-155-EB-4-175-5-180.

Guards Training Centre, Kota

4065. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government propose to increase the capacity of Guards' Training Centre and Kota ;

(b) if so, the present number of trainees in the said centre ;

(c) the extent to which and the time by which its capacity would be increased ;

(d) whether Government propose to open centres to impart training to operate aircraft at ships ; and

(e) if not, the reasons therefor specially when the means for imparting training to operate aircraft and ships are available there ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) No.

(b) and (c). Does not arise.

(d) No—not at Kota.

(e) Adequate arrangements already exist elsewhere for this.

भारत जर्मनी लोकतंत्रात्मक गणराज्य सहयोग पर विचार गोष्ठी

4068. **डा० रानेन सेन :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 अक्तूबर, 1969 को बम्बई में भारत-जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य सहयोग पर एक विचार गोष्ठी हुई थी ;

(ख) क्या गोष्ठी में सरकारी अधिकारियों ने भी भाग लिया था ;

(ग) गोष्ठी में किन किन विषयों पर चर्चा हुई और उसके क्या परिणाम निकले ; और

(घ) क्या गोष्ठी में दिए गए कुछ सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए कब कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) गोष्ठी में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई :—

(1) जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के आर्थिक विकास के बीस वर्ष और विकासशील देशों के साथ, भारत के विशेष संदर्भ में, आर्थिक तथा औद्योगिक सहयोग ;

(2) विकासशील देशों के साथ, भारत के विशेष संदर्भ में, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य का विदेशी व्यापार ;

(3) जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य को भारतीय माल का निर्यात बढ़ाना ।

गोष्ठी में भारत-जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्धों का और भी विकास करने की संभाव्यताओं और इस सम्बन्ध में जो उपाय किए जाने चाहियें उन पर विशेष प्रकाश डाला गया ।

(घ) गोष्ठी में की गई सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

हथकरघा तथा खादी और ग्रामोद्योग को एक पृथक मंत्री के अधीन लाने का प्रस्ताव

4069. **श्री एस० के० संबंधन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को देखते हुए कि हथकरघा उद्योग तथा खादी और ग्रामोद्योग पर अनेक लोग निर्भर करते हैं ; उन उद्योगों को एक पृथक मन्त्री के अंतर्गत लाने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग). हथकरघा उद्योग विदेश-व्यापार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है और खादी सहित ग्रामोद्योग औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय के अधीन है। इस व्यवस्था को संतोषजनक समझा गया है और इस समय इसमें किसी परिवर्तन का विचार नहीं है।

अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड को एक सांविधिक बोर्ड में बदलना

4070. **श्री एस० के० संबंधन :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड को एक सांविधिक बोर्ड बनाने के लिए विधान लाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हाँ, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). मौजूदा अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड को एक सांविधिक बोर्ड बनाने के लिए भारत सरकार ने शक्ति-चालित करघा जांच समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

त्यौहार के समय कच्चा टीवू द्वीप में श्री लंका की पुलिस

4071. **श्री शिवचंद्र झा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में (सेंट कम्पनी के) त्यौहार के अवसर पर श्रीलंका सरकार ने कच्चाटीवू द्वीप में फिर पुलिस तैनात की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस विवाद के बाद में श्री लंका सरकार के साथ पहले की गई बातचीत को ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत और श्रीलंका दोनों की सरकारों के अधिकारियों ने इस त्यौहार में इस द्वीप की यात्रा की।

(ख) पहले से ही यह प्रथा रही है।

खेल के सामान का निर्यात

4072. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत खेल के सामान का निर्यात करता है ;

(ख) यदि हां, तो किन देशों को तथा किस प्रकार के खेल के सामान का निर्यात किया जाता है ; और

(ग) उनसे प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) भारत से खेल के सामान का निर्यात 70 से भी अधिक देशों को किया जा रहा है । भारत के खेल के सामान के लिए प्रमुख विदेशी बाजार आस्ट्रेलिया, घाना, इराक, कीनिया, मलयेशिया, न्यूजीलैंड, नाईजीरिया, जम्बिया मलावी, सूडान, तन्जानिया, ब्रिटेन, सं० रा० अमरीका, पश्चिमी जर्मनी, वेस्ट इंडीज, यूगांडा तथा श्रीलंका है ।

निर्यात किए जाने वाले सामान में, फुटबाल, चमड़े की गेंदें, स्पोर्ट्स होजरी, ई० पी० एन० एस० का स्पोर्ट्स का सामान, ब्लैडर, हाकी की गेंदें, क्रिकेट की गेंदें, बेडमिंटन स्केवश रैकिट, हाकि स्टिक, जाल, मछली पकड़ने की बंसी, कैरम बोर्ड, खेल के जूते, जिमनास्टिक का सामान, क्रिकेट के बल्ले, टेबल टेनिस के बल्ले, पोलोस्टिक आदि शामिल हैं ।

(ग) गत पांच वर्षों में खेल के सामान के निर्यातों का मूल्य निम्नोक्त रहा :—

वर्ष	निर्यात मूल्य: लाख रु० में
1965	71.84
1966	81.60
1967	98.02
1968	111.49
1969	128.95

Purchase of Small Aircraft 'Islander' Manufactured by a British Firm

4073. **Shri Deven Sen** : Will the Minister of Defence be please to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to purchase a small aircraft—'Islander' manufactured by Messrs Britten—Norman Limited of U. K., which is being demonstrated in the country at present ; and

(b) the cost and the special qualities of said aircraft and the reaction of Government with a view to purchasing it ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) (a) and (b). There is at present no proposal in the Ministry of Defence to buy the 'Islander' aircraft. The other aspects raised in the Question do not arise.

Setting up of Hydro-Electric Projects in Himachal Pradesh, Assam, Nagaland and Jammu-Kashmir

4074. **Shri Deven Sen** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) wheter it is a fact that Government propose to set up soon three hydro-electric projects in Himachal Pradesh, Assam, Nagaland and Jammu-Kashmir ;

(b) if so, the investment likely to be made on each of them and the time by which they are likely to be commissioned ; and

(c) whether Government propose to set up the said type of hydro-electric projects in hilly areas of Uttar Pradesh and backward areas of Bihar ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The Government have proposed to implement the following hydo-electric projects in the Central Sector during the Fourth Plan ;

(i) Baira Siul Hydro-Electric Project—Himachal Pradesh

(ii) Loktak Hydro Electric Project —Manipur

(iii) Salal Hydro-Electric Project —Jammu and Kashmir.

(b) The Baira Siul Project (estimated cost Rs. 20.94 crores) and the Loktak Hydro-Electric Project (estimated cost Rs. 10.66 crores) are likely to be commissioned by the end of the Fourth Plan. The Salal Project (estimated cost Rs. 55.15 crores) is expected to be commissioned during the Fifth Plan period.

(c) There is no such proposal at present.

दक्षिण पूर्व एशिया सांझा बाजार की स्थापना

4075. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व एशियाई सांझा बाजार बनाने के बारे में भारत सरकार और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच कोई बातचीत हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). जी नहीं। परन्तु इकाफे क्षेत्र के सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए एशियाई आर्थिक सहयोग सम्बन्धी तीसरे मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन में सर्वसम्पति से पारित किये गये, एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के समाकलित विकास की नीति विषयक संकल्प के अनुसरण में कुछ पहल की गयी हैं।

गोयवल की डायरियों में नेताजी के सम्बंध में उल्लेख

4076. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से संबंधित अमरीका में प्रकाशित गोयवल की डायरियों के प्रथम संस्करण के फुटनोट की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या उपर्युक्त फुटनोट में नेताजी के लापता हो जाने के रहस्य पर कुछ प्रकाश पड़ता है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में साक्ष्य का पता लगाने का है जो जापान पर अधिकार करने वाली अमरीकी सेना संबंधी अभिलेखागार में उपलब्ध हो सकता है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (घ). भारत सरकार ने नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के गायब होने के सम्बन्ध में जांच आयोग नियुक्त करने का निश्चय किया है । यह आयोग निस्संदेह ऐसे सभी मामलों की जांच करेगा जो इससे सम्बद्ध हैं ।

विमान वाहक जहाज की उपयोगिता के बारे में विचार

4077, **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि विमान वाहक जहाजों की उपयोगिता के बारे में एक वरिष्ठ नौसैनिक अधिकारी के विचारों की उपेक्षा की गई थी और उसको समय से पहिले सेवानिवृत्त होने पर विवश किया गया था ;

(ख) क्या सरकार ने अब तक स्वयं उन्हीं विचारों को स्वीकार कर लिया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच का कोई आदेश दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस जांच के क्या परिणाम निकले है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) विमान वाहक जहाजों के कार्य सम्बन्धी नीति का निर्णय लेते समय, नौसेना मुख्यालय के विचारों को समुचित गुरुता प्रदान की जाती है । सरकार ऐसे किसी मामले से अवगत नहीं है जिसमें वरिष्ठ नौसेना अफसर को विमान वाहक जहाजों के कार्य पर उसके विचारों के कारण उसे स्थायी रूप से सेवानिवृत्त होने के लिए वाध्य किया गया ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

अणुशक्ति का शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए प्रयोग

4078. **श्री न० रा० देशपांडे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों के सहयोग से अणुशक्ति का शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए प्रयोग करने की सम्भावनाओं का पता लगाने का फैसला किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और सरकार का विचार किन-किन देशों के सहयोग से इस बात का पता लगाने का है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) और (ख). भारत सरकार ने अपने अणुशक्ति कार्यक्रम के आरम्भ से ही परमाणु शक्ति का उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करने हेतु अनेक बाहरी देशों से सहयोग किया है और इस संबंध में कोई नया निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है ।

एच० एफ०-24 विमान

4079. **श्रीमती शारदा मुकर्जी : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हिन्दुस्तान ऐरोनोटिक्स लिमिटेड में बनाये जाने वाले एच० एफ०-24 विमान को केवल भूमि आक्रमण के लिये निश्चित कर दिया है ;

(ख) क्या एच० एफ०-24 विमान का मैच 2 के रूप में विकसित करने का विचार त्याग दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार अपने पूर्व निर्णय पर विचार कर रही है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ). एच० एफ०-24 विमान के मेक 1 का संस्करण मुख्यतः स्थल आक्रमण कृत्य के लिए अभिकल्पित किया गया है। और अधिक सूचना देना लोकहित में नहीं होगा।

ब्रिटेन द्वारा सूती कपड़ों पर शुल्क लगाया जाना

4080. **श्री रवि राय : क्या वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वह राष्ट्रमण्डल सचिवालय के महासचिव मि० हैरल्डस्मिथ से मिले थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हैरल्डस्मिथ ने उनको स्पष्टरूप से यह बता दिया था कि ग्रेट ब्रिटेन का विचार 1972 में राष्ट्रमण्डल के देशों से आने वाले सूती कपड़ों पर 15 प्रतिशत शुल्क लगाने का है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). राष्ट्रमण्डल के महासचिव श्री रल्ड स्मिथ के साथ हुई चर्चा के दौरान विदेशी व्यापार मन्त्री ने, राष्ट्रमण्डलीय देशों से ब्रिटेन में आयात किये जाने वाले सूती वस्त्रों पर 15 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने के बारे में ब्रिटिश सरकार के वक्तव्य के विषय में, भारत में व्याप्त तीव्र भावना व्यक्त की। किन्तु श्री स्मिथ ने इस सम्बन्ध में कुछ निश्चित बात नहीं कही।

रुपयों में भुगतानों संबंधी व्यापार प्रणाली का दुरुपयोग

4081. **श्री रवि राय : क्या वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय, व्यावहारिक तथा आर्थिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त अध्ययन दल द्वारा की गई इस आशय की टिप्पणी की ओर दिलाया गया है कि रुपयों में भुगतान सम्बन्धी व्यापार प्रणाली का दुरुपयोग किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टिप्पणी से सहमत है ; और

(ग) इस दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). सरकार को राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली से एक रिपोर्ट 'भारत की निर्यात नीति' प्राप्त हुई है जिसमें 'रुपया व्यापार के योगदान' पर भी एक अध्याय सम्मिलित है। यह रुपये से होने वाले व्यापार का वास्तविक मूल्यांकन दर्शाता है और केवल रुपयों में भुगतान संबंधी व्यापार प्रणाली के दुरुपयोग का संकेत केवल व्यापार के दिशा-परिवर्तन के संदर्भ में किया गया है।

पूर्वी यूरोपीय देशों के उद्यमों द्वारा भारतीय माल के अन्य देशों को पुनः निर्यात के छुट-फुट मामलों की ही रिपोर्टें मिली हैं। जब कभी भी ऐसी रिपोर्टें सरकार के ध्यान में लाई जाती है, उपयुक्त कार्यवाही की जाती है तथा मामले पर यथावश्यक संबंधित सरकार के साथ लिखापढ़ी की जाती है।

विभिन्न राज्यों से केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने वाले अधिकारियों की संख्या

4083. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों से केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में प्रतिनियुक्ति पर आए हुए अधिकारियों की राज्यवार संख्या कितनी है ; और

(ख) आयोग में मध्य प्रदेश के कितने अधिकारी निदेशक तथा इससे उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राज्य सरकारों, राज्य बिजली बोर्डों और संघीय प्रदेशों के जो अधिकारी इस समय केंद्रीय जल तथा विद्युत आयोग में, प्रति नियुक्ति आधार पर कार्य कर रहे हैं, उनकी राज्यवार संख्या का एक विवरण संलग्न किया जाता है।

(ख) कुछ नहीं।

विवरण

प्रतिनियुक्ति के आधार पर केंद्रीय जल तथा विद्युत आयोग में इस समय राज्य सरकारों, राज्य बिजली बोर्डों और संघीय प्रदेशों के जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनकी राज्यवार संख्या का विवरण।

राज्य का नाम	अधिकारियों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	11
2. बिहार	9
3. गुजरात	5
4. हरियाणा	7

1	2
5. केरल	1
6. मध्य प्रदेश	4
7. महाराष्ट्र	2
8. मैसूर	1
9. उड़ीसा	25
10. पंजाब	3
11. रांजस्थान	8
12. तमिलनाडु	6
13. उत्तर प्रदेश	10
14. पश्चिम बंगाल	2
संघीय प्रदेश	
15. मणिपुर	1
16. पांडिचेरी	1

चम्बल नहर से सिंचित क्षेत्र

4084. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में वर्ष 1969-70 में चम्बल नहरों से कितने क्षेत्र सिंचित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) इस वर्ष वास्तव में कितने क्षेत्र में सिंचाई की गई ;

(ग) क्या यह सच है कि प्रस्तावित क्षेत्र के 50 प्रतिशत से कम क्षेत्र में ही सिंचाई हुई ; और

(घ) इस कमी के फलस्वरूप किसानों को हुई हानि का अनुमान क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). मध्य प्रदेश में 1969-70 के दौरान चम्बल परियोजना से 210000 एकड़ भूमि की सिंचाई करने का विचार है (जिसमें खरीफ की 25000 एकड़ भूमि और मैकसीकन गेहूँ की 40000 एकड़ भूमि शामिल है) । किन्तु चम्बल की नहरों को चलाने में कठिनाइयों के फलस्वरूप वास्तव में कुल 152000 एकड़ भूमि में सिंचाई की गई (जिसमें 25000 एकड़ खरीफ की भूमि और 18000 एकड़ मैकसीकन गेहूं की भूमि थी) कम सिंचाई के कारण लगभग 70 लाख रुपये की हानि होने का अनुमान है ।

नागपुर के निकट कोराडी परियोजना

4085. **श्री देवराव पाटिल :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागपुर के निकट कोराडी परियोजना जो पूर्णतः घटिया किस्म के स्थानीय कोयले पर आधारित है, चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था और केंद्रीय सरकार ने भी मंजूरी दे दी थी, उसमें दो वर्ष का विलम्ब हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और विद्युत पैदा करने के बिजलीघर कब तक चालू हो जाने की आशा है ; और

(ग) इस दो यूनिटों से राज्य की विद्युत क्षमता में कितनी वृद्धि हो जायेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) देरी के कई कारण रहे हैं नामशः स्थल में परिवर्तन, विभिन्न स्रोतों से वृहत् संयंत्र उपकरण मंगाने और उन की कीमतों को निर्धारित करने में देरी, वित्तीय संसाधनों की तंगी, इत्यादि । प्रथम उत्पादक यूनिट के अगस्त, 1973 तक और दूसरे यूनिट के फरवरी, 1974 में चालू होने की संभावना है ।

(ग) इस स्कीम के पूरा हो जाने पर राज्य की बिजली क्षमता में 240 मैगावाट की वृद्धि हो जायेगी ।

बन्दरदारा बांध का पूर्ण होना

4086. **श्री देवराव पाटिल :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र में अहमदनगर में स्थित बन्दर दारा बांध की दशा का अध्ययन कर लिया है ;

(ख) बांध को मजबूत बनाने के लिए क्या उपाय करने की सिफारिश की गई है ;

(ग) उक्त उपायों पर अनुमानतः कितना खर्च होगा और केन्द्रीय सरकार ने उसके लिए कितनी वित्तीय सहायता दी ; और

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने अमरीका के ब्यूरो आफ रिक्लेमेशन से बांध के डिजाइन तैयार करने और आधार बनाने वाले विशेषज्ञ भेजने का अनुरोध किया है और क्या उन विशेषज्ञों की भारत आने की संभावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). भंडारदारा बांध की मरम्मत करने और उसे पक्का करने की समस्याओं की जांच करने के लिए

महाराष्ट्र सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जिस में केन्द्रीय सरकार के अधिकारी भी शामिल हैं। निम्नलिखित तात्कालिक प्रतिकारात्मक उपाय पहले ही हाथ में हैं :—

1. अतिरिक्त उभड़-मार्ग और निकास क्षमता की व्यवस्था ।
2. निःस्राव को रोकने के लिए बांध की प्रतिस्रोतीय परत के निकट विशेषत: मुख्यबांध में प्रतिस्रोतीय परत पर विपत्तिग्रस्त कटिबंध में पतली भराई ।
3. तुरन्त विपत्ति से ग्रस्त कटिबंध में पतली भराई के आवरण की अनुस्रोतीय दिशा में जल निकास की व्यवस्था ।
4. बांध के प्रतिस्रोतीय भाग पर पूर्व-बलित केबल टाइज रखना ।
5. अनुस्रोतीय क्षेत्र में, जिसमें भराई के निकलने के लिए निर्बाध रास्ता है, पतली भराई करने के पश्चात् बांध के अनुस्रोतीय भाग को (बांध के ऊपर से 140 फुट नीचे के भाग में) प्रतिस्रोतीय पिंड के साथ जोड़ना। पतली भराई के बांध, पर्याप्त जल-निकास की व्यवस्था
6. 1970 के संचय-काल से पहले पूरे किये गए प्रतिकारात्मक उपायों के अनुरूप स्तर तक जलाशय का नियन्त्रण ।

यह समिति बांध के लिए निकास गेलरी और एक उपयुक्त पुश्त के निर्माण जैसे दीर्घकालीन उपायों के प्रस्तावों की जाँच कर रही है ।

(ग) जिन कार्यों को हाथ में लिया जा चुका है, उनकी अनुमानित लागत 166.74 लाख रुपये है । महाराष्ट्र सरकार का यह अनुमान है कि अन्य कार्यों के लिए लगभग 225 लाख रुपये अपेक्षित होंगे । यह सारा व्यय राज्य सरकार ने वहन करना है ।

(घ) केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मन्त्री के कहने पर अमरीकी भूमि-सुधार ब्यूरो के दो विशेषज्ञ फरवरी, 1970 में बांध का पहले ही निरीक्षण कर चुके हैं ।

तेजपुर में भारतीय वायु सेना के अधिकारी की मृत्यु

4087. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना का एक अधिकारी तेजपुर के समीप हाल ही में हुई एक दुर्घटना में मारा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) एक कोर्ट आफ इन्क्वायरी दुर्घटना की जाँच कर रही है । उसकी रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

Anti-India Propaganda by Chinese and Pakistan Embassies in India

4088. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chinese Embassy and Pakistan High Commission in Delhi are indulging in anti-India propaganda ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Sureudra Pal Singh) : (a) and (b). Whenever the Chinese Embassy and the Pakistan High Commission fail to observe the instruction issued to Diplomatic Missions in India regarding circulation of publicity material, Government draw their attention to their lapses in an appropriate manner.

वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास में चोरी

4089. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास में 3 मार्च, 1970 को चोरी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई ऐसी जांच की गई है जिससे यह पता लग सके कि कुछ गोपनीय दस्तावेज तो वहां से चोरी नहीं हुए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). जी नहीं। लेकिन मार्च 1970, की रात में, भारतीय सूचना सेवा के कार्यालय में सेंध मारी गई थी, जो मुख्य चांसरी से लगभग चार मील दूर, नेशनल प्रेस बिल्डिंग के एक कमरे में स्थित है। उस रात को कई अन्य कार्यालयों में भी सेंध मारी गई थी, जो उसी भवन में स्थित हैं । हमारे राजदूतावास ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि किसी चीज की चोरी नहीं हुई। भारतीय सूचना सेवा के अधिकांश प्रलेख अवर्गीकृत हैं और जिस कमरे में सुरक्षा अलमारियां हैं जिनमें कुछ गोपनीय कागज रखे जाते हैं उसमें अनधिकृत रूप से कोई नहीं घुसा। विदेश विभाग से यह अनुरोध किया गया है कि वह इस प्रकार की उपयुक्त कार्रवाई करे जिससे इस प्रकार की घटना फिर से न हो।

स्थानीय पुलिस जांच-पड़ताल कर रही है।

श्रीलंका में भारत मूलक व्यक्तियों द्वारा नागरिता के लिए आवेदन करने की समय सीमा बढ़ाना

4090. **श्री देविन्दर सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका वर्कर्स कांग्रेस ने भारत सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह श्रीलंका में भारत मूलक 10 लाख व्यक्तियों द्वारा नागरिता के लिए आवेदन करने की समय सीमा को आगामी 30 अप्रैल, से और आगे बढ़ावें ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) श्रीलंका वर्कर्स कांग्रेस ने श्रीलंका में भारत के कार्यकारी उच्चायुक्त को 28 फरवरी, 1970 के प्रस्ताव की प्रति भेजी है, जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त, श्रीलंका और भारत सरकारों से यह आग्रह किया गया कि वे नागरिता के लिए दिये जाने वाले आवेदन पत्रों की अन्तिम तिथि बढ़ायें।

(ख) श्रीलंका में भारत के कार्यकारी उच्चायुक्त ने श्रीलंका वर्कर्स कांग्रेस को इस बात से अवगत कराया है कि 30 अप्रैल, 1970 से आगे तिथि बढ़ाने का भारत सरकार का कोई इरादा नहीं है।

राष्ट्रमण्डल को अधिक उपयोगी बनाने के लिए सुझाव

4091. **श्री देविन्दर सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने राष्ट्रमंडल सचिवालय के महा सचिव, श्री स्मिथ को यह सुझाव दिया है कि यदि राष्ट्र मंडल को जीवित रखना है तो उसके राजनीति तथा आर्थिक कार्यक्रम अधिक उपयोगी और उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए ;

(ख) राष्ट्रमंडल के सुधार के लिए मंत्री महोदय ने अन्य क्या सुझाव दिया है ; और

(ग) उनके बारे में श्री स्मिथ की क्या प्रतिकिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री श्री (सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) श्री आर्नल्ड स्मिथ के साथ जो विचार-विमर्श हुए वे सामान्य प्रकृति के थे और इनका सम्बन्ध किसी विशिष्ट प्रायोजन से नहीं था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्वी पाकिस्तान-पश्चिम बंगाल सीमा का सीमांकन

4092. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पाकिस्तान टाइम्स में लगाये गये इस आशय के आरोप की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल पूर्वी पाकिस्तान सीमा में महा नन्द, बरंग तथा कर्राटोआ क्षेत्रों के सीमांकन में विलम्ब के लिए भारत उत्तरदायी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 10-2-1970 को पाकिस्तान टाइम्स ने सरकारी सूत्रों का हवाला देते हुए भारत के विरुद्ध पश्चिम बंगाल-पूर्व पाकिस्तान सीमा के सीमांकन के सम्बन्ध में कुछ आरोप लगाये हैं।

(ख) ये आरोप निराधार हैं। पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल के बीच सीमांकन के सम्बन्ध में 24 दिसंबर, 1969 को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या 797 के उत्तर की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Completion of Rana Pratap Sagar Dam

4093. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the construction work of Rana Pratap Sagar Dam relating to Chambal Project has since been completed ; and

(b) the total expenditure incurred thereon and the details of the benefits likely to accrue therefrom ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) The total expenditure incurred on Rana Pratap Sagar Dam upto January, 1970 was Rs. 44.29 crores. An additional area of 3 lakh acres of land in Madhya Pradesh and Rajasthan will be irrigated from the storage behind the Rana Pratap Sagar Dam. The installed capacity at Rana Pratap Sagar Dam Power Station is 172 M. W. The power generated from this station is being fed into the common grid of Madhya Pradesh and Rajasthan.

उधम पुर जम्मू तथा काश्मीर में क्षेत्रीय सेवा रियायतें समाप्त करना

4094. **श्री विक्रम चन्द महाजन** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊधम पुर (जम्मू तथा काश्मीर) में मिलने वाली क्षेत्रीय सेवा रियायतें अब समाप्त कर दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) वहां पर कितने अधिकारियों और अन्य रैंक वालों को परिवार क्वार्टर दिए गये हैं और उक्त रियायतें समाप्त कर दिये जाने के उाद वहां सैनिक कर्मचारियों के लिये कितने और स्कूल तथा कालेज खोले गए हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) (क) और (ख). फील्ड सेवा रियायतें 1-3-1968 से वापस ले ली गई थीं । रियायतें इसलिए वापस ले ली गई थीं क्योंकि पुनरीक्षण के पश्चात् सरकार इस निर्णय पर पहुँची कि उधमपुर की स्थितियां देश में अनेक स्थानों से बहुत भिन्न नहीं थीं ।

(ग) सूचना सहज प्रायः नहीं है, और इकट्ठी की जा रही है, और यथा समय सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

रूई का आयात

4095. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सूती कपड़ा उद्योग की कपास की मांग को पूरा करने के लिए पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात की जाने वाली एक लाख गांठों के अतिरिक्त 70 हजार गांठ रूई और मंगवाने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) देश में कपास की वार्षिक मांग कितनी है और उसमें से कितनी देश में उपलब्ध है ; और

(घ) 1970-71 में कपड़ा उद्योग को उसकी पूरी क्षमता के साथ चालू रखने के लिए कितनी रूई की आवश्यकता होगी ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). वस्त्र उद्योग की आवश्यकता को, जो फिलहाल उपलब्ध संभरणों से अधिक है, पूरा करने के लिए विश्वव्यापी आधार पर रूई की 50,000 अतिरिक्त गांठों के आयात की अनुमति देने का विनिश्चय किया गया है ।

(ग) देश में रूई की आवश्यकता और इसकी घरेलू प्राप्यता हर वर्ष बदलती रहती है और यह सूती माल की आन्तरिक तथा विदेशी मांग और देश में रूई की पैदावार जैसे विभिन्न संगत कारणों पर निर्भर है ।

(घ) रूई वर्ष 1970-71 में वस्त्र उद्योग में सामान्य खपत के लिए रूई की अनुमानतः 65 लाख गांठों की आवश्यकता होगी ।

भारत तथा श्रीलंका द्वारा संयुक्त चाय सार्थ संघ का बनाया जाना

4096. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दोनों देशों से चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए भारत और श्रीलंका सरकारी कम्पनी के आधार पर एक संयुक्त राज्य चाय सार्थ संघ बनाने के लिए सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) वह किस प्रकार का होगा उसके क्या कृत्य होंगे, उसके कार्यालय कहां स्थित होंगे तथा उस पर कुल कितनी पूंजी लगाई जायेगी ; और

(घ) यह कब से काम करना शुरू करेगा ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). मई/जून 1968 में नई दिल्ली में भारत और श्रीलंका के प्रतिनिधिमंडलों के बीच हुई बातचीत की अनुमोदित टिप्पणी के अनुसार चाय सम्बन्धी भारत-श्रीलंका संयुक्त सार्थ संघ के ज्ञापन और संगम के अन्तर्नियमों को अन्तिम रूप देने के लिए सम्बद्ध सरकारों द्वारा दो कार्यकारी दलों का गठन किया गया था । कार्यकारी दलों द्वारा अपना-अपना अलग प्रतिवेदन किये जाने के पश्चात् 12 नवम्बर, 1969 को कोलम्बो में उनकी संयुक्त बैठक हुई और सभी प्रमुख विषयों पर उनमें समझौता हो गया । अभी उनकी सिफारिशों पर दोनों सरकारों द्वारा विनिश्चय किया जाता है ।

(ग) कार्यकारी दलों की सिफारिश के अनुसार दो अलग-अलग राष्ट्रीय समवाय होंगे और सार्थ संघ एक संयुक्त प्रबन्ध समिति होगी जिसका नाम 'इण्डो-सीलोन टी कंसोर्टियम' होगा। इसका कार्य खुली अथवा पैकेटबन्द दोनों प्रकार की चाय का सभी रूपों में विपणन करना और व्यापारिक कारोबार करना, आवश्यक होने पर अपने राष्ट्रिकों के सहयोग से विदेशों में संमिश्रण तथा संवेष्टन एकक स्थापित करना, पैकेट बन्द चाय की बिक्री बढ़ाना और बाजार सर्वेक्षण करना होगा। दलों ने सिफारिश की है दोनों राष्ट्रीय समवायों में से प्रत्येक की प्राधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपये हो और प्रदत्त पूंजी की राशि प्रत्येक राष्ट्रीय समवाय सार्थ संघ से परामर्श करके निश्चित करेगा।

कार्यालय के स्थान के सम्बन्ध में कार्यकारी दल कोई विनिश्चय नहीं कर सके और यह मामला दोनों सरकारों पर छोड़ दिया गया है।

(घ) कार्यकारी दल की सिफारिशों का दोनों सरकारों द्वारा अनुसमर्थन कर दिये जाने के पश्चात् राष्ट्रीय समवायों तथा सार्थसंघ की स्थापना के लिए कार्यवाही की जायेगी।

अमरीका को भारतीय माल के निर्यात में कमी

4097. **श्रीमती इलापाल चौधरी :** क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका को भारतीय माल के निर्यात में सितम्बर, 1969 में उससे पिछले महीने की तुलना में 2,000,000 डालर की कमी हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अक्तूबर से दिसम्बर, 1969 तक की अवधि में भारत से अमरीका को भारतीय माल के निर्यात में कमी हुई है ;

(ग) यदि हां, तो इसमें कमी होने के क्या कारण हैं और किन वस्तुओं के निर्यात में कमी हुई ; और

(घ) स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) अगस्त, 1969 में 20.95 करोड़ रुपये मूल्य के निर्यात हुए जब कि सितम्बर, 1969 में 17.32 करोड़ रुपये के निर्यात हुए थे। इससे लगभग 3.63 करोड़ रुपये अथवा 48 लाख डालर की गिरावट दिखाई देती है।

(ख) अक्तूबर से दिसम्बर, 1969 के तीन महीनों में कुल 60.19 करोड़ रुपये के निर्यात हुए। जुलाई से सितम्बर, 1969 की अवधि में कुल 57.73 करोड़ रुपये के निर्यात हुए थे। जुलाई सितम्बर के आंकड़ों की तुलना में लगभग 2.4 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। 1968 के उन्हीं महीनों अर्थात अक्तूबर से दिसम्बर, 1960 की अवधि में 58.69 करोड़ रुपये के निर्यात हुए थे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल जनवरी, 1970 में सं० राज्य अमरीका गया था जिसने परम्परागत मदों के विषय में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए और संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात बढ़ाने के निमित्त निर्यात योग्य नये उत्पादों का पता लगाने के लिए सिफारिशें की थीं जिन पर सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। इंजीनियरी सामान, समुद्री उत्पाद आदि विशिष्ट मदों के विषय में बाजार अध्ययन किये गये हैं। चालू वर्ष में सं० रा० अमरीका में एक दो प्रदर्शनियों में भाग लेने का भी विचार है।

General Motors Company in U. S. A. Negotiating Trade with China through Indian Embassy

4098. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the General Motors Company in America has started negotiations for entering into trade with China through the Indian Embassy; and

(b) if so, the reason therefor ?

The Depury Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Import of Cotton

4099. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the year-wise details of the import of cotton during the last 2 years and during the year 1970 ;

(b) whether it is a fact that there has been a sufficient increase in the amount of foreign exchange spent for importing cotton from abroad ;

(c) whether it is also a fact that import of cotton from abroad has adversely affected the cotton production and cotton price in the country ; and

(d) if so, the details of the programme chalked out to reduce the extent of import of cotton ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) Import of cotton during the cotton years (September-August) 1967-68 and 1968-69 was 7.78 lakh bales and 4.30 lakh bales respectively. For 1969-70 an import of 6 5 lakh bales was envisaged on the expection of a normal cotton crop. Subsequently however, additional imports of 5),000 bales of cotton and 1.5 lakh bales of Staple fibre to be used as a substitute for cotton, have been arranged to meet the shortage caused by the cotton crop being less than the original estimate.

(b) Yes, Sir.

(c) No, Sir. Addition import of cotton this year had to be arranged because of downward revision of cotton crop estimate and the high ruling market prices.

(d) The broad details are as follows i—

(i) package programme covering intensified use of fertilisers, pest and disease control measures growing cotton in rice fallows etc. which have been in operation and are being intensified.

(ii) special programme has been drawn up for maximising production of long-staple cotton in areas of assured water supply by making available the required inputs.

(iii) The system of fixing ceiling prices for cotton was terminated w.e.f. 1-9-67 and minimum support prices are being fixed at which Government would be prepared to purchase cotton if offered.

Posting Hindi Officers in Embassies

4100. **Shri Ramesh Chandra Vyas :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the number of Hindi Assistants and Hindi Stenographers separately in Indian Embassies abroad country-wise ;

(b) the steps proposed to be taken by Government to post Hindi officers in those indian Embassies in the foreign countries soon where these officers have not so far been posted ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b). There are two posts of Hindi Stenographers in the Embassy of India, Kathmandu and steps will be taken to post Hindi Officers in our Missions abroad whenever and wherever necessary.

इंडोनेशिया के साथ व्यापार करार

4101. **श्री बाल्मीकी चौधरी :**

श्री देवकी नंदन पाटोदिया :

क्या वैदेशिक-व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडोनेशिया के साथ नये व्यापार के लिए बातचीत करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में इण्डोनेशिया के विदेश कार्य मंत्री से जो हाल ही में भारत आये थे, बातचीत की थी ;

(ग) वर्ष 1969-70 में दोनों देशों के बीच कितना व्यापार हुआ था ;

(घ) भारत से किन-किन वस्तुओं का निर्यात होता है ; और

(ङ) नये करार द्वारा किन वस्तुओं का निर्यात करने की बातचीत की जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क), (ख) और (ङ). भारत सरकार तथा इण्डोनेशिया गणराज्य की सरकार के बीच व्यापार करार, जिस पर 28 दिसम्बर, 1966 को जकार्ता में हस्ताक्षर हुए थे, 25 अक्तूबर 1970 तक वैध है। विदेशी व्यापार मंत्री तथा इण्डोनेशिया के विदेश मंत्री के बीच, इस महीने के प्रारम्भ में उनकी भारत

यात्रा के दौरान, हुए विचार विमर्श में दोनों मंत्रियों ने व्यापार करार को 25 अक्तूबर, 1970 से और आगे बढ़ाने की आवश्यकता स्वीकार कर ली।

(ग) और (घ). अप्रैल से नवम्बर 1969 की अवधि में भारत से इण्डोनेशिया को 2.65 करोड़ रु० मूल्य के निर्यात हुए, जबकि इण्डोनेशिया से भारत ने 13 लाख रु० मूल्य के आयात किये। इण्डोनेशिया को निर्यात होने वाली हमारी प्रमुख मदें ये थी : सूती कपड़ा, लोहे तथा इस्पात से बना सामान, परिवहन उपकरण, पटसन से बना माल, कागज, गत्ता तथा उससे बना सामान, अनिर्मित तम्बाकू मशीनें, मछली तथा मछली से बने पदार्थ आदि। भारत से इंडोनेशिया को निर्यात के लिए उपलब्ध प्रमुख वस्तुओं की तालिका वर्तमान व्यापार करार में दी गई हैं। उनमें कोई वृद्धि और/या कोई परिवर्तन करने के प्रश्न पर उचित समय पर विचार किया जायेगा।

अमरीकी सांस्कृतिक केन्द्रों को चलाने के वैकल्पिक प्रबन्ध के लिए अमरीका का अनुरोध

4102. **श्री बाल्मीकी चौधरी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 मार्च, 1970 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में "सांस्कृतिक केन्द्रों के संबंध में अमरीका की पेशकश" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि अमरीका लखनऊ, पटना हैदराबाद, बंगलौर तथा त्रिवेन्द्रम स्थित पांच सूचना केन्द्रों के चलाने के लिए वही वैकल्पिक प्रबन्ध करने जिनके अनुसार ब्रिटिश काउंसिल, भारत-जापान संघ, तथा भारत-रूस सांस्कृतिक संगठन को चलाया जा रहा है, के लिए भारत से बातचीत करने को तैयार है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने 5 मार्च के इण्डियन एक्सप्रैस में यह अखबारी खबर देखी है जिसका शीर्षक था—"सांस्कृतिक केन्द्रों के संबंध में अमरीकी प्रस्ताव"। भविष्य में लखनऊ, पटना, हैदराबाद, बंगलौर और त्रिवेन्द्रम में, पांच अमरीकी सूचना सेवा केन्द्रों को चलाने के बारे में सरकार ने अमरीकी सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया है।

(ख) इन केन्द्रों के कार्य संचालन के लिए, ऐसे प्रस्तावों पर जो इस त्रिवेन्द्रम पर सरकार की नीति के अनुकूल है, वह बातचीत करने के लिए तैयार है।

भारत तथा नेपाल के बीच व्यापार करार का नवीकरण

4103. **श्री बाल्मीकि चौधरी** : **श्री क० प्र० सिंह देव** :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार भारत के साथ व्यापार करार का नवीकरण करनें में कोई आनाकानी कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसके कारणों का पता लगा लिया है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). किसी व्यापार करार अथवा सन्धि के नवीकरण के लिए बातचीत प्रायः उसके समाप्त होने से कुछ मास पूर्व शुरू की जाती है। भारत और नेपाल के बीच व्यापार तथा परिवहन सन्धि (1960) 31 अक्तूबर, 1970 को ही समाप्त होगी और उस तारीख के पश्चात् लागू रहने वाली व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में दोनों सरकारों ने अभी बातचीत शुरू नहीं की है ।

विद्युत पैदा करने के लिए केन्द्रीय वन अनुसंधान संस्था का सुझाव

4104. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पहले केन्द्रीय वन अनुसंधान संस्था ने सुझाव दिया था कि घटिया किस्म के कोयले से खान मुहाने पर बेस लोड बिजली पैदा की जाये और बढ़िया किस्म के कोयले अथवा पन बिजली से खपत केन्द्र पर पीक लोड बिजली पैदा की जाये ;

(ख) क्या क्षेत्रीय ग्रिडों को एक राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने से उक्त सुझाव के कार्यान्वयन में सुविधा रहेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सरकार की नीति यह रही है कि घटिया किस्म के कोयले का समुपयोजन करने के लिए वृहत तापीय बिजली घर कोयला-खान के मुहानों और कोयला-वाशरी के पास स्थित हों। आमतौर पर ऐसा होता है कि विभिन्न राज्यों की वर्तमान स्थिति के अनुसार, ताप-विद्युत केन्द्रों से यह अपेक्षित होता है कि वे उच्चतम भार (पीक लोड) को पूरा करने वाले जल विद्युत केन्द्रों के साथ बेस लोड की पूर्ति करें।

(ख) और (ग). बहुत से अन्तर्राज्यीय और अन्तःक्षेत्रीय परिक्षण पथों का पहले ही निर्माण हो चुका है। अन्ततः अखिल भारतीय ग्रिड का निर्माण करने के उद्देश्य से अतिरिक्त अन्तः सम्पर्कों का निर्माण हो रहा है। इससे देश में जल तथा तापीय बिजली केन्द्रों पर उपयुक्त भार के साथ-साथ अन्तः सम्पर्क प्रणालियों के प्रचालन में सुविधा होगी।

वियतनाम में बड़े पैमाने पर हुई हत्याओं के प्रश्न को मानव अधिकार आयोग में उठाना

4105. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वियतनाम में बडे पैमाने पर हुई हत्याओं के ब्यौरे का सरकार को पता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस प्रश्न को मानव अधिकार आयोग को उठाने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने वियतनाम में, दोनों पक्षों द्वारा जन संहार किए जाने के बारे में खबरें देखी हैं।

(ख) और (ग). सरकार अभी इस प्रकार की कार्रवाई करने का विचार नहीं कर रही है क्योंकि उनका ख्याल है कि वियतनाम की वर्तमान स्थितियों में इससे कोई खास फायदा नहीं होगा ;

"रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस" द्वारा कांग्रेस (ओ०)नेताओं की आलोचना

4106. **श्री बलराज मधोक** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस मास्को अपने दलों में भारतीय दलों तथा नेताओं की निरन्तर निन्दा कर रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसने फरवरी, 1970 के अपने प्रसारण में श्री चन्द्र भानु गुप्त तथा कांग्रेस (ओ०) के अन्य नेताओं की कटु आलोचना की थी ; और

(ग) यदि हां, तो एक मित्र देश होने का दावा करने वाले रूस द्वारा हमारे आन्तरिक मामलों में किए जाने वाले ऐसे हस्तक्षेप को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). इन प्रसारणों में भारत के राजनीतिक दलों और नेताओं के प्रति कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियां भी की गई हैं जिनमें श्री सी० बी० गुप्त तथा अन्य लोग भी शामिल हैं।

(ग) "रेडियो पीस प्रोग्रेस" के प्रसारणों में भारत के राजनीतिकों और व्यक्तियों के प्रति जो आलोचनात्मक टिप्पणियां की गई हैं उनके प्रति सरकार ने उन अधिकारियों का ध्यान विगत में आकर्षित किया है। सरकार जानती है कि भारत की हाल की घटनाओं के बारे में विदेशी प्रसारणों में जो टिप्पणियां की गई हैं उनका रूप अलग-अलग इस बात पर निर्भर रहा है कि संबध लेखक का आकलन और संरचना क्या है। "रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस" के प्रसारणों की ओर सरकार सोवियत अधिकारियों का ध्यान बराबर आकर्षित करती रहेगी क्योंकि इनसे गलतफहमी पैदा हो जाने की आशंका है।

Export of Steel to U. S. S. R. and other European Countries

4107. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an agreement in respect of export of structural steel of the value of 24 crores of rupees has recently been concluded between Soviet Union and India ;

(b) if so, whether there is possibility of the export of more quantity of such type of steel to Soviet Union ;

(c) if so, the action taken by Government in this regard

(d) whether Government have examined the possibility of the export of steel to other East European countries ;

(e) if so, the details in this regard ; and

(f) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) M/s. Hindustan Steel Ltd., Calcutta have recently concluded a contract with V/O PROMSYRIOIMPORT, Moscow for the supply of 200,000 tonnes of structurals, beams, channels and Angles to USSR during 1970.

(b) and (c). For the present there is no pending demand for supply of additional quantity of steel to Soviet Union during the current year.

(d) to (f). Rolled Steel products are also being exported to other countries in the Eastern Europe. During the 9 months ending 31st December, 1969, the following exports have taken place :

Sl. No.	Country	Commodities	Quantities exported (Metric tonnnes)
1.	Yugoslavia	Rounds/Flats	4,880
2.	Bulgaria	Rounds/Flats	468
		Structurals	609

Completion of Western Kosi Canal

4108. **Shri K. M. Madhukar :**
Shri Bhogendra Jha :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Minister for River Valley Projects, Government of Bihar had recently announced that the work on the Western Kosi Canal would definitely be undertaken this year ;

(b) if so, whether all the formalities have been completed in this respect with the Government of Nepal ;

(c) if not, the reasons therefor ;

(d) whether Government propose to help the Government of Bihar in overcoming the difficulties being faced by them in this regard by holding talks with Nepal ; and

(e) if so the details in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) No, Sir.

(b) to (e). Approval of His Majesty's Government of Nepal to the alignment of the first 22 miles of the Western Kosi Canal lying in their territory is still awaited. The matter is already being pursued by the Government of India at the highest level.

Letters Received in Hindi in Prime Minister's Secretariat

4109. **Shri Ramesh Chandra Vyas** : Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) the number of letter received in Hindi in her Secretariat from January, 1969 to December, 1969 and number of those replied to in Hindi itself ;

(b) the ratio between the letters sent in Hindi and Engligh ;

(c) whether all the letters received in Hindi are replied to in Hindi itself ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Smt. Indira Gandhi) : (a) The total number of letters received in Hindi in the Prime Minister's Secretariat during the year 1969 was 59,881. Out of these 34,078 were replied to in the same language. (No replies were necessary in respect of the remaining letters).

(b) The ratio between the letters sent from the Prime Minister's Secretariat in Hindi and English during the year was 17 : 40.

(c) Yes, Sir.

(d) Does not arise.

उत्तर वियतनाम के विरुद्ध युद्ध में लाओस के पक्ष में अमरीका द्वारा सहयोग दिया जाना

4110. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि अमरीका की वायुसेना उत्तर वियतनाम की सेना के विरुद्ध लाओस सरकार की ओर से सैनिक कार्यवाहियों में भाग ले रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका लाओस के संबंध में 1962 के जेनेवा करार का उल्लंघन कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो अमरीका द्वारा जेनेवा करार का उल्लंघन किए जाने के बारे में सरकार का क्या रवैया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार को अमरीकी सरकार के इन बयानों के विषय में जानकारी है कि अमरीकी वायु सेना लाओस की कतिपय कार्रवाइयों में भाग लेती रही है ।

(ख) और (ग). 25 फरवरी को इस सदन में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में सरकार पहले ही यह बता चुकी है कि कई पक्ष पर जेनेवा कक्ष की व्यवस्थाओं का पालन नहीं कर रहे हैं । उनसे आग्रह किया गया है कि ये इस करार का पालन करें ।

राष्ट्रमंडल के नागरिकों पर ब्रिटेन आने पर प्रतिबन्ध

4111. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि ब्रिटेन ने, ब्रिटेन में बसे गये राष्ट्रमंडल के आप्रवासियों के पास जाकर रहने के इच्छुक कुछ निर्भर व्यक्तियों पर, विशेषकर बच्चों तथा वयोवृद्धों पर, कड़ा प्रतिबन्ध लगा दिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे वयोवृद्ध लोगों को ब्रिटेन नहीं जाने दिया जायेगा जिनके लड़के और लड़कियां कहीं अन्य स्थानों पर रहते हैं जिन पर वे निर्भर कर सकते हैं ; और

(ग) यदि यह बात सही है, तो क्या सरकार उन भारतीयों के हितों की रक्षा करने के लिए जो ब्रिटेन के नागरिक बन गये हैं तथा जिनके संबंधी इस समय भारत में हैं आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). माननीय सदस्य का ध्यान लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 478, दिनांक 27-7-1969 के उत्तर की ओर दिलाया जाता है ।

तारापुर परमाणुशक्ति परियोजना में लोटोनियम की उत्पादन लागत

4112. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तारापुर परमाणु शक्ति परियोजना के पुनर्परिष्करण संयंत्र जोकि निर्माणाधीन है, में लोटोनियम संयंत्र में लेटोनियम की पूंजीगत उत्पादन लागत कितनी है ;

(ख) लोटोनियम के उत्पादन के विश्व के स्तर की तुलना में यह कैसी है ; और

(ग) लोटोनियम पर आधारित अणु बम तथा तापनाभिकीय बम की उत्पादन लागत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) माननीय सदस्य सम्भवतः प्लूटोनियम के बारे में कह रहे हैं जिसका उत्पादन तारापुर में स्थापित होने वाले ईन्धन पुनर्परिष्करण संयंत्र में किया जायेगा ।

(ख) तारापुर में स्थापित किये जाने वाले इस ईन्धन पुनर्परिष्करण संयंत्र की पूंजीगत लागत की तुलना दुनिया भर में इसी प्रकार के संयंत्रों की पूंजीगत लागत से की जा सकती है ।

(ग) इस विषय में कोई अध्ययन नहीं किया गया है ।

नाभिकीय विद्युत संयंत्र की लागत

4113. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाभिकीय विद्युत संयंत्र की लागत का अनुमान लगा लिया गया है ;

(ख) नाभिकीय, तापीय, जल तथा तेल संयंत्रों से पैदा होने वाली बिजली की तुलनात्मक लागत प्रति दस लाख वाट कितनी है तथा उससे पैदा होने वाली विद्युत की प्रति यूनिट लागत पृथक-पृथक कितनी है ;

(ग) फासिल चालित संयंत्र उक्त संयंत्रों की तुलना में कैसे हैं ?

(घ) क्या फासिल चालित संयंत्रों के भारत में बनने की सम्भावना है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). तारापुर परमाणु बिजली घर, 200 मैगावाट रेंज के एक कैन्डू (CANDU) प्रकार के नाभिकीय विद्युत संयंत्र, बड़ी मात्रा में भारतीय साज-सामान से तैयार उसी आकार के एक विशेष प्रकार के ताप बिजली घर तथा जल विद्युत संयंत्रों की अनुमानित लागत का तुलनात्मक ब्यौरा निम्न प्रकार है :

विद्युत संयंत्र	प्रति 10 लाख वाट की दर से लाख रुपयों में पूंजीगत लागत	प्रति किलोवाट की दर से पैसों में उत्पादन लागत
तारापुर परमाणु बिजली घर	18 50	5.61***
कैंडू (CANDU) प्रकार का नाभिकीय	30.50	लगभग 5.60
विद्युत संयंत्र विशिष्ट प्रकार का तापीय विद्युत संयंत्र जल संयंत्र	20.00	लगभग 6.6*
जल विद्युत संयंत्र	10.00 से 15.00 तक	3 से 4 तक**

*इसकी गणना कोयले की 60 रुपये प्रति टन की लागत के आधार पर की गई है जो उस कोयले पर लागू होती है जोकि कोयला खानों से 600 से 100 किलोमीटर की दूरी तक उपलब्ध है ।

**जल विद्युत संयंत्र का उपयोग सामान्यतः चरमोत्पादन करने के लिये लाभकर रहता है । यदि उनकी चालू क्षमता जोकि निर्धारित क्षमता से कहीं कम होती है, का भी हिसाब लगाया जाये तो लागत काफी अधिक हो जायेगी ।

***75 प्रतिशत वार्षिक संयंत्र फैक्टर की दर से औसत बिक्री मूल्य ।

(घ) जी हां ।

(ङ) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक संयंत्रों का निर्माण किया जायेगा ।

दिल्ली में सेना मुख्यालय के आयुध विदेशालय में निर्धारित सेवावधि के बाद तक कार्य करने वाले कर्मचारी

4114. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली में सेना मुख्यालय के आयुध विदेशालय में आवधिक सेवाओं के लिपिक संवर्ग के अनेक कर्मचारी अपनी अवधि के बाद भी वहां पर कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या ऐसे कुछ कर्मचारियों को, जोकि दिल्ली/नई दिल्ली में किसी प्रकार 10 वर्ष से अधिक समय तक कार्य करते रहे, थोड़ी अवधि के लिए दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित कर दिया गया था, और उन्हें अब पुनः दिल्ली/नई दिल्ली में वापस नियुक्त किया गया है अथवा किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) आयुध डिपुओं तथा आयुध कारखानों जैसे अधीनस्थ कार्यालयों में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो पांच वर्ष से भी अधिक समय से दिल्ली/नई दिल्ली से बाहर कार्य कर रहे हैं तथा जिन्होंने दिल्ली/नई दिल्ली में नियुक्ति किये जाने के लिये अभ्यावेदन दिया है ; और

(ङ) उपरोक्त (घ) भाग में वर्णित कर्मचारियों के न्यायांगत दावों की अवहेलना करके उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) में वर्णित कर्मचारियों को लगातार ये लाभ देने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) ए०ओ०सी० के दो अपर डिवीजन क्लर्कों और 3 असैनिक स्टोर-कीपरों को जो अब नई दिल्ली के आर्डनेंस निदेशालय में काम कर रहे हैं चार वर्षों की साधारण टेन्योर के पश्चात् सेवा मुख्यालयों में रखा हुआ है । इनमें से चार व्यक्तियों को एक वर्ष के लिए सेवावधि में वृद्धि दी गई है जिसके लिए अनुमति देय है । एक असैनिक स्टोरकीपर की तब्दीली के आदेश साधारण प्रक्रिया अनुसार जारी किये गये हैं ।

सेवा मुख्यालयों में आर्डनेंस सेवा निदेशालय में सेंट्रल प्रोवीजन कक्ष के बारे में एक कक्ष है, जो एक आर्डनेंस यूनिट के रूप में काम कर रहा है और मुख्यतः उसमें आर्डनेंस सेविनर्स काम करते हैं । 41 असैनिक सेविनर्ज उप-कक्ष में 10 वर्षों से अधिक सेवा कर रहे हैं । इस कक्ष में काम कर रहे कर्मचारीगण के सम्बन्ध टेन्योर 6 वर्ष है इस टेन्योर में संशोधन का प्रश्न निरीक्षण आधीन है ।

(ख) से (ङ). आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

विद्युत चालित करघा उद्योग को वित्तीय सहायता

4115. **श्री अदिचन** : क्या **वैदेशिक व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत चालित करघा उद्योग को वित्तीय सहायता देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) वर्ष 1970-71 के दौरान केरल में विद्युत चालित करघा उद्योग के लिए कितनी सहायता दी जायेगी और वर्ष 1968-69 और 1969-70 में इस उद्योग के लिए इस प्रकार की कितनी सहायता दी गई थी ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) सरकार द्वारा निम्नोक्त कदम उठाये गये हैं :

1. शक्तिचालित करघे लघु क्षेत्र में शामिल हैं और उन्हें, उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम के अन्तर्गत और राज्य वित्त निगमों, स्टेट बैंक तथा वाणिज्यिक बैंकों अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित किये जाने वाले किसी भी वित्तीय संस्थान से, सहायता लेने के लिए पात्र बना दिया है ।
2. भारतीय रिजर्व बैंक को इस बात के लिए राजी कर लिया गया है कि वह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17(2) (बी० बी०) के अन्तर्गत शक्ति-चालित करघों की सहकारी समिति को भी ऋण दे ।

(ख) वर्ष 1968-69 में केरल सरकार को कोई सहायता नहीं दी गई । जहां तक वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 का सम्बन्ध है, चतुर्थ योजना में राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को जो केन्द्रीय सहायता दी जा रही है, वह समेकित ऋणों तथा अनुदानों के रूप में हैं तथा किसी योजना अथवा प्रायोजना से सम्बन्धित नहीं है ।

सैनिक स्कूलों से प्रति वर्ष उत्तीर्ण होने वाले लड़के

4116. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक स्कूलों से प्रति वर्ष कुल कितने लड़के उत्तीर्ण होकर निकलते हैं और उनमें से कितने राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी और भारतीय सैनिक अकादती में दाख़िला लेते हैं ; और

(ख) इस भारी अपव्यय के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) गत 5 वर्षों में सैनिक स्कूलों से उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या इस प्रकार है :

1965	176
1966	223
1967	254
1968	340
1969	490

गत वर्ष में एन०डी०ए० में प्रविष्ट होने वाले लड़कों की संख्या इस प्रकार है :

1965	99
1966	130
1967	171
1968	237
1969	90

1969 के आंकड़े जुलाई 1969 की परीक्षा से सम्बन्धित हैं। दिसम्बर, 1969 की परीक्षा के परिणाम अभी ज्ञात नहीं हैं। आई०एम०ए० में प्रविष्ट होने वाले सैनिक स्कूलों के लड़कों की संख्या सम्बन्धी सूचना इकट्ठी की जा रही है।

(ख) एन०डी०ए० में प्रवेश न पाने वाले सफल लड़कों को भी, जीवन के अन्य क्षेत्रों में वृतिकाओं का अनुसरण करने के लिए व्यापक शिक्षा से सुसज्जित किया जाता है।

अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को नियमित अधिकारियों के रूप में रखने के लिए अनुपयुक्त पाया जाना

4117. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में अल्प सेवा कमीशन प्राप्त कुल कितने अधिकारियों को नियमित अधिकारियों के रूप में रखने के लिए अनुपयुक्त पाया गया ; और

(ख) भर्ती किए गए अधिकारियों की संख्या से उनका क्या अनुपात था ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सेवा के 175 अल्पकालीन कमीशन प्राप्त अफसर और नौसेना के 2 अल्पकालीन कमीशन प्राप्त अफसर गत तीन वर्षों में स्थाई कमीशन के लिए अनुपयुक्त पाये गये थे।

(ख) सेना के लगभग 29 प्रतिशत अल्पकालीन कमीशन प्राप्त अफसर और नौसेना के 6 प्रतिशत अल्पकालीन कमीशन प्राप्त अफसर स्थाई कमीशन के लिए विचारे गए थे और अनुपयुक्त पाए गए थे।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा भारतीय सेना अकादमी के माध्यम से प्रतिवर्ष अफसरों का लिया जाना

4118. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा भारतीय सेना अकादमी के माध्यम से सशस्त्र सेना के तीनों अंगों के नियमित संवर्ग में इस समय प्रतिवर्ष कितने अफसर लिये जाते हैं तथा कितने नहीं लिये जाते हैं ;

(ख) अल्पकालिक सेवा कमीशन के माध्यम से प्रति वर्ष कितने अफसर भर्ती किये जाते हैं ;

(ग) क्या उनकी योग्यता धीरे-धीरे कम हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो यदि योग्यता तथा संख्या में सुधार करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है तो क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सेना, नौ-सेना और वायु-सेना के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के माध्यम से अफसरों की वार्षिक आयोजित प्रविष्टि क्रमश: 300, 65 और 110 है। भारतीय सैनिक अकादमी के माध्यम से, कि जो केवल सेना के लिए है, प्रविष्टि, 300 भूतपूर्व राष्ट्रीय रक्षा अकादमी छात्रों सहित 900 वार्षिक दर से आयोजित है। इस प्रविष्टि से वार्षिक क्षति लगभग 3 प्रतिशत है।

(ख) सेना में अल्पकालीन कमीशनों के लिए भर्ती का लक्ष्य 1350 वार्षिक है, और नौ-सेना में 300 वार्षिक। वायु-सेना में कोई अल्पकालीन कमीशन नहीं होती, सिवाए तकनीकी और मौस विज्ञान शाखाओं में प्रोबेशन पर अफसरों के।

(ग) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैनिक अकादमी के प्रशिक्षित अफसरों की कोटि में किसी प्रकार की कमी का कोई इंगित नहीं है।

(घ) सैनिक स्कूलों, राष्ट्रीय भारतीय सैनिक कालिज, राष्ट्रीय छात्रदल और समाचार-पत्रों तथा रेडियो के माध्यम से प्रचार अफसरों की भर्ती में सुधार लाने में सहाई होते हैं। कमीशन से पूर्व और बाद की, विभिन्न संस्थानों में प्रशिक्षण अफसरों की कोटि में सुधार करते हैं।

नई दिल्ली नांगल राया गांव की भूमि पर प्रतिरक्षा मन्त्रालय को अवैध कब्जा

4119. **श्री हुकम चन्द कछवाय**: क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में नांगल राया गांव की 18.39 एकड़ भूमि पर 1946 से प्रतिरक्षा मन्त्रालय ने गैर-कानूनी रूप में कब्जा कर रखा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस भूमि के उपयोग के लिये पिछले 25 वर्षों से न तो किराया ही दिया गया है और न ही कोई करार किया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उनके मन्त्रालय ने पिछले वर्ष जमीन के मालिकों को किराये के रूप में मुआवजा देने की पेशकश की थी जिसे लेने से उन्होंने इन्कार कर दिया था ; यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ;

(घ) सरकार का विचार इस मामले को कब तक निपटाने और भूमि के मालिकों को बकाया किराये की सन्तोषजनक राशि देने का है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस भूमि को खरीदने और भूमि के मालिकों को बाजार मूल्य देने का है ; यदि हाँ, तो कब तक और किस मूल्य पर और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). सम्भवत: संदर्भ 18.39 एकड़ भूमि के विषय में है जिसका अधिग्रहण और कब्जा 1943 में किया गया था तथा जिसके अधिग्रहण मोचन के सम्बन्ध में अधिसूचना 1946 में जारी की गई थी। यदि ऐसा है तो क्षेत्र का कब्जा स्वामियों को अभी तक नहीं दिया गया है और कब्जा रक्षा अग्नि-अनुसंधान संस्थान के हाथ में है। वर्तमान कब्जेदार की वैध स्थिति के सम्बन्ध में

विधि निर्वाचन निहित है । अधिग्रहण मोचन आदेश के सम्बन्ध में यह और अन्य पक्ष जांचे जा रहे हैं ।

(ग) और (घ). 1946 के आगे से स्वामियों को प्रति वर्ष 883 रुपये की दर से प्रति कर देना प्रस्तावित किया गया है, किन्तु उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह इस राशि को समुचित नहीं समझते हैं । मामले की आगे जांच की जा रही है ।

(ङ) रक्षा अग्नि-अनुसंधान संस्थान स्थापना के लिए उचित स्थान की तलाश कर रहे हैं । भूमि के क्रय करने या उसे खाली करने का निर्णय स्थान के अन्तिम चुनाव पर निर्भर करेगा ।

यूनिट कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट (इण्डिया) से अर्जित लाभ का सभाओं के कल्याण के लिए उपयोग

4120. **श्री सूरजभान** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनिट कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट (इंडिया) द्वारा अर्जित मुनाफा सेनाओं के कल्याण पर खर्च करना होता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 18 पंजाब रेजिमेन्ट के कमांडिंग अफसर के यूनिट कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट के लाभ में से 600 रुपये आफिसर्स मैस को 1964 में हुई पार्टियों के भुगतान के लिए दे दिये थे ;

(ग) यदि हां, तो इस अनियमितता के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस अनियमितता पर कोई गौर किया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) यूनिटों द्वारा चलाई गई कैन्टीनों द्वारा अर्जित लाभों का यूनिट कल्याण निधि, अफसरी मैस निधि और अन्य ऐसी निधियों के लिए विभाजन यूनिट के कमान अफसर की समझ बूझ पर निर्भर है ।

(ख) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

18 पंजाब रेजीमेंट के दैनिक रूटीन आर्डर में 'रम' देने संबंधी समाचार को प्रकाशित न करना

4121. **श्री सूरजभान** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़े कमांडरों के रम देने के आदेश को जवानों के सूचनार्थ हमेशा यूनिट के दैनिक रूटीन आर्डर में प्रकाशित किया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मई, 1964 से लेकर अक्टूबर, 1967 तक 18 पंजाब रेजीमेंट में ऐसा नहीं किया गया ;

(ग) इसे दैनिक रूटीन आर्डर में प्रकाशित न करने के क्या कारण तथा इसे किस रीति से प्रकाशित किया गया है ; और

(घ) इसके लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ). जी हां ; संक्रियात्मक क्षेत्र में स्थित यूनिटों को छोड़ कर। सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

जापान में आयोजित होने वाली "एक्स्पो-70" प्रदर्शनी में भाग लेना

4122. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत जापान में ओसाका में होने वाले 'एक्स्पो-70,' मेले में भाग ले रहा है ;

(ख) हमारे मंडप में हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने व्यक्ति भारत से गये हैं ; और

(ग) हमारे मंडप की विभिन्न आकर्षक वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) 65।

(ग) भारतीय मण्डप का लक्ष्य भारतवर्ष की सांस्कृतिक परम्पराओं, कलाओं, प्रथाओं की पृष्ठभूमि के संदर्भ में विकासोन्मुख भारत के स्वरूप को दर्शाना है। मंडप में प्रस्तुत की गयी कुछ दिलचस्प मदों में हस्तशिल्प तथा वस्त्रों के उत्कृष्ट नमूने, कीमती तथा दुर्लभ रत्ना भूषण, बौद्धमत से सम्बन्धित मूल कला कृतियां, आधुनिक चित्रकला तथा मूर्तिकला तथा ताजमहल का 15 फुट ऊंचा प्रतिरूप शामिल है। औद्योगिक अनुभाग में आणविक ऊर्जा, इस्पात, मशीनी औजार, खनिज तथा धातु, जैट प्रशिक्षक विमान इत्यादि के विकास के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की चुनी हुई आधुनिक तथा जटिल मशीनें और उत्पाद प्रस्तुत किये गये हैं। मंडप के अन्य महत्वपूर्ण आकर्षणों में एक राष्ट्रीय जलपान गृह भारतीय नृत्य तथा संगीत प्रस्तुत करने वाला एक प्रेक्षागृह, और एक सफेद चीता है। मडप के मुख्य धवल भवन के सामने एक भारतीय गांव का दृश्य, झरना और एक तलाब का सुरूचिपूर्ण चित्रांकन है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकीय भाषा के रूप में हिंदी

4123. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसार में क्रमश: कितने व्यक्ति (1) अंग्रेजी, (2) रूसी, (3) स्पेनिश, (4) चीनी, (5) अरबी तथा (6) हिन्दी बोलते हैं ;

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकीय भाषाएं क्या-क्या हैं ;

(ग) क्या भारत सरकार ने कहा है कि हिन्दी को संयुक्य राष्ट्र संघ की एक राजकीय भाषा के रूप में माना जाए, क्योंकि चीनी तथा अंग्रेजी के बाद यह संसार में सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) 'हिन्दुस्तान ईयर बुक' के अनुसार सूचना इस प्रकार है :

(1) इंगलिश 29 करोड़ 40 लाख, (2) रूसी 17 करोड़, (3) स्पेनी 15 करोड़ 90 लाख, (4) चीनी 64 करोड़ 50 लाख। (5) अरबी 8 करोड़ 30 लाख और हिन्दी 16 करोड़ 50 लाख (ये आंकड़े अनुमानित हैं)।

(ख) चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, स्पेनी और इसी सयुक्त राष्ट्र महासभा की कामकाज की भाषाएं हैं।

(ग) और (घ). जी नहीं। संयुक्त राष्ट्र के कामकाज की भाषाओं में किसी नई भाषा को शामिल करवाना बहुत मुश्किल है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के कामकाज की भाषाओं की सूची में कोई नई भाषा शामिल करने के लिए प्रक्रिया नियमों में सशोधन करना होगा जिस पर उपस्थित और मतदाता सदस्यों का बहुमत होना आवश्यक है। इस बात की सम्भावना नहीं दीख पड़ती कि वर्तमान स्थिति में इस बारे में किसी परिवर्तन के प्रस्ताव को बहुमत का समर्थन मिल सकेगा।

पूर्वी क्षेत्रों में संयंत्रों तथा मशीनों के लिये घटिया किस्म के ईंधन का इस्तेमाल

4124. **श्री इंद्रजीत गुप्त :**
डा० रानेन सेन :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयन्त्रों तथा मशीनों पर घटिया किस्म के ईंधन के प्रभाव पर विचार किये बिना ही पूर्वी क्षेत्र में तापीय बिजली के उत्पादन के लिए अधिक राख की मात्रा वाला घटिया किस्म का कोयला तथा कोयला धोने के कारखानों से घटिया कोयला तथा बेकार कोयला इस्तेमाल करने की सरकार की नीति मुख्यत: लोहे तथा इस्पात उद्योगों के हितों को देखते हुए अपनाई गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो किन प्रमुख कारणों से पूर्व क्षेत्र के उपरोक्त असंतोषजनक तथा अलाभ-प्रद स्थिति को स्वीकार करने को बाध्य किया गया है जिससे संयन्त्रों तथा मशीनों के खराब हो जाने के कारण बिजली की बहुत अधिक कमी हो जाती है ; और

(ग) उपरोक्त स्थिति को शीघ्र दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). बढ़िया दर्जे के उस कोयले के संरक्षण के लिये, जो धातुकर्मीय उद्देश्यों के लिए अनिवार्यतः अपेक्षित होता है, और इस्पात के कारखानों में प्रयोग के लिये मध्यम दर्जे के धातुकर्मीय कोयले को धोने के पश्चात् बच गए उपोत्पाद पदार्थों के समुपयोजन को बढ़ावा देने के लिये, सरकार की यह नीति है कि इस समय जिन तापीय विद्युत केन्द्रों का अभिकल्पन किया जा रहा हैं, वे घटिया दर्जे के कोयलों और वाशरियों में बच गए उपोत्पाद पदार्थों को प्रयोग में ला सकें। यह नीति देश के सभी क्षेत्रों पर लागू होती है। क्योंकि वायलरों के अभिकल्प घटिया दर्जे के कोयलों और वाशरियों में बच गए उपोत्पाद पदार्थों को जलाने के बनाए गए हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि तापीय विद्युत केन्द्रों में खराबियां घटिया दर्जे के ईंधन के प्रयोग से आ गई हैं।

(ग) तापीय उत्पादन यूनिटों की दक्षता को सुधारने के विचार से, सरकार वर्तमान और भावी वाशरियों के उपोत्पाद ईंधनों के गुणों को बढ़ाने के पगों पर विचार कर रही है।

गुजरात के मुख्य मंत्री द्वारा प्रधान मन्त्री को दिया गया ज्ञापन

4125. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जब वह हाल ही में 23 जनवरी, 1970 को गुजरात गई थीं तो उन्हें वहाँ के मुख्य मन्त्री ने एक ज्ञापन दिया था जिसमें उस राज्य की विकास योजनाओं के सम्बन्ध में गुजरात द्वारा सहे गये अन्यायों का उल्लेख किया गया था ; और

(ख) क्या वह उपरोक्त ज्ञापन की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगी और इसका कारण बतायेंगी कि प्रत्येक मामले में ऐसे विकास का अवरोध क्यों किया गया अथवा उसकी मंजूरी क्यों नहीं दी गई विशेषतः जबकि गुजरात में योजनाएं शीघ्रता तथा कुशलता से निस्पादित की जाती है ?

प्रधान मन्त्री वित्त मन्त्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). प्रधान मन्त्री की 22/23 जनवरी, 1970 की गुजरात यात्रा में उन्हें एक पत्र प्राप्त हुआ। इसके साथ कई नोट भी थे, जिसमें गुजरात की समस्याओं का वर्णन था। तत्काल यह नोट सम्बद्ध मंत्रालयों के पास जांच के लिए इस आदेश के साथ भेज दिए गए कि वे अपने निर्णयों की सूचना गुजरात को यथासमय भेज दें। केन्द्र और राज्य सरकार के बीच पत्रव्यवहाराधीन विषय के सम्बन्ध में पत्रोत्तर सदन-पटल पर रखना उचित नहीं होगा।

अतारांकित प्रश्न संख्या 3475 दिनांक, 10 दिसम्बर, 1969 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

Correcting Statement to Unstarred Question No. 3475 dated 10-12-69

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : अध्यक्ष महोदय, 10 दिसम्बर 1969 को उत्तर दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3475 के भाग (ख) के उत्तर में कहा गया था, कि ब्रिटेन, यू०एस०ए०, यू०एस०एस०आर०, फ्रांस, जापान, ईरान, थाईलैंड,

ईथोपिया और आस्ट्रेलिया के 27 विदेशी युद्धपोतों ने 1969 के दौरान भारतीय बन्दरगाहों का भ्रमण किया था।

बाद में पता चला कि भारत का भ्रमण करने वाले विदेशी युद्धपोतों की संख्या 29 (उनत्तीस) थी, न कि जैसे प्रश्न के उत्तर में कहा गया है, 27 (सत्ताईस)। तदनुसार, प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर इस प्रकार पढ़ा जाये :

"अब तक 1969 के दौरान, ब्रिटेन, यू०एस०ए०, यू०एस०एस०आर०, फ्रांस, जापान, ईरान, थाईलैंड, ईथोपिया, और आस्ट्रेलिया के 29 विदेशी युद्धपोतों ने भारतीय बन्दरगाहों का भ्रमण किया है।"

भूकम्प-पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति
SYMPATHY FOR EARTHQUAKE VICTIMS

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मैं यह सुझाव देता हूँ कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेने से पहले हमें क्षण भर के लिए मौन खड़ा होना चाहिए और भूकम्प में मरे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए।

श्री राम सुभग सिंह (बक्सर) : मैंने इसी आशय का एक प्रस्ताव दिया है। भूकम्प-पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : डा० राम सुभग सिंह और श्री हेम बरुआ के सुझावों के अनुसरण में मैं सभा की ओर से भूकम्प में मरने वालों के प्रति शोक प्रकट करता हूं और भूकम्प-पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूँ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE
गुजरात में अंकलेश्वर तेल-क्षेत्र के निकट भूकम्प

श्री मनु भाई पटेल (डभोई) : मैं पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ और प्रार्थना करता हूं कि वह उस पर एक वक्तव्य दें :

"गुजरात में अंकलेश्वर तेल-क्षेत्र के निकट भूकम्प के तेज झटके" जिनके परिणाम-स्वरूप बहुत से व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा मकानों को भारी क्षति पहुंची।"

श्री नाथ पाई (राजपुर) : इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में या तो प्रधान मंत्री या गृह मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए।

श्री न० कु० सोंधी : मैंने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना गृह मंत्री के नाम दी थी।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : भविष्य में यह ध्यान रखा जाये कि ऐसे प्रस्तावों का उत्तर वही मंत्रालय दे, जिसका कि वह विषय है।

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : गुजरात की राज्य सरकार ने पूछे जाने पर सूचना दी है कि ब्रोच जिले में भूकम्प 23 मार्च, 1970 को प्रातः 7.25 बजे दो भारी प्रकम्पनों के साथ प्रारम्भ हुआ था। उसके पश्चात् 7.30 बजे प्रातः एक हल्का प्रकम्पन हुआ और दोपहर के 12 बजे एक और हल्का प्रकम्पन भी हुआ। यह प्रकम्पन ब्रोच जिले के बहुत बड़े क्षेत्र में, जिसमें ब्रोच, आंकलेश्वर, हंसोट, वागरा, आमोद, जम्बूसार, राजपिपला और झगातिया तालुके शामिल हैं, अनुभव किये गये। हानि अधिकतर ब्रोच नगर और इसके आस-पास के क्षेत्रों तक ही सीमीति रही है। दुर्घटना ग्रस्तों की गणना में 23 लोगों का हताहत होना और 200 जख्मी, जिन में 84 हस्पताल में हैं, सम्मिलित है। ब्रोच नगर में लगभग 200 घर नष्ट हुए हैं तथा 2500 घर क्षतिग्रस्त हैं। जिले के दूसरे हिस्सों से अन्य 2000 घरों के क्षतीग्रस्त होने की सूचना मिली है।

2. भूकम्प के झटके बड़ौदा के कुछ क्षेत्रों में, भावनगर, सूरत तथा बम्बई में भी अनुभव किये गये। इन क्षेत्रों में हानि बहुत कम हुई बताई जाती है।

3. ऋतु.विज्ञान विभाग ने बताया है कि झटके सभी भारतीय भूकम्पीय वेधशालाओं में अकित हुए हैं। उस विभाग द्वारा प्राप्त की गई सूचना के प्रारम्भिक परीक्षणों से पता चला है कि भूकम्प में निम्नलिखित प्राचल (पैरामीटर) थे :

अधिकेन्द्र (एपीसेन्टर)	अक्षांश 21.6° उत्तर आंकलेश्वर के पास
	देशान्तर रेखांश 72.6° पूर्व
मूल समय	01—53—00 ग्री० मे० स०
	07—23—00 भा० सा० स०
गहराई	ऊपरी
विस्तार	6.0 रिकटर स्केल पर

4. भूकम्प का विस्तार अध्ययन ऋतु विज्ञान विभाग द्वारा सभी भारतीय तथा विदेशीय वेधशालाओं से पूरे आंकड़े तथा विस्तृत सूचना प्राप्त होने पर किया जायेगा।

5. ब्रोच नगर वहां स्थित है जहां विभंग पश्चिमी समुद्र तट नर्मदा निभंग के साथ मिलता है। नर्मदा नदी के तट पर कई स्थानों पर भूकम्प भूतकाल में भी अर्थात् 27 मार्च, 1847, 18 नवम्बर, 1865, 2 जनवरी, 1927, 14 मार्च 1938 को अंकित किये जा चुके हैं। इस क्षेत्र में कच्छ की खाड़ी और पश्चिमी समुद्र तट के आस-पास आये हुए भूकम्प भी अनुभव किये गये हैं। पिछली बार का भूकम्प, जिसने अंजड़ (गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र) में भारी क्षति की थी, 21 जुलाई, 1956 को आया था।

6. राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक, आवास तथा खाद्य सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है।

7. अहमदाबाद स्थित भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण सस्था के अधिकारियों को शीघ्र ब्रोच पहुंचकर इस दैविक प्रकोप का विस्तारपूर्ण विवरण भेजने के लिए कहा गया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बताया गया है कि प्रधान मंत्री दूसरी सभा में है और वह इस विषय पर दोपहर बाद इस सभा में वक्तव्य देंगी।

श्री मनु भाई पटेल : यह दैवी विपत्ति है। इसका प्रभाव पूरे राष्ट्र पर पड़ता है। इस प्रकार के संकट के बाद सरकार को उसके बारे में स्वयं ही वक्तव्य देना चाहिए था। किन्तु इस विषय पर ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव की सूचना के पश्चात् सरकार वक्तव्य देने को तैयार हुई है। दूसरे सम्बद्ध मंत्री को उत्तर देना चाहिए। क्या यह सच नहीं है कि इस भूकम्प के प्रति केन्द्रीय सरकार का उपेक्षापूर्ण रवैया रहा है? मंत्री महोदय ने यह बताया है कि इसके बारे में मौसम विभाग जांच करेगा और उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर इसका पूर्ण अध्ययन किया जायेगा। क्या सरकार इसके अध्ययन के लिए सम्पूर्ण विश्व से विशेषज्ञ बुलायेगी जैसाकि कोयना भूकम्प के बारे में किया गया था। क्या उक्त भूकम्प की जांच किन्हीं अच्छे विशेषज्ञों द्वारा कराई जायेगी? जब इतनी बड़ी दैवी आपत्ति राष्ट्र पर आती है और देश का एक बड़ा भाग भूचाल से प्रभावित होता है तो भूकंप-पीड़ित लोगों की राहत के काम की जिम्मेदारी न केवल राज्य सरकार तक ही सीमित रहती है बल्कि केन्द्रीय सरकार भी इसके लिए उत्तरदायी होती है। क्या सरकार राहत के लिए विशेष रूप से सहायता देगी? यह न केवल 1500 घरों के नष्ट हो जाने का प्रश्न है, बल्कि यह 30,000 लोगों का प्रश्न है, जो इस समय बेघर हो गये हैं। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि राहत-सहायता देते समय राजनीतिक विचारधारा को आधार न बनाया जाये। संक्षेप में, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उच्च शक्ति-प्राप्त दल इस मामले की जांच करेगा और क्या प्रधान मंत्री या अन्य सम्बद्ध मंत्री इस बात का ध्यान रखेंगी कि पर्याप्त सहायता देते समय राजनीति को आधार न बनाया जाये?

श्री दा० रा० चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना ठीक नहीं है कि सरकार का रवैया उक्त भूकम्प के प्रति उपेक्षापूर्ण रहा है। जैसे ही प्रधान मंत्री को इसका संदेश मिला वैसे ही उन्होंने शोक संदेश भेजा और भूकम्प-पीड़ितों को राहत के लिए 51,000 रु० की राशि भेजी। जहां तक राहत-कार्य से राजनीति को दूर रखने का सम्बन्ध है, मैं आश्वासन देता हूं कि इस मामले से राजनीति निश्चय ही दूर रहेगी। यहाँ तो माननीय जीवन की रक्षा का प्रश्न है, यहां राजनीति को पास नहीं आने दिया जायेगा। भूकम्प-पीड़ित लोगों के लिए जो भी सहायता अपेक्षित होगी, वह केन्द्रीय सरकार द्वारा शीघ्र ही दी जायेगी। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि तेल निकालने के कार्य से भूकम्प आने का कोई सम्बन्ध नहीं है। अंकलेश्वर में भूकम्प 1927 में भी आया था जबकि वहां तेल का एक भी कुआं नहीं खोदा गया था। इस भूकम्प का मौसम विभाग तथा भू-सर्वेक्षण विभाग दोनों द्वारा घटना स्थल पर ही अध्ययन किया जा रहा है। उनकी जांच की रिपोर्ट के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। जाँच रिपोर्ट के अध्ययन के बाद यदि आवश्यक समझा गया तो उच्च-शक्ति-प्राप्त समिति की नियुक्ति पर विचार किया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : क्या इस बात के सम्बन्ध में कोई जांच की जा

रही है कि यह भूकम्प उस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल के लिए किये गये ड्रिल्लण-कार्य के कारण तो नहीं आया ?

श्री दा० रा० चव्हाण : भारतीय भू-सर्वेक्षण के अधिकारियों को तुरन्त भड़ौच जाकर अध्ययन करने और रिपोर्ट देने को कह दिया गया है।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : यह बात महत्वपूर्ण है कि भूकम्प किस मंत्रालय का विषय है।

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री कु० ल० राव) : भूकम्प के लिए पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री जिम्मेदार हैं क्योंकि मौसम विभाग उनके मंत्रालय के अन्तर्गत है।

श्री लोबो प्रभु : किन्तु भूकम्प वायुमंडल में तो नहीं आते, पृथ्वी पर आते हैं। जांच कराने से पूर्व हमें यह निश्चय कर लेना चाहिए कि यह विषय किस मंत्रालय के अन्तर्गत ठीक रहेगा। क्या सरकार सभा में यह आश्वासन देगी कि जिन लोगों के मकान आदि नष्ट हो गये हैं, उन्हें हुई हानि को सरकार पूरा करेगी। दूसरी बात यह है कि जापान की भाँति क्या भारत में भी उन स्थानों पर,जहां भूकम्प अधिक आते हैं, विशेष प्रकार के मकान बनाने के संबंध में अध्ययन किया जायेगा ?

श्री दा० रा० चव्हाण : भूकम्प से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिये आवश्यक सहायता दी जायेगी। 'अपेक्षित सहायता' से तात्पर्य उस सहायता से जिसकी राज्य सरकार ने मांग की है। किन्तु मुआवजे का इस मामले में प्रश्न नहीं उठता।

श्री नाथ पाई : श्री लोबो प्रभु का सुझाव विचारणीय है। क्या सरकार भूकम्प से लगातार प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लिये उपयुक्त मकानों की योजना पर विचार करेंगे।

श्री दा० रा० चव्हाण : यह एक सुझाव है और इसे राज्य सरकार के पास भेज दिया जायेगा।

श्री न० कु० सांघी (जोधपुर) : मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि गुजरात राज्य का मन्त्रीमंडलीय स्तर का कोई भी मन्त्री घटना स्थल पर नहीं पहुंचा।

हमारे देश में आजकल अधिक भूकम्प जल्दी-जल्दी आते हैं और उनके झटके भी भारी होते हैं। क्या सरकार देश के सभी भागों में आये भूकम्पों के आंकड़े एकत्र करके यह जांच करेगी कि क्या भारत में अब अधिक भूकम्प आया करेंगे ? क्या इस सम्बन्ध में कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया जायेगा ताकि भूकम्प से होने वाली भौतिक हानि को रोका जा सके और लोगों के होने वाले कष्टों को दूर किया जा सके ?

श्री दा० रा० चव्हाण : जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, हमें भारतीय भू-सर्वेक्षण के अधिकारियों द्वारा की जा रही जांच की प्रतीक्षा करनी होगी। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए माननीय सदस्य को तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जबकि आज दोपहर बाद प्रधान मन्त्री वक्तव्य दें।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 के अन्तर्गत अधिघोषणाएं

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं सेठी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 962, की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधि-सूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 413, जो दिनांक 7 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) जी० एस० आर० 414, जो दिनांक 7 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [**ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-2975/70**]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क के निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) नवां संशोधन नियम, 1970 जो दिनांक 7 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 416 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) ग्यारहवां संशोधन नियम, 1970 जो दिनांक 7 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 417 प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) दसवां संशोधन नियम, 970, जो दिनांक 7 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 418 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) आठवां संशोधन नियम, 1970 जो दिनांक 7 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 419 में प्रकाशित हुए थे । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 2976/70**]

(3) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्तत जारी की गई अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 337 से 387 की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 1 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । तथा एक

व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०—2977/70]

राज्य सभा से संदेश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना देता हूं कि 20 मार्च, 1970 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने उच्चतम न्यायालय (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का परिवर्धन) विधेयक, 1969 को, 19 दिसम्बर, 1969 को लोक-सभा द्वारा पास किये गये रूप में, संशोधनों सहित पास किया और विधेयक को इस प्रार्थना के साथ लौटा दिया कि संशोधनों के सम्बन्ध में लोक-सभा की सहमति के बारे में राज्य सभा को बताया जाय।

2. श्रीमान्, मैं उच्चतम न्यायालय (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का परिवर्धन) विधेयक, 1969 की एक प्रति, जो संशोधनों सहित राज्य सभा द्वारा लौटाया गया था, सभा-पटल पर रखता हूं।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

110वां प्रतिवेदन

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : मैं गृह-कार्य मन्त्रालय—केन्द्रीय सतर्कता आयोग पर प्राक्कलन समिति के 84वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में समिति का 110वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

Shri Deorao Patil (Yeotmal) : Mr. Speaker, I want to submit that the reports of Public Accounts Committee and Estimate Committee are very important. But the Hindi version of these reports is not supplied to the Members, though a demand for it has been made again and again in the House. I would like to know the steps taken for making Hindi copies these reports available to the Members.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Sir, you can ask the Minister of Parliamentary Affairs about printing position of these reports in Hindi.

Mr. Speaker : A meeting was arranged and this matter was discussed there. It was said that there was some difficulty in the printing of these debates in the Government Press of Faridabad. As soon as a decision is arrived at in this matter. I will let the House know.

Shri Atal Bihari Vajpayee : If it is difficult to get these reports printed immediately, the cyclostyled copies of the same may be distributed to the Members.

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

94वां और 97वां प्रतिवेदन

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Sir, I beg to present the following **Reports** of the Public Accounts Committee :

(1) Ninety-fourth Report regarding action taken by Governments on the **recommendations** contained in their Sixtieth Report on Appropriation **Accounts** (Railways), 1966-67 and Audit Report (Railways) 1968.

(2) Ninety-seventh Report regarding action taken by Government on the **recommendations** contained in their Seventy-first Report on Appropriation **Accounts** (Civil), 1966-67 and Audit Report (Civil), 1968 relating to the Ministries **of** Steel and Heavy Engineering (Department of Steel) ; Health, Family **Planning** Works, Housing and Urban Development ; Food, Agriculture, **Community** Development and Co-operation (Department of Co-operation) and **Irrigation** and Power.

अनुदानों की अनुपूरक माँगें (सामान्य) 1969-70
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL)—1969-70

वित्त मन्त्रालयों की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
25	1	**श्री श्रद्धाकर सूपकार** :	प्रत्यक्ष कर जांच समिति का प्रवाहहीनता।	100 रु०
44	2	**श्री यशपाल सिंह** :	प्रधान मन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों के यात्रा भत्ते सम्बन्धी व्यय में वृद्धि।	,, ,,
51	3	**श्री यशपाल सिंह** :	आन्दोलन के दौरान मुअत्तिल किये गये पुलिस कर्मचारियों को वापस लेने की वांछनीयता।	,, ,,
53	4	**श्री श्रद्धाकर सूपकार** :	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह को आने जाने के लिए जहाजरानी सेवा।	,, ,,
66	5	**श्री श्रद्धाकर सूपकार** :	महानदी क्षेत्र के जल सम्बन्धी अध्ययन के लिए क्षेत्रीय संगठन।	,, ,,
77	6	**श्री श्रद्धाकर सूपकार** :	किरिबुरु की कच्चे लोहे की खानों में हानि।	,, ,,
5	7	**श्री कंवरलाल गुप्त** :	सेवा निवृत्त सेना के कर्मचारियों के फिर से बसाये जाने की आवश्यकता	100 रु०

1	2	3	4	5
25	8	**श्री कंवरलाल गुप्त :**	बकाया आयकर में वृद्धि तथा काले धन का पता लगाने में असफलता	100 रु०
26	9	**श्री कंवरलाल गुप्त :**	बाढ़ सूखा सम्बन्धी सहायता उपयोग के लिए कुछ राज्य सरकारों को दी गई सहायता का अनुचित उपयोग	,, ,,
33	10	**श्री कंवरलाल गुप्त :**	भारतीय खाद्य निगम को हुई हानि में वृद्धि	,, ,,
51	11	**श्री कंवरलाल गुप्त :**	दिल्ली नगर निगम को कई अनुदानों की अदायगी न करना तथा दिल्ली पुलिस के बारे में खोसला आयोग के प्रतिवेदन में की गई सिफ़ारिशों का क्रियान्वित न किया जाना ।	
51	12	**श्री कंवरलाल गुप्त :**	दिल्ली में खोसला आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वित किया जाना	,, ,,
59	13	**श्री कंवरलाल गुप्त :**	औद्योगिक बिकास मन्त्रालय में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता	,, ,,
64	14	**श्री कंवरलाल गुप्ता :**	आकाशवाणी आदि से समाचार प्रसारण में राजनीतिक दलों में भेद-भाव करना ।	,, ,,
5 ✓	15	**श्री के० आनन्द नम्बियार :**	जवानों की पेंशन सम्बन्धी तथा अन्य लाभ देने और अच्छी सुविधाएं देने की आवश्यकता ।	100 रु०
19	16	**श्री के० आनन्द नम्बियार :**	सरकारी उपक्रमों की और अच्छी लेखा-परीक्षा करने की आवश्यकता जिससे विभिन्न सरकारी उपक्रमों में अनाचार को समाप्त किया जाय ।	,, ,,
20	17	**श्री के० आनन्द नम्बियार :**	विभिन्न मूल्यों के नोटों के आकार और रंग में अन्तर करने की आवश्यकता जिससे लोग भ्रम में न पड़े ।	,, ,,
23	18	**श्री के० आनन्द नम्बियार :**	10 रुपये की तदर्थ वृद्धि रेलवे के उन पेंशनभोगियों सहित जिन्हें अनुग्रह पूर्वक पेंशनें दी जाती हैं, सभी पेंशन भोगियों को देने की आवश्यकता :	,, ,,
25	19	**श्री के० आनन्द नम्बियार :**	450 करोड़ रुपये के बकाया आय-कर की वसूली तेज करने की आवश्यकता ।	100 रु०

1	2	3	4	5
43	20	श्री के० आनन्द नम्बियार :	4000 रुपये मासिक के वेतन के विशेष सचिव के तथा ऊंचे वेतन के दूसरे अधिकारियों के पदों के बनाये जाने की आयुक्तता ।	100 रुपये
46	21	श्री के० आनन्द नम्बियार :	विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय आरक्षित पुलिस को बनाकर तथा नियुक्त कर सारे देश को एक पुलिस राज्य बना कर लोक मत की पूरी तरह से उपेक्षा करना ।	,,
53	22	श्री के० आनन्द नम्बियार :	मुख्य भूमि से बसने के लिए जाने वालों में खास तौर से दंडिण के लोगों को जिनके अनुकूल आबहवा है, बसने की अनुमति देने तथा उपबंध वन और प्राकृतिक साधनों की पूरी तरह से सदुपयोग करने की आवश्यकता ।	,,
53	23	श्री के० आनन्द नम्बियार :	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर अत्याचार समाप्त करने तथा उन्हें रहने के लिए मकान बनाने के लिए जमीन के प्लाट देने की आवश्यकता ।	,,
53	24	श्री के० आनन्द नम्बियार :	लिटिल अण्डमान के "ओंजिस" लोगों के, जिनकी सभ्य बनने की मनोवृत्ति है, पुनर्वास के लिए तुरन्त कदम उठाने की आवश्यकता ।	,,
53	25	श्री के० आनन्द नम्बियार :	कार निकोबार द्वीप में हवाई अड्डे का सदुपयोग कर पोर्ट ब्लेयर, निकोबार तथा मद्रास के बीच सीधी वायु-सेवा चलाने के लिए शीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता ।	,,
83	26	श्री के० आनन्द नम्बियार :	खुले बाजार में इस्पात के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि से उत्पन्न गम्भीर स्थिति ।	,,
103	27	श्री के० आनन्द नम्बियार :	तुरुचिरापल्ली के आयुध कारखाने की 80 प्रतिशत क्षमता का जो इस समय	,,

1	2	3	4	5
			उपयोग में नहीं लाई जा रही हैं, उपयोग करने और उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता ।	100 रु०
103	28	श्री के० आनन्द नम्बियार :	तिरुचिरापल्ली के आयुध कारखाने में कर्मचारियों के उत्पीड़न को समाप्त करने और जो अधिकारी खराब श्रमिक संबंध के लिए उत्तरदायी हैं उनका तबादला करने की आवश्यकता ।	
23	29	श्री गणेश घोष :	जो व्यक्ति 1964 से पहले सेवा-निवृत्ति हो गये हैं उनकी पेंशन की राशि बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
26	30	श्री गणेश घोष :	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सभी सरकारों को दिये जाने वाले अनुदानों को पर्याप्त रूप से बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
43	31	श्री गणेश घोष :	केन्द्र और राज्यों के बीच संबंध सुधारने की आवश्यकता ।	,,
46	32	श्री गणेश घोष :	विभिन्न राज्यों में जनता के लोकतंत्रीय आन्दोलनों को दबाने के लिए केन्द्रीय रक्षित पुलिस और सीमा सुरक्षा बल का प्रयोग किया जाना ।	,,
46	33	श्री गणेश घोष :	पश्चिमी बंगाल राज्य के तत्कालीन गृह-मंत्री की सलाह की उपेक्षा करते हुए पश्चिमी बंगाल में केन्द्रीय रक्षित पुलिस को बलपूर्वक भेजना ।	,,
50	34	श्री गणेश घोष :	स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के मामले में अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में 5 वर्ष के कारावास की शर्त को हटाने की आवश्यकता ।	,,
50	35	श्री गणेश घोष :	उन सभी स्वतन्त्रता सेनानियों को उचित भत्ता देने की आवश्यकता जो इस समय कठिनाई में हैं ।	,,
53	36	श्री गणेश घोष :	भारत और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच नौवहन सेवा में सुधार करने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
77	37	श्री गणेश घोष :	गोवा में उर्वक कारखाना लगाने के लिए बिड़ला बन्धुओं को लाईसेंस देना ।	100
109	38	श्री गणेश घोष :	जो व्यक्ति 1964 से पहले सेवा निवृत्ति हो चुके हैं उनकी पेंशन की राशि को बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
114	39	श्री गणेश घोष :	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की मात्रा बढ़ाने और मूल्य में कमी करने की आवश्यकता ।	,,

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : श्रीमान् मैंने अनुदानों की अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में कुछ कटौती प्रस्ताव दिए हैं । खर्च के इन कुछ मदों के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं । सबसे पहले मैं 275 करोड़ रुपये की उस राशि के बारे में, जिसके संबंध में श्री कुन्ते ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, यह पूछना चाहता हूं, कि उसका ब्यौरा क्या है ? एक स्थान पर एक ऐसी समिति नियुक्त किये जाने का जिक्र भी किया गया है, जो कर अपवंचन की समस्या का अध्ययन करेगी और उसे रोकने के लिए वैधानिक और प्रशासनिक उपाय सुझायेगी । मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने ऐसी समिति नियुक्त कर दी है । जहां तक दैवी विपत्तियों—अकाल, सूखा, बाढ़ आदि के समय विभिन्न राज्यों को अनुदान और ऋण देने का सम्बन्ध है, मेरा यह सुझाव है कि इसके लिए एक स्थायी समिति नियुक्त की जाये, जो सूखा, अकाल, बाढ़ या तूफान आदि प्राकृतिक प्रकोपों के मामलों की जांच करे और प्रभावित राज्य को अपेक्षित सहायता देने की सिफारिश करे । मेरे राज्य में किरिबुरू परियोजना है । इससे आधुनिक मशीनें प्रयोग में नहीं लाई जा रही हैं और इसलिए उसे बहुत हानि हो रही है । सरकार को उसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए । पेज 84 में 138.42 लाख रुपयों की शुद्ध हानि दिखाई गई है, मूल्यह्रास और परिशोधन से यह लगभग 15 करोड़ रुपये बैठेगा, एक ही परियोजना में ऐसी स्थिति होना भयावह है ।

पेज 64 पर, अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह को नौवहन सेना के बारे में उल्लेख किया हुआ है । हम जनवरी के महीने में अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह गये थे और हमने वहां नौवहन सेना का अध्ययन किया था । हमने वर्तमान नौवहन सेवा व्यवस्था को असंतोषजनक पाया है क्योंकि यहां होने वाली हानि को भारतीय जहाजरानी निगम के खर्चे में डाल दिया जाता है । यह हानि उसके खर्चे में नहीं डाली जानी चाहिए । चालू वर्ष के बजट में इसके लिए 58.50 लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है और 101.50 लाख रुपये अतिरिक्त और चाहिए ।

श्री एस० कंडप्पन (मैंदूर) : मैं खाद तथा कृषि मन्त्रालय की मांग संख्या 33 के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ तमिलनाडु की मांग को रखना चाहूंगा कि वहां गेहूं के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए गेहूँ को राजकीय सहायता प्राप्त दर पर बेचा जाये क्योंकि वहां के लोग चावल खाने की अभ्यस्त हैं, मुझे आशा है कि सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनायेगी ।

मांग संख्या 34 में नई दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में आन्तरिक वित्त संगठन स्थापित करने के बारे में उल्लेख किया हुआ है। इस प्रकार के संगठन को मद्रास में भी स्थापित किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना वक्तव्य मध्याह्न भोजन के उपरान्त जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok-Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजकर पांच मिनट पर पुनः समवेत हुई।

The Lok-Sabha re-assembled after Lunch at Five Minutes Past Fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एस० कन्डप्पन अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री एस० कंडप्पन : मैं केन्द्रीय आरक्षित पुलिस के बारे में मांग संख्या 46 के बारे में कह रहा था। मेरे विचार में केन्द्रीय बलों पर लगभग 100 करोड़ रुपया व्यय किया जाता है, यह एक अजीब सी बात है कि इन पर प्रति वर्ष व्यय बढ़ता जा रहा है, हम जानते हैं कि कानून तथा व्यवस्था राज्य का विषय है और बिना राज्यों की सहमति से वहां केन्द्रीय आरक्षित दल को नहीं भेजा जा सकता है। केन्द्रीय सरकार ने भी इस स्थिति को स्वीकार है, हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने पश्चिमी बंगाल में केन्द्रीय आरक्षित दल की उपस्थिति के बारे में यह तर्क दिया है कि यह वहां केन्द्रीय संस्थानों की सुरक्षा के लिए नियुक्त की गई है। परन्तु मैं कहना चाहूँगा कि इस कार्य के लिए वहां पहले ही औद्योगिक सुरक्षा दल है। इसलिए केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस की व्यवस्था समाप्त कर दी जाये तथा राज्य की पुलिस की संस्था बढ़ाई जाये और उसे मजबूत बनाया जाये। जब कभी भी आपात स्थिति आये तो अन्य दलों को भेजा जा सकता है। मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार इसके लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त निश्चित करेगी नहीं तो केन्द्र और राज्य सरकारों में तनाव बढ़ता रहेगा।

अब मैं अन्दमान और निकोबार द्वीप समूहों से संबंधित मांग संख्या 53 की चर्चा करूंगा। श्री लंका बर्मा, और अन्य क्षेत्रों से लोगों को वहां पर बसाया जा रहा है इसलिए में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि वहां सड़कें, पक्के घाट बनाये जायें तथा मुख्यभूमि और द्वीपसमूहों के बीच यातायात चलाने के लिए मोटर-बोटों तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाये जो कि अभी ठीक स्थिति में नहीं है।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात मैं जानना चाहूंगा कि क्या पोर्ट ब्लेयर और मद्रास के बीच वायु-सेवा से सम्बन्ध जोड़ने का कोई प्रभाव सरकार के विचाराधीन है क्योंकि इन दोनो के बीच यातायात बढ़ रहा है, और वहां के व्यापारियों को मद्रास में उनके मुख्य कार्यालयों से सम्बन्ध स्थापित करने में कठिनाई होने के कारण परेशानी उठानी पड़ रही है।

अब मैं सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के मांग संख्या 62 पर चर्चा करूंगा। मैंने सभा में

यह प्रश्न कई बार उठाया था कि आकाशवाणी के विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के कार्यक्रमों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के शब्द जनता में बोली जाने वाली भाषा के नहीं है, मेरा सुझाव है कि ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यक्रमों में इस ओर अनुसंधान कार्य किया जाना चाहिए और किसानों द्वारा वस्तुतः प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा को स्थान दिया जाये ताकि वे इस कार्यक्रम को समझ सकें, मुझे याद है कि मंत्री महोदय ने बताया था कि हिन्दी भाषा के बारे में इस प्रकार का कार्य हो रहा है, मैं कहना चाहूँगा कि सभी भाषाओं के लिए समान व्यवस्था की जाये ताकि आकाशवाणी कार्यक्रम और अधिक लोकप्रिय बन सके ।

अन्त में मैं परमाणु ऊर्जा आयोग के कार्य के बारे में कहूँगा । इसके अतिरिक्त मांगों का मैं विरोधी नहीं हूं अपितु मैं चाहूँगा कि इसको सुव्यवस्थित किया जाये । जहां तक मेरे राज्य का सम्बंध है, वहां बिजली की बहुत कमी है, इस कमी को तमिलनाडु सरकार पूरा नहीं कर पा रही है, हमें केरल और मैसूर से कुल खपत का एक-तिहाई बिजली प्राप्त होती है । अतएव यह आवश्यक है कि हम राज्य में बिजली का उत्पादन बढ़ाये, हमारे पास केवल नीवेली परियोजना और कलापक्कम परियोजना है । मेरा अनुरोध है कि कलापक्कम परियोजना पर काम शुरू किया जाये और उसमें सुधार लाया जाये । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे तथा भविष्य में राज्य में बिजली की कमी नहीं होगी, तमिलनाडु में 1971 से पूर्व सभी गांवों में बिजली पहुँचाने का एक बड़ा कार्यक्रम है और इसके लिए बिजली की बहुत आवश्यकता होगी, मुझे आशा है कि सरकार कलपक्कम परियोजना के दूसरे चरण पर कार्य आरम्भ कर देगी ।

Shri Deorao Patil (Yeotmal) : Under Demand No. 33, a provision of Rs. 11.95 crores has been made for consumer subsidy. This will be given to Food Corporation of India to make up the difference caused by the economic price of foodgrains and price of its supply. The difference between Purchase Price and Consumer Price is higher. So the State Governments and its agencies earn profits by purchasing and selling the Foodgrains. The farmer is given Rs. 65 per quintal Thus there is a difference of Rs. 15 to Rs. 20. My suggestion is that efforts should be made to reduce the expenditure.

Under Demand No. 134, a grant of Rs 30.18 lakhs has been demanded for the establishment of a new Telephone Exchange in Malabar Hill, Bombay. I do not know why this provision was not made in the present Budget. According to a survey there will be need of 1,10,000 new lines. So this work may be completed without delay.

This is a Profit making Project. A sum of Rs. 20.69 lakhs will be earned as a Profit annually. So this Project may be taken up early. It has been seen that no priority is fixed giving the connections. I have received many complaints in this regard. The Communication Minister is not here. All the concerned Ministers should be present in the House.

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : अनुदानों की मांगों को देखने से पता चलेगा कि बहुत से मंत्री अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए वैदेशिक व्यापार और पूर्ति मंत्रालय को ही लें । हमारे मंत्री महोदय श्री भगत तीन सचिवों की माँग कर रहे हैं, इसी प्रकार गृह-कार्य मंत्रालय की भी लम्बी सूची है । इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय 2.5 लाख रुपये अपने प्रशासन पर और व्यय करना चाहता है ।

मैं यह कहना चाहूंगा कि जब श्री मोरारजी देसाई ने वित्त विभाग का पद संभाला था । तो उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि प्रशासन पर व्यय को कम किया जाएगा और वे यह

सुनिश्चित करेंगे कि अधिकारियों से अधिक से अधिक काम लिया जाए और कहीं यदि अधिक पद हों तो एक मंत्रालय से अधिकारियों को वहां स्थानान्तरण किया जाए ताकि नई भरतियों की आवश्यकता हों। दूसरे शब्दों में भरती पर रोक होनी चाहिए। हमें इसी का आश्वासन दिया गया था। परन्तु अब मितव्ययिता की सब कार्यवाहियां ताक पर रख दी गई हैं। और अब वे अपने कर्मचारियों तथा अधिकारियों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। मेरे विचार में यह सब सार्वजनिक धन का दुरुपयोग है अतएव प्रशासन व्यय और यात्रा भत्ता से सम्बन्धित मांगों को धारित नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त गैर योजना व्यय भी बढ़ रहा है जो ठीक नहीं है।

मांग 112 पर विचार करने से पता चलेगा कि वित्त मंत्रालय राज्यों पर कोई वित्तीय अनुशासन लागू करने पर असफल रहा है। केन्द्रीय सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाती है और उसकी देखा-देखी राज्य भी ऐसा करते हैं। वे भी अपने ओवरड्राफ्ट को बढ़ा रहे हैं। और केन्द्रीय सरकार भी उनको ऋण तथा अनुदान के रूप में धन देती जाती है।

मैं अब अफीम के विषय पर कहूंगा जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित है, यदि आप अफीम के कारखाने का उचित ढंग से विस्तार करें और इसकी मांग को ध्यान में रखें तो इसका निर्यात कई गुना बढ़ सकता है। अतएव इस बारे में मेरा पहला सुझाव है कि किसानों को दिया जाने वाला बढ़ाया जाये, दूसरा अफीम पैदा करने का क्षेत्र भी बढ़ाया जाये। तीसरा उन किसानों को पट्टा या लाइसेंस पुनः दिए जाये जिनसे यह किन्हीं कारणों से ले लिये गये थे। अंत में उनको दी जाने वाली बकाया धन राशि दे दी जाए।

करापवंचन की जाँच के लिये एक आयोग नियुक्त किया गया है। परन्तु इसके मूल कारणों का पता लगाया जाना चाहिए। यदि कर लेने का ढांचा उचित तथा ईमानदार है तो हमें जांच आयोग आदि नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे अधिक कर लगाये जाते हैं और लोगों का यह विचार है कि वर्तमान दर पर कर देना ठीक नहीं है, सरकार को कर ढांचे का पुनरीक्षण करना चाहिए ताकि लोगों के पास भी कुछ धन बच सके और वे इसके अन्य कार्यों में लगा सकें।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : In connection with this Demand, a reference has been made for the increase in amount for the expenditure in Excise department. Recently it was said in the House that the Hon. Minister Shri Patil had connection with the Smugglers. So I urge that this matter may be looked into.

A reference of giving assistance to the State has been made in this Demand. In this connection I would like to say there are many backward States in our country. They are esposed to famine and other calamities frequently. There are some districts like, Dharbanga, Sharasha in Bihar where this year the yield is very low. Besides this the same conditions are prevailing to some areas of Rajasthan, Assam and Bengal etc. too. So you should give special considerations to these areas and more assistance should be given to them.

A reference for the provision of finance has been made in this demand for the census to be held in 1971. Sample surveys are conducted but the results prove flop. When the Government officials demand upgradation of this cities then you only talk of imminent census. When you depend on census then what is the use of having this Sample Survey.

Recently I went to Andaman and Nicobar with the Estimates Committee. You are asking for Finance for the P.W.D. Circle, being constructed there, in this Demand. But I request to say that there is no provision of accommodation for the workers. We were astonished to find a number of persons living under one roof. This is the treatment which is being given to those workers who are helping in the progress of Andaman. The behaviour of officials is not good with them and they are not given salaries in a proper way.

A number of industries can be set up there. Sugarcanes are being produced in large scale. So Sugar mills are also needed there. There is a vast forests. We had seen two or three saw mills. The conditions of workers are not good and they are given less salaries. These workers come from far flung areas, like Kerala, Tamilnadu, Bihar etc. So proper attention should also be given to them.

At the end I want to say about Heavy Engineering, Ranchi. During communal troubles our Muslims brothers were rendered homeless. And now they have no rooms to live in. So adequate arrangements for accommodation be made for them.

There is acute water shortage in Andaman and Nicobar Islands. So water provison be made for them. With these words I support the demand.

श्रीमती इला पालचौधरी (कृष्णनगर) : मैं पेंशन तथा सेवा निवृति सम्बन्धी अन्य सुविधाओं के बारे में बात करना चाहती हूँ। आज आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बहुत वृद्धि हो गई है परन्तु पेंशन पाने वालों की पेंशन में विशेष वृद्धि नहीं की गई है। इस से उन लोगों को कोई राहत नहीं मिली है। ब्रिटेन में अब एक नये कानून द्वारा यह आवश्यक कर दिया गया है कि जब भी सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाये सेवा निवृत्त कर्मचारियों के वेतन में भी साथ ही साथ वृद्धि कर दी जाये। पश्चिम बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार ने सेवारत सरकारी कर्मचारियों के वेतन तो बढ़ाये परन्तु सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन नहीं बढ़ाये गये हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस बारे में कुछ करे। अब मांग संख्या 46 को लेती हूं। यह एक बड़ी मांग है। इसका सम्बन्ध केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सीमा सुरक्षा दल से है। इनको अब अधिक जिम्मेदारियां निभानी है। सीमा सुरक्षा के लिये सड़कों का बहुत महत्व है। उनके सुधार की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। पश्चिमी बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की बहुत आवश्यकता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

श्री पी० गोपालन तेल्लीचेरी) : मैं मांग संख्या 46 पर बोलना चाहता हूँ। हमें कल ही बम्बई से तार प्राप्त हुये हैं कि वहां पर दक्षिण भारत के लोगों पर शिव सेना वालों की ओर से आक्रमण किये जा रहे हैं। यह घटनायें गृह मंत्री के राज्य में हो रही हैं। यह बहुत चिन्ता की बात है। समाचारपत्रों में अनेक ऐसे समाचार छप रहे हैं। फिर वहां पर सत्तारूढ़ कांग्रेस वाले शिवसेना के साथ मिले हुए हैं। शिव सेना वालों ने वहां आंतक फैलाया हुआ है। शिव सेना का बड़े-बड़े सरकारी अधिकारियों पर भी प्रभाव पढ़ता जा रहा है। बम्बई बन्द के दिन रेलवे से सम्बन्धित सरकारी कारखाने भी बन्द कर दिये गये थे। दूसरा अर्थ यह हैं कि केन्द्रीय सरकार ने भी शिव सेना वालों के साथ सांठगांठ कर रखी है।

बम्बई नगर निगम में सत्तारूढ़ कांग्रेस दल शिव सेना के समर्थन से सत्ता में चल रहा है। बम्बई नगर का विकास देश के सभी भागों के लोगों के परिश्रम से हुआ है। अतः शिव सेना की नीति और उसके जैसी प्रवृत्ति को समाप्त करना होगा।

श्री चव्हाण के बारे में कहा जाता है कि वह एक बहुत कठोर स्वभाव के व्यक्ति हैं और वह गड़बड़ को दबाने में बहुत कुशल व्यक्ति हैं। परन्तु दक्षिण भारत के बम्बई स्थित वासियों पर शिव सेना के जुल्म के मामले में उनकी कठोरता समाप्त हो जाती है। शिव सेना एक बहुत ही खतरनाक संगठन है। सरकार को इस बारे में गम्भीरता से विचार करके कार्यवाही करनी चाहिए।

केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों में केन्दीय रिजर्व पुलिस तैनात कर रखी है। मेरे राज्य में इस पुलिस ने बहुत अत्याचार किये हैं। हमारे दल के नक्सलवादियों के साथ विचारधारा के बारे में मतभेद हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम क्षेत्र में ऐसी घटनाएं हुई है जो किसी लोकतंत्रीय तथा सभ्य देश में नहीं होंगी। केरल में भी नक्सलवादियों पर पुलिस ने बहुत अत्याचार किये हैं। उनको न्ययोचित दण्ड दिया जाना चाहिये।

Shri Meetha Lal Meena (Swai Madhopur): There is danger to our country from anti-national elements, similarly there is danger from corruption and internal regional imbalances. The corruption is rampant in our country. The names of big public men are being mentioned very frequentiy these days. The other day gold worth of Rs. 4 lakhs was seized at Rohtak Road. It was told that persons keeping that gold were connected with the Chief Minister of Haryana and that is why the case has not been referred to customs and it has been assigned to local Police.

There is great corruption in Police Department. The Ministers and M.L.As. are giving protection to corrupt persons. This thing is spreading in all Departments. Now even the Judicial Department is not free from this. I want to bring to the notice of Hon. Minister that smuggling of foodgrains is taking place on borders of Haryana, Rajasthan and Gujarat. Rice is being smuggled into Gujarat from other States. All these things should be set right immediately.

Swai Madhopur and Jalaur Districts of Rajasthan were declared as backward districts in 1967. It is a pity that inspite of repeated requests to the Central Government nothing has been done to improve the condition of those districts. The people of these districts will be compelled to start agitation if no steps are taken to ameliorate the condition of those districts. The proposed oil refinery should immediately be set up there

Necessary arragements must be made to provide drinking water in rural areas of Rajasthan. There is great need of improvement in the working of P and T Department in the Rajasthan area. Large quantities of wire of this Department is being stolen. It should be checked.

Hindi should be introduced in Banks in Hindi areas. Similar measures should be taken in Income-tax Department. People in general do not know English language.

Food Zones in respect of wheat have been abolished. I want that likewise decision should be taken in the case of rice. It will help farmers in Rajasthan. Government should give more assistance for the victims of earthquake in Gujrat.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): मैं गृह मन्त्रालय से संबंधित उठाई गई बातों के बारे में ही बोलूंगा। श्री गोपालन ने केरल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कार्य का उल्लेख किया है। यह पुलिस राज्यों की सरकारों की सहायतार्थ भेजी जाती है। इस पुलिस द्वारा आतंक फैलाने की बात निराधार है। इस बारे में राज्य सरकार के द्वारा शिकायत करने पर हम जांच करते हैं। ऐसा आरोप लगाना बिल्कुल गलत है।

शिव सेना की गतिविधियों का हम समर्थन नहीं करते। यह कहना गलत है कि हम उसका

साथ दे रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भी शिव सेना को दबाने के प्रयत्न किए हैं। दिल्ली पुलिस के बारे में कल सभी दलों के सदस्यों की बैठक हुई थी।

इस बैठक के बाद निर्णय किया गया था कि 1967 में अन्दोलन के आरोप में जिन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी उसपर पुनः विचार किया जाये। दिल्ली पुलिस के बारे में खोसला आयोग की बहुत सी सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है।

पुलिस आयुक्त के बारे में सिफारिश पर अभी तक हमने कोई निर्णय नहीं किया है। यदि पुलिस आयुक्त की नियुक्ति की जाती है तो बहुत से ऐसे कार्य अब मैजिस्ट्रेटों द्वारा किये जा रहे हैं जो पुलिस आयुक्त को सौंपने पड़ेंगे। अन्तिम निर्णय करने से पहले हमें सभी पहलुओं पर विचार करना होगा।

पश्चिम बंगाल में गड़बड़ करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक ढांचे में कुछ अन्तर किया जा रहा है। इसके लिए कुछ अतिरिक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के पद बनाये जा रहे हैं। यह प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही किया जा रहा है।

Sari Kanwar Lal Gupta : Sir, I want to ask one question. Budget Session has commenced in two States. The Governor of those states have criticised the Central Government. Though it is a fact that the responsibility of State Governments rests on them, but it is improper to criticise the Central Government by Governors. Hence, I would lika to know whether Government is proposing to formulate any rule to see that Centre is not criticised by Governors.

श्री स० कुण्डू (बलासौर) : यदि यह वार्तालाप जारी रहेगा तो हमें बोलने के लिए समय ही नहीं मिलेगा।

श्री कंवर लाल गुप्त : मुझे केवल एक प्रश्न पूछना है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप को दुबारा मौका मिला, तो आप को प्रश्न पूछना चाहिए था। अब मैं आप और माननीय गृह मन्त्री महोदय के बीच के इस वार्तालाप को अनुमति नहीं दे सकता हूं। यहां अन्य सदस्य भी उपस्थित हैं जो बोलना चाहते हैं।

श्री जि० मो० विश्वास (वांकुटा) : महोदय ! हम सदन के कार्य में बाधा डालना नहीं चाहते हैं। परन्तु हमें भी मौका मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया ध्यान दीजिये। आप के दल को बोलने का मौका दिया गया है।

श्री जि० मो० विश्वास : आप अन्य सदस्यों को प्रश्न पूछने का मौका देते जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है। अगर कोई सदस्य मेरी आपत्ति के बावजूद भी बोलता है तो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Half of the amount demanded in respect of supplementary demands, is unnecessary. For example, take the demand No. 25. It is for Finance Ministry. This demand is presented with the aim of preventing tax-evasion. They say that an expert committee is going to be set up to probe into the tax-evasion, which is a social evil, and this committee will give valuable suggestion regarding this. But, as a matter of fact, so many committees have been set up before, and the Government have received the reports of these committees. But they have not raised a single finger so far to implement the proposals put forward. Prof. Caldor has suggested that Central auditing system may be adopted. But the Government is not paying any heed to this. This Government is imposing property tax, but they are not setting up Central evaluation machinery for property. There is great difference between what they say and what they do.

Demand No. 34 is regarding foreign trade and supply. They have demanded a sum of Rs. 10,33 lakhs. Trade de egation is being sent to foreign countries. But they are not taking any measure to foster the export trade. Britain had charged 15 percent import duty on Indian goods imported them. But the Government is silent in this regard. Hence the demand is a ludicrous one. .

Demand No. 42 is regarding Housing works and urban developments. Whatever construction is going on, is a wastage. For example take the construction works going on in South Avenue. There money is being wasted abundantly. I want the Government to order a probe into this construction. I have written many times to the Minister regarding this but of no use.

Demand No. 44 relates to Cabinet. In this connection I have to say one thing that the amount of Rs. 4.99 lakhs, for travelling expenses is unnecessary.

Now I want to say something about Home department. There is much furore over the activities of Central Reserve Police. Their activities have a totalitarian nature. This should not be allowed. They should be democratised soon, otherwise our democracy will become a shame. Similarly, a judicial inquiry should be instituted into the accident occured in Stonipur and Asansol where so many people were dead.

Demand No. 47 is about census. In this item an amount of 35.71 lakhs is demanded. In Bihar, the total population of 'Mythilee' speaking people is about 2 crores. I had raised question about this census. This is not known to the Government what is the population of these people. As a result, their demands regarding language etc. are not fulfilled. I want the Government present before the House the data regarding these people.

Demand No. 49 is about Privy-purse. Really it is an unnecessary expense. Even-though the amount is less, but it is a matter of principle. Had the Government acted wisely and honestly, this problem could have been tackled long back Even now, the Government can resort to measures to abolish privy-purse. The more they would delay, the more complicated the issue becomes. Therefore they should amend the Constitution and abolish the privy-purse-

Demand No. 90 is regarding atomic energy. An amount of 4.50 crores is demanded in this respect. It is for the development in nuclear energy. In Bihar, an atomic plant is necessary. In this connection I have presented a bill before the House. In Jadugara, in Bihar, raw materials and natural resources available in plenty. But the Prime Minister, who is incharge of this department, did not pay any heed to this side so far. This is severe injustice that is being done to Bihar.

If we go into the details of all the other demands, we will be aware of the fact that more than half of the expenses is provided for conspicuous consumption which is unnecessary. The most of the demands may be passed.

Now I want to say one thing about the Tribals and Harijans. Whenever a bill was introduced in the House on banks, we strongly pleaded for their representation and I have introduced amendment also to this effect.

But the Government is doing nothing in this direction. Jayaprakash Committee had suggested for full employment of Tribals. But this Government is not interested in these things. They should be honest to what they say.

Finally I have to say one thing about the department of Information and Broadcasting. There is unsavoury favouritism in the items like "Today in Parliament", 'Sansad Sameeksha' etc. This should be stopped.

In Darbhanga a radio station should be installed. This Government has done nothing in this direction. This should be implemented expeditiously.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुण्दू को बुलाने के पहले मैं सदन को सूचना देता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री साढ़े चार बजे, गुजरात में हुए भूकंप के सम्बन्ध में सदन में वक्तव्य देंगी।

श्री स० कुण्दू : मैं इस्पात और भारी इन्जीनियरिंग सम्बन्धी मांग के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूँ कि मुझे यह देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि कार्यालय के स्थानांतरण के सिलसिले में दो लाख रुपये खर्च किए गए हैं। एक मन्त्री की नियुक्ति के सिलसिले में फरनीचर, वातानुकूलकों, हीटरों आदि के प्रबन्ध के लिए 82,000 रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया है। यह नया मंत्री कौन है ? सरकार संसद को पथभ्रष्ट कर रही है।

फिर हम देखते हैं कि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति ने देश का दौरा किया था। मनोरंजन कार्यक्रम आदि पदों पर 64,000 रुपये खर्च हुये हैं। यह कैसा मनोरंजन कार्यक्रम था ? इस मांग में इसका पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। मेरा प्रश्न यह है कि क्या वह कोई मामूली मनोरंजन कार्यक्रम का या कोई 'फ्लोर शो' था ? हमारा देश गरीब है। हम लोगों में ऐसे मनोरंजन में होने वाले व्यय को सहन करने की क्षमता नहीं है। अतः हम इन व्ययों का अनुमोदन नहीं कर सकते हैं।

एशिया के सुदूर पूर्व देशों के लिये आर्थिक आयोग ने देश के विभिन्न भागों में इस्पात कारखाना स्थापित करने की सिफारिश की थी। इन में एक था उड़ीसा। वहां लोहा आयस्क और कांच बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। विशेषकर उडीसा एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है। अब, जब सरकार दो-तीन इस्पात कारखाने स्थापित करने जा रही है। मैं आशा करता हूँ कि वे उड़ीसा की ओर भी ध्यान देगी। मैंने प्रधान मन्त्री को पत्र लिखे थे। मगर मुझे अब तक अनुकूल उत्तर नहीं प्राप्त हुआ। आशा है कि सरकार उड़ीसा के मामले में सहानुभूति से ध्यान देगी।

अब मैं राजाओं को दी जाने वाली निजी थैली के सम्बन्ध में, जिसके बारे में पृष्ठ संख्या 45 में कहा गया है, कुछ कहना चाहता हूँ। 85,000 रुपये बकाया राशि के भुगतान के रूप में राजाओं महाराजाओं के लिए खर्च किये जा रहे हैं। राज्य सभा में पारित संकल्प के आधार पर सरकार निजी थैली समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है। जब वे लोकतंत्रात्मक समाजवाद की घोषणा कर चुकी है तो उन्हें अपने वचन के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। उन्हें छल एवं ढोंग का काम करना चाहिये। अतः उन्हें यह मांग प्रस्तुत नहीं करनी चाहिये थी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को अनुदान और सहायता के रूप में पर्याप्त राशि मिलती है। इस धन को बाढ़, सूखा, तूफान जैसे प्राकृतिक प्रकोपों का सामना करने के लिए प्रयोग में

लाया जाता है। यह सहायता सामान्यतया 75 प्रतिशत तक होती है जिसमें 50 प्रतिशत अनुदान और 25 प्रतिशत ऋण है। राज्यों को दी जाने वाली ऐसी राशि को पूर्णतया अनुदान के रूप में ही दिया जाना चाहिए, यह मांग हमेशा से की जा रही है। इसका कारण यह है कि राज्य सरकारें प्रकृति के इन प्रकोपों से पीड़ित और दुखी जनता को सहायता में धन खर्च करने में असमर्थ हैं। राहत कार्यों के लिए 60 करोड़ रुपये की मांग विभिन्न राज्य सरकारों के लिए रखी गई है।

कुछ राज्यों को ऋण के रूप में सहायता देने के लिए 265 करोड़ की राशि मांगी गई है। अगामी वर्ष के बजट में भी ऋण देने के लिए 175 करोड़ रुपये का प्रावधान है। बजट पर बहस करते समय यह शंका प्रकट की गई थी कि इस राशि को देते समय राज्यों पर राजनीतिक दबाव डाला जा सकता है।

कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के लिए भी वित्त का प्रावधान रखा गया है। कई सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उत्पादन से पहले ही तैरने के तालाब और विशाल बंगले तैयार करा लिए जाते हैं। वस्तुतः निर्धन जनता के धन को इस प्रकार बरबाद नहीं होने देना चाहिए और इन मामलों में धन व्यय करने से पहले कुछ कसौटी रखनी चाहिए। समस्त राशि का 45 प्रतिशत निर्माण पर खर्च हो रहा है। इसके लिए सरकार को विचार करना चाहिए।

Shri Onkar Lal Bohra (Chitorgarh) : Mr. Deputy-Speaker . Sir before I say something about the Supplementary Demands I would like to congratulate the hon. Minister of Home Affairs for giving a chance to crores of people to move freely by proclaiming President Rule in West Bengal.

First of all I would like to call the attention to the drought stricken areas of Rajasthan. Certain cut motions have been moved regarding the complaints of corruption prevalent in the relief works organised here. I would like to say that investigation may be made in this matter and he persons found guilty must be punished. It was necessary that sufficient amount should be made available to the people affected with the drought. Rajasthan is a backward State and at the same time border State too. We want that special grant may be sanctioned for assisting Rajasthan which directly needs crores of rupees.

The financial condition of Rajasthan is not sound and there is 700 mile long border line adjoining Pakistan. The famine problem is there and the amount granted for the drought is very little. I want that the Ministry of Finance may avail much more money for tiding over the problem of drought-stricken people of Rajasthan so that they can get solace.

The Government of Rajasthan, the Chief Minister and Members of Parliament belonging to that State had repeatedly demanded that priority should be given to the construction of the Rajasthan Canan. With this project not only drought stricken will be given relief but it would go a long way in strengthening the economy of the whole country. But it seems that there no provision for these demands as if Central Government has not followed its importance.

There are so many such tourist centres which are equal in number with those of whole of the country's but in these demands very small amount has been sanctioned for the development of these centres in Rajasthan. No attention has been given to the communications facilities thereof.

3 million Adivasi live in the Southern and Western regions of Rajasthan and they are always in trouble. For their assistance undoubtedly money is allotted but how much

amount is distributed among tribals--can only be known by the person who goes there and watches the situation thereof. I do not agree with the fact that the money is not being misused. Until and unless this amount be utilised by the distinguished and honest persons no right use of this money can be done.

After 22 years of freedom, even now the people get drinking water from three hundred feet deep wells and even then they get hard water.

I request that having in mind the weak financial position of Rajasthan, a special amount for drinking water may be granted in these supplementary demands so that maximum tube-wells can be installed.

I would like to congratulate the hon. Minister of Finance. Shri Sethi who saved those farmers, who grow opium in my constituency, from injustices done by the Sales-tax Authorities for realizing Sales-Tax or opium. Opium is such a thing by which we can increase our export and collect much more money. This is why facilities may be provided for growing more opium in the Chitors, Mandsaur and Malwar areas.

श्री दत्तात्रय कुंटे (कोलाबा) : मांग संख्या 112 में राज्यों को करोड़ों रुपये ऋण और अग्रिम धन के रूप में देने की व्यवस्था की गई है। सर्वप्रथम मैं संबंधित मन्त्री से जानना चाहता हूँ कि प्राकृतिक संकटों के लिए 35 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये की मांग में वृद्धि का विस्तृत ब्यौरा क्या है तथा क्या यह राशि उचित रूप से व्यय की जा रही है और तमिलनाडु को क्या आवश्यकता से अधिक राशि प्राप्त हो रही है अथवा क्या उसे दूसरे राज्यों से अधिक राशि दी जा रही है।

दूसरा यह कि 275 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था संसाधनों में अन्तर को पूरा करने के लिये की गई है। यदि मांग संख्या 112 के ब्यौरों पर विचार किया जाये, तो हम देखते हैं कि इनमें प्राकृतिक संकटों आदि के लिए योजना गैर-योजना और अस्थायी ऋण है। पिछले वर्षों में वित्तीय संसाधनों में अन्तर पाटने के लिए कोई मांग नहीं की गई थी, जिसे इस वर्ष शुरू किया गया है। संसाधनों में अन्तर पाटने के लिए ये एक नये किस्म के ऋण हैं और ये सभा में एक नए कार्य के रूप से आने चाहिए और इन्हें पृथक से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

वित्तीय संसाधनों से प्राप्त आय एवं व्यय में हुए अन्तर को मिटाने के लिये 275 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। यह बात ठीक है कि उक्त रकम गैर-योजना अनुदान के शीर्षक से पेश की गयी है। परन्तु, यह एक नए प्रकार का अनुदान है, अतः इसे पृथक रूप से सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। चूंकि ऐसा नहीं किया गया है, इसीलिए यह अनुच्छेद 115 के अनुसार अवैध है।

सरकार ने, योजना-अनुदान के ढांचे में, लद्दाख नागा लैंड तथा अन्य ऐसे प्रदेशों के हित में परिवर्तन किया है। यह अच्छी बात है कि अनुदान की राशि 70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत बढ़ा दी गयी और ऋण की राशि 30 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक कम कर दी गयी है। परन्तु इस प्रकार परिवर्तन लाने के पहले सरकार को सदन के समक्ष इन चीजों को प्रस्तुत करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश सरकार ने ज्ञापन के भाग II में यह कह कर कि "इस पर निर्णय किया गया" संसद के अधिकारों को स्वयं हडप लिया है। इन परिवर्तनों पर अन्तिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार संसद को है। सरकार को इस का अधिकार नहीं है।

मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि इस मामले में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने निर्णय किया है।

वहां भी मुख्यमंत्रियों ने इस रकम के व्यय के तरीकों के बारे में शिकायतें की थीं। समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा है कि आठ राज्यों को इस से लाभ प्राप्त हो रहा है। अगर जब अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गयी थीं, उस समय इस संबंध में विवरण प्राप्त नहीं थे, तो इस समय जबकि वह प्राप्त हैं, सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये। विवरण प्रस्तुत करने के पहले सदन का मत मागना उचित नहीं है।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Mr. Deputy-Speaker, regarding the Demand No. 5 I have to bring the fact to the notice of Defence Ministry, that the family accommodation given to any area is very little. During his tenure, he is unable to keep his family with his whereas an ordinary peon can. Hence any appeal to the Government is that ample family accommodation should be provided to them.

The second thing which is to be noted is that when the wife of an ordinary policeman become widow, his wife and children will receive pension, whereas when the wife a military officer becomes widow her pension will be stopped. Why it is so ? The Minister may note this point.

Thirdly, I want to say something about the Demand No. 29. The Government have imposed wealth-tax on urban property worth Rs. 6 lakhs, where the maximum limit in rural area is Rs. 2½ lakhs whatever the nature of land may be. I want clear reply from the Agricultural Minister as to why this kind of discrimination is being done. There is great agitation on the issue in the villages throughout India.

I urge the Government to replace the present officials in Agricultural Prices Commission by peasants. This time, the price of agricultural products is decreased by 4 rupees. It is good that they were given some relief after the Chief Minister conference. But I want more and more peasants to be appointed in the conversion. It should be taken into account how much the products cost and it should be given to peasants including a marginal profit.

Demand No. 37 relates to the purchasing of flats by M.Ps. Those who want to purchase more than 150 yards, they are not allowed. This matter is under the jurisdiction of Housing Ministry. But the hon. Minister is not present now.

Demand No. 51 is regarding the unauthorised colonies. In these colonies there is no arrangement or electricity, water or schools. I urge the Government to draw their attention towards this.

Demand No. 52 is concerned with Chandigarh. It is reported that a commission is going to be set up to go into the details of border disputes and suggest remedial measures. Really we are much harassed by these commissions. If this commission is set up there will be wide spread in Punjab, Haryana and Himachal Pradesh. It is better to reach a mutual settlement.

One thing I wish to say about Fazilka that this area should be immediately handed over to our possession.

Demand No. 62 is related to Ministry of Broadcasting. Our A.I.R. station is alotted to Rohtak. For this, land should be acquired immediately and all the otner necessary works should be begun as soon as possible. Now a programme for villages is broadcast from Delhi, but there the man who is speaking belongs to city and not to a village. When a station will be established in village, our people will be able to take part in the functions more and more and this will encourage them by and large.

Demand No. 124 is regarding irrigation and power. From 20 onwards, water supply to Pakistan is being stopped In this context we want our due share of water.

Demand No. 75 is related to Ministry of Petrolium. It is alleged that there are impropreities in giving agency of Petrol Pump and Gas. In cities like Delhi, bribes for lakhs of rupees are given. I want the Government to nationalise the Petrol industry.

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : श्रीमान्, चालू वित्त वर्ष की अनुपूरक मांगों में यह तृतीय और अन्तिम वर्ग की मांग है जिन में कुछ 53 मांगें हैं। इन में से 39 माँगों का विनियोग राजस्व लेखा में, 13 पूंजी खाते में और शेष एक ऋण और पेछागी के भुगतान के खाते में है। मांगें मार्च 16वीं तरीख को संसद के समक्ष प्रस्तुत की गयी थीं। अनुपूरक मांगों में दिखाया गया व्यय कुल मिलाकर 383.16 करोड़ रुपये है जबकि अनुमानित शुद्ध व्यय 288.49 करोड़ रुपये है। इसमें से 94.67 करोड़ रुपये प्राप्तियों वसूली तथा हिसाब किताब मिलाने इत्यादि पर व्यय होंगे।

श्री सूपकार और श्री कुन्टे 275 करोड़ रुपये की विशेष सहायता राशि का विवरण और आधार जानना चाहते थे। मैंने उस दिन अत्यन्त परिश्रम से यह समझाने का प्रयत्न किया था कि यह सहायता कोई नई सेवा नहीं है और सदन ने भी इसे स्वीकार कर लिया था अत: मैं इस प्रश्न पर और चर्चा नहीं करूंगा। मैं केवल सिद्धान्तों को दोहराए देता हूं और वे ये हैं: प्रत्येक राज्य की आवश्यकतानुसार उचित योजना परिव्यय वित्त निगम की सिफारियों के आधार पर किए गये अन्तरण का सम्बद्ध राज्यों पर प्रभाव केन्द्र द्वारा अतिरिक्त साधनों को गतिशील बनाने के परिणामस्वरूप प्रत्येक राज्य को होने वाला लाभ, राज्य की पिछले ऋणों को लेकर अदायगी और शेष भुगतान की स्थिति तथा राज्य सरकारों द्वारा अपने साधनों को गतिशील बनाने की दिशा में उचित प्रयत्न इन सिद्धान्तों के आधार पर योजना आयोग ने राज्य सरकारों से विस्तृत चर्चा की थी जिसके आधार पर वे कुछ परिणामों पर पहुंचे है योजना आयोग द्वारा लगाये गये अनुमानों के अनुसार संसाधनों तथा कुल व्यय के बीच 279.5 का अन्तर रहेगा।

[**श्री श्रीचन्द गोयल पीठासीन हुए**
Shri Shri Chand Goyal *in the Chair*]

यह अन्तर विभिन्न राज्यों में इस प्रकार होगा आंध्र प्रदेश 23.71 करोड़ रु० आसाम 48.54 करोड़ रु०, जम्मू-काश्मीर 56.92 करोड़ रु० मध्य प्रदेश 1.50 करोड़ रु० मैसूर 17.50 करोड़ रुपये उड़ीसा 32.13 करोड़ रुपये राजस्थान 64.11 पश्चिम बंगाल 9.91 करोड़ रु० तथा तमिलनाडु 7 करोड़ रुपये।

श्री प्र० चं० सेठी : उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात को क्यों छोड़ दिया गया है इस विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा पांचवे वित्त आयोग के वित्त के विभाजन में कुछ सिफारिशें की थीं।

श्री दत्तात्रय कुन्टे : 100 करोड़ रुपये के विवरण के विषय में आप को क्या कहना है?

श्री प्र० चं० सेठी . श्री कुन्टे और कुछ अन्य सदस्यों ने सूखा पीड़ितों को राहत देने के आधार के विषय में पूछा है। जब कभी भी किसी राज्य पर कोई विपत्ति आती है, तो कुछ राहत धन दिया जाता है श्री कोठारी ने कहा है यद्यपि गुजरात पर विपत्ति आई है, प्रधान मन्त्री ने केवल 50,000 रुपये ही दिए है। यह धन प्रधान मंत्री ने राहत-कोष से दान के रूप में दिया है। यदि किसी राज्य पर बाढ़ भूकम्प अथवा सूखे के कारण विपत्ति आती है तो राज्य सरकार सारी सारी स्थिति का निरीक्षण कर केन्द्र को सूचना देती है तब केन्द्र स्थिति का निरीक्षण करने के

लिए एक विशेषज्ञ दल भेजता है और उसकी सिफारिशों के आधार पर ही राहत-धन दिया जाता है।

सहायता का विवरण इस प्रकार है। आंध्र प्रदेश 2.50 करोड़ साइक्लोन के कारण 10 करोड़ और 1.70 करोड़ रुपये, बिहार 1 करोड़, गुजरात 12.50 करोड़, केरल 50 लाख, मध्य प्रदेश 50 लाख, मैसूर 1.50 करोड़, उड़ीसा 50 लाख तथा 50 लाख, राजस्थान 43.50 करोड़, तमिलनाडु 13 करोड़, उत्तर प्रदेश 1.50 करोड़ तथा 50 लाख तथा पश्चिम बंगाल 1 करोड़ इस प्रकार कुल योग 90.70 करोड़ रुपया हुआ श्री सूपकार ने जिरिबुरु द्वारा उठाई गई हानि को लेकर भी प्रश्न उठाए हैं साथ ही श्री कंडप्पन ने अंडमान और निकोबार का प्रश्न भी उठाया है। जहां तक किरिबुरु द्वारा उठाई गई हानि का सम्बन्ध है, यह सत्य है कि जापान को रेलवे का निर्यात बहुत लेने और रेल भाड़े तथा पत्तन-शुल्क में वृद्धि के कारण इस खान को हानि उठानी पड़ रही है इस कारण हमने यह विचार किया है कि बाद में इस खान का उपयोग बीकारो के लिए किया जाए और जापान की निर्यात आवश्यकता बैलडिला से पूरी की जाए। इस व्यवस्था के होने तक किरिबुरू द्वारा जापान को हानि के साथ निर्यात करना होगा।

रेलवे एवं पत्तन अधिकारियों के साथ इस मामले में बातचीत हुई है और भाड़े शुल्क में कुछ कमी की संभावना है। इसके साथ ही सरकार ने भी इसे कुछ सहायता दी है। किरिबुरू की हानि का कारण यह भी है कि इसके द्वारा मूल्यवान विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो रही है जो कि 1968-69 के अंत तक 34 करोड़ रुपये थी जबकि हानि केवल 5.50 करोड़ रुपये की हुई है।

जहां तक अण्डमान निकोबार द्वीप-समूह का प्रश्न है, केन्द्र इसके विकास के लिये वचनबद्ध है। योजना में इस द्वीप-समूह के लिए व्यय में बढ़ोत्तरी होती जा रही है। जबकि योजना में अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति 97 रुपये की औसत बैठती है, अण्डमान और निकोबार के लिए यह प्रति व्यक्ति 1001 रुपये है।

इस सम्बन्ध में श्री सूपकार ने इस द्वीपसमूह को जाने वाले जल-पोतों एवं भारतीय नौवहन निगम के प्रश्न को भी उठाया है। यह निश्चय किया गया है कि भविष्य में यात्री जल-पोत भी नौवहन निगम को हस्तान्तरित कर दिये जाएं।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : क्या इससे निगम के लाभ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस समय निगम को 23 प्रतिशत लाभ हो रहा है। अण्डमान की सेवा भी निगम के अन्तर्गत आने के कारण निगम को हानि उठानी पड़ेगी आपको इसे पूरा करना चाहिए।

श्री प्र० चं० सेठी : इस मामले को सम्बद्ध विभाग के साथ उठाना चाहिए।

श्री कंडप्पन ने कलपक्कन स्थित अणु शक्ति संयंत्र के विकास के प्रश्न को लिया था। इस संबंध में स्थिति यह है कि 1970-71 वर्ष के दौरान 'रिएक्टर' तथा 'टरबाईन' के लिए इमारत बिजली-घर आदि बनाने का कार्य अग्रिम चरण में पहुँच रहे हैं देशी एवं आयातित दोनों प्रकार की मशीनों आदि को प्राप्त करने के लिए भी पूर्ण प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री एस० कण्डप्पन : मैंने द्वितीय चरण के सम्बन्ध में प्रश्न किया था। तमिलनाडु सरकार ने भी इस विषय में अभ्यावेदन किया है कि अनुमानित उत्पादन शायद आवश्यकता पूर्ति न कर

पाये । क्या सरकार दूसरे चरण को भी पूरा करेगी और क्या उसके लिए अभी से योजना बनाई जा रही है ।

श्री प्र० चं० सेठी : इस समय तो मेरे पास ऐसे किसी विस्तार की सूचना नहीं है । परन्तु जब तक पहला चरण पूरा नहीं हो जाता, माननीय सदस्य को विस्तारण के प्रश्न पर चिन्ता नहीं करनी चाहिए । उसके लिए साधनों, योजना आयोग को स्वीकृति आदि कई बातों को देखना पड़ेगा ।

माननीय सदस्य श्री देवराव पाटिल ने बम्बई में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को टेलीफोन न दिये जाने के प्रश्न को उठाया है । मैं डाक तथा तार विभाग के मंत्री को यह सूचना भेज दूंगा । उन्होंने खाद्य निगम का जिक्र भी किया है । खाद्य निगम को हुई हानि का कारण यह है कि उनका वितरण भाव खरीद-भाव से कम है और इन दोनों भावों को सरकार ही निश्चित करती है । देशी गेहूँ का खरीद भाव 76 रु० है जबकि वितरण भाव आनुषंगिक व्यय को मिलाकर 78 रु० के लगभग है अनाज के आयात की कमी को सरकार पूरा करेगी । अतः माननीय सदस्यों का यहविचार ठीक नहीं है कि खाद्य निगम अपने कार्य को ठीक से नहीं कर पा रहा ।

श्री कोठारी ने कुछ मंत्रालयों में बढ़ रहे व्यय की और भी ध्यान दिलाया है । गृह मंत्रालय में बढ़ रहे व्यय के विषय में श्री शुक्ल ने स्थिति स्पष्ट कर दी है ।

श्री कोठारी ने कहा है कि विकासात्मक व्यय की तुलना में अविकासात्मक व्यय बढ़ रहा है । एक तो ब्याज के कारण हमारा भुगतान बढ़ रहा है, दूसरे प्रतिरक्षा व्यय भी बढ़ता जा रहा है । यदि आप इन दोनों प्रकार के व्यय और राज्यों को (योजना से अलग) दिये गये अनुदान को लें तो मेरा विचार है कि अविकासात्मक व्यय बहुत अधिक नहीं है । 1960-61 में यह लगभग 45% था । चालू वर्ष में आशा है यह व्यय 39% होगा । अविकासात्मक व्यय को कम करने का पूर्ण प्रयत्न किया जायेगा । इसी प्रकार श्रीमती इलापाल चौधरी ने पेंशन भोगी व्यक्तियों के मामलों का उल्लेख भी किया है । मैं यहां यह कहना चाहूँगा कि जहाँ तक आगामी वर्ष के बजट-प्रस्तावों का सम्बन्ध है यह मात्र पिछली तदर्थ बढ़ोत्तरी को लेकर हैं । किन्तु अब यह निर्णय किया गया है और उसे बजट प्रस्तावों के समय घोषित भी किया गया है कि प्रत्येक पेंशन भोगी के लिए न्यूनतम पशन प्रतिमास 40 रु० होगी जबकि पहले कई बार 7 या 8 या 10-15 रु० की पेंशन भी होती थी हम इन लोगों को और भी अधिक सुविधाएं देना चाहेंगे किन्तु साधनों की उपलब्धि और राज्य की समग्र आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है जो भी तदर्थ बढ़ोतरी दी गई थी वह 200 रु० तक ही दी गई थी । श्रीमती इलापाल चौधरी ने सीमावर्ती सड़क विकास के प्रश्न को भी लिया था प्रतिरक्षा और अन्य उद्देश्य को लेकर जहां भी आवश्यकता समझी जाती है, सड़कों का विकास किया जा रहा है । यदि उनके ध्यान में कोई विशेष सीमावर्ती सड़क है जिसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया तो मैं निवेदन करूंगा कि वे इस विषय पर सम्बद्ध मंत्री के साथ चर्चा करें अथवा तत्सम्बन्धी सूचना मुझे दे दें तो मैं मंत्री महोदय को इस विषय में बता दूंगा ।

14-3-70 को रोहतक रोड पर पकड़े गये सोने का जहां तक सम्बन्ध है, दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को दे दिया गया था । पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है ।

जैसाकि हमने सूचित किया था यह सोना चाहे तश्करी का हो अथवा अन्य किसी प्रकार का, स्वर्ण नियंत्रण कानून के अन्तर्गत सोने को रखना अपराध है। अतः इस सोने के मामले की सीमा-शुल्क अधिकारियों ने ही निपटाना है। मामला न्यायालय तक ले जाया गया था जिसने इसे सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंप दिया है। 20-3-1970 को सीमा शुल्क अधिकारियों को सोना सौंप दिया गया है। अतः ये अनुत्तरदायित्वपूर्ण बातें गलत है अमुक मंत्री या मुख्य मंत्री अथवा उनके संबंधी इस मामले से संबद्ध हैं।

सवाई माधोपुर क्षेत्र में हुए राहत कार्यों के विषय में कुछ प्रश्न उठाये गये हैं। इस संबंध में स्थिति यह है कि केन्द्र द्वारा निरीक्षण के पश्चात सम्पूर्ण धन राज्य सरकार को दे दिया जाता है शेष राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है।

माननीय सदस्य ने आयकर कार्य के विषय में भी प्रश्न उठाया है और कहा है कि विशेष रूप से हिन्दी भाषी राज्यों में यह कार्य हिन्दी में होना चाहिए। जहां तक आयकर विभाग का प्रश्न है हमने पहले ही ये निदेश दे दिया है कि जहां तक सम्भव हो इन हिन्दी भाषी राज्यों में विशेष रूप से हिन्दी माध्यम को अपनाया जाए। इस ओर रिजर्व बैंक का भी ध्यान आकर्षित किया जायेगा जिससे वह हिन्दी-भाषी राज्यों के बैंकों को आवश्यक निर्देश दे सके।

संसद् के दोनों सदनों में सरकार से अनुरोध किया गया था वह चोरी के धन के मामलों की छान-बीन करें और विशेषज्ञ समिति का गठन भी करे। सदन की इच्छानुसार श्री वाँचू की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। अब यह समिति धन के बिना तो कार्य नहीं कर सकती। विभिन्न प्रकार के व्यय करने होते हैं, आवश्यकताएं होती हैं उन्हीं की पूर्ति के लिए मांग संख्या 25 में कुछ धन इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किया गया है।

श्री शिवचन्द्र झा ने मूल्यांकन विभाग के कुछ मामलों की ओर से इंगित किया है। हमने विभिन्न स्थानों पर सम्पति के मूल्यांकन के लिए मूल्य निर्धारकों की नियुक्ति की थी जो कि मूल्यांकन सम्बन्धी मामलों की जांच करेंगे इन लोगों ने 800 मामलों की जांच कर ली है जिसके परिणामस्वरूप यह पता लगा है कि बहुत से मामलों में प्रमाणिक मूल्य निर्धारकों के द्वारा ठीक से मूल्य निर्धारण नहीं किया गया था और अब इनका मूल्य निर्धारण फिर से किया जायेगा।

श्री शास्त्री ने नगरों की श्रेणी को बढ़ाने की बात कही है। इस सम्बन्ध में हमने एक समिति का गठन किया था किन्तु समिति के प्रतिवेदन प्राप्ति के उपरान्त तो अनेक अन्य नगरों से प्रतिनिधित्व की बाढ़ सी आ गई जिसमें कहा गया कि उन नगरों की जांच समिति के मामलों में सम्मिलित किया जाए। अतः इस मामले को बीच में रोकना पड़ा। हम पुनः इस पर ध्यान देंगे ?

तस्करी के सम्बन्ध में कुछ विशेष व्यक्तियों का नाम लिया जा रहा है। यदि उचित जानकारी दी गई तो मामले की जांच-पड़ताल हो जाएगी। व्यय को लेकर मैंने पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया है। इन्होंने प्रिवीपर्स के प्रश्न को भी उठाया था। सरकार के विचार से सदन भली भांति परिचित है। किन्तु जब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाता और उसे वैद्य रूप नहीं दिया जाता तब तक उन्हें दी जाने वाली राशि न निकाली जाए। हम 1969-70 की पूरक मांगे पारित कर रहे हैं।

राजस्थान नगर और अन्य विकासात्मक कार्यक्रमों तथा पर्यटन आदि विषय तो पूरक मांगों के अन्तर्गत आते हैं यह कोई विस्तृत बजट नहीं है जिसमें सम्पूर्ण कार्यक्रमों को ध्यान में रखा जाता है हम सदन से केवल व्यय हुई अतिरिक्त राशि को स्वीकृत चाहते हैं।

श्री कुन्ते ने 'उकाए' क्षेत्र के विकास के प्रश्न को उठाया है। इस विषय में जाँच करनी पड़ेगी अतः इस समय जुताई के लिए किसी क्षेत्र विशेष को लेने के लिए वचन देना बहुत कठिन होगा किन्तु उनके सुझाव पर जांच पड़ताल कराई जा सकती है।

जहां तक 275 करोड़ रुपये का सम्बन्ध है मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। श्री रणधीर सिंह ने जवानों के परिवारों में विधवाओं की पेश का प्रश्न उठाया था। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे आवश्यक जानकारी मुझे दे दें जिसे मैं प्रतिरक्षा मन्त्री को भेज दूँगा और उनसे इस विषय पर विचार-विमर्श करूंगा।

नगरों और गांवों के सम्पति कर के सम्बन्ध में माननीय सदस्य को कुछ भ्रम है सम्पतिकर संयुक्त हिन्दू परिवार पर दो लाख से भी अधिक सम्पति पर लगाया जाता है। जहाँ तक कृषि पर सम्पति कर का सम्बन्ध है प्रारम्भिक छूट के बाद बाद 2½ लांख की सीमा निश्चित की गई है। संयुक्त परिवार पर सम्पति कर की सीमा 3½ लाख रुपये तक निश्चित करने की है। ...माननीय सदस्य ने जिस बात को ध्यान में रखकर यह बात कही है वह सम्पत्ति कर न होकर 5 लाख रुपये से अधिक सम्पदा पर लगाया जाने वाला पूँजी लाभ कर है माननीय सदस्थ श्री कुन्ते ने विवरण को लेकर प्रश्न उठाया है। इसमें 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ऋण और अनुदान का कुल योग 125 करोड़ बनता है। अब तक 98 करोड़ रुपया दिया जा चुका है जिसमें बकाया राशि की सहायता भी शामिल है इसमें 78 करोड़ रुपये तो ऋण के रूप में तथा 20 करोड़ अनुदान के रूप में दिए गए शेष राशि 31 मार्च 1970 तक दे दी जाएगी।

श्री दत्तात्रेय कुन्ते : अब तो विवरण मिल गया होगा।

श्री प्र० चं० सेठी : मैंने मुख्य विवरण दे दिया है। शेष धन विभिन्न राज्यों में वितरित कर देना है यदि इस धन में कुछ कमी पड़ेगी तो उसको ध्यान में रखा जाएगा क्योंकि यह तो 31 मार्च 1970 तक है जिसके लिए मैं सदन की स्कीकृति मांग रहा हूं।

सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

All the Cut Motions were put and negatived

सभापति महोदय द्वारा वर्ष 1969-70 के लिए निम्नलिखित अनुदानों की अनुपूरक मांगे(सामान्य) मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई

The following Supplementary Demands for grants (General) 1969-70 were put and adopted

मांग संख्या	माँग का नाम	मांग की राशि जो सभा के मतदान के लिए रखी जायेगी
		रुपये
	(रक्षा मंत्रालय)	
5	रक्षा सेवाएं, निष्क्रिय	1,85,00,000
	(वित्त मन्त्रालय)	
16	केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क	27,46,000
19	लेखा-परीक्षा	200,00,000
20	मुद्रा और सिक्का-ढलाई	35,00,000
21	टकसाल	1,48,000
23	पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	47,05,000
24	अफीम	1,08,17,000
25	वित्त मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,000
26	राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों को सहायक अनुदान	15,84,00,000
	(खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय)	
29	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय	5,62,000
33	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	12,21,60,000
	(विदेश व्यापार और पूर्ति मंत्रालय)	
34	विदेश व्यापार और पूर्ति मन्त्रालय	10,33,000
37	विदेश व्यापार और पूर्ति मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	15,53,000
	(स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय)	
40	लोक-निर्माण-कार्य	2,71,94,000
42	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	10,00,000
	(गृह मंत्रालय)	
43	गृह मन्त्रालय	8,60,000
44	मंत्रिमंडल	4,90,000
46	पुलिस	9,49,46,000

1	2	
47	जन-गणना	35,71,000
49	भारतीय राजाओं की निजी थैलियां और भत्ते	7,000
50	प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशने	1,79,000
51	दिल्ली	3,79,51,000
52	चण्डीगढ़	63,05,000
53	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2,06,11,000
54	आदिम जाति क्षेत्र	3,69,96,000
	(औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय मन्त्रालय)	
59	उद्योग	5,00,000
	(सूचना और प्रसारण मन्त्रालय)	
62	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	2,20,000
64	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	9,98,000
	(सिंचाई और बिजली मंत्रालय)	
66	बहु-प्रयोजनी नदी योजनाएं	1,000
	(पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मन्त्रालय)	
75	पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय	2,39,000
77	पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	61,71,000
	(जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय)	
78	जहाजरानी और परिवहन मन्त्रालय	90,000
	(इस्पात और भारी इन्जीनियरी मंत्रालय)	
83	इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय	2,50,000
	(पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय)	
87	विमानन	57,82,000
	(परमाणु ऊर्जा विभाग)	
90	परमाणु ऊर्जा विभाग का अन्य राजस्व व्यय	4,50,01,000
	(संचार विभाग)	
93	डाक और तार का कार्यचालन व्यय	10,51,29,000

1	2	3
	(रक्षा मन्त्रालय)	
103	रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय	2,000
	(वित्त मन्त्रालय)	
109	पेशनों का राशिकृत मूल्य	32,43,000
112	केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम	5,000
	(खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय)	
114	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय का अन्य पूँजी परिव्यय	9,16,65,000
	(गृह मंत्रालय)	
119	संघीय राज्य क्षेत्रों और आदिम जाति क्षेत्रों का पूंजी परिव्यय	1,13,55,000
120	गृह मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	55,50,000
	(औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय मंत्रालय)	
121	औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय मन्त्रालय का पूंजी परिव्यय	1,000
	(सिंचाई और बिजली मंत्रालय)	
124	सिंचाई और बिजली मन्त्रालय का अन्य परिव्यय	3,000
	(श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय)	
125	श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	60,34,000
	(पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय)	
126	पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मन्त्रालय का पूंजी परिव्यय	1,48,58,000
	(जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय)	
129	जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	40,01,000
	(पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय)	
132	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	1,81,66,000
	(संचार विभाग)	
134	डाक और तार पर पूंजी परिव्यय (राजस्व से नहीं)	10.18.00,000

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Mr. Speaker, I beg to move for adjournment of present proceedings. I request that the happenings of Punjab Legislative Assembly should be discussed first. Punjab Legislative Assembly has not allowed submission of the appropriation bill, with the result constitutional crisis is emerged there.

I want to know whether Central Government has received the report or not.

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi): We have not received any detailed report we have heard the same whatever Hon'ble Member has heard.

विनियोग विधेयक—1970

(APPROPRIATION BILL-1970)

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 1969-70 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : कि वित्तीय वर्ष 1969-70 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री प्र० चं० सेठी : मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि वित्तीय वर्ष 1969-70 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ "कि वित्तीय वर्ष 1969-70 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

Shri Madhu Limaye : I want to say one thing about Demand No. 16, in which an amount of Rs. 20 lakhs is demanded to roof-out the smuggling business on the border areas of Nepal. On November, 1968 Nepal and India came to a settlement in which Nepal had consented that it would control the import of synthetic fibres and stainless steel. I want to know whether the Government has acted according to this agreement what step the Government has taken to checks the inflow of materials which is far exceeding to that prescribed at the time of settlement.

Rakseal and Jogbani are border areas. But there are no sufficient custom arrangements. When I went there to my surprise I found that there was no arrangement even for sheds for the people coming there. I want to get details regarding this from the Minister.

There is one other thing regarding Nepal that those who are involved the textile business getting letters from Nepal to the effect that the ban has been lifted from readymade garments. I want to know what is the points at push ?

I want to say one thing regarding the Demand relating to Cabinet. At first it was Rs. 9 lakhs and 1 thousand and at the second time Rs. 4 lakhs and 90 thousands. I want to know whether this amount is spent in tour connected with mid-term poll. I do ask you have gone on tours to topple the Governments so for propaganda in mid-term election. And

now additional demand is presented before us. At present the whole secretariat work is being done on three different levels. One is in the Ministry concerned. Second is cabinet Secretariat and the third is Prime Minister's Secretariat.

Prime Minister have no time to go into the files sent by secretaries of the concerned Ministry, because she is deeply involved in toppling the Governments. She is least interested in administrative affairs. It is a fact that the people working in the invisible secretariat make arbitrary changes in the suggestions proposed by secretaries, of the concerned Ministries and hence they are discontent. I want the Prime Minister to make clear the relation among these different secretariats. And also State clearly whether there is any invisible hand binding the functing of Secretariat and the Government.

श्री नरेन्द्र सिंह गढ़ौदा (आनन्द) : विनियोग विधेयक पर विचार करते समय मैं सरकार का ध्यान कुछ व्यवस्थाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हम जनता के धन का उपयोग करते हैं अतः हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में अपना विचार व्यक्त करने का अवसर मुझे नहीं दिया गया था। मैं जानता हूं कि राष्ट्रपति के सचिवालय में 76,000 रुपये करके वानशीतकों तथा वातानुकूलकों का प्रबन्ध किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए दो लाख रुपयों का प्रबन्ध किया गया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए भी फरनीचर एवं वातानुकूलकों का प्रबन्ध किया गया है। यह बात सर्वथा अनुचित है। जब हम सार्वजनिक धन का उपयोग करते हैं तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए और इस तरह वातानुकूलकों या बात शीतकों के लिए व्यय नहीं करना चाहिए। जब तक भारत की औसत जनता को दो बार खाने को एवं रहने को मकान और औषध एवं शिक्षा की पूर्ण सुविधायें नहीं मिलती हैं, तब तक इस प्रकार का व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Government has set up an expert committee to prevent tax-evasion. I welcome this step. But it is not proper to change the income-tax law every year. It is necessary that the law should be simplified and for that a special body should be set up which can make necessary suggestions regarding this.

Now the bank nationalisation is over. The Government may make it clear how much percentage of amount will go to agricultural sector and how much to industries. Difficulties of small traders in taking locus should be removed.

Almost all Governors have criticised the Centre. It is true that since the responsibility of State Governments rests on these they have to express the opinion of State Governments. But they have to play another role also. They are the representatives of Central Government. So a complicated situation is created. Provisions must be made so as to make it clear when the House should be prorogued and when not. The Government may go into the matters of Kashmir, Haryana etc.

As far as Delhi is concerned, Prime Minister is indifferent towards this. In 1958 Reddy Commission in its report had stated that water supply should be improved fast. But hither to no amount is sanctioned to this affect. The D.T.U. operation is also on decline. No amount is given to it for two years. Politics should not be allowed to intervene in these matters. Delhi is the capital city and hence the Government have special responsibility in its matter.

The deficit in Food Corporation is increasing day by day. My view is that there must be healty competition between private trade and public trade. These food zones should be stopped once for all. I welcome the wheat zones.

श्री प्र० चं० सेठी : हम समझौते की प्रक्रिया को अन्तिम रूप देने के लिए नैपाल की

सरकार से पत्रव्यवहार कर रहे थे, परन्तु हमें इस सम्बन्ध में पर्याप्त जवाब नहीं मिला। अतः 1969 अप्रैल से, नेपाल वर्ष 1967-68 के दौरान में किये हमारे आयात के आंकड़ों के आधार पर ही आयात की अनुमति दी जा रही थी। मगर नेपाल सरकार और हमारे बीच में हुए समझौते के भंग को ध्यान में रखते हुए 1-9-1969 से किसी प्रकार के आयात को अनुमति नहीं दी जाती है। भारत और नेपाल के सम्बन्ध में हुए समझौते की स्थिति यह है। सीमावर्ती प्रदेशों में तस्कर व्यापार को रोकने का हम विशेष रूप से प्रयत्न करते हैं। और सीमाकर अधिकारियों को वाहन और अन्य सभी उपलब्ध साधन प्रदान करते हैं। मगर भारत-नेपाल सीमा बहुत विशाल है और नेपाल से भारत में आने के कई अन्य गुप्त मार्ग है। अतः भरसक प्रयत्न के बावजूद भी तस्कर व्यापार को पूर्ण रूप से रोका नहीं जा सकता। फिर भी हम इस ओर हमेशा जाग्रत रहते हैं और बहुत सावधानी से काम करते हैं।

और श्री मधुलिमये ने दौरे के व्यय सम्बन्धी प्रश्न उठाया। जहां तक इन पदों का सम्बन्ध है, मैं कह चुका हूं कि 1-9-1969 से आयात की अनुमति नहीं दी जाती है।

Shri Madhu Limaye : I have raised the question of readymade garments. That is a different question. I have written to the Minister several times, but he has no information regarding this.

श्री प्र० चं० सेठी : मुझे इस समय इसकी कोई जानकारी नहीं है। फिर, जहां तक दौरों में जाने वाले मन्त्री आदियों के व्यय का सम्बन्ध है, मैं सदन को एवं श्री मधुलिमये को आश्वासन देता हूँ कि किसी भी मन्त्री को जब या तो वह कांग्रेस सम्मेलन में भागलेने के लिए जाते हैं या चुनाव के दौरान राजनैतिक तौर पर जाते हैं, यात्रा भत्ता या मंहगाई भत्ते के रूप में सरकार की धनराशि खर्च करने की अनुमति नहीं दी गयी है। अतः यह धारणा कि व्यय में वृद्धि हुई है, न्याय संगत नहीं है। **(व्यवधान)**

Shri Madhu Limaye : I have wanted the details regarding the demand of additional 8 lakhs rupees.

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक प्रधान मन्त्री के सचिवालय के बारे में श्री मधुलिमये के कथन का सम्बन्ध है, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उक्त कथन बिलकुल अरुचिकर हैं। **(व्यवधान)**

Shri Madhu Limaye : It is not in bad taste. The Minister has no power to criticise in this way. I have said that some fundamental principles regarding administration are involved in this. Prime Minister may clarify it. What Mr. Sethi knows about it ? **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : उन्हें भाषण पूर्ण करने दीजिये। आपको जो बोलना था, बोल चुके।

श्री प्र० चं० सेठी : अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए हर एक मन्त्री को कर्मचारियों की आवश्यकता है। जब कभी हमें संसद सदस्यों से पत्र मिलते हैं, वे चाहते हैं कि इसका शीघ्रता से जवाब मिले। जब कभी कुछ शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन पर विचार करना होता है सरकारी कार्य यथा सम्भव शीघ्र किया जाना चाहिए। अतः सरकारी कार्य की विविध आवश्यकताओं का

निबटारा करने के लिए प्रधान मन्त्री का भी एक सचिवालय होता है। उसमें कोई गलती नहीं है।

और उन्होंने यह भी कहा कि सचिवों के जो भी सुझाव हैं हम उनकी अवहेलना करते हैं। यह बिलकुल गलत है।

Shri Madhu Limaye : Mr. Chairman, either the Minister has not followed my point or he is deliberately distorting it. My question was whether the Prime Minister's Secretariat intervenes in the departmental affairs arbitrarily, of which Prime Minister herself is ignorant, sometime. Is it functioning like an invisible Government ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह बात ठीक नहीं है। वे अन्य विभागों के साथ पूरी मेल जोल से काम करते हैं। यह आरोप कि प्रधान मंत्री यह तक नहीं जानती हैं कि कब आदेश जारी किये जाने हैं, बिल्कुल गलत है।

श्री कंवर लाल गुप्त ने बैंक द्वारा की जाने वाली पेशगी के बारे में प्रश्न उठाये हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना कार्य में अतिरिक्त पूंजी-संग्रह द्वारा प्रत्याशित 3000 करोड़ रुपये कि जमा राशि में से 28 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों में जाता है। और कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली पेशगी में 7.5 प्रतिशत से 11 प्रतिशत बढ़ रही है। इस ढंग में कोई टार्गेट निश्चित नहीं किया जा सकता है। उत्पादन की आवश्यकताओं को निभाने के लिए पेशगी दी जायेगी। कृषि, व्यापार आदियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जायेगा

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"वित्तीय वर्ष 1969-70 की सेवाओं के लिए भारतकी संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड 2 और 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक नाम विधेयक का से जोड़ दिये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 2 और 3 अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक से जोड़ दिये गये।

Clouse 2 and 3, the Schedule, clause 1, the Enecting formula and the Title were added to the Bill.

श्री प्र० चं० सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"विधेयक को पारित किया जाय।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"विधेयक को पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

गुजरात में आये भूकम्प के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. GUJRAT EARTH QUAKE

सभापति महोदय : माननीय प्रधान मन्त्री।

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, वित्त मन्त्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : सोमवार को गुजरात में हुए भीषण भूकंप से जनता की जान और संपत्ति की हुई भारी क्षति से हम बहुत दुखी हैं। मेरा सहयोगी श्री दा० रा० चव्हाण ने इस सम्बन्ध में पहले ही वक्तव्य दिया है।

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार भड़ौच और आस पास के अन्य गांवों में एक पुरुष, छः स्त्रियों और 16 बच्चों की मृत्यु हुई है तथा गंभीर रूप से घायल हुए 144 लोगों को हस्पताल में दाखिल किये हैं। 150 और 175 के बीच मकान या तो गिर गये हैं या आवास योग्य नहीं रह गये हैं। अन्य 2000 से 2500 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं।

राज्य सरकार ने भूकंपग्रस्त क्षेत्रों में चिकित्सक दलों को शीघ्र भेज दिया तथा लोगों को राहत कार्य के सिलसिले में नगद राशि दी जा रही है। उन्होंने हमें सूचित किया है कि अन्य राहत कार्य भी जारी किया जा रहा है।

हम राज्य सरकार से संपर्क बनाये रखते हैं और अधिक विवरण प्राप्त करने की आशा करते हैं। क्या तुरंत राहत कार्य के लिये प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय राहत निधि से 51,000 रुपये का लीक अनुदान राज्य सरकार को दिया जा चुका है।

जैसा मेरे सहयोगी श्री दा० रा० चव्हाण ने कहा था भूकंप के संबन्ध में विस्तृत अध्ययन किया जायेगा। भूकम्प-विज्ञान संगठन के अध्यक्ष, केन्द्रीय जल व शक्ति आयोग का एक वरिष्ठ अभियंता तथा भूविज्ञान सर्वेक्षण के अधिकारियों को इसके लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। हम राज्य सरकार के प्रति और विशेषकर वहां की भूकंप पीड़ित जनता के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं।

Shri Ishaq Sambhali (Amroha) : Is it a fact that some engineers had worked the Statement of impending danger ? If so, about action the State Government resorted to ?

सभापति महोदय : प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य पर किसी भी प्रश्न को अनुमति नहीं दी जाती है।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (मणिपुर) तथा मणिपुर का बजट

SUPPLEMENTARY DEMAND FOR GRANT (MANIPUR) AND MANIPUR BUDGET

सभापति महोदय : अब सदन में वर्ष 1969-70 के लिए मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र के बजट सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान, वर्ष 1970-71 के लिए संघ राज्य क्षेत्र बजट पर आम चर्चा तथा वर्ष 1970-71 के लिए मणिपुर संघ राज्य-क्षेत्र के बजट सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान होंगे। इन तीनों मदों पर एक ही साथ चर्चा होगी और इसके लिए दो घंटे आबंटित किये गये हैं। मांगें सदन के समक्ष प्रस्तुत हैं।

Dr. Ram Subhag Singh (Buxar) : Mr. Chairman, it is quite unfortunate that Manipur, which is a beautiful place, and the people there are very smart and industrious is under President's rule. From October 16, 1969 onwards President's rule is imposed on this State and the Assembly is prorogued. After the Government has fallen dark, Government of India did not allow the majority party to form alternative Government because the Government of India did not like them. But we see that in Bengat Assembly is not prorogued, it is only dissolved sine die. Hence they are staging a peculiar drama,

The Central Government has been doing injustice to the people of Manipur. They brought four of the sub-divisions of Manipur under the administration of Nagaland State Council. The people of Manipur have raised the demand that these sub-divisions with all its development operations should come under Manipur administration.

Now the supplementary demands for grants in respect of Manipur are before the House. It is said that Jails in Manipur are packed to their capacity. It is also mentioned that buses are to be purchased. I say that had the administration been proper, there would not have arisen the problem of jails. Jails are fully packed because there the people demanded statehood for Manipur. As a result there is a mass upsurge and the people are voluntarily going to jails. Since all the jails are filled with agitators, they want more jails and hence want more money This is such a demand that cannot be conceded at any rate.

Similar is the case of purchasing of buses. In Manipur we see so many un-authorised tax-collectors. The total area is of 7½ thousand square miles. Out of it 7 hundred square miles are mountain valleys. At present a trip to Imphal is highly dangerous. Same is the case in the trip from Imphal to Chuda Chandpur. There was a proposal of constructing a road from Silchar to Imphal, but for the previous three years not a single step is taken to this effect. Therefore the people want full statehood. If nagaland is given statehood, there is no wrong in giving statehood to Manipur also. Hence urge the Government to give full Statehood to Manipur. The Government must have a consistant policy. This kind of dual policy is unfair. I want arrangement for fresh election should be made in Manipur immediately. Let the people of Manipur be given power to formulated policies, and implement them. The officers sent there, are bunglers. Here, there is severe competition in the secretariat Each secretary is waiting for the mercy of the private secretary of Prime Minister. And the Prime Minister is giving exhortations to the people.

I want the Government to construct good road in Manipur so that the common man can walk about for without having the fear of being engulfed in danger.

We want fresh election should be held off in Manipur. The Government should implement the same policy in Bengal also as they do in Manipur. The officers who are posted there and who have no interest in the well-being of Manipur, should be called back.

The Government should review and revise their policy regarding this. Similarly, the four sub-divisions, kept under the peace-council, should be kept under the administration of Manipur.

श्री रंगा (श्री काकुलम) सभापति महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री डा० रामसुभग सिंह ने मणिपुर की जनता की आवश्यकताओं, उनके अधिकारों के सम्बन्ध में जो बातें कही हैं । मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूँ ।

मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इस प्रबन्ध के सामरिक महत्व को ध्यान में रखें । यह प्रदेश बाहर से बन्द पड़ा था । संचार की व्यवस्था अपूर्ण है । इस प्रदेश को देश के अन्य भागों से रेल द्वारा या बड़ी सड़कों द्वारा जोड़ा नहीं गया है दिन में एक या दो बार केवल हवाई जहाज द्वारा लोग वहां पहुँच सकते हैं । अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वे इस एकत्रित प्रदेश की जनता की आवश्यकताओं, मांगों की ओर वे अपना ध्यान दें । संचार व्यवस्थाओं की ओर ध्यान द । और इस प्रदेश की बहुमुखी विकास के लिए सभी उपलब्ध सुविधाओं का पूर्ण उपयोग करें ।

यह आश्चर्य की बात है कि वहा की स्थानीय विधान सभा को एक सलाहकार परिषद् के रूप में परिवर्तित क्यों न किया जाता और अनुदान की मांग और अन्य सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक आवश्यकताओं के सम्बन्ध में इसकी सलाह नहीं ली जाती । इस सम्बन्ध में कुछ ठोस सामाजिक कदम उठाये जाने चाहिए ।

मणिपुर की जनता अपने देश के राज्य का दर्जा देने की लगातार मांग करती रही है । माननीय मित्र श्री रामसुभग सिंह ने इस तथ्य की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित किया कि कोई भी मंत्री वहा जाकर वहा की जनता की समस्याओं को समझने का प्रयास अब तक नहीं किया है । वहां जो अफसर भेजे जाते हैं वे सक्षम हैं । क्या सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं दे सकती है कि वहा प्रवीण अफसरों को भेज दिया जाय ताकि वहां की जनता का हित साधन संपन्न हो । उच्चस्तर के अधिकारी वहां जाना क्यों पसन्द नहीं करते हैं ? इसीलिए है कि उन्हें यहां जो भत्ता मिलती है, जो विशेषाधिकार मिलते है, मकान और विद्यालय सम्बन्धी जो सुविधायें मिलती है, वे मणिपुर में उपलब्ध नहीं है । अतः हमारे अफसरों को उस तरफ आकर्षित करने के लिए और वहा की सेवा को अधिकाधिक आकर्षक बनाने के लिए सरकार को कुछ प्रयास करना चाहिए । बाहर के अफसरों पर हमेशा आश्रित रहना उचित नहीं है । जिम्मेदार पदों पर काम करने के लिए स्थानीय लोगों को उसकी ओर आकर्षित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें भी अपनी जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा ।

मणिपुर में हमारी विशेष आरक्षी सेवा गठित की गई है । सेना या विशेष पुलिस दल से आदमी वहां भेजे जाते है । मुझे पता लगा कि उन्हें जो वेतन, भत्ता आदि मिल रहे हैं वे दुखद रूप से अपर्याप्त हैं ।

अतः जो व्यक्ति आर्थिक एवं सामाजिक रूप से दुख पा रहे हैं उनकी सेवा को आकर्षक बनाने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिएं ।

सौभाग्यवश खाद्य की सप्लाई इतनी है कि उससे उनकी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है । जो अतिरिक्त खाद्यान बचता है उसे सरकार बहुत कम मूल्य पर ले लेती है । क्या यह सरकार

के लिए सम्भव नहीं कि वह प्राप्त खाद्य के बदले अधिक धन दे और उस राशि को उन लोगों के स्थानीय एवं सामाजिक विकास के लिए जमा कर दे ?

मनीपुर में पॉलिटेक्नीक एवं मेडिकल कालेज खोलने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिये । मैं नहीं चाहता कि राष्ट्रपति-शासन को हटा दिया जाए क्योंकि इससे पहले की शासन-प्रणाली भी संतोषजनक नहीं थी । मनीपुर सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है । अतः राष्ट्रपति-शासन को 6 मास के लिए और बढ़ा दिया जाए ताकि स्थानीय लोग एवं विधायक अधिक बुद्धिमान एवं योग्य बन सकें ।

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : The area of Manipur is 9 thousand square miles with the population of eleven lakhs. It is a State which has so far maintained its culture, religion and language. It was under British rule during the period of British domination and now it constitutes a heart of India's Republic. These people are not traitors and they do not look for inspiration towards any foreign power as they are too closed to Government of India.

Manipuri is a well developed language and is used for office purposes as well as for education purposes. But no importance has been given to this language in our constitution. On the other hand, importance has been given to Kashmiri language which is neither used in offices nor taught in Primary Classes. Why there is discrimination with the Manipur language.

Nagaland and Meghalya are full fledged states whereas Manipur is still a union territory although it has got more population than the other two states. So Statehood may also be given to Manipur.

Nagaland, which has got a population of 4 lakhs and revenue of 40 lakhs was given grant of 30 crores. On the other hand, Manipur, which has got population of 11 lakhs and revenue of 2 crores, has been given grant of only 14 crores. Why such discrimination is being made ? I do not want that the people of Manipur should adopt destructive methods like Nagas and Mizos.

Manipur is a frontier State. Chinese elements and Naga rebels are very much active there but Government is not paying any attention The people of Manipur are going to Pakistan and China for training purposes. So I want that Manipur should be regarded as full-fledged State and provision of grants should be made immediately.

Manipur territory is cut off from the rest of India and there is only one road that goes to Manipur via Kohima. Since there is unrest in Nagaland, Trucks and Vans are being looted. Regarding airways, there is no regular trip of planes for Manipur.

Unemployment in Manipur is increasing day by day. Government should take steps in this connection. Now industries should be started to check the increasing unemployment. In case, Government do not pay attention towards such problems, it will have to face consequences.

Most of the Manipur's land has been given to Nagaland and underground Government or upper ground Government is having its control on the land. This land should be returned to Manipur Government so that the Government can suppress the activities of Naga rebels.

There should be direct road way between Manipur and Gohati and until this is done there should be facilities of airways which should charge subsidised fare.

I know that efficient administration is functioning under President's rule. But what is required is to win the heart of people of Manipur and that is possible only when full statehood is given to them. This is the only solution that can gave Manipur from becoming next to Nagaland.

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : मनीपुर अब भी केन्द्रशसित प्रदेश है और उसे राज्य का दर्जा नहीं दिया गया । वहां के छात्रों एवं राष्ट्रीय केडट कोर के छात्रों ने गणतन्त्र दिवस नहीं मनाया क्योंकि वे अपने को भारतीय नहीं समझते । वहां पर कोई कारखाना नहीं है । हजारों डाक्टर एवं इन्जीनियर वेकार हैं । अब वहां के लोगों ने हिंसात्मक कारवाईयां करनी प्रारम्भ कर दी है । कुछ लोग प्रशिक्षण पाने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं । लेकिन सरकार ने वहाँ की सभा को भी समाप्त कर दिया है । वहां के कुछ संयुक्त मोर्चे के नेता दिल्ली आए और मांग की कि उन्हें सरकार वनाने की अनुमति दी जाए लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया । वहां की स्थिति तभी सुधर सकती है जब वहां मध्यावधि चुनाव की तिथि की घोषणा कर दी जाए ।

मनीपुर में श्री कोहली को वहां का लेफ्टिनेन्ट गर्वनर बनाकर भेजा गया है परन्तु इससे स्थिति पर नियन्त्रण नहीं किया जा सकता । अतः वहां शांति के अनुकूल वातावरण तैयार करना ही पड़ेगा ताकि उन्हें अनुभव हो कि वे भारत का अंग है । उन्हें राजनीतिक स्वायतता दी जानी चाहिए । मनीपुर के लोग मांग कर रहे हैं कि मनीपुर को राज्य का दर्जा दिया जाए । नागालैंड की जनसंख्या केवल 5 लाख है फिर भी उसे राज्य का दर्जा दे दिया गया है । उधर नागालैंड की जन संख्या 15 लाख है फिर भी उसे राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया ? जब नागालैंड को वित्तीय सहायता दी जाती है तो मणिपुर को भी दी जानी चाहिये । हर प्रदेश के लिए अलग अलग मानदण्ड नहीं होने चाहिए । अतः सर्व प्रथम तो मध्यावधि चुनाव की तिथि घोषित कर दी जाए और दूसरे उसे राज्य का दर्जा दे दिया जाए । मणिपुर के लोग लोकटक परियोजना को क्रियान्वित करने की मांग कर रहे हैं । अगर इसे क्रियान्वित नहीं किया गया तो न तो बाढ़ों को नियन्त्रित किया जा सकता है और न ही बिजली उत्पन्न की जा सकती है । अतः इसे शीघ्र क्रियान्वित किया जाना चाहिये । मणिपुर के कर्मचारियों को वेतनमान आसाम सरकार के वेतनमान के अनुसार दिए जाते हैं । इसी प्रकार मंहगाई भत्ता भी अपर्याप्त है । अतः उन्हें वही वेतन-मान और मंहगाई भता दिया जाना चाहिये जो दिल्ली के कर्मचारियों को दिया जाता है ।

Shri Bhagban Das (Ausgram) : The people of Manipur are demanding for the statehood and mid-term elections but Government is not paying any heed. It seems that it is the policy of Government to take action after the agitation. The demand for Statehood should be accepted immediately.

Manipur is a frontier State and therefore Government should pay attention towards the difficulties of Manipur. The project has been undertaken by Government for the last 4 years but it has not been completed. There should be industrial development in the State. Government should take action to check the increasing unemployment. An amount of Rs. 30.20 crores has been sanctioned by National Development Council but the amount is not sufficient. Government should pay attention towards the development of language. It has been reported that when Prime Minister went to Manipur, firing was resorted to suppress the demands of people of Manipur in which three persons were killed. No problem can be solved this way. Government should consider their demands sympatically and take necessary action.

Government should pay attention towards the development of roads in Manipur.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : An amount of Rs. 64.07 lakhs has been demanded for Manipur. Out of this amount, Rs. 23 09 lakhs have been demanded

for repayment of loans and Rs. 16.86 lakhs have been demanded for the interest. If we go in details about loan and interest, we find that Manipur is being exploited.

In Demand No. 9 certain amount has been demanded for the printing of electrical rolls but nothing has been mentioned about the arrangement of mobile booths.

The demand of Manipur people is that statehood should be given to Manipur. An amount of Rs. 1.82 lakhs has been demanded for the construction of additional jails because there the existing jails are filled to their capacity. What is the condition of the people who are in jail ?

I want that a parliamentary delegation should visit Manipur and summit its report to the House regarding the political demands of full statehood and the measures to be adopted for the development of the state.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Manipur has played an important role in India's freedom struggle. I.N.A. has fought a dicisive battle there. We have witnessed the Chivalrons deeds performed by these national heroes who shed their blood for the sake of the country. I have made this reference simply to stress upon the prtriotism of the inhabitants of Manipur. However there are antinational forces working there. Government should enquire as to how the anti-national feelings have penetrated in the people of that region.

Manipur abounds in natural beauty. That area should be developed to attract more and more tourits. Development of tourism in Manipur may earn a good amount of foreign exchange. Factories should be set up in Manipur. More Roads, Rail and Postal facicities should also be provided in the State so that the people may not complain regarding Transport rnd Communication facilities. The demand of the people of Manipur for full-statehood is justified and should be accepted. The Government should ascertain their grievances and take steps to remove them.

The Government should pay its special attention towards the development of Fisheries, torests and horticulture. I want an expert team be sent such for an on the spot study so fhat required developments might be achieved.

A memorial for Netaji is to be raised in Manipur. We should pay more attention to it. A memorial pillar comemorating the memory of martyrs should also be put up in Manipur and the names of martyrs be inscribed on it.

श्री स० कुन्दू : संसद सदस्यों को भारत के सुन्दर क्षेत्रों विशेषतया सुन्दर संघीय क्षेत्रों को देखने का बहुत कम अवसर प्राप्त होता है । मैं कभी कभी विचार करता हूं कि इन सुन्दर क्षेत्रों को भारत के अन्य भागों के व्यक्तियों तथा संसद-सदस्यों को दृष्टि से ओझल क्यों रखा गया है आजकल इन स्थलों का उपयोग अधिकारी तथा मन्त्रियों द्वारा अपने विनोद के लिये किया जाता है । मेरे विचार से इन स्थलों को देश के व्यक्तियों की दृष्टि से इसलिये ओझल रखा गया है जिससे कि दूसरे व्यक्ति यह न जान सकें कि मन्त्री तथा अधिकारी गठन अपने व्यक्तिगत एश्वर्य में उलझे रहते हैं, राज्य के विकास की इन्हें चिन्ता नहीं ।

पर्यटन की दृष्टि से मणिपुर का उचित विकास होना चाहिए । यदि पर्यटन का विकास किया गया तो मणिपुर केवल करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा ही नहीं कमायेगा अपितु वहां के निवासियों का भारत की बड़ी जनसंख्या से सम्पर्क भी स्थापित करेगा । यदि मणिपुर के देश के अन्य भाग से अलग रखा जायेगा वहां के युवकों के मस्तिष्कों में यह भावना दृढ़ होती जायेगी कि मणिपुर भारत देश का अभिन्न अंग नहीं है और वे अपने को भारतीय संघ से अलग रखने के लिए आन्दोलन प्रारम्भ कर देंगे ।

बहुत दिनों से मणिपुर निवासी पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं । इनकी मांग को सरकार के द्वारा न मानने के कारण को समझ पाना कठिन है । नागालैण्ड जिसकी जनसंख्या 1 तिहाई है उसे पूर्ण राज्य का स्तर मिल गया है । मंत्री महोदय को यह घोषणा कर देनी चाहिए कि 4 अथवा 5 माह के अन्दर मणिपुर को पूर्ण राज्य का स्तर प्रदान कर दिया जायेगा । वहां के लोगों की समस्याओं तथा उनके समाधान के लिए सरकार को एक निकाय की स्थापना करनी चाहिए । आने वाले वर्ष में मणिपुर के प्राक्कलन के लिए प्राक्कलन समिति को निर्दिष्ट कर देना चाहिये और संसद सदस्यों को इस राज्य में नियमित रूप से जाना चाहिये ।

प्रत्येक वर्ष पुलिस पर किया जाना वाला व्यय बढ़ रहा है । 1969-70 में बन्दी ग्रहों पर 278,000 रुपये व्यय किया गया जबकि यह 1970-71 में बढ़कर 534,000 हो गया । इसी प्रकार यदि पुलिस पर किये गये व्यय के आंकड़े ठीक है तो 1969-70 में 2 9 करोड़ से बढ़कर 1970-71 में यह व्यय 3.30 करोड़ हो गया । इससे राज्य में होने वाली हल चल का संकेत मिलता है । वास्तविक समस्या को जानने के लिये गहन अध्ययन अपेक्षित है ।

सरकार को मणिपुर में कुटीर उद्योग तथा हाथ करघा उद्योग को प्राथमिकता प्रदान करते हुए लघु उद्योगों का विकास करना चाहिये । इस कार्यवाही के पश्चात प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तथा लोगों को रोजगार मिल जायेगा ।

Shri Sheo Narain (Basti) ; We must feel proud of Manipur State. The people of Manipur are for more patriotic than the Bengalies of Calcutta. I would like to ask from the Government not to repeat the mistakes made in Tibet. We should not forget that Manipur is like of shield against the inslaught from Pakistan and China.

I would like to request the Government not to play with the interests of Manipur people. The State must be granted full-statehood as early as possible. Nagaland with the population of 5 lakhs has been granted full-statedhood, why it is not being granted to Manipur even then its population goes to 11 lakhs. The demand of the people of Manipur is genuine and the same must be granted at an early date. The Prime Minister is responsible what has happened in Manipur.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker ***in the Chair***]

The Government should pay its attention to the industrial development in Manipur State and also arrange for educational facilities and construction of roads etc Minerals are found in abundance there but the Government does not pay any heed to all that.

The culture of Manipur is Indian culture. Each of the citizen is a true patriot there. Would it not be unwise to ignore such a place where Rama, Krishna and Arjun—the pillars of our culture are worshiped.

Let us make all sorts of efforts for the development of this State. All the condemned officers should be withdrawn here and the people be given employment and their language its proper status. Their educational facilities should also be cared for because Manipur is our Switzerland and another Kashmir.

श्री जी० विश्वनाथन (वन्डी वाश) : मणिपुर के लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । वहां के व्यक्ति बहुत परिश्रमी हैं परन्तु उन्हें उनके परिश्रम का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है । उनके कृषि उत्पादनों तथा फार्म के अन्य उत्पादों की बिक्री के लिए न कोई

बाजार है न रेल की सुविधायें। अतः यहां के लोगों को अपनी वस्तुओं के विक्रय के लिए कलकत्ता तथा देश के अन्य दूसरे बन्दरगाहों पर आना पड़ता है जैसा कि आपको ज्ञात है वहां बहुत से महाजन हैं जो उनकी वस्तुओं को सस्ते मूल्य पर खरीद लेते हैं और कलकत्ता आदि स्थानों पर अधिक मूल्य में बेचते हैं। जब मैं पिछली बार वहां गया था तो वहां के निवासियों ने परिवहन तथा संचार व्यवस्था के विषय में चिन्ता व्यक्त की।

भाषा सम्बन्धी एक दूसरी समस्या है। वहां के निवासी मणिपुर भाषा को संविधान की अनुसूची 8 में समाविष्ट कराना चाहते हैं यहां के अधिकतर निवासी ना ही अंग्रेजी जानते हैं और ना ही अंग्रेजी। वहां के लोग चाहते हैं कि उनकी भाषा को विकसित किया जाय। इसका व्यवहार राज्य भाषा के रूप में होना चाहिये। मणिपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूचित में जोड़ने के लिए एक विधेयक सरकार के समक्ष लंबित है, सभा द्वारा यह पास किया जाना चाहिये। पूर्ण राज्य स्तर की जो मांग की गई है सरकार द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिये। मणिपुर में सुन्दर स्थानों को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास करने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : यह प्रश्न पूछा गया है कि मणिपुर की सभा क्यों भंग की गई। गृह कार्य मन्त्री ने सभा को भंग करने का कारण बता दिया है। मणिपुर के प्रशासन ने 24 सितम्बर 1969 को सभा का सत्रावसान करा दिया। इसके पश्चात् उन्होंने संयुक्त मोर्चे के नेता चुने जाने वाले व्यक्तियों से संघ शासित क्षेत्रो में स्थाई सरकार बनाने की संभावना का निर्धारण करने के लिये बात चीत की। अन्त में निर्णय किया गया कि कोई भी दल मणिपुर में स्थाई सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति ने 16 अक्तूबर, 1969 को एक आदेश जारी किया जिसके अन्तर्गत मणिपुर के विधान मंडल तथा मन्त्री परिषद सम्बन्धी संघ शासित क्षेत्रों की सरकार अधिनियम 1967 की व्यवस्था को एक वर्ष के लिए निलम्बित कर दिया गया और विधान सभा का सत्रावसान कर दिया गया।

हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे सभी संघ शासित क्षेत्र पूर्ण राज्य स्तर की मांग कर रहे हैं और अपने पक्ष के समर्थन में नागालैण्ड का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इस सम्बन्ध में हमारे समक्ष बहुत सी बातें हैं जैसे यदि इन क्षेत्रों को पूर्ण राज्य स्तर प्रदान किया जाता है तो इस सम्बन्ध में प्रशासन सुधार आयोग ने जो मार्ग निदिष्ट किया है उसका अनुसरण किया जाना चाहिये।

जहां तक मणिपुर तथा त्रिपुरा को वित्तीय स्थिति का प्रश्न है, यदि उन्हें पूर्ण राज्य का स्तर प्रदान कर दिया जाता है तो मणिपुर को 60 करोड़ रुपया उन मदों पर व्यय करने के लिए दिया जायेगा जो योजना के अन्दर समाविष्ट नहीं है। त्रिपुरा को इसी प्रकार की दी जाने वाली राशि 48 करोड़ होगी। ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिनपर विचार करना आवश्यक है।

पूर्ण राज्य स्तर प्रदान करने का निर्णय गृह-कार्य मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री द्वारा किया जा सकता है यह मेरा विषय क्षेत्र नहीं है।

यह कहा गया है, कि वहाँ के निवासियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है तथा

बन्दी गृहों में जन संख्या बढ़ रही है। विभिन्न राजनैतिक दलों की एक कार्यकारी समिति बनाई गई और उन्होंने पूर्ण राज्य स्तर के लिए आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। इस आन्दोलन की अवधि में 521 व्यक्ति बन्दी बनाये गये जिन्हें कुछ समयोपरान्त छोड दिया गया। यह सच है कि कुछ व्यक्तियों को बन्दी गृहों में रखा गया इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वहां के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। कानून और व्यवस्था को भी दृष्टि में रखना होता है तथा कानून के अतिक्रमण की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

मणिपुर के विकास के लिए तीसरी योजना की अवधि में योजना व्यय 12.87 करोड़ था तथा चौथी योजना की अवधि में यह व्यय 30.25 हो गया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मणिपुर के विकास के लिये योजना व्यय में वृद्धि की गई है।

जहां तक अनाज के मूल्यों का प्रश्न है, इन्हें कृषि मूल्य आयोग के सुझावों के अनुसार निश्चित किया जाता है। जो भी मूल्य निश्चित किया जाता है वह बाजार के मूल्य की अपेक्षा अधिक ही होता है।

यह कहा गया है कि वहां अयोग्य तथा अशिक्षित कर्मचारी ही भेजे जाते हैं स्थानी प्रतिभा को उचित अवसर नहीं दिया जाता। अब परिस्थिति भिन्न है। 19,000 सरकारी अधिकारियों में से केवल 50 प्रतिनियुक्ति पर हैं। स्थानीय प्रतिभा को सेवाओं में पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है और केवल उन्हीं प्रशिक्षित तथा अनुभवी अधिकारियों को वहां भेजा जाता है जिन्हें वहां भेजना आवश्यक समझा जाता है। लोकटक पन-बिजली परियोजना के विषय में कहा गया है। इसके लिये 10 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है और परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

यह भी कहा गया है कि इस क्षेत्र में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। 1970-71 में यहां खांडसारी मिल चालू की जा रही है। एक सीमेंट फैक्टरी चालू करने का भी प्रस्ताव है।

यह कहना कि स्थानीय भाषा को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है बल्कि उसकी उपेक्षा की जा रही है उचित नहीं है विभिन्न पुस्तकों तथा साहित्यिक पत्रिकाओं के प्रकाशकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

यह कहा गया कि मणिपुर में कर्मचारियों के वेतन के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 6 मार्च 1970 को गृह-कार्य मन्त्री ने इस सदन में कहा था कि मणिपुर तथा अन्य सभी संघ शासित क्षेत्रों के कर्मचारियों को दिल्ली प्रशासन द्वारा दिये जाने वाले वेतन तथा भत्ते दिये जायेंगे। अतः इस ओर पूरा ध्यान दिया जा रहा है।

यह कहा गया है कि पुलिस व्यय काफी बढ़ रहा है। कारण यह है कि हमने मणिपुर में नियत राज्य सरकार की पुलिस बटैलियन की व्यवस्था के लिए धनराशि बढ़ाई। मद्रास के स्थान पर मध्यप्रदेश की जो पुलिस बैटालियन मणिपुर में है, संशोधित प्रबन्धों के अनुसार इनका व्यय मणिपुर सरकार को ही वहन करना है। इस कारण से भी व्यय में वृद्धि हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें मतदान के लिए रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं ।

The following supplementary demands in respect of union Territory Manipur were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
9	संसद, राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों के विधान मण्डल	82,000
12	जेल	1,82,000
16	चिकित्सा	3,00,000
25	सिंचाई	1,00,000
26	बिजली	4,50,000
31	पेंशन और सेवा निवृत्ति सम्बन्धी अन्य लाभ	1 86,000
37	सिंचाई के छोटे कार्यों पर पूंजी परिव्यय	82,000
42	सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय	4,00,000
48	ऋण और अग्रिम	7,00,000

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र को निम्नलिखित अनुदानों की मांगें मतदान के लिये रखी गयी तथा स्वीकृत हुई ।

The following demands for grants in respect of union Territory Manipur were put and adopted.

मांग संख्या 1	शीर्षक 2	राशि 3
		रुपये
1	भूराजस्व	18,00,000
2	राज्य उत्पादन शुल्क	2,00,000
3	मोटर गाड़ियों पर कर	1,20,000
4	बिक्री कर	1,06,000
5	अन्य कर और शुल्क	3,000
6	स्टाम्प	25,000
7	रजिस्ट्रेशन	72,000
8	संसद, राज्य और संघीय राज्य क्षेत्रों के विधान मण्डल	12,45,800
9	सामान्य प्रशासन	77,29,600
10	न्याय प्रशासन	4,25,000

1	2
11 जेलें	5,34,000
12 पुलिस	3,29,87,000
13 नागरिक पूर्ति	2,40,000
14 शिक्षा	4,18,01,000
15 चिकित्सा	56,88,000
16 लोक स्वास्थ्य	32,72,000
17 कृषि और मीन क्षेत्र	42,70,000
18 पशु पालन	19,29,400
19 सहकारिता	10,24,000
20 उद्योग	18,20,900
21 सामुदायिक विकास	22,80,000
22 श्रम	3,90,000
23 अंक संकलन	5,90,000
24 सिंचाई	4,50,000
25 बिजली	52,49,000
26 लोक निर्माण कार्य (मूल निर्माण कार्य और मरम्मत)	72,00,000
27 लोक निर्माण कार्य (प्रतिष्ठान)	1,42,32,700
28 सड़क परिवहन	62,00,000
29 दुर्भिक्ष सहायता	1,00,000
30 पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	4,06,000
31 लेखन सामग्री और मुद्रण	6,50,000
32 बन	14,20,000
33 विविध	51,41,000
ऋणों सहित पूंजी खाते से व्यय	
34 लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	10,00,000
35 छोटे सिंचाई कार्यों पर पूंजी परिव्यय	5,50,000
36 बाढ़ नियंत्रण पर पूंजी परिव्यय	13,00,000
37 बिजली पर पूंजी परिव्यय	80,53,000
38 सड़कों पर पूंजी परिवय	1,60,00,000

1	2	3
39	इमारती पर पूंजी परिव्यय	1,26,40,000
40	सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय	12,00,000
41	राज्य व्यापार पर पूंजी परिव्यय	2,08,29,000
42	उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	14,50,000
43	सहकारिता पर पूंजी परिव्यय	4,93,000
44	ऋण और अग्रिम	30,00,000

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1969-70 की सेवाओं के लिए मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग को अधिकार देने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1969-70 की सेवाओं के लिए मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग को अधिकार देने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री प्र० चं० सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि वित्तीय वर्ष 1969-70 की सेवाओं के लिए मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र को संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

Shri George Fernandes (Bombay South) : I rise on a point of order. It is saie that Speaker can prevent anybody to speak if he thinks that arguments will be repeated. I want to tell you that I have not spoken on the demands of Manipur and assure that I shall not repeat anything which had alre dy been said. I want to tell you that the people of Manipur are pressing that the status of Manipur should be raised to that of full state, but I do not want to say any more in this regard. I want to draw the attention of the House that our Army has harassed the people and this is evident by the Statement given by a ex-development Minister Shri K. Anwoy.

I want to quote his words. He said :

"I was shocked and pained that the authorities could hide facts about the atrocities of the Army in Uksal area. It is necessary for me to give you some more details of the serious instances so that you may kindly pursue the matter in your own way. But I want to make it clear that the replies of the Defence Minister are far from correct and I can challenge the distorted facts given by him."

By your permission I want to lay on the Table his original report. In the end I demand that the hon. Defence shoul d clarify his statement in this matter.

श्री प्र० चं० सेठी : मेरी सूचना के अनुसार इस मामले की पूरी जांच की गई है तथा पाया गया है कि आरोपों को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है परन्तु फिर भी इस बारे में आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"वित्तीय वर्ष 1969-70 की सेवाओं के लिए मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जावे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 तथा 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 2 तथा 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये
Clauses 2 and 3, Schedule, Clause 1 the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री प्र० चं० सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

मणिपुर विनियोग (संख्या 2) विधेयक
MANIPUR APPROPRIATION (NO 2) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1970-71 की सेवाओं के लिए मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1970-71 की सेवाओं के लिए मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का आधार देने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री प्र० चं० सेठी : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विनियोग विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विनियोग विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 तथा 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 2 तथा 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का विधेयक में जोड़ दिए गए

Clause 2 and 3, the Schedule, Clause 1, the Ehacting Formula and the Title were then added to the Bill

श्री प्र० चं० सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये !"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अनुदानों की माँगें (रेलवे) 1970-71

DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS) 1970-71

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन में वर्ष 1970-71 के बजट (रेलवे) संबंधी अनुदानों की मांगें पर चर्चा तथा मतदान किया जायेगा ।

अनुदानों की मांगों पर बहुत बड़ी संख्या में कटौती प्रस्ताव हैं अतः इच्छुक माननीय सदस्य 15 मिनट तक पर्ची भेज दें।

रेलवे की मांगों [मंत्रालय] सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए

मांग संख्या 1	कटौती संख्या 2	प्रस्तावक का नाम 3	कटौती का आधार 4	कटौती की राशि 5
1	18	**श्री श्रीचन्द गोयल :**	रेलवे बोर्ड की उपयोगिता	100 रु०
2	19	**श्री श्रीचन्द गोयल :**	दिल्ली-अम्बाला लाइन की करनाल होकर दुहरी लाइन बनाने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण करने में असफलता।	,,
2	20	**श्री श्रीचन्द गोयल :**	पानीपत-गोहाना लाइन के सर्वेक्षण को फिर से शुरू करने में असफलता।	,,
9	21	**श्री श्रीचन्द गोयल :**	विभागीय खान-पान व्यवस्था की बिगड़ती हुई दशा।	,,
9	22	**श्री श्रीचन्द गोयल :**	दीवानी मुकदमों के सम्बन्ध में किया गया अत्यधिक खर्च।	,,
10	23	**श्री श्रीचन्द गोयल :**	सभी वर्गों के कर्मचारियों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने में सरकार की असफलता।	,,
10	24	**श्री श्रीचन्द गोयल :**	चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक पाठशाला की व्यवस्था करने में सरकार की असलता।	,,
10	25	**श्री श्रीचन्द गोयल :**	वाणिज्यिक क्लर्कों को वर्दियां प्रदान करने में सरकार की असफलता।	,,
10	26	**श्री श्रीचन्द गोयल :**	चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों के लिए एक औषधालय की व्यवस्था करने में सरकार की असफलता।	,,
13	27	**श्री श्रीचन्द गोयल :**	चण्डीगढ़ में कर्मचारियों के पर्याप्त क्वार्टरों का निर्माण करने में सरकार की असफलता।	,,
14	28	**श्री श्रीचन्द गोयल :**	पानीपत-गोहाना लाइन को फिर से शुरू करने में सरकार की असफलता।	,,
14	29	**श्री श्रीचन्द गोयल :**	चण्डीगढ़ को मुख्य लाइन पर लाते हुए लुधियाना—जगाधरी रेलवे लाइन का निर्माण करने में सरकार की असफलता।	,,

1	2	3	4	5
1	33	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	रेलवे बोर्ड के सदस्यों के अधिकारों को कम करने में असफलता ।	100 रु०
1	34	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	रेलवे बोर्ड द्वारा कर्मचारियों की याचिकाओं पर समय पर विचार किया जाना सुनिश्चित करने में असफलता ।	,,
1	35	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	रेलवे कर्मचारियों के प्रति रेलवे बोर्ड द्वारा सहानुभूति पूर्ण रवैया अपनाने में असफलता ।	,,
1	36	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	रेलवे बोर्ड द्वारा की गई फिजूलखची को रोकने में असलफता ।	,,
1	37	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	रेलवे बोर्ड में अफसरशाही और लाल-फीताशाही रोकने में असफलता ।	,,
1	38	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	उच्च अधिकारियों तथा साधारण कर्मचारियों के वेतन और सेवा सम्बन्धी शर्तों में भारी विषमता दूर करने में असफलता ।	,,
1	39	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	रेलवे बोर्ड के उच्च स्तरीय अधिकारियों पर किया जाने वाला फिजूलखर्च रोकने में असफलता ।	,,
1	40	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	रेलवे प्रशासन में उच्च स्तरीय अधिकारियों की संख्या कम करने में असफलता ।	,,
1	41	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	रेलवे बोर्ड में प्रशासनिक कुशलता लाने में असफलता ।	,,
1	42	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	रेलवे बोर्ड के तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को मौलिक सुविधाओं सुनिश्चित करने में असफलता ।	,,
2	66	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	पूर्वोत्तर रेलवे पर साहिबगंज और केसरी होकर हाजीपुर और लालगंज के बीच एक नई लाइन निकालने के लिए सर्वेक्षण शुरू करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
2	67	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	पूर्वोत्तर रेलवे पर छपरा और मोतीहारी के बीच एक शाखा लाइन निकालने के लिए सर्वेक्षण शुरू करने में असफलता ।	,,
2	68	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	पूर्वोत्तर रेलवे पर गोरखपुर तथा नरकटियागंज के बीच एक नई सीधी सम्पर्क लाइन निकालने के लिए सर्वेक्षण शुरू करने में असफलता ।	,,
2	69	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	पूर्वोत्तर रेलवे पर मेहसी तथा सीतामही के बीच एक नई सीधी लाइन निकालने के लिए सर्वेक्षण शुरू करने में असफलता	,,
2	70	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	पूर्वोत्तर रेलवे पर मुजफ्फर होकर समस्तीपुर और नरकटियागंज के बीच एक चौड़ी लाइन के निर्माण करने में असफलता ।	,,
2	71	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	पूर्वोत्तर रेलवे पर उराज की और मोतीहारी और छपरा के बीच एक नई शाखा लाइन निकालने की सम्भाव्यता का पता लगाने में असफलता ।	
2	72	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	विदेशी पदाधिकारियों के स्वागत तथा आतिथ्य पर फिजूलखर्च को रोकने में असफलता ।	,,
2	73	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	रेलवे में स्वचालन को शुरू करने के कारण छंटनी को बंद करने में असफलता ।	,,
2	74	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	रेलवे कर्मचारियों के लिए मुजफ्फरपुर स्थित प्रशिक्षण विद्यालय का उचित उपयोग करने में असफलता ।	,,
2	75	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	पूर्वोत्तर रेलवे डिवीजनल मुख्यालय का मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर स्थानांतरण करने के कारण प्रशासनिक क्षति को रोकने में असफलता ।	,,
2	76	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	विदेशों की तरह दुर्घटनाओं के फिर से शुरू किए जाने में कम से कम देरी करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
2	77	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	रेल सेवाओं में सुधार के लिए रेलवे सम्बन्धी अनुसंधान कार्य के परिणामों को लागू करने में असफलता ।	100 रु०
5	78	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	पूर्वोत्तर रेलवे पर सांगली जंकशन का विकास करने में असफलता ।	,,
5	79	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	पूर्वोत्तर रेलवे पर चकिया स्टेशन में शेड की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
5	80	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	पूर्वोत्तर रेलवे पर चकिया स्टेशन और बाजार को मिलाने वाले रेलवे मार्ग को उठाने और मरम्मत करने में असफलता ।	,,
5	81	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	पूर्वोत्तर रेलवे पर मेहसी स्टेशन और शहर के बाजार के बीच की रेलवे सड़क को पक्की करने में असफलता ।	,,
5	82	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	पूर्वोत्तर रेलवे पर मोतीपुर और मेहवल स्टेशनों आदि में प्रतीक्षालयों के विस्तार करने तथा उनकी मरम्मत करने में असफलता ।	,,
5	83	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	पूर्वोत्तर रेलवे पर पिपरा स्टेशन में प्रतीक्षालयों के विस्तार करने तथा मरम्मत करने में असफलता ।	,,
6	84	श्री श्रीचन्द गोयल :	वाणिज्यिक (कमर्शियल) क्लर्कों के वेतनमानों और भत्तों को बढ़ाने में असफलता ।	,,
6	85	श्री श्रीचन्द गोयल :	रेलवे गार्डों के वेतनमान और भत्तों में वृद्धि करने में असफलता ।	,,
6	86	श्री श्रीचन्द गोयल :	स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों की मांगों को पूरा करने में असफलता ।	,,
6	87	श्री श्रीचन्द गोयल :	वाणिज्यिक (कमर्शियल) क्लर्कों की श्रेणी में वर्णान्धों के आने पर रोक लगाने में असफलता ।	,,
6	88	श्री श्रीचन्द गोयल :	वाणिज्यिक (कमर्शियल) की पदोन्नति के कोटे में वृद्धि करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
6	89	श्री श्रीचन्द गोयल :	रेलवे सुरक्षा बल द्वारा वाणिज्यिक (कमर्शियल) क्लर्कों को परेशान करने से रोकने में असफलता ।	100 रु०
9	92	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	रेलवे द्वारा भेजे गये माल की चोरी और उठाईगिरी की क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में अदायगी की रकम में वृद्धि को रोकने में असफलता ।	,,
9	93	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	रेलवे यात्रियों की सुरक्षा करने में सरकार की असफलता ।	,,
9	94	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	रेलवे में विभागीय भोजन व्यवस्था सम्बन्धी सेवा की खराबी को रोकने में सलफलता ।	,,
9	95	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	रेलवे यात्रा के दौरान हुए जख्मी यात्रियों को उपयुक्त क्षतिपूर्ति मन्जूर करने में असफलता ।	,,
14	116	श्री श्रीचन्द गोयल :	दिल्ली के चारों ओर उपनगरीय रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण करने में विफलता ।	,,
14	117	श्री श्रीचन्द गोयल :	भारी यातायात की मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली रेलवे लाइनों का निर्माण करने में विफलता ।	,,
16	118	श्री श्रीचन्द गोयल :	चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन को सुधारने में विफलता ।	,,
16	119	श्री श्रीचन्द गोयल :	चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक जलपान-गृह खोलने में विफलता ।	,,
16	120	श्री श्रीचन्द गोयल :	रेलवे द्वारा भोजन के स्तर को सुधारने में विफलता ।	,,
16	121	श्री श्रीचन्द गोयल :	सभी वर्गों के रेलवे कर्मचारियों की पेन्शन राशि में पर्याप्त वृद्धि करने में सरकार की विफलता ।	,,
1	156	श्री वेणीशंकर शर्मा :	कर्मचारियों की भूल के कारण हुई दुर्घटनाओं को रोकने से प्रशासन की असफलता ।	,,

1	2	4	4	5
1	157	श्री वेणीशंकर शर्मा :	प्रशासन में मितव्ययता करने में असफलता ।	100 रु०
1	158	श्री वेणीशंकर शर्मा :	परिहार्य तथा अनावश्यक व्यय को रोकने में असफलता ।	,,
1	159	श्री वेणीशंकर शर्मा :	बड़े-बड़े यार्डों में सामान की चोरी तथा उठाईगिरी रोकने में असफलता ।	,,
1	160	श्री वेणीशंकर शर्मा :	माल-गाड़ियों के देरी से चलाने को रोकने में असफलता जिससे इंजनों और चल-स्टाक का कम उपयोग होता है और रेक अनावश्यक तौर पर रुका रहता है ।	,,
1	161	श्री वेणीशंकर शर्मा :	अनावश्यक सामान की विवेकहीन खरीद को रोकने में असफलता जिससे स्टाक जड़ अथवा आवश्यकता से अधिक हो जाता है ।	,
1	162	श्री वेणीशंकर शर्मा :	खरीदे गये माल की कम प्राप्ति तथा बेचे गये माल को अधिक सप्लाई करने के दुराचारों को रोकने में असफलता ।	,,
1	163	श्री वेणीशंकर शर्मा :	रेलवे वर्कशापों में 'ओ' किस्म के डिब्बों के दोषपूर्ण निर्माण के कारण अतिरिक्त व्यय ।	,,
1	164	श्री वेणीशंकर शर्मा :	अनुपयुक्त मसीनी स्टोकरों के निर्माण से हुई हानि ।	,,
1	165	श्री वेणीशंकर शर्मा :	बिना टिकट यात्रा को रोकने में असफलता ।	,,
1	166	श्री वेणीशंकर शर्मा :	मजदूरों तथा कर्मचारियों में ड्यूटी तथा उत्तरदायित्व की भावना पैदा करने में पर्यवेक्षी कर्मचारियों की असफलता ।	,,
1	167	श्री वेणीशंकर शर्मा :	रेल-गाड़ियों में डिब्बों तथा जुड़नारों के उचित रख-रखाव की कमी ।	,,
2	171	श्री वेणीशंकर शर्मा :	बरहत स्टेशन पर बंका आउट एजेंसी के लिए गाड़ी के समय पर बसों के न होने के कारण यात्रियों को होने वाली असुविधा ।	,

1	2	3	4	5
3	172	श्री वेणीशंकर शर्मा :	पटना को जाने वाली गाड़ी में जो मन्दर-हिल स्टेशन से सुबह जाती है, एक सीधी बोगी जोड़ने की आवश्यकता जिसे भागल-पुर जंकशन में अपर इंडिया एक्सप्रैस में जोड़ दिया जाये ।	100 रु०
8	173	श्री वेणीशंकर शर्मा :	(पूर्व) रेलवे की भागलपुर मन्दरहिल शाखा पर बरहत स्टेशन और बंका आउट ऐजेंसी के बीच अनियमित बस सेवा ।	,,
8	174	श्री वेणीशंकर शर्मा :	अपर इंडिया एक्सप्रैस के सम्बन्ध में समय सारणी में परिवर्तन करने की आवश्यकयता जिससे यह सियालदह स्टेशन पर 10.30 बजे सुबह की बजाये 6.00 बजे सुबह पहुँच जाये ।	,,
9	175	श्री वेणीशंकर शर्मा :	अपर इंडिया एक्सप्रैस तथा दीनापुर तेज सवारी गाड़ी समेत साहिबगंज चाप (लूप) लाइन पर चलने वाली गाड़ियों में पर्याप्त रोशनी तथा पंखों की कमी ।	,,
13	176	श्री वेणीशंकर शर्मा :	दीनापुर तेज सवारी गाड़ी को बरास्ता चाप (लूप) लाइन चलाना तथा इसे एक्सप्रैस गाड़ी बनाना ।	,,
14	177	श्री वेणीशंकर शर्मा :	भागलपुर मन्दरहिल शाखा के बरास्ता संथाल परगना विस्तार की आवश्यकता ।	,,
14	178	श्री वेणीशंकर शर्मा :	चाप (लूप) लाइन होकर हावड़ा-बरौनी सवारी गाड़ी के समस्तीपुर तक विस्तार की आवश्यकता ।	,,
14	179	श्री वेणीशंकर शर्मा :	खेत्री तांबा परियोजना को रेलवे लाइन द्वारा मिलाने के लिये रेलवे लाइन के निर्माण में असफलता ।	,,
14	180	श्री वेणीशंकर शर्मा :	बिहार में संथाल परगना के मुख्यालय दुम्का को, जो एक बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और जहां संथाल जन जातियों की आबादी है,	,,

1	2	3	4	5
			इस क्षेत्र के लोगों द्वारा लगातार मांग किये जाने के बावजूद, रेलवे लाइन द्वारा मिलाने में असफलता ।	
14	181	श्री वेणीशंकर शर्मा :	भागलपुर-मन्दरहिल शाखा को इस प्रकार मोड़ने की आवश्यकता जिस से यह बंका से होकर जाये, जो इस क्षेत्र का सब-डिवीजन कस्बा है और जिस क्षेत्र से होकर लाइन मुख्यतः जाती है ।	100 रुपये
2	262	श्री श्रद्धाकर सूपकार :	विमलगढ़ और तालचेर के बीच रेलवे लाइन के लिए इंजीनियरी एवं यातायात सम्बन्धी सर्वेक्षण करने में विलम्ब ।	,,
4	263	श्री श्रद्धाकर सूपकार :	रेल गाड़ियों के चलने में अनियमितता और देरी ।	1 रु०
4	264	श्री श्रद्धाकर सूपकार :	रेल किराये तथा भाड़े में तेजी से वृद्धि ।	,,
4	265	श्री श्रद्धाकर सूपकार :	सुरक्षा संगठन—दोहरी पुलिस लगाना ।	,,
4	266	श्री श्रद्धाकर सूपकार :	रेलवे सुरक्षा संगठन में कुशलता की कमी ।	100 रु०
6	278	श्री श्रद्धाकर सूपकार :	परिचालन कर्मचारियों में कार्यकुशलता का अभाव ।	1 रु०
6	282	श्री श्रद्धाकर सूपकार :	बिना टिकट यात्रा को रोकने में असमर्थता :	100 रु०
6	283	श्री श्रद्धाकर सूपकार :	रेलवे सम्पत्ति का नष्ट किया जाना तथा चुराया जाना ।	,,
9	284	श्री श्रद्धाकर सूपकार :	गाड़ियों में यात्रियों के लिए सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता जिनमें खाने की चीजें सुलभ करना और रोशनी का प्रबन्ध करना भी शामिल है ।	,,
14	286	श्री श्रद्धाकर सूपकार :	उड़ीसा में छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में शीघ्र बदलने की आवश्यकता ।	,,
9	289	श्री आ० कु० गोपालन :	रेलवे द्वारा भोजन व्यवस्था के अन्तर्गत दिये जाने वाले खाद्यपदार्थों की कीमत घटाने में विफलता ।	100 रु०

1	2	3	4	5
9	290	श्री आ० कु० गोपालन :	पैकेट बन्द खाद्य पदार्थों को सस्ती दर पर देने में विफलता ।	100 रु०
9	299	श्री सी० के० चक्रपाणि :	त्रिचूर, दक्षिण रेलवे पर रेलवे स्टेशन का एक नए भवन का निर्माण कराने में विफलता ।	,,
9	300	श्री प० गोपालन :	दक्षिण रेलवे में कोटिकुलम रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म तैयार करने में विफलता ।	,,
9	301	श्री प० गोपालन :	ग्रांड ट्रंक एक्सप्रैस और सदर्न एक्सप्रैस में नई दिल्ली से मंगलोर तक शायिका वाला रेल डिब्बा लगाने में विफलता ।	,,
9	302	श्री प० गोपालन :	दक्षिण रेलवे में पुरुर रेलवे स्टेशन पर प्लेट-फार्म तैयार करने में विफलता ।	,,
14	303	श्री सी० के० चक्रपाणि :	एरणाकुलम से त्रिवेन्द्रम तक मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने में विफलता ।	,,
14	306	श्री प० गोपालन :	कुट्टिपुरम-गुरुवयूर-ग्रंगनोर-एरणाकुलम रेलवे—तटवर्ती रेलवे (दक्षिण रेलवे) का निर्माण करने की आवश्यकता ।	,,
14	307	श्री प० गोपालन :	एरणाकुलम-एलेंप्पी (दक्षिण रेलवे) लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता ।	,,
14	308	श्री प० गोपालन :	तेल्लिचेरी-मैसूर लाइन (दक्षिण रेलवे) का निर्माण करने की आवश्यकता ।	,,
1	349	श्री रामावतार शास्त्री :	रेलवे बोर्ड को समाप्त करने में विफलता ।	1 रु०
1	350	श्री रामावतार शास्त्री :	रेलवे बोर्ड की मजदूर-विरोधी नीति ।	,,
1	351	श्री रामावतार शास्त्री :	रेलवे बोर्ड के नाम पर डेढ़ करोड़ रुपये से भी अधिक धनराशि का दुरुपयोग ।	,,
1	352	श्री रामावतार शास्त्री :	रेलवे बोर्ड के अधिकारियों की ऊंची-ऊंची तनख्वाहों को कम करने में विफलता ।	
1	353	श्री रामावतार शास्त्री :	रेलवे बोर्ड पर होने वाले खर्चे में कमी करने में विफलता ।	100 रु०

1	2	3	4	5
1	354	श्री रामावतार शास्त्री :	रेलवे बोर्ड के सदस्यों के नौकरशाही रुख को सुधारने में विफलता ।	100 रुपये
1	355	श्री रामावतार शास्त्री :	रेलवे बोर्ड की सार्थकता और औचित्य ।	,,
2	356	श्री रामावतार शास्त्री :	बिहार में खगोललख से देहरी-आन सोन के साथ-साथ एक नई रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए सर्वेक्षण करने की आवश्यकता ।	,,
2	357	श्री रामावतार शास्त्री :	विक्रम-पालीगंज-अखाल-कुरका होकर बिहटा से जहानाबाद तक एक नई रेलवे लाइन के निर्माण की आवश्यकता ।	,,
2	358	श्री रामावतार शास्त्री :	इस्लामपुर होकर जहानाबाद से बिहार शरीफ तक एक नई रेलवे लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता ।	,,
1	394	श्री रामावतार शास्त्री :	तीसरे दर्जे के यात्रियों पर टिकट दर बढ़ाने की जन-विरोधी नीति ।	1 रु०
1	395	श्री रामावतार शास्त्री :	अफसर बोझिल प्रशासन ।	
1	400	श्री किरुतिनन :	रेलवे के किराये और भाड़े की दरों में प्रस्तावित वृद्धि को समाप्त करने की आवश्यकता ।	100 रु०
1	401	श्री किरुतिनन :	तीसरे दर्जे के यात्रियों को उचित सुविधायें देने की आवश्यकता ।	,,
1	402	श्री किरुतिनन :	दिल्ली से मद्रास तक की जनता एक्सप्रेस में डीजल इंजन लगाने की आवश्यकता ।	,,
4	403	श्री किरुतिनन :	दिल्ली से मद्रास तक की जनता एक्सप्रेस में तीसरे दर्जे के और डिब्बे लगाने की आवश्यकता ।	,,
1	404	श्री किरुतिनन :	दिल्ली से मद्रास तक चलने वाली जी० टी० एक्स-प्रेस और लिंक एक्सप्रेस के समय को कम न करना ।	,, 100 रु०
1	405	श्री किरुतिनन :	दक्षिण रेलवे में अरुप्पुकोटई मनमदुरै तिरुची और कार्ड से होते हुए विरुदुनगर से मद्रास तक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
1	406	श्री किरुतिनन :	दक्षिण रेलवे में मदुरै से रामेश्वरम तक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने की आवश्यकता ।	100 रु०
1	407	श्री किरुतिनन :	जिन लोगों ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल में भाग लिया उनके सेवा प्रावधान को हटाने की आवश्यकता ।	,,
1	408	श्री किरुतिनन :	दक्षिण और दक्षिण केन्द्रीय-रेलवे में उन 16 फायरमैनों को बहाल न करना जिन्हें फायरमैनों को आन्दोलन में भाग लेने के कारण सेवा से हटा दिया गया है अथवा निलम्बित कर दिया गया है जबकि उस समय के रेल मन्त्रियों ने भी इस बारे में आश्वासन दिये थे ।	,,
1	409	श्री किरुतिनन :	अखिल भारतीय वाणिज्यिक क्लर्क संस्था की मांगों पर विचार न करना ।	,,
1	410	श्री किरुतिनन :	रेलवे के ए० एस० एस० योग्यता प्राप्त कर्मचारियों की मांगों पर विचार न करना ।	,,
1	411	श्री किरुतिनन :	रेलवे कर्मचारियों विशेषतया तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वास्तविक शिकायतों को दुर न करना ।	,,
1	483	श्री किरुतिनन :	उप-परिपत्र को जिसमें रेलवे कर्मचारियों को हिंदी में अर्हता प्राप्त करने के लिए बाध्य किया गया है, वापस लेने की आवश्यकता ।	,,
1	484	श्री किरतिनन :	राजभाषा के नाम पर खर्च किये जाने वाले धन की बर्बादी ।	,,
1	485	श्री किरुतिनन :	रेलवे कर्मचारियों के लिए अलग से एक वेतन आयोग नियुक्त करने या वर्तमान वेतन आयोग को रेलवे कर्मचारियों के बारे में विशेष और अलग प्रतिवेदन देने के लिए कहने की आवश्यकता ।	,, ,,
1	486	श्री किरुतिनन :	डी०ए०आर० को बदलने की आवश्यकता ताकि रेलवे कर्मचारी अपने मामलों के बारे में श्रम न्यायाधिकरण से अपील कर सकें ।	,,
1	487	श्री किरुतिनन :	चतुर्थ श्रेणी यातायात कर्मचारियों और ट्राली-चालकों को जोखिम भत्ता देने में विफलता ।	,,

1	2	3	4	5
1	500	श्री जी० विश्वनाथन :	चिंगलपट से चिन्ना सेलम तक रेलवे लाइन बिछाने की आवश्यकता ।	100 रु०
1	501	श्री जी० विश्वनाथन :	वालाजाहपेट से तिंडीवनम तक एक रेलवे लाइन बिछाने की आवश्यकता ।	,,
1	502	श्री जी० विश्वनाथन :	अरकोनामांड और मद्रास के बीच रेलवे लाइन का विद्युतीकरण करने की आवश्यकता ।	,,
10	532	श्री किरुतिनन :	वाणिज्यिक क्लर्कों के वेतनमानों को बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
10	533	श्री किरुतिनन :	जांच समितियों के बजाये स्थायी प्रशासनिक न्यायाधिकरण नियुक्त करने की आश्यकता जो न्यायिक प्राधिकारियों के अधीन हों ।	,,
10	534	श्री किरुतिनन :	चालित लाइन और अत्यावश्यक कर्मचारियों के लिए किराये से मुक्त क्वार्टर देने की आवश्यकता ।	,,
10	535	श्री किरुतिनन :	उन भवनों से, जिनका 1953 के पश्चात् निर्माण हुआ है, बिजली लगाने के प्रभारों की वसूली को रोकने की आवश्यकता चूंकि नक्शे और लागत में बिजली लगाने की लागत भी शामिल थी ।	,,
10	536	श्री किरुतिनन :	रेल कर्मचारियों के लिए आधुनिक आधार पर विस्तृत स्वास्थ बीमा योजना तैयार करने की आवश्यकता ।	,,
10	537	श्री किरुतिनन :	सचिवीय श्रेणी के पदों पर लगाये प्रतिबन्ध को हटाने की आवश्यकता।	,,
10	538	श्री किरुतिनन :	रनिंग कर्मचारियों को सख्त कार्य करने वाले कर्मचारी वर्गीकृत करने की आवश्यकता, यात्रा को ड्यूटी समझना और मुख्यालय पर 16 घण्टे का विश्राम देने की आवश्यकता ।	,,
1	539	श्री किरुतिनन :	सभी आकस्मिक श्रमिकों को नियमित रेल कर्मचारी बनाने की आवश्यकता ।	,,
10	540	श्री किरुतिनन :	सभी गेंगमैनों को 5 रुपये प्रतिमास का मेहनत दैनिक भत्ता देने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
10	541	श्री किरुतिनन :	बीमारी के कारण जिन कर्मचारियों को वैकल्पिक कार्य नहीं दिया जा सकता और उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत कर दिया जाता है उन्हें एक मुश्त मुआवजा देने की आवश्यकता ।	100 रु०
10	542	श्री किरुतिनन :	दक्षिण रेलवे में मदुरै में रेलवे मिश्रित स्कूल में उस समय के मंत्री द्वारा मंजूर किये गये अतिरिक्त कक्षाओं को आरम्भ न करना ।	,, ,,
14	543	श्री किरुतिनन :	तमिलनाडु में नई रेल लाइनों के निर्णय की मंजूरी न देना ।	,, ,,
14	544	श्री किरुतिनन :	तमिल नाडु में करूर, डिडीगुल, मदुरै, मनियाची और ट्टोकोरीन के बीच बड़ी लाइन के निर्माण में अत्यधिक विलम्ब ।	,, ,,
14	545	श्री किरुतिनन :	तमिल नाडु में तिरुनेलवेली नागरकोयल, कन्या-कुमारी और त्रिवेन्द्रम के बीच रेलवे लाइन के निर्माण में अत्यधिक विलम्ब ।	,, ,,
14	546	श्री किरुतिनन :	तमिल नाडु मेंचिंगलपेट और चित्तासेलम के बीच रेल लाइन का निर्माण न करना ।	,, ,,
14	547	श्री किरुतिनन :	बड़ी लाइन पर अन्तिम स्टेशन मद्रास सेन्ट्रल और छोटी लाइन पर अन्तिम स्टेशन मद्रास एगमोर को ना मिलाना, जिससे पूरे दक्षिण रेलवे में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर माल लाने ले जाने की लागत को कम से कम किया जा सके ।	,, ,,
14	548	श्री किरुतिनन :	मद्रास शहर में बिजलों से चलने वाली वृत्ताकार रेलवे लाइन के लिये प्राक्कलन तैयार करने का प्रस्ताव पेश करने में असफलता ।	,, ,,
2	549	श्री किरुतिनन :	रेलवे तक जाने वाली सड़कों का उचित रख-रखाव न करना ।	,, ,,
2	550	श्री किरुतिनन :	दक्षिण रेलवे के परमाकुड़ी स्टेशन को जाने वाली रेलवे सड़क पर डामर डालने का काम समय पर पूरा न करना ।	,, ,,
2	551	श्री किरुतिनन :	दक्षिण रेलवे में पम्बन और धनुषकोटि के बीच उखाड़ी गई रेलवे लाइन फिर से न बनाना ।	,, ,,

1	2	3	4	5
2	552	श्री किरुतिनन :	दक्षिण रेलवे में मनमदुरै विरुधुनगर लाइन पर मनमदुरै के निकट ऊपरी पुल का निर्माण पूरा न करना ।	100 रु०
3	553	श्री किरुतिनन :	मितव्ययता लाने की आवश्यकता ।	,, ,,
3	554	श्री किरुतिनन :	दक्षिण रेलवे में वाणिज्यिक क्लर्कों की संख्या में कमी करने की रोकने की आवश्यकता ।	,, ,,
3	555	श्री किरुतिनन :	रेलवे सुरक्षा बल में की गई अनावश्यक वृद्धि ।	,, ,,
3	556	श्री किरुतिनन :	प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के मामले में किफायत बर्तने की आवश्यकता ।	,, ,,
3	557	श्री किरुतिनन :	दक्षिण रेलवे मनमदुरै, क्विलोन और तिरुनेलवेली जंकशनों पर पृथक टिकटघर बनवाने की आवश्यकता ।	,, ,,
2	597	श्री किरुतिनन :	तमिलनाडु में आरनतंकी, तोंडी रामाराथपुरम और तूतिकोरन के बीच तटवर्ती रेलवे लाइन के लिये सर्वेक्षण करने में विफलता ।	,, ,,
2	598	श्री किरुतिनन :	तमिलनाडु में बारास्ता इलायन गुडी तोंडी और मानमदुराई के बीच एक रेलवे लाइन के लिये सर्वेक्षण करने में विफलता ।	,, ,,
2	599	श्री किरुतिनन :	तमिलनाडु में मानमदुराई और तूतिकोरन के बीच एक रेलवे लाईन के लिये सर्वेक्षण करने में विफलता ।	,, ,,
2	600	श्री किरुतिनन :	दक्षिण रेलवे के करनाईकुडी—मानमदुराई लाईन पर शिवगंगा कालिज के निकट एक फ्लेग स्टेशन की व्यवस्था करने में विफलता ।	,, ,,
2	601	श्री किरुतिनन :	दक्षिण रेलवे के तिरूपूवनम और तुपाचेरी रेलवे स्टेशनों के बीच पप्पमकुलम ग्राम के निकट कर्मचारी रहित रेलवे फाटक बनाने में विफलता ।	,, ,,
2	602	श्री किरुतिनन	दक्षिण रेलवे की मनमदुराई लाइन पर राजागन बीरन के निकट एक फ्लेग स्टेशन की व्यवस्था करने में विफलता ।	,, ,,
1	608	श्री रामावतार शास्त्री :	दानापुर में सभी रेलवे कर्मचारियों को क्वार्टर देने में विफलता ।	

1	2	3	5
1	609	**श्री रामावतार शास्त्री :** दानापुर रेलवे स्टेशन पर रिलीविंग कर्मचारियों के ठहरने का कोई प्रबन्ध न होना ।	100 रु०
1	610	**श्री रामावतार शास्त्री :** चूँकि पूर्व रेलवे के नेउरा स्टेशन पर मालगाड़ियां लगातार खड़ी रहती हैं इसलिये वहां पर यात्रियों को आरपार जाने के लिये लकड़ी का एक ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता ।	,,
1	611	**श्री रामावतार शास्त्री :** पूर्व रेलवे के नेउरा स्टेशन पर एक पार्सल घर खोलने की आवश्यकता ।	,,
1	612	**श्री रामावतार शास्त्री :** दानापुर रेलवे स्टेशन पर वर्तमान ऊपरी पुल को चौड़ा करने में विफलता ।	
1	613	**श्री रामावतार शास्त्री :** दानापुर रेलवे स्टेशन पर विश्राम गृह बनाने की आवश्यता ।	,,
1	614	**श्री रामावतार शास्त्री :** 427 अप बरौनी दानापुर सवारी गाड़ी को आरा स्टेशन तक बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
1	615	**श्री रामावतार शास्त्री :** 4 8 डाऊन दानापुर-बरौली सवारी गाड़ी की दानापुर के बजाय आरा स्टेशन से चलाने की आवश्यकता ।	,,
1	616	**श्री रामावतार शास्त्री :** पी० जी० लाइन पर स्थित नरवान स्टेशन पर प्लेटफार्म को ऊंचा करने, पेय जल का प्रबन्ध करने और शेडों का निर्माण करने की आवश्यकता ।	,,
1	617	**श्री रामावतार शास्त्री :** पी० जी० लाइन पर स्थित परसा स्टेशन पर शेडों का निर्माण करने और प्लेटफार्म को ऊंचा करने की आवश्यकता ।	,,
1	618	**श्री रामावतार शास्त्री :** पी० जी० लाइन पर स्थित फुलवारी शरीफ स्टेशन पर प्लेटफार्म को ऊंचा करने की आवश्यकता :	,,
1	619	**श्री रामावतार शास्त्री :** बख्तियारपुर और राजगीर रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली गाड़ियों में पानी की कमी और रोशनी की अपर्याप्त व्यवस्था की कठिनाई को दूर करने में विफलता ।	,,

1	2	3	4	5
4	620	श्री रामावतार शास्त्री :	रेलवे के इन्जीनियरों कर्मचारी की न्यायोचित मांगों को स्वीकार करने में विफलता ।	100 रु०
4	621	श्री रामावतार शास्त्री :	लोको मैकेनिकल कर्मचारियों की मांगों को, जो इंडियन रेलवे लोको मैकेनिकल स्टाफ एसोसियेशन द्वारा प्रस्तुत की गई है, मानने में विफलता ।	,,
4	622	श्री रामावतार शास्त्री :	आल इण्डिया रेलवे मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसियेशन की मांगों को स्वीकार करने में विफलता ।	,,
4	623	श्री रामावतार शास्त्री :	आल इण्डिया रेलवे मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसियेशन की धनवाद साखा द्वारा प्रस्तुत की गई चार सूत्री मांगें पूरा करने की आवश्यकता ।	,,
4	624	श्री रामावतार शास्त्री :	अखिल भारतीय रेलवे फेडरेशन द्वारा रेलवे कर्मचारियों की 28 सूत्री मांगे मानने में विफलता ।	,,
4	625	श्री रामावतार शास्त्री :	अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर एसोसियशन द्वारा प्रस्तुत की गई मांगों को स्वीकार करने में विफलता ।	,,
5	626	श्री रामावतार शास्त्री :	पटना-गया रेलवे लाइन (पूर्व रेलवे) को दोहरा करने में विफलता ।	,,
5	627	श्री रामावतार शास्त्री :	उत्तरी बिहार की छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने में विफलता ।	,,
5	628	श्री रामावतार शास्त्री :	रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों की कमी को दूर करने में विफलता ।	,,
5	629	श्री रामावतार शास्त्री :	रेलवे सम्पत्ति की चोरी को रोकने में विफलता ।	,,
5	630	श्री रामावतार शास्त्री :	रेलवे सम्पत्ति की चोरी में जिन उच्च अधिकारियों का हाथ है उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में विफलता ।	,,

1	2	3	4	5
5	631	श्री रामावतार शास्त्री :	रेलवे कर्मचारियों के सभी क्वार्टरों में पंखे लगाने की आवश्यकता ।	,,
1	650	श्री रामावतार शास्त्री :	दानापुर लोको शैड में सीमेंट का फर्श डालने की आवश्यकता ।	100 रू०
1	651	श्री रामावतार शास्त्री :	पूर्व रेलवे में न्योड़ा स्टेशन पर प्लेटफार्म को ऊंचा करने की आवश्यकता ।	,,
1	652	श्री रामावतार शास्त्री :	पूर्व रेलवे में पटना जंकशन से 5.30 बजे सांय छूटने वाली 387 अप गाड़ी चलाने की आवश्यकता ।	,,
1	653	श्री रामावतार शास्त्री :	पटना-गया लाईन पर ऐसी एक गाड़ी चलाने की आवश्यकता जो पटना जंकशन पर 6 बजे प्रातः पहुंचे ।	,,
1	654	श्री रामावतार शास्त्री :	पटना जंकशन से मुगलसराय यात्री गाड़ी छूटने का समय 3.15 से बदल कर 4.30 बजे सांय करने की आवश्यकता ।	,,
1	655	श्री रामावतार शास्त्री :	पूर्व रेलवे में बख्तयारपुर स्टेशन के टिकट घर को सुविधाजनक स्थान पर खोलने की आवश्यकता क्योंकि इस समय यह बहुत दूर स्थित है ।	,,
1	656	श्री रामावतार शास्त्री :	गाड़ियों को समय पर न चलाना और न ही उनका देर से चलना रोकना ।	,,
1	657	श्री रामावतार शास्त्री :	पूर्व रेलवे में बख्तयारपुर से राजगीर के बीच गाड़ियां समय पर न चलने से यात्रियों को असुविधा और विभाग को 15 लाख रुपये की वार्षिक आय की हानि ।	,,
1	658	श्री रामावतार शास्त्री :	पूर्व रेलवे में न्योड़ा स्टेशन के दोनों प्लेटफार्मों पर छत बनाने की आवश्यकता ।	,,
1	659	श्री रामावतार शास्त्री :	पूर्व रेलवे में बेहटा स्टेशन पर तूफान मेल और वाराणसी एक्सप्रैस रोकने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
1	660	श्री रामावतार शास्त्री :	अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर संघ को मान्यता देने की आवश्यकता ।	100 रु०
1	661	श्री रामावतार शास्त्री :	भारतीय रेलवे लोको मैकनीकल कर्मचारी संघ को मान्यता देने की आवश्यकता ।	
1	662	श्री रामावतार शास्त्री :	अखिल भारतीय रेलवे सचिवीय कर्मचारी संघ को मान्यता देने की आवश्यकता ।	,,
1	663	श्री रामावतार शास्त्री :	अखिल भारतीय रेलवे स्विचमैन कैबिनमैन और लोवरमैन संघ को मान्यता देने की आवश्यकता ।	,,
1	664	श्री रामावतार शास्त्री :	अखिल भारतीय गार्ड परिषद् को मान्यता देने की आवश्यकता ।	,,
1	665	श्री रामावतार शास्त्री :	अखिल भारतीय रनिंग स्टाफ एसोशियेशन को मान्यता देने की आवश्यकता ।	,,
1	666	श्री रामावतार शास्त्री :	पूर्व रेलवे मजदूर सभा को मान्यता देने की आवश्यकता ।	,,
1	667	श्री रामावतार शास्त्री :	पूर्व रेलवे के दानापुर डिवीजन के डिवीजनल सुपरिटेन्डेन्ट के श्रमिक विरोधी रवये को बन्द न करना ।	,,
1	668	श्री रामावतार शास्त्री :	पूर्व रेलवे के दानापुर डिवीजन के डिवीजनल सुपरिटेन्डेन्ट को दानापुर और गया के गार्डों को तंग करने की नीति का अन्त न करना ।	,,
1	669	श्री रामावतार शास्त्री :	भारतीय रेलों में काम कर रही विभागीय संघों और संस्थाओं को मान्यता न देना ।	,,
1	670	श्री रामावतार शास्त्री :	भारतीय राष्ट्रीय रेल कर्मचारी महासंघ को मान्यता समाप्त न करना ।	,,
1	671	श्री रामावतार शास्त्री ।	पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे स्थाई मार्ग निरीक्षक तथा सहायक स्थाई मार्ग निरीक्षक संस्था को मान्यता देने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
1	672	श्री रामावतार शास्त्री :	विभागीय (श्रेणीवार) संघों और संस्थानों की मांगें स्वीकार न करना ।	100 रु०
1	673	श्री रामावतार शास्त्री :	रेलवे में स्वचालित यन्त्रों का प्रयोग बन्द करने की आवश्यकता ।	,,
1	674	श्री रामावतार शास्त्री :	कुंजरू रेलवे दुर्घटना जांच समिति, 1962 की सिफारिशों को पूरी तरह लागू करने में असफलता ।	,,
1	675	श्री रामावतार शास्त्री :	वांचू रेलवे दुर्घटना जांच समिति. 1968-69 की सिफारिशों को पूरी तरह लागू करने में असफलता ।	,,
1	676	श्री रामावतार शास्त्री :	रेलवे द्वारा श्रम कानूनों के उल्लंघन को रोकने में असफलता ।	,,
6	677	श्री रामावतार शास्त्री :	स्थानापन्न श्रमिकों को विनियमित करने में असफलता ।	,,
6	678	श्री रामावतार शास्त्री :	स्थानापन्न श्रमिकों को पूरे समय के लिए काम देने में असफलता ।	,,
6	679	श्री रामावतार शास्त्री :	1966 के बाद भर्ती किये गये स्थापन्न श्रमिकों के सम्बन्ध में डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट द्वारा जारी किये गये छंटनी के आदेशों को रद्द करने की आवश्यकता।	,,
6	680	श्री रामावतार शास्त्री :	जो कर्मचारी रेलवे में 10 से 12 वर्ष तक की नौकरी पूरी कर चुके हैं उन्हें स्थानापन्न कर्मचारियों के रूप में रखने की नीति को समाप्त करने में असफलता ।	,,
6	681	श्री रामावतार शास्त्री :	रेलवे में नैमित्तिक श्रमिकों की नौकरियों की स्थाई करने में असफलता ।	
6	682	श्री रामावतार शास्त्री :	गैंगमैनों की कठिनाइयों को दूर करने में असफलता ।	

1	2	3	4	5
6	683	श्री रामावतार शास्त्री :	परमानेन्ट वे इन्सपैक्टरों और असिस्टैन्ट परमानेन्ट वे इन्सपैक्टरों से सम्बन्धित वांचू समिति की सिफारिशों के पैरा 291(1) को लागू करने में असफलता ।	100 रु०
6	684	श्री रामावतार शास्त्री :	पब्लिक वे इन्सपैक्टरों और असिस्टैन्ट पब्लिक वे इन्सपैक्टरों को औजार देने के बारे में बांचू समिति की सिफारिशों के पैरा 527 को लागू करने में असफलता ।	,,
6	685	श्री रामावतार शास्त्री :	वांचू समिति की सिफारिशों के पैरा 105 (एक, दो, तीन और चार) को लागू करने में असफलता, अर्थात् परमानेन्ट वे इन्सपैक्टरों और असिस्टेन्ट परमानेन्ट वे इन्सपैक्टरों की स्थिति और प्राधिकार की पुनःस्थापना करके उन्हें प्रबन्धकों में कनिष्ट सदस्य के रूप में माना जाना चाहिए ।	,,
6	686	श्री रामावतार शास्त्री :	पब्लिक वे इन्सपैक्टरों और असिस्टैन्ट पब्लिक वे इन्सपैक्टरों के सम्बन्ध में वांचू समिति की सिफारिशों के पैरा 210-213 को लागू करने में असफलता ।	,,
6	687	श्री रामावतार शास्त्री :	गैंगमैनों की संख्या और उनके रहन-सहन की दशाओं से सम्बन्धित वांचू समिति की सिफारिशों के पैरा 250-252 को लागू करने में असफलता ।	
6	688	श्री रामावतार शास्त्री :	पब्लिक वे इन्सपैक्टरों और असिस्टैन्ट पब्लिक वे इन्सपैक्टरों से सम्बन्धित वांचू समिति की सिफारिशों के पैरा 278-279 (एक, दो और तीन) को लागू करने में असफलता ।	,,
1	689	श्री गणेश घोष :	सवारी गाड़ियों में रोशनी की उपयुक्त व्यवस्था करने में विफलता ।	
1	690	श्री गणेश घोष :	सवारी गाड़ियों के शौचालयों में पानी की उपयुक्त व्यवस्था करने में विफलता ।	

1	2	3	4	5
1	691	श्री गणेश घोष :	रेलगाड़ियों को विशेष रूप से डाक और एक्सप्रैस गाड़ियों को समय पर चलाने में विफलता ।	100 रु०
1	692	श्री गणेष घोष :	सवारी रेल डिब्बों में पेय जल देने में विफलता ।	,,
1	693	श्री गणेश घोष :	रेलवे स्टेशनों पर पेय जल की पर्याप्त सुविधा देने में विफलता ।	,,
1	694	श्री गणेश घोष :	स्टेशनों पर भोजनयानों और भोजन घरों में दिये जाने वाले खाद्य पदार्थों की कीमत घटाने में विफलता ।	,,
1	695	श्री गणेश घोष :	पूर्व रेलवे के डमडम जंकशन और बनगांव के बीच दोहरी लाइनें बिछाने के लिए रेलवे प्रशासन की अनिच्छा ।	,,
1	696	श्री सूरज भान :	अम्बाला सिटी और जगाधरी रेलवे स्टेशनों पर कोई रेलवे रेस्तरां की व्यवस्था करने में विफलता ।	,,
1	697	श्री सूरज भान :	अम्बाला सिटी और जगाधरी रेलवे स्टेशनों पर रेलवे प्रतीक्षालयों, स्नानगृहों और शौचालयों को साफ तथा स्वच्छ रखने में विफलता ।	,,
1	698	श्री सूरज भान :	जनता के लगातार अभ्यावेदनों के बावजूद भी अम्बाला सिटी और सहारनपुर से सुबह को एक अतिरिक्त सवारी गाड़ी और इन स्टेशनों तक सुबह को एक अतिरिक्त सवारी गाड़ी चलाने में विफलता ।	,,
1	698-क	श्री सूरज भान :	जनता की आवश्यकता के अनुसार अम्बाला सिटी और सहारनपुर के बीच सवारी गाड़ियों के समय को समंजित करने में विफलता ।	,,
1	699	श्री सूरज भान :	अम्बाला सिटी और सहारनपुर के बीच यात्रियों के भारी यातायात को सम्भालने के लिए डीजल शटल रेल गाड़ी चलाने में विफलता ।	,,
1	700	श्री सूरज भान :	अम्बाला सिटी और अम्बाला केन्ट रेलवे स्टेशनो के बीच एक फ्लेग रेलवे स्टेशन खोलने में विफलता ।	,,
1	701	श्री सूरज भान :	रेलवे स्टेशनों पर बुक स्टालों के मामले में एकाधिकार को समाप्त करने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
1	702	श्री सूरज भान :	तीसरे दर्जे के यात्रियों के वर्तमान बढ़े हुए किरायों को घटाकर जन साधारण को कोई राहत देने में विफलता ।	100 रु०
1	703	श्री सूरज भान :	तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए न्यूनतम सुविधाएं देने में विफलता ।	,,
1	704	श्री सूरज भान :	तीसरे दर्जे में यात्री किरायों को घटाने के लिए किराए और भाड़े के ढांचे को युक्त संगत बनाने में विफलता ।	,,
1	705	श्री सूरज भान :	रेल दुर्घटनाओं को रोकने में विफलता ।	,,
1	706	श्री सूरज भान :	रेल दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के सम्बन्ध में पर्याप्त मुआवजा देने में विफलता ।	,,
1	707	श्री गणेश घोष :	सेवाओं के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आरक्षित कोटा पूरा करने में विफलता ।	,,
1	708	श्री गणेश घोष :	सरकार के स्थायी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को पदोन्नत करने में विफलता ।	,,
1	709	श्री गणेश घोष :	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सरकारी कर्मचारियों को लगातार सताना रोकने में विफलता ।	,,
1	710	श्री गणेश घोष :	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के सेवा रिकार्ड को जान-बूझकर खराब करना रोकने में विफलता ।	,,
1	711	श्री गणेश घोष :	रेलवे विभाग में विभिन्न रूप में चल रही अस्पृश्यता के तरीकों को समाप्त करने में विफलता ।	,,
1	712	श्री गणेश घोष :	सभी विभागीय पदोन्नति अथवा चुनाव समितियों में एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के अधिकारी को शामिल करने के आदेश जारी करने में विफलता ।	100 रु०
1	713	श्री गणेश घोष :	प्रशासनिक खर्चों में मितव्यथा बरतने में विफलता ।	,,

1	2	3	4	5
1	714	श्री गणेष घोष :	स्टोरों, वर्कशापों और बड़े यार्डों में चोरी को रोकने में विफलता ।	100 रु०
1	715	श्री गणेश घोष :	रेलवे अधिकारियों द्वारा सैलूनों का उपयोग किया जाना रोकने में विफलता ।	,,
1	716	श्री गणेश घोष :	उच्च अधिकारियों तथा साधारण कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों में व्यापक विषमता कम करने में विफलता ।	,,
1	717	श्री गणेश घोष :	ठेका मजदूरों के बारे में नीति ।	,,
1	718	श्री गणेश घोष :	काम का भार बढ़ने के बाद भी तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में झूठे मितव्ययता के नाम पर छंटनी को रोकने की आवश्यकता ।	,,
1	719	श्री गणेश घोष :	1960 की आम हड़ताल में भाग लेने वाले रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध सेवा सम्बन्धी की गयी सभी दाण्डिक कार्यवाही को वापस लेने की आवश्यकता ।	,,
1	720	श्री गणेश घोष :	तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी पदों का दर्जा बढ़ाने के लिए ताकि इन संवर्गों में अवरोध दूर हो सके, गत बजट सत्र में दिये गये आश्वासन को पूरा करने में विफलता ।	,,
1	721	श्री गणेश घोष :	निम्न श्रेणी के रेल कर्मचारियों को और पोर्टरों को उत्तम आवास सुविधा सुलभ करने में विफलता ।	,,
1	722	श्री गणेश घोष :	कर्मचारियों को पूरे उपकरण देने में विफलता ।	,,
1	723	श्री गणेश घोष :	रेलवे कर्मचारियों के लिए कल्याण सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता ।	
1	724	श्री गणेश घोष :	रेलवे बोर्ड की श्रमिक विरोधी नीति ।	,,
1	725	श्री गणेश घोष :	राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों को अन्य विशेष भत्तों की तरह ही विशेष मरुस्थलीय भत्ता देने की आवश्यकता ।	,,
1	726	श्री गणेश घोष :	आकस्मिक श्रमिकों को क्वार्टर, जूते और वरदी देने में विफलता ।	,,

1	2	3	4	5
1	727	श्री गणेश घोष :	1968 सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने के कारण कर्मचारियों के विरुद्ध चलाये गये मुकदमे वापिस लेने में विफलता ।	100 रु०
1	128	श्री गणेश घोष :	रेलवे बोर्ड को समाप्त करके एक स्वायत्तशासी रेलवे निगम बनाने में विफलता ।	,,
1	731	श्री गणेश घोष :	कलकत्ता वृत्ताकार रेलवे के विद्युतीकरण तथा विभिन्न रेल विभागों में अन्य विद्युतीकरण परियोजनाओं में रेलवे विद्युतीकरण यूनिट के फालतू और छटनी किये गये कर्मचारियों को नौकरी न देना ।	1 रु० ,, ,, ,,
1	732	श्री गणेश घोष :	रेलवे विद्युतीकरण यूनिट के कर्मचारियों के प्रति युक्तियुक्त और उचित नीति न अपनाना, जिनमें से बहुत से कर्मचारियों को न्याय के लिए न्यायालयों में जाना पड़ा है ।	,,
1	733	श्री गणेश घोष :	बढ़ती हुई मंहगाई के अनुसार मंहगाई भत्ता न देना ।	
1	734	श्री गणेश घोष :	सभी भारतीय रेल विभागों में स्टेट यूनियनों को बैलट द्वारा मान्यता देने की नीति को स्वीकार न करना ।	,,
1	735	श्री गणेश घोष :	19 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने के कारण कर्मचारियों को दिये गये सभी प्रकार के दण्ड को वापिस लेने और रद्द करने में असफलता ।	,,
1	736	श्री गणेश घोष :	रेलवे बोर्ड को समाप्त करने में असफलता ।	,,
1	737	श्री गणेश घोष :	लम्बी दूरी की गाड़ियों के साथ डिब्बे लगाने से पहले उसमें लगाये गये पुर्जों की जांच न करना ।	,,
1	738	श्री गणेश घोष :	लम्बी दूरी की गाड़ियों में यात्री डिब्बों में हटाये गये पंखों और बिजली के बल्बों को पुनः न लगाना ।	,,
1	739	श्री गणेश घोष :	तीसरे दर्जे के यात्रियों की सुविधाओं और आराम के प्रति रेलवे प्रशासन की उदासीनता ।	

1	2	3	4	5
1	740	**श्री गणेश घोष :**	उत्तर रेलवे में कोच अटैंडेंट को कैरेज एण्ड वैगन डिपार्टमेंट के अधीन रखना जिससे उनकी भावी पदोन्नति और सेवा लाभ को काफी हानि पहुँचती है, जबकि अन्य सभी रेल विभागों में कोच अटेन्डेन्ट वाणिज्यिक विभाग के अधीन काम करते हैं ।	1 रु०
1	741	**श्री गणेश घोष :**	रेलवे विद्युतीकरण यूनिट के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी के पदों के लिए पदोन्नति की पर्याप्त सुविधायें न देना ।	,,
1	742	**श्री गणेश घोष :**	किसी विद्युतीकरण परियोजना के पूरा हो जाने पर चालित लाइन को सौंपे दिये जाने के पश्चात् रेलवे विद्युतीकरण यूनिट के बहुत से अनुभवी कर्मचारियों की पदोन्नति करना और उनकी छंटनी कर देना तथा उनके स्थान पर रख रखाव के लिए नए कर्मचारियों की भर्ती करना ।	
1	743	**श्री जी० विश्वनाथन :**	रेलवे बोर्ड को समाप्त न करना ।	,,
1	744	**श्री जी० विश्वनाथन :**	प्रादेशिक स्वायत्त रेलवे निगम गठित करने में असफलता ।	,,
1	747	**श्री भोगेन्द्र झा :**	पुरबोस्सर रेल मजदूर सभा को पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों के प्रतिनिधि संघ के रूप में मान्यता न देना ।	,,
1	748	**श्री भोगेन्द्र झा ।**	समय-समय पर जनमत संग्रह द्वारा प्रतिनिधि संघों को मान्यता न देना ।	,,
1	749	**श्री भोगेन्द्र झा :**	प्रबन्ध में कर्मचारियों द्वारा भाग लेना सुनिश्चित न करना ।	,,
1	750	**श्री भोगेन्द्र झा :**	तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण न करना ।	,,
1	751	**श्री जी० विश्वनाथन :**	कटपोड़ी और जलारपेट जंकशनों पर वृन्दावन एक्सप्रैस की सीटों की संख्या को न बढ़ाना ।	,,
1	752	**श्री जी० विश्वनाथन :**	मद्रास और बंगलौर के बीच गाड़ियों का विद्युतीकरण न करना ।	,,

1	2	3	4	5
1	753	श्री सूरज भान :	रेलवे के कर्मचारियों को आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी देने में असफलता ।	1 रु०
1	754	श्री सूरज भान :	तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रेल कर्मचारियों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधायें देने में असफलता ।	,,
1	755	श्री सूरज भान :	रेल कर्मचारियों के लिए पृथक मजूरी बोर्ड न बनाना ।	,,
1	756	श्री सूरज भान :	भारतीय रेल मजदूर संघ और इसके सम्बद्ध संघों को मान्यता न देना।	,,
1	757	श्री सूरज भान :	रेल कर्मचारियों के 90 प्रतिशत भाग को भी आवास न देना ।	,,
1	758	श्री सूरज भान :	उत्तर रेलवे में आधुनिक सिगनलों को व्यवस्था न करना ।	,,
1	771	श्री सूरज भान :	रेलगाड़ियों का ठीक समय पर चलना सुनिश्चित करने में असफलता ।	100 रु०
1	772	श्री सूरज भान :	उत्तरी प्रदेश में विद्युत चालित रेलगाड़ियां चलाने में असफलता ।	,,
1	773	श्री सूरज भान :	रेलवे कर्मचारियों द्वारा अपने घरेलू उपयोग के लिए कोयला और इमारती लकड़ी की चोरी को रोकने में असफलता ।	,,
1	774	श्री सूरज भान :	रेलवे प्रशासन के सभी विभागों से बढ़ते हुये भ्रष्टाचार को समाप्त करने में असफलता ।	,,
1	775	श्री सूरज भान :	दिल्ली रेलवे डिवीजन को दो भागों में बांटने और नये डिवीजन के मुख्यालय को अम्बाला में खोलने में असफलता ।	,,
1	776	श्री सूरज भान :	अम्बाला और सहारनपुर के बीच दिन के समय किसी नई डाकगाड़ी को चलाने अथवा किसी डाकगाड़ी का मार्ग बदल कर इस मार्ग से चलाने में असफलता ।	,,
1	777	श्री सूरज भान :	अम्बाला छावनी और दुखेरी उ० रे० स्टेशनों के बीच में छीआनाला पर रेलवे पुल को चौड़ा करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
5	794	श्री सूरज भान :	उत्तर रेलवे में चलती हुई गाड़ियों में बत्तियों का बारबार बुझ जाना ।	10 रु०
14	805	श्री सूरज भान :	जगाधरी और लुधियाना के बीच, बरास्ता चण्डीगढ़ एक नई रेलवे लाइन का निर्माण करने में असफलता ।	,,
14	806	श्री सूरज भान :	अम्बाला और दिल्ली के बीच, बरास्ता करनाल, दोहरी लाइन बनाने में असफलता ।	,,
14	807	श्री सूरज भान :	बराड़ा और नाहन (हिमाचल प्रदेश) के बीच एक नई लाइन के निर्माण के लिये सर्वेक्षण करने में असफलता ।	,,
1	860	श्री रामावतार शास्त्री :	रेलवे सम्पत्ति की बड़े पैमाने पर हो रही चोरी को रोकने में असफलता ।	1 रु०
1	861	श्री रामावतार शास्त्री :	रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिये कुँजरु समिति तथा वांचू समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने में असफलता ।	,,
1	862	श्री रामावतार शास्त्री :	रेलवे अधिकारियों को दी गई सैलून सम्बन्धी सुविधाओं को वापस लेने में असफलता ।	,,
1	863	श्री रामावतार शास्त्री :	रेलगाड़ियों को समय पर चलाने में विलम्ब को रोकने में असफलता ।	,,
1	911	श्री गणेश घोष :	रेलवे विद्युतीकरण यनिट के सभी तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके वर्तमान वेतन, श्रेणी तथा पद के अनुसार, किसी विशिष्ट विद्युतीकरण परियोजना के समाप्त हो जाने पर, नई लाइनों के निर्माण में नौकरी देने में विफलता ।	,,
1	912	श्री गणेश घोष :	किसी विशिष्ट विद्युतीकरण परियोजना के पूरा हो जाने पर, रेलवे विद्युतीकरण यूनिट के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को अपनी वर्तमान श्रेणी और वेतन में जारी रहने के लिये अपनी क्षमता की जांच हेतु चयन समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिये बाध्य करना ।	,,

1	2	3	4	5
1	913	श्री गणेश घोष :	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अंतर्गत सिलीगुड़ी में स्थित डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर के वर्तमान कार्यालय को कटिहार में स्थानान्तरित करने की नीति का निरनुमोदन ।	1 रु०
1	914	श्री गणेश घोष :	उन नैमित्तिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जिन्होंने रेलवे विद्युतीकरण संगठन में गत दस वर्षों से निरन्तर सेवा की है, कोई नियमित वेतनमान देने में विफलता ।	,,
1	915	श्री गणेश घोष :	रेलवे विद्युतीकरण संगठन में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा में हर तीसरे महीने व्यवधान पैदा करना ताकि वे लोग नियमित वेतनमान के लिये कोई दावा करने से वंचित रह जायें ।	,,
1	916	श्री गणेश घोष :	किसी विद्युतीकरण परियोजना के मुख्यालय को इस उद्देश्य से स्थानान्तरित करना कि उस परियोजना में काम करने वाले रेलवे विद्युतीकरण कर्मचारी दैनिक भत्ते का कोई दावा करने से वंचित रहें ।	,,
1	917	श्री गणेश घोष :	धीरे चलने वाली यात्री गाड़ियों में तीसरे दर्जे के रेल डिब्बों में यात्रियों को सुविधायें विशेष रूप से रोशनी और जल की सुविधा देने में विफलता जो कि पश्चिमी बंगाल के इलाकों में क आम बात हो गई है ।	100 रु०
1	920	श्री रामावतार शास्त्री :	रेल दुर्घटनाओं के संदर्भ में कर्मचारियों की चूक को दूर करने के लिए उपचारी उपाय करने की आवश्यकता ।	,,
1	921	श्री रामावतार शास्त्री :	सभी रेल कर्मचारियों को विशेष वेतन देने की आवश्यकता ।	
1	922	श्री रामावतार शास्त्री :	नये वेतनमानों में वेतन निर्धारित करके स्टेशन मास्टरों, सहायक स्टेशन मास्टरों तथा अन्य रेल कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं को ध्यान में रखना ।	,,

1	2	3	4	5
1	923	श्री रामावतार शास्त्री :	विवाद के सम्बद्ध किसी भी दल की इच्छा पर स्थाई समझौता तंत्र और अनिवार्य मध्यस्थता की आवश्यकता ।	100 रु०
1	924	श्री रामावतार शास्त्री :	सभी कर्मचारियों को निःशुल्क आवास और किराया भत्ता देने की आवश्यकता ।	,,
1	925	श्री रामावतार शास्त्री :	सभी कर्मचारियों के लिए 8 घण्टे से अनधिक कार्य और समयोपरि भत्ता निश्चित करने की आवश्यकता ।	,,
1	926	श्री रामावतार शास्त्री :	पूर्वी रेलवे की दानापुर डिवीजन के कतिपय रेल कर्मचारियों के विरुद्ध निलम्बन, आदेशों, आरोप पत्रों को रद्द न करना ।	,,
1	927	श्री रामावतार शास्त्री :	पूर्वी रेलवे की दानापुर डिवीजन के कुछ कर्मचारियों को बीमारी के दौरान पूरा प्रतिकर और पूरा वेतन देने की आवश्यकता ।	,,
1	928	श्री रामावतार शास्त्री :	पूर्वी रेलवे में मुगल सराय और दानापुर में हुए हाल ही के अन्दोलन मे जिन लोको-कर्मचारियों ने भाग लिया उनको उपस्थित दिखाने की आवश्यकता ।	,,
6	929	श्री रामावतार शास्त्री :	स्टेशन मास्टरों, सहायक स्टेशन मास्टरों तथा अन्य रेल कर्मचारियों को राजनीतिक अधिक कर देने की आवश्यकता ।	
6	930	श्री रामावतार शास्त्री :	स्टेशन मास्टरों ओर सहायक स्टेशन मास्टरों को मुख्य कार्यालय नियंत्रक पदों और अन्य पदों के बारे में उचित स्थानान्तरण नियम बनाने की आवश्यकता ।	
6	931	श्री रामावतार शास्त्री :	स्टेशन मास्टरों, सहायक स्टेशन मास्टरों और अन्य रेल कर्मचारियों को सरकारी छुट्टियां देने की आवश्यकता ।	

1	2	3	4	5
6	932	श्री रामावतार शास्त्री :	रेलवे लेखा क्लर्क ग्रेड II की वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति न करना ।	100 रु०
6	933	श्री रामावतार शास्त्री :	लेखा क्लर्कों के अप्रेन्टिस दो एक परीक्षा को समाप्त न करना और उन्हें अप्रेन्टिस तीन-एक परीक्षा में सीधे न बैठने देना ।	,,
6	934	श्री रामावतार शास्त्री :	लेखा क्लर्क-ग्रेड II की वरिष्ठता के आधार पर सब II हैड (वेतनमान 210-380) के पद पर पदोन्नति न करना ।	,,
6	635	श्री रामावतार शास्त्री :	स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के बारे में 15वें श्रम सम्मेलन, 1957 में किए गये निर्णयों को देखते हुए मजूरी निर्धारण के सिद्धान्तों को निर्धारित न करना ।	,,
6	936	श्री रामावतार शास्त्री :	936 स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों की सेवाओं का वर्गीकरण करने की आवश्यकता ।	,,
6	937	श्री रामावतार शास्त्री :	स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के लिए अनुशासनात्मक नियमों जिनमें वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील सम्बन्धी नियम शामिल हैं, बनाने की आवश्यकता ।	,,
6	938	श्री रामावतार शास्त्री :	स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों की पदोन्नति करने की आवश्यकता ।	,,
6	939	श्री रामावतार शास्त्री :	स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के बारे में युक्तिसंगत, सरलीकरण, एक समानता और शुद्धि लाने के उद्देश्य से उनके वेतन तथा सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
1	940	श्री रामावतार शास्त्री :	पूर्व रेलवे के दानापुर डिवीजन में जिन कर्मचारियों के नाम ट्रेड अप्रेन्टिस प्रशिक्षण के लिए निकाल दिए गये हैं उनके नाम फिर से शामिल करने की आवश्यकता ।	,,
1	941	श्री रामावतार शास्त्री :	वर्तमान खाली पदों पर वरिष्ठता के अधार पर रेलवे कर्मचारियों को नियमत रूप से पदोन्नति देने की आवश्यकता ।	100 रु०
1	942	श्री रामावतार शास्त्री :	चलती गाड़ियों में काम करने वाले रसोइयों, खानसामों को नियमत कर्मचारी मानने की आवश्यकता ।	,,
1	943	श्री रामावतार शास्त्री :	पूर्व रेलवे के दानापुर डिवीजन के लोको मेकेनिकल कर्मचारियों की पांच सूत्री मांगों को पूरा करने में विफलता ।	,,
1	944	श्री रामावतार शास्त्री :	लोको शेड कर्मचारियों के लिए ट्रेड परीक्षा लेने की व्यवस्था करने में विफलता ।	,,
1	945	श्री रामावतार शास्त्री :	पूर्व रेलवे के दानापुर डिवीजन में वर्तमान खाली स्थानों पर एवजी कर्मचारियों को लगाने में विफलता ।	,,
1	946	श्री रामावतार शास्त्री :	पूर्व रेलवे के दानापुर डिवीजन में क्लीनरों और बी० टी० एम० एस० के स्थानान्तरण आदेशों को खारिज करने में विफलता ।	,,
1	947	श्री रामावतार शास्त्री :	दानापुर में 'ए' श्रेणी के फायरमेनों को पदोन्नति करने और उन्हें वरदी देने की आवश्यकता ।	,,
1	948	श्री रामावतार शास्त्री :	चलती रेलगाड़ियों में काम करने वाले कर्मचारियों को मील भत्ते का हिसाब 'आने के हस्ताक्षर करने' और 'जाने के हस्ताक्षर करने' के समय से लगाने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
1	949	श्री रामावतार शास्त्री :	परीक्षण कर्मचारियों को रनिंग कर्मचारी मानने में विफलता ।	100 रु०
1	950	श्री रामावतार शास्त्री :	सभी रेल कर्मचारियों के लिये छुट्टी संबंधी नियम बनाने की आवश्यकता ।	,,
1	951	श्री रामावतार शास्त्री :	सभी रेल कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधायें देने की आवश्यकता ।	,,
1	952	श्री रामावतार शास्त्री :	सभी रेल कर्मचारियों को शिक्षा सहायता देने की व्यवस्था ।	,,
1	953	श्री रामावतार शास्त्री :	सभी रेल कर्मचारियों को भत्ते देने की आवश्यकता ।	,,
1	954	श्री रामावतार शास्त्री :	सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों को शीघ्र समाप्त करने की आवश्यकता ।	,,
1	955	श्री रामावतार शास्त्री :	सभी रेल कर्मचारियों को यात्रा पास और अन्य छुट्टी यात्रा रियायतें देने की आवश्यकता ।	,,
1	956	श्री रामावतार शास्त्री :	सभी रेल कर्मचारियों को ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार देने, यूनियनों और सेवा संस्थाओं को मान्यता देने और समझौता सम्बन्धी सुविधाएं देने की आवश्यकता ।	,,
1	957	श्री रामावतार शास्त्री :	रेल कर्मचारियों को सुविधायें देने की आवश्यकता ।	,,
1	958	श्री रामावतार शास्त्री :	सेवा निवृति आयु की सीमा बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
1	959	श्री रामावतार शास्त्री :	सभी रेल कर्मचारियों को सेवा निवृति सुविधायें देने की आवश्यकता ।	,,
1	960	श्री रामावतार शास्त्री :	सभी रेल कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने की आवश्यकता ।	,,
1	961	श्री रामावतार शास्त्री :	कर्मचारियों को वर्दी और बचाव के लिए कपड़े देने की आवश्यकता ।	,,
1	962	श्री रामावतार शास्त्री :	कर्मचारियों के कल्याण के लिये उपाय करने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
1	963	श्री रामावतार शास्त्री :	आचरण सम्बन्धी गोपनीय रिपोर्टों को समाप्त करने की आवश्यकता ।	100 रु० ,,
1	965	श्री रामावतार शास्त्री :	इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रेलवे कर्मचारियों के बहुत से संरक्षित बच्चे समस्तीपुर कालेज में पढ़ते हैं उस कालेज को रेलवे बोर्ड द्वारा वित्तीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता ।	,,
1	966	श्री रामावतार शास्त्री :	गड़हरा (बरौनी) में मिडिल स्कूल को उच्चतर माध्यमिक स्कूल का स्तर प्रदान करने की आवश्यकता ।	,,
1	967	श्री रामावतार शास्त्री :	दरभंगा में सैनिक हवाई अड्डे के महत्व को ध्यान में रखते हुए समस्तीपुर से दरभंगा तक बड़ी लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता ।	,,
1	968	श्री रामावतार शास्त्री :	समस्तीपुर से दिल्ली के लिए "मिथिला एक्सप्रैस" नाम से एक नई रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता ।	,,
1	969	श्री रामावतार शास्त्री :	गड़हरा (बरौनी) में रेलवे कर्मचारियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए जो कि लगभग 5000 है वहां की प्रत्येक रेलवे बस्ती में प्राथमिक स्कूल खोलने की आवश्यकता ।	,,
1	970	श्री रामावतार शास्त्री :	पूर्वोत्तर रेलवे में विभाग द्वारा चलाये जा रहे होटलों में सप्ताह में एक बार भोजन न देने की प्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता ।	,,
1	971	श्री रामावतार शास्त्री :	पूर्व की ओर जाने वाली जनता एक्सप्रैस का पूर्वोत्तर रेलवे में गुलजारी बाग स्टेशन पर एक स्टोपेज बनाने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
1	972	श्री रामावत र शास्त्री :	पटना एक्सप्रैस रेलगाड़ी का पूर्वोत्तर रेलवे में पटना सिटी पर एक स्टोपेज बनाने की आवश्यकता ।	100 रु० ,,
1	973	श्री रामावतार शास्त्री :	प्रातः काल के समय रांची से पटना तक एक रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता ।	,,
1	974	श्री रामावतार शास्त्री :	प्रथम श्रेणी और तृतीय श्रेणी के सभी शयन डिब्बों में अटेन्डेन्टों की व्यवस्था की आवश्यकता ।	,,
1	975	श्री रामावतार शास्त्री :	समस्ती पुर डिवीजन (उत्तर रेलवे) के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आवास देने के लिए शीघ्र व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
1	976	श्री रामावतार शास्त्री :	ट्रेन क्लर्कों की न्यायोचित मांग पूरा करने और उनकी कठिनाइयां दूर करने में विफलता ।	,,
1	977	श्री रामावतार शास्त्री :	पूर्व रेलवे के दानापुर डिवीजन के रेल-गाड़ी प्रकाश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा 30 जुलाई, 1969 को डिवीजनल अधीक्षक को लिखित रूप में दी गई मांगें स्वीकार करने में विफलता ।	,,
1	978	श्री रामावतार शास्त्री :	पूर्व रेलवे के बिजली विभाग के फिटरों और खलासियों तथा उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे के फिटरों तथा खलासियों को वर्दी देने में अपनाई गई भेदभाव पूर्ण नीति को छोड़ने की आवश्यकता ।	,,
1	979	श्री रामावतार शास्त्री :	पूर्व रेलवे की पटना-गया लाइन पर स्थित परसा, पोठही, नडोल, तारेगना तथा अन्य सभी स्टेशनों पर पेय जल देने की संतोषजनक व्यवस्था करने में विफलता ।	,,

1	2	3	4	5
1	980	श्री रामावतार शास्त्री :	पूर्व की पटना-गया लाइन पर स्थित परसा, पोठही, नडोल, तारगेना तथा अन्य सभी स्टेशनों पर शौचालयों और रोशनी की उपयुक्त व्यवस्था की स्थापना करने की विफलता ।	100 रु०
1	981	श्री रामावतार शास्त्री :	गार्ड 'सी' (रुपये 130—225) की सीधी भर्ती को रोकने और 1958 से पहले की तरह ही ट्रेन क्लर्कों के लिए कोटा शीघ्र ही पुनः निर्धारित करने की आवश्यकता ।	,,
1	982	श्री रामावतार शास्त्री :	ट्रेन क्लर्कों को व्यापारिक विभाग में पदोन्नति का रास्ता खोलने और उसके लिये प्रतिशत निर्धारित करने की आवश्यकता ।	,,
1	983	श्री रामावतार शास्त्री :	'ट्रेन क्लर्कों' के काम की प्रकृति के अनुसार उन्हें 'गाड़ी वहन नियंत्रक' का पदनाम देने की आवश्यकता ।	,,
1	984	श्रीरामावतार शास्त्री :	ट्रेन-क्लर्कों की कोटि बढ़ाने की प्रतिशतता को अन्य तृतीय श्रेणी के समकक्ष लाने की आवश्यकता ।	,,
1	985	श्री रामावतार शास्त्री :	आल इण्डिया ट्रेन क्लर्क एसोसियशन को मान्यता देने की आवश्यकता ।	,,
1	986	श्री रामावतार शास्त्री :	रेलवे में कार्यालय क्लर्कों की तरह ही ट्रेन क्लर्कों को दिन की ड्यूटी, नियमित शैड ड्यूटी, वेतन मान, कोटि बढ़ाने की प्रतिशतता, राजपत्रित छुट्टियाँ और सेवा-शर्तें जैसी सुविधाएं देने की आवश्यकता ।	,,
1	987	श्री रामावतार शास्त्री :	अन्य रेलवे की तरह ही पश्चिम रेलवे में मैकेनिकल कर्मचारियों को समयोपरि काम की सुविधा देने की आवश्यकता ।	

1	2	3	4	5
1	988	श्री रामावतार शास्त्री :	पश्चिम रेलवे मैकेनिकल कर्मचारियों के बारे में रेलवे बोर्ड द्वारा लिये गये सभी निर्णयों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता ।	100 रु०
1	989	श्री रामावतार शास्त्री :	अन्य रेलवे की तरह ही पश्चिम रेलवे में बी० टी० फिटर के पद समाप्त करने और उन्हें फीटर की पदोन्नति देने की आवश्यकता ।	,,
1	990	श्री रामावतार शास्त्री :	पश्चिम रेलवे लोको शैडो में काम करने वाले बढ़इयों, लोहारों और टिन स्मिथों को पदोन्नति का मार्ग निश्चित करने की आवश्यकता ।	,,
1	991	श्री रामावतार शास्त्री :	मशीनिस्टों की तरह ही लोको शैडो में टर्नरों को समान सुविधायें देने की आवश्यकता ।	,,
1	992	श्री रामावतार शास्त्री :	लोको शैडों में बायलर मेकरों की दशा सुधारने की आवश्यकता ।	
1	993	श्री रामावतार शास्त्री :	मैकेनिक कर्मचारियों की कुशलता तथा उन्हें सौंपे गये काम के अनुसार पदोन्नति देने की आवश्यकता ।	,,
1	994	श्री रामावतार शास्त्री :	मैकेनिक कर्मचारियों की सेवायें स्थायी करने की आवश्यकता ।	
1	997	श्री रामावतार शास्त्री :	पश्चिम रेलवे में बिगड़ी हुई गाड़ियों के स्थान पर जो गाड़ियां आती हैं उनके सुपरवाईजरों को सितम्बर, 1969 से समयोपरि भत्ते का भुगतान न करना ।	,,
1	998	श्री रामावतार शास्त्री :	पश्चिमी रेलवे में विशेषज्ञों द्वारा उच्च स्तरीय परीक्षण करने की आवश्यकता ।	,,
1	999	श्री रामावतार शास्त्री :	डीजल शेडों में भाप लोको शेडों के प्रवर खलासियों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
1	1000	श्री रामावतार शास्त्री :	अन्य खलासियों की अपेक्षा लोको शेड फिलर खलासियों को दुगुना वेतन देने की आवश्यकता ।	100 रु०
1	1001	श्री रामावतार शास्त्री :	फिटरों के कार्य और जिम्मेवारी को देखते हुए उनकी मजूरी को बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
1	1002	श्री रामावतार शास्त्री :	यान्त्रिक कर्मचारियों के कार्यभार को कम करने की आवश्यकता ।	,,
1	1003	श्री रामावतार शास्त्री :	दिल्ली लोको शेड के औजार कक्ष में पर्याप्त माल रखने की आवश्यकता ।	,,
1	1004	श्री रामावतार शास्त्री :	दिल्ली लोको शेड में प्राथमिक उपचार बक्स रखने की आवश्यकता जो कि इन दिनों वहां नहीं है ।	,,
1	1005	श्री रामावतार शास्त्री :	दिल्ली लोको शेड में फिटिंग कर्मचारियों की दैनिक ड्यूटी के कार्यकाल को प्रतिदिन निर्धारित करने की आवश्यकता ।	,,
1	1006	श्री रामावतार शास्त्री :	उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में रख-रखाव कर्मचारियों की सभी प्रवर पदों का दर्जा बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
1	1007	श्री रामावतार शास्त्री :	रेल कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान के हटाये जाने के पश्चात् दिल्ली लोको शेड के 24 कर्मचारियों को जिन विशेषाधिकार से वंचित रखा गया उन्हें पुनः देने की आवश्यकता ।	,,
1	1008	श्री रामावतार शास्त्री :	पश्चिमी रेलवे में डीजल प्रशीक्षण के सम्बन्ध में वरिष्ठ कर्मचारियों को उनके अधिकार से वंचित रखना ।	,,
1	1009	श्री रामावतार शास्त्री :	सभी पात्र व्यक्तियों को स्थानापन्न भत्ता देने की आवश्यकता तथा उत्तर रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन में अधिकारियो द्वारा शैडवार तालिका तैयार करने की आवश्यकता ।	,

1	2	3	4	5
1	1010	श्री रामावतार शास्त्री :	उन सभी कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता देने की आवश्यकता जो अपने कार्यकाल से अधिक काम करते हैं और तदनुसार उत्तर रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन में लोको-फौरमैन, जालन्धर छावनी द्वारा रिकार्ड रखा जाय ।	100 रु०
1	1011	श्री रामावतार शास्त्री :	दिल्ली लोकोशेड में पटरी की नियमित देखभाल रखने में असफलता ।	,,
1	1012	श्री रामावतार शास्त्री :	दिल्ली लोको शैड में जलपान गृह का कार्य और जलपान गृह समिति के लिए नये चुनाव करने की आवश्यकता ।	,,
1	1013	श्री रामावतार शास्त्री :	दिल्ली लोको शैड में टिप्ड औजारों के बारे में अनुभव हो रही कठिनाई दूर करने की आवश्यकता ।	,,
1	1014	श्री रामावतार शास्त्री :	शंकर शर्मा पंचाट की सिफारिशों के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में सिफारिशों को कार्यान्वित न करना तथा 25 प्रतिशत पदों का दर्जा न बढ़ाना ।	,,
1	1015	श्री रामावतार शास्त्री :	दास आयोग की सिफारिश के अनुसार लोको यान्त्रिक कर्मचारियों को वर्दी न देना ।	,,
1	1016	श्री रामावतार शास्त्री :	उत्तर रेलवे में जालन्धर शहर के स्थानीय प्रशासन द्वारा नियोजन के कार्यकाल नियम के उल्लंघन को रोकने की आवश्यकता ।	,,
1	1017	श्री रामावतार शास्त्री :	उत्तर रेलवे में जालन्धर शहर में इंजिनों की आसान मरम्मत के लिए डगों की नियमित सफाई करने की आवश्यकता ।	,,
1	1018	श्री रामावतार शास्त्री :	उत्तर रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन में धार्मिक समारोहों के लिए आधे दिन का अवकाश जारी रखने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
1	1019	श्री रामावतार शास्त्री :	उत्तर रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन में औजार कक्ष को 24 घंटे खुला रखने की तथा आवश्यकतानुसार महैया करने की आवश्यकता ।	100 रु०
1	1032	श्री रामावतार शास्त्री :	कलकत्ता के लिए बरास्ता पटना एक और डिलक्स रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता ।	,,
1	1033	श्री रामावतार शास्त्री :	दिल्ली और कलकत्ता के बीच चलने वाली डिलक्स रेलगाड़ियों में संसद् सदस्यों के लिए सीटों का कोटा नियत करने की आवश्यकता ।	,,
1	1034	श्री रामावतार शास्त्री :	दुर्घटनाओं से बचने की और दुर्घटनाओं में मरने वाले यात्रियों के रिश्तेदारों को पर्याप्त मुआवजा देने की आवश्यकता ।	,,
1	1035	श्री रामावतार शास्त्री :	जो कर्मचारी सेवा के दौरान ही घायल हो जाते हैं अथवा जो सेवानिवृत्त होते हैं उनके परिवारों के सदस्यों को रोजगार देने में असफलता ।	,,
1	1036	श्री रामावतार शास्त्री :	जिन रेलवे कर्मचारियों ने 19 सितम्बर, 1968 को हड़ताल में भाग लिया था उनके विरुद्ध अभियोगों को वापस लेने में असफलता ।	,,
1	1037	श्री रामावतार शास्त्री :	जमालपुर रेलवे वर्कशाप से हर साल करोड़ों रुपये के मूल्य की वस्तुओं की चोरी को रोकने में असफलता ।	,,
1	1038	श्री रामावतार शास्त्री :	रेलवे बोर्ड के कार्यालय में हिन्दी के कार्य के लिए पदों को मंजूर करने और संयुक्त निदेशक (हिन्दी) के पद को उसके बनाये जाने की तारीख से ही खाली रखे रहने में रेलवे बोर्ड का उपेक्षापूर्ण रवैया ।	,,
1	1039	श्री रामावतार शास्त्री :	राज्यों में रेलवे के कार्यालयों में भारत के संविधान की अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं का प्रयोग किये जाने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
7	1040	श्री रामावतार शास्त्री :	नियमों के अनुसार इन्जनों के लिए टूटा हुआ कोयला देने में असफलता ।	100 रु०
7	1041	श्री रामावतार शास्त्री :	कोयले की बड़े पैमाने पर चोरी और बरबादी को रोकने में असफलता ।	
7	1042	श्री रामावतार शास्त्री :	ठेकेदारों से घटिया किस्म का कोयला स्वीकार करने और उन्हें बढ़िया किस्म के कोयले का मूल्य भुगतान करने के मामले में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता ।	,,
8	1043	श्री रामावतार शास्त्री :	जाली टिकटों की बिक्री को रोकने में असफलता ।	,,
8	1044	श्री रामावतार शास्त्री :	लेखन-सामग्री की बड़े पैमाने पर बर्बादी को रोकने की आवश्यकता ।	,,
8	1045	श्री रामावतार शास्त्री :	बिना टिकिट यात्रा को कठोरता से रोकने की आवश्यकता ।	,,
1	1058	श्री रामावतार शास्त्री :	रेलवे टेरिटोरियल सेना का, जिसमें रेल कर्मचारी शामिल किये गये हैं, 19 सितम्बर, 1970 को हुई एक दिन की, सांकेतिक हड़ताल के समय तथा रेल कर्मचारियों की न्यायोचित आन्दोलनों को दबाने के लिए दुरुपयोग करना ।	,,
1	1059	श्री रामावतार शास्त्री :	पत्रातु डीजल इंजन शैड में काम करने वाले रेल कर्मचारियों की सही तथा न्यायोचित मांगों को दूर करने मे विफलता ।	,,
1	1060	श्री सूरज भान :	अम्बाला कैंट रेलवे अस्पताल में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नियुक्त करने में विफलता ।	,,
1	1061	श्री सूरज भान:	कालानोर स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर वाटरमैन नियुक्त करने में विफलता ।	,,
1	1062	श्री सूरज भान :	केसरी स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर बिजली की व्यवस्था करने और रेलवे स्टेशन के निकट ही कर्मचारियों को क्वार्टर देने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
1	1063	**श्री सूरज भान :**	रेलवे कालोनी, अम्बाला कट, में स्वच्छता की स्थिति सुधाने में विफलता ।	100 रु०
1	1064	**श्री सूरज भान :**	अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर निकलने वाले द्वारों पर बिजली के पंखे लगाने में विफलता ।	,,
1	1065	**श्री सूरज भान :**	कालानोर स्टेशन (उत्तर प्रदेश) पर बिजली लगाने और रेलवे स्टेशन के निकट ही कर्मचारियों को क्वार्टर देने में विफलता ।	,,
1	1066	**श्री सूरज भान :**	अम्बाला कैंट की रामपुरा रेलवे कालोनी में आधारभूत नगरीय सुविधायों का न होना ।	,,
1	1067	**श्री सूरज भान :**	रेलवे कालोनी अम्बाला कैंट में स्वच्छता की स्थिति सुधारने में विफलता ।	,,
1	1068	**श्री सूरज भान :**	अम्बाला छावनी में रेलवे अस्पताल का असंतोष-जनक कार्य ।	,,
1	1069	**श्री सूरज भान :**	अम्बाला छावनी और अम्बाला शहर के रेल कर्मचारियों के लिये अपर्याप्त चिकित्सा सुविधायें ।	,,
1	1070	**श्री सूरज भान :**	कालका रेलवे वर्कशाप के कर्मचारियों के व्यक्तिगत मामलों को सुलझाने में अत्याधिक और अनावश्यक विलम्ब ।	,,
1	1071	**श्री सूरज भान :**	कालका रेलवे वर्कशाप के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अपर्याप्त चिकित्सा सुविधायें ।	,,
1	1072	**श्री सूरज भान :**	कालका वर्कशाप में कर्मचारियों की घटती हुई संख्या और वहां से कर्मचारियों का अनुचित, अवांछित और भेदभावपूर्ण स्थानान्तरण ।	,,
2	1073	**श्री सूरज भान :**	कालका रेलवे वर्कशाप के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच बिगड़ते हुए संबंध ।	,,
1	1074	**श्री सूरज भान :**	कालका (उत्तर रेलवे) में रेलवे कालोनी (ढोल प्रकार की) में गलियों, पीने के पानी की व्यवस्था और सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था में सुधार करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
1	1075	**श्री सूरज भान :**	टीन की चादरों से बनाये गए ढोल किस्म के क्वार्टरों को ना गिराना जो न सर्दी और न ही गर्मी में उपयोगी है और उसके बजाय कालका के कर्मचारियों के लिये आधुनिक नये क्वार्टर बनाना ।	100 रु०
1	1076	**श्री सूरज भान :**	रेलवे वर्कशाप, जगाधरी के अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की उनकी पदोन्नति के संबन्ध में शिकायतों को दूर करने में रेलवे प्रशासन की असफलता ।	,,
1	1077	**श्री सूरज भान :**	लालरू रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) में और इसके साथ लगे कर्मचारियों के क्वार्टरों में बिजली न लगाना ।	,,
1	1078	**श्री सूरज भान :**	अम्बाला छावनी/शहर के रेलवे स्टेशनों में रेल कर्मचारियों के लिए पृथक पेशाबघर/पाखाने बनाने की आवश्यकता ।	,,
1	1079	**श्री सूरज भान :**	अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर आर० एम० एस० के डाक के थेलों के कारण प्लेट-फार्म पर भीड़ भाड़ को रोकने में असफलता ।	,,
1	1080	**श्री सूरज भान :**	अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त प्रतीक्षालयों को बनाने की आवश्यकता ।	
1	1081	**श्री सूरज भान :**	अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर बिस्तर आदि सप्लाई किये जाने की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
1	1083	**श्री रामावतार शास्त्री :**	रेलवे अधिकारियों से साक्षात्कार के समय उम्मीदवारों से हिन्दी तथा संविधान सम्मत अन्य भाषाओं में प्रश्न पूछने तथा उन्हीं भाषाओं में उत्तर प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने में विफलता ।	,,
1	1084	**श्री रामावतार शास्त्री :**	पटना में सहायक स्टेशन मास्टर्स का कार्यालय स्टेशन के मुख्य द्वार के निकट रखने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
1	1085	श्री रामावतार शास्त्री :	पूर्व रेलवे के पटना जंक्शन के निकट मीठापुर में पक्का ऊपरी पुल बनाने में असफलता ।	100 रु०
1	1086	श्री रामावतार शास्त्री :	लाइट रेलवे की फतुहा से इस्लामपुर तक जाने वाली रेलवे लाइन को सरकार के अधीन लेकर बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता ।	,,
1	1087	श्री रामावतार शास्त्री :	खगौल (दानापुर) नगरपालिका के अन्तर्गत हजारों रेल कर्मचारियों के रहने के कारण रेलवे प्रशासन की ओर से नगरपालिका को सहायता के रूप में दी जा रही राशि में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	,,
1	1088	श्री रामावतार शास्त्री :	पूर्व रेलवे एवं पूर्वोत्तर रेलवे के केन्द्र गढ़हरा में रेल मजदूरों के साथ एवं उन की कालोनी में समय-समय पर होने वाली गुंडागर्दी को रोकने में विफलता ।	,,
1	1089	श्री रामावतार शास्त्री :	पूर्वोतर रेलवे के थाना बिहपुर जंक्शन पर बने वर्तमान ऊपरी पुल को उत्तर की तरफ बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
1	1090	श्री रामावतार शास्त्री :	पूर्वोत्तर रेलवे पर स्थित सोनपुर में ए० डी० टी० एस० का कार्यालय खोलने की आवश्यकता ।	,,
1	1091	श्री रामावतार शास्त्री :	पूर्वोत्तर रेलवे के मानसी स्टेशन पर गंगा नदी के कटाव के कारण उत्पन्न आसन्न संकट के हल निकालने की आवश्यकता ।	,,
1	1092	श्री रामावतार शास्त्री :	पूर्वोत्तर रेलवे के थाना बिहपुर जंक्शन स्टेशन पर तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय बनवाने की आवश्यकता ।	,,
1	1094	श्री सूरज भान :	दिल्ली स्टेशन पावर केबिन कर्मचारियों को पर्याप्त ग्रेड देने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
1	1095	श्री सूरज भान :	उन वाणिज्यिक कर्मचारियों को नकद प्रतिकर देने की आवश्यकता जिनका विश्राम दिवस राष्ट्रीय छुट्टियों में पड़ता है ।	100 रु०
1	1096	श्री सूरज भान :	फायरमैनों की मांगों को स्वीकार न करना ।	,,
1	1097	श्री सूरज भान :	टिकट परीक्षकों की मांगों को स्वीकार न करना ।	,,
1	1098	श्री सूरज भान :	हिमाचल प्रदेश में जगाधरी से पाओंटा साहेब तक नई रेलवे लाइन (उत्तर रेलवे) बनाने की आवश्यकता ।	,,
1	1099	श्री सूरज भान :	रेलवे गार्डों की बकाया माँगों को स्वीकार न करना ।	,,
1	1100	श्री सूरज भान :	रेलवे विभाग में चिकित्सा सम्बन्धी खर्च की प्रतिपूर्ति करने की आवश्यकता ।	,,
1	1101	श्री सूरज भान :	रेल कर्मचारियों को स्नातक परीक्षा तक अध्या पन प्रतिपूर्ति करने की आवश्यकता ।	,,
1	1102	श्री सूरज भान :	अम्बाला छावनी, अम्बाला शहर और जगाधरी रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक टेलीफोन लगाने की आवश्यकता ।	,,
1	1103	श्री सूरज भान :	कलानौर रेलवे स्टेशन पर ऊंचे प्लेटफार्म बनाने की आवश्यकता ।	,,
1	1104	श्री सूरज भान :	सभी वाणिज्यिक क्लर्कों को मध्याह्न भोजन की छुट्टी देने की आवश्यकता ।	,,
1	1105	श्री सूरज भान :	जिन वाणिज्यिक क्लर्कों को नकदी में लेन देन करना पड़ता है उन्हें विशेष भत्ता देने की आवश्यकता ।	,,
1	1106	श्री सूरज भान :	रेलवे विभाग में, विशेषतया अम्बाला, नई दिल्ली और दिल्ली में वाणिज्यिक कर्मचारियों की संख्या में संशोधन करना ।	,,
1	1107	श्री सूरज भान :	नई दिल्ली में पार्सल साईडिंग पर शैड और पक्का प्लेटफार्म बनाने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
1	1108	**श्री सूरज भान :**	ऊंचे दर्जे के वाणिज्यिक क्लर्कों के पदों की प्रतिशतता में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	100 रु०
1	1109	**श्री सूरज भान :**	सम्बद्ध विभागों में जिन कर्मचारियों को डाक्टरी परीक्षा में अयोग्य पाया गया है उनको कही और लगाने की व्यवस्था न करना ।	,,
1	1110	**श्री सूरज भान :**	अम्बाला शहर और अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशनों पर हाथ द्वारा खींचे जाने वाले ठेलों को पर्याप्त संख्या में देने तथा पुराने ठेलों की मरम्मत करने की आवश्यकता ।	,,
1	1111	**श्री सूरज भान :**	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाथ द्वारा खींचे जाने वाले ठेलों की पर्याप्त संख्या में सप्लाई करने तथा पुराने ठेलों की मरम्मत करने की आवश्यकता ।	,,
1	1112	**श्री सूरज भान :**	आते समय हस्ताक्षर करने से जाते समय हस्ताक्षर करने तक परिचालन कर्मचारियों के कार्य के घंटों की गणना करने की आवश्यकता ।	,,
1	1113	**श्री सूरज भान :**	आचरण सम्बन्धी गोपनीय रिपोर्टों की पद्धति में सुधार की आवश्यकता ।	,,
1	1114	**श्री सूरज भान :**	रेल कर्मचारियों को तुरन्त अन्तरिम राहत देने की आवश्यकता ।	,,
1	1115	**श्री सूरज भान :**	परीक्षक कर्मचारियों को परिचालक कर्मचारी समझने की आवश्यकता ।	,,
1	1116	**श्री सूरज भान :**	सरलीकरण करने और समानता लाने की दृष्टि से स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के मामले में उनके वेतन के ढांचे और सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने की आवश्यकता ।	,,
1	1117	**श्री सूरज भान :**	रेलवे में यंत्रीकरण को रोकने की आवश्यकता ।	,,
1	1118	**श्री सूरज भान :**	जोधपुर डिवीजन (उत्तर रेलवे) में स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों के लिए सहायक सम्बन्धी प्रबंध का निकेन्द्रीकरण करने में सफलता ।	,,

1	2	3	4	5
1	1119	श्री सूरज भान :	राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों को रेगिस्तानी-भत्ता देने में असफलता ।	100 रु०
1	1120	श्री सूरज भान :	रेलवे के अन्तर्गत विद्यालयों के अध्यापकों पदोन्नति का कोई माध्यम प्रदान करने में असफलता ।	,,
1	1121	श्री सूरज भान :	प्राथमिक विद्यालयों की कार्यचालन सम्बंधी शर्तों को सुधारने में असफलता ।	,,
1	1122	श्री सूरज भान :	लोकोशैड, दिल्ली की रेलवे कालोनी में आवश्यक सेवा सम्बंधी कर्मचारियों के लिए शौचालय/गुसलखानों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
1	1123	श्री सूरज भान :	लोको शैड कालोनी, दिल्ली में वरिष्ठ परिचालन कर्मचारियों को परिवार के साथ एक कमरे के क्वार्टर में रहने के लिए अनुचित रूप से बाध्य करना ।	,,
1	1124	श्री सूरज भान :	रेलवे कालोनियों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अलग शौचालय/गुसलखानों की व्यवस्था किये जाने में असफलता ।	,,
1	1125	श्री सूरज भान :	रेलवे कर्मचारियों को अन्य केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की तरह बच्चों का शिक्षा भत्ता देने में असफलता ।	,,
1	1126	श्री सूरज भान :	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उनके रहने के क्वाटरों में बिजली के पंखे की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
1	1127	श्री सूरज भान :	दिल्ली/नई दिल्ली की रेलवे कालोनियों में सर्दियों में बल्ब लगाने तथा गलियों में प्रकाश की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
1	1128	श्री सूरज भान :	दफ्तरियों को फिर से वर्दियां देने में असफलता ।	
1	1129	श्री सूरज भान :	वर्दियों की किस्में, खासतौर से सिलाई में सुधार करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
1	1130	श्री सूरज भान :	रेलवे मुद्रणालय के कर्मचारियों को भारत सरकार के मुद्राणालयों के कर्मचारियों की तरह आकस्मिक छुट्टी देने में असफलता ।	100 रु०
1	1131	श्री सूरज भान :	रेलवे मुद्रणालय के नजदीक उसके कर्मचारियों की सुविधा के लिए यात्री गाड़ियों का विराम स्थान बनाये जाने में असफलता ।	,,
1	1132	श्री सूरज भान :	फीरोजपुर डिवीजन (उत्तर रेलवे) में कार्य सम्बंधी कोई विश्लेषण करने में असफलता ।	,,
1	1133	श्री सूरज भान :	सम्पूर्ण रेलवे में ड्राइंग सम्बन्धी कर्मचारियों के कार्य का विश्लेषण करने की आवश्यकता ।	,,
1	1134	श्री सूरज भान :	पार्सल डिलवरी क्लर्कों को परिचालन कर्मचारियों के रूप में मान लिये जाने की आवश्यकता	,,
1	1135	श्री सूरज भान :	रेलवे कर्मचारियों को जहाँ रेलवे अस्पताल नहीं हैं वहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा की चिकित्सा सुविधाएं देने में असफलता ।	,,
1	1136	श्री रामावतार शास्त्री :	रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को कोटे के अनुसार नौकरियां देने में असफलता ।	,,
1	1137	श्री रामावतार शास्त्री :	रेलवे में तीसरी श्रेणी के यात्रियों को और अधिक सुविधाएं देने की आवश्यकता।	,,
1	1138	श्री रामावतार शास्त्री :	जैसा डा० के० एल० राव, सिंचाई तथा बिजली मंत्री ने सुझाव दिया था, दक्षिण-पूर्व रेलवे पर स्टेशन की नदी से भूमि के कटाव को रोकने के लिए गंगा नदी के वर्तमान बहाव को बदलकर उसके पुराने रास्ते से मिलाने में असफलता ।	,,
1	1139	श्री रामावतार शास्त्री :	रेलवे की क्षेत्रीय अनोपचारिक सलाहकार समितियों द्वारा दिये गये सुझावों को कियान्वित करने में असफलता ।	,,

क्रम संख्या		सदस्य का नाम तथा कटौती प्रस्ताव का पाठ	माँग संख्या
1	1142	**श्री विनय कृष्ण दासचौधरी :** रेलवे बोर्ड को जिसके प्रशासनिक ढांचे में उच्च स्तरीय अधिकारियों की संख्या अधिक है, बनाये रखने की निरर्थकता ।	100 रुपये
1	1143	**श्री विनय कृष्ण दासचौधरी :** इस शीर्षक के अन्तर्गत प्रतिवर्ष खर्चा बढ़ाने की निरर्थकता ।	,,
1	1144	**श्री विनय कृष्ण दासचौधरी :** प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार रेलवे बोर्ड के सदस्यों की संख्या घटाने में विफलता ।	,,
1	1145	**श्री विनय कृष्ण दासचौधरी :** प्रक्षासन की कार्यकुशलता बढ़ाने में विफलता ।	,,
2	1146	**श्री विनय कृष्ण दासचौधरी :** रेल-टक्करों को रोकने के लिए रेल-गाड़ी नियंत्रण की कोई नई मशीन का आविष्कार करने में रेलवे अनुसन्धान, अभिकल्प तथा मानक संगठन की विफलता ।	,,
2	1147	**श्री विनय कृष्ण दासचौधरी :** अलीपुर द्वार के एक युवक वैज्ञानिक द्वारा, जो कि आजकल पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में एक कर्मचारी है, आविष्कार की गई इलेक्ट्रोनिक सेफ्टी डिवाइस मशीन की सराहना करने में विफलता, जबकि यह मशीन संशोधित ढांचा रडार के सिद्धांत पर काम करती है और स्वचालित ढंग से रेल इंजिन पर नियंत्रण रखती है, दुर्घटनाओं को रोकती है और रेलगाड़ियों की चाल को तेज करती है ।	,,

1	2	3	4	5
2	1148	श्री विनय कृष्ण दासचौधरी :	नये कूच बिहार से गितालदाह और बामनहाट, पूर्वोतर सीमा रेलवे, तक की वर्तमान मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण कार्य आरम्भ करने में विफलता ।	100 रु०
2	1149	श्री विनय कृष्ण दासचौधरी :	आसाम में नये कूच बिहार से हासीमारा और नये कूच बिहार से गोलकगंज, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, तक दो नई लाइनों हेतु सर्वेक्षण करने के लिए कोई कदम उठाने में विफलता ।	,,
4	1150	श्री विनय कृष्ण दासचौधरी :	अधिकारियों की कार्यकुशलता और कर्मचारियों के साथ उनके सम्बन्धों को सुधारने की आवश्यकता ।	,,
4	1151	श्री विनय कृष्ण दासचौधरी :	वर्तमान अधिकारियों की संख्या घटाने की आवश्यकता ।	,,
4	1152	श्री विनय कृष्ण दासचौधरी :	रेलवे सेवा आयोग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों का एक सदस्य शामिल करने की आवश्यकता ताकि सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लोगों को ठीक-ठीक प्रतिनिधित्व मिले ।	,,
4	1153	श्री विनय कृष्ण दासचोधरी :	क्षेत्र अधिकारियों को, जहां कहीं भी नियुक्त किये जाते हैं, हटाने की आवश्यकता ।	,,
5	1154	श्री विनय कृष्ण दासचौधरी :	अलाभकारी रेलवे लाइनों संबंधी समिति द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार पूर्वोत्तर सीमा रेलवे कडी०-एच० खण्ड पर डीजल इंजिनों को प्रयोग करने में विफलता ।	,,

1	2	3	4	5
5	1155	श्री विनय कृष्ण दासचौधरी :	अक्तूबर, 1968 में उत्तरी बंगाल में आयी भयंकर बाढ़ द्वारा जो हलदीबाड़ी जलपाईगुडी और लतागुडी चंगभान्धा ब्रांच लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई थी उन्हें पुनः काम लायक बनाने में विफलता ।	100 रु०
5	1156	श्री विनय कृष्ण दासचौधरी :	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के नये कूच बिहार (बड़ी लाईन) पर एक लोको गैरेज और लोको रनिंग शैड का अनुरक्षण करने में विफलता ।	,,
5	1157	श्री विनय कृष्ण दासचौधरी :	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर स्थित नये कूच बिहार में एक कैरिज और माल डिब्बा वर्कशाप बनाने की आवश्यकता जिसके बारे में पहले योजना बनाई जा चुकी थी ।	,,
6	1158	श्री विनय कृष्ण दासचौधरी :	सभी परिचालन कर्मचारियों को समयोपरि और रात्रि ड्यूटी का भत्ता देने की आवश्यकता ।	,,
6	1159	श्री विनय कृष्ण दासचौधरी :	सिगनलर और दूर संचार कर्मचारियों को आगे पदोन्नति का मार्ग खोलने की आवश्यकता ।	,,
6	1160	श्री विनय कृष्ण दासचौधरी :	सिगनलर और दूर संचार कर्मचारियों की सेवा शर्तों को सुधारने की आवश्यकता ।	,,
10	1161	श्री विनय कृष्ण दासचौधरी :	एक ऐसी समिति नियुक्त करने की आवश्यकता जो पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कुछ प्रतिकारी अधिकारियों जैसे क्षेत्र अधिकारी, डी०सी०एस०, डी०-ओ०एस० की गतिविधियों, कर्मचारियों के विरुद्ध प्रतिकार की भावना से दिये गये उनके आदेशों की समीक्षा करें ।	,,

1	2	3	4	5
10	1162	श्री विनय कृष्ण दासचौधरी :	कर्मचारियों के कष्टों संबंधी एक सेल या परिषद स्थापित करने की आवश्यकता जिसमें रेलवे और कर्मचारियों के प्रतिनिधि और हाईकोर्ट का एक सेवा निवृत्त न्यायाधीश ये तीन व्यक्ति शामिल हो और जिसके पास विभागीय प्रक्रिया से कोई फल न निकलने के पश्चात् कर्मचारी अपने कष्टों के बारे में अपील कर सके ।	100 रु०
10	1163	श्री विनय कृष्ण दासचौधरी :	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में कर्मचारियों के बच्चों की सुविधा के लिए स्कूलों के निकट ही राज सहायता प्राप्त छात्रावास खोलने आवश्यकता ।	,,
10	1164	श्री विनय कृष्ण दासचौधरी :	विभिन्न श्रेणियों की संस्थाओं को उचित मान्यता देने की आवश्यकता ।	,,
14	1165	श्री विनय कृष्ण दासचौधरी :	कलकत्ता नगर में जनता तक शीघ्र माल पहुंचाने की प्रणाली के लिए अधिक धन की व्यवस्था करने में विफलता ।	,,
14	1166	श्री विनय कृष्ण दासचौधरी :	कलकत्ता के लिए वृत्ताकार रेलवे परियोजना को शीघ्र आरम्भ करने में विफलता ।	,,
1	1208	श्री रामावतार शास्त्री :	दिल्ली लोकोशेड के कूपों को सदैव साफ रखने की आवश्यकता और इस प्रयोजन के लिए इम्प्रोबाइजेशन इंजेक्टर माप का प्रयोग किया जाना चाहिये ।	,,
1	1209	श्री रामावतार शास्त्री :	लोकोशेडों के रख-रखाव तथा तकनीकी कार्यकुशलता के लिये औजारों सहित पर्याप्त और नियमित सामग्री देने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
1	1210	श्री रामावतार शास्त्री :	रेल पथ निरीक्षकों के क्षेत्राधिकार को कम करने के बारे में कुंजरु समिति की सिफारिश को कार्यान्वित करने की आवश्यकता ।	100 रु०
1	1211	श्री रामावतार शास्त्री :	रेल पथ निरीक्षकों को स्टोर के कार्यभार से मुक्त करने के बारे में कुजंरू समिति की सिफारिश को कार्यान्वित करने की आवश्यकता ।	,,
1	1212	श्री रामावतार शास्त्री :	महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रेल पर निरीक्षकों को राजपत्रित बनाने के बारे में वांचू समिति की सिफारिश को कार्यान्वित करने की आवश्यकता ।	,,
1	1213	श्री रामावतार शास्त्री :	आकस्मिक मजदूरों को स्थायी मजदूरों के समान मजूरी देने की आवश्यकता चूंकि वे उतना ही काम करते हैं ।	,,
1	1214	श्री रामावतार शास्त्री :	स्थायी मैनों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	,,
1	1215	श्री रामावतार शास्त्री :	छुट्टी रिजर्वो और विश्राम देने वालों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	,,
1	1216	श्री रामावतार शास्त्री :	रेल पथ निरीक्षकों और सहायक रेल पथ निरीक्षकों को सभी गैर तकनीकी दायित्वों से अबिलम्ब मुक्त करने की आवश्यकता ।	,,
1	1217	श्री रामावतार शास्त्री :	रेल पथ निरीक्षकों और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों की दर्जे के आधार पर जिम्मेवारी निर्धारित करने और तदनुसार सामान्य और अनुषंगी नियमों (197) में संशोधन करने की आवश्यकता ।	,,
1	1218	श्री रामावतार शास्त्री :	की-मैनों और मेटों को कारीगर पर्यवेक्षक और गैगमैनों को अर्द्ध कारीगर समझने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
1	1219	श्री रामावतार शास्त्री :	की-मैनों और मेटों के वेतनमानों को सिगनल और दूर संचार विभाग के मिकैनिकल सिगनल मेंटेनर के समकक्ष लाने की आवश्यकता ।	100 रु०
1	1220	श्री रामावतार शास्त्री :	अन्तरिम व्यवस्था के तौर पर सहायक रेल पक्ष निरीक्षकों के वेतनमान को 250 रु० 380 रु० (जो इस समय रेल पथ निरीक्षकों का आरम्भ का वेतन है) निर्धारित करने की आवश्यकता ।	,,
1	1221	श्री रामावतार शास्त्री :	रेल पथ निरीक्षकों और सहायक रेलपथ निरीक्षकों के कार्य के समय, आवधिक अवकाश और छुट्टी को निश्चित करने की आवश्यकता ।	,,
1	1222	श्री रामावतार शास्त्री :	तीव्र गति के मार्गों के लिये जहां ऊंचे दर्जे के रेलपथ निरीक्षक रखे जाते हैं, सहायक रेलपथ निरीक्षकों को विशेष भत्ता देने की आवश्यकता ।	,,
1	1223	श्री रामावतार शास्त्री :	रात्रि भत्ते, सहायता कार्य सम्बन्धी भत्ते जैसे भत्तों में अन्तर को दूर करने की आवश्यकता ।	,,
1	1224	श्री रामावतार शास्त्री ।	रेलपथ निरीक्षकों और सहायक रेलपथ निरीक्षकों के आवास, चिकित्सा, बच्चे की शिक्षा की आवश्यकताओं पर ध्यान देना ।	,,
1	1225	श्री रामावतार शास्त्री :	रेलपथ निरीक्षकों और सहायक रेलपथ निरीक्षकों की शिकायतों को दूर करने की आवश्यकना ।	,,
1	1226	श्री रामावतार शास्त्री :	रेलपथ निरीक्षकों की पदोन्नति की प्रतिशतता में, जो इस समय 7 प्रतिशत है वृद्धि करने की आवश्यकता ।	,,
1	1227	श्री रामावतार शास्त्री :	उत्तर रेलवे में सभी लोको शेडों में बी० टी० एम० नीति को कार्यान्वित करने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
1	1228	श्री रामावतार शास्त्री :	उत्तर रेलवे में सभी लोको शेडों में अर्द्ध-कारीगर पदों को समाप्त कर और उनका दर्जा बढ़ा कर उन्हें कारीगर का पद बनाने की आवश्यकता ।	100 रु०
1	1229	श्री रामावतार शास्त्री :	उत्तर रेलवे में सभी लोकोशेडों में पर्यवेक्षकों (एफ० आई० सी० एस०) को डीजल प्रशिक्षण देने की आवश्यकता ।	,,
1	1230	श्री रामावतार शास्त्री :	उत्तर रेलबे सभी डीजल शेडों में एफ० आई० सी० एस० के लिए सीधे भर्ती की आवश्यकता ।	,,
1	1231	श्री रामावतार शास्त्री :	उत्तर रेलवे के दिनांक 27-12-69 के जी० एम० (पी०) पत्र संख्या 755-ई/216 (ई० एन० सी०) में प्रकाशित एफ० आई० सी० ग्रेड 'ए' सेलेक्शन पेनल को रद्द करने की आवश्यकता ।	,,
1	2232	श्री रामावतार शास्त्री :	राष्ट्रीय भारतीय रेल कर्मचारी महासंघ की मान्यता को वापस लेने की रोकने की आवश्यकता ।	,,
1	1233	श्री फ० गो० सेन :	रेल गाड़ी के डिब्बों को उचित दशा में न रखना ।	,,
1	1234	श्री फ० गो० सेन :	सभी रेल विभागों में टिकट परीक्षकों (टी० टी० ई०) को, परिचालक कर्मचारी मान कर उनके यात्रा भत्ते के सम्बन्ध में उनके साथ एक समान व्यवहार करने की आवश्यकता ।	,,
1	1243	श्री वेणी शंकर शर्मा :	उत्तरी भागलपुर में नौगाछिया में जो एक बड़ा व्यापारिक केन्द्र है, सभी डाक तथा एक्सप्रैस गाड़ियों को रुकवाने की आवश्यकता ।	
1	1244	श्री वेणी शंकर शर्मा :	वैद्यनाथधाम और जसिडीही के बीच रात को 10 बजे से 2 बजे के बीच जसिडीही में वैद्यनाथधाम से यात्रियों के लिए, जिनमें अधिकांश यात्री देश के विभिन्न भागों से	,,

1	2	3	4	5
			होते हैं, अप और डाउन गाड़ियों से मिलान करने के लिए एक नयी गाड़ी चलाने की आवश्यकता ।	
1	1245	श्री वेणी शंकर शर्मा :	वैद्यनाथधाम के यात्रियों को सुबह पटना पहुँचने के लिए रात को वैद्यनाथधाम से जाने वाली गाड़ी सीधे पटना के लिए एक डिब्बा जोड़ने की आवश्यकता ।	100 रु०
1	1246	श्री फ० गो० सेन :	कटिहार पूछताछ कार्यालय में रात पारी के सेवा निवृत्त प्रभारी अधिकारी के स्थान पर दूसरे व्यक्ति की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
1	1247	श्री फ० गो० सेन :	कटिहार—बरौनी लाइन को, जो इस क्षेत्र की एक मात्र लाइन है, अविलम्ब चौड़ा करने के लिए पर्याप्त धन राशि की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
1	1248	श्री फ० गो० सेन :	मिस्त्री और चार्ज मैन के जिनकी एकसी ड्यूटी है, श्रेणी और पदनाम को चार्ज मैन एक ही पदक्रम में बदलने में असफलता ।	,,
1	1249	श्री फ० गो० सेन :	बरौनी—कटिहार लाइन पर मंशी में स्थानीय निवासियों के विस्थापित होने के विचार से रक्षात्मक निर्माण कार्यों की आवश्यकता ।	,,
1	1250	श्री फ० गो० सेन :	रात में सफर करने के लिए सवारी गाड़ियों में शयनयान (स्लीपर) लगाने में असफलता ।	,,
1	1251	श्री फ० गो० सेन :	गाड़ियों में भीड़-भाड़ को दूर करने में असफलता ।	,,
1	1252	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :	कटक-प्रदीप रेलवे लाइन के निर्माण में विलम्ब और रेल प्रशासन द्वारा रेल मन्त्री के निर्णय का बदला जाना ।	,,
1	1253	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :	दक्षिण-पूर्व रेलवे में कोराई रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रैस गाड़ियों को रोकना ।	,,
1	1254	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :	उड़ीसा के क्योंझर जिले में बोरबिल खान क्षेत्रों के बीच सवारी गाड़ी चलाने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
1	1255	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :	दक्षिण-पूर्व रेलवे में हरदासपुर और गढ़माधुपुर रेलवे स्टेशन क्षेत्र में काश्तकारों को रेलवे की भूमि पट्टे पर देना ।	100 रु०
1	1256	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :	दिल्ली से पुरी तक उत्कल एक्सप्रैस की रफ्तार बढ़ाना ।	,,
1	1257	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :	गाड़ी नियन्त्रकों को श्रेणी की पदोन्नति में रुकावट को दूर करना ।	,,
1	1258	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :	मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ते के मिलाये जाने के पश्चात जो अनुषंगी लाभ हटा लिये गये थे उनको दोबारा देना ।	,,
1	1259	श्री सुरेन्द नाथ द्विवेदी :	उन सभी नियन्त्रण कर्मचारियों को, जो रात की ड्यूटी करते हैं, रात्रि भत्ता देने की आवश्यकता, चाहे उनका वेतन मान कुछ भी हो ।	,,
1	1260	श्री सुरेन्द नाथ द्विवेदी :	रेलवे बोर्ड की हिदायतों के अनुसार केन्द्रीकृत वातानुकूलन का उपबन्ध करना ।	,,
1	1261	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :	गाड़ी नियन्त्रकों के ग्रेड i और ii को मिलाना ।	,,
1	1262	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :	नियन्त्रण कार्यालयों में संचार के नवीनतम साधनों का उपबन्ध करना ।	
1	1263	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :	उप गाड़ी नियन्त्रकों को अविच्छिन्न के बजाये उद्यमी कर्मचारी घोषित करने की आवश्यकता ।	,,
4	1264	श्री वेणी शंकर शर्मा :	गार्डों, चल-टिकट परीक्षकों और आरक्षित (रिजर्वड) डिब्बों के परिचरों की सेवा सम्बन्धी शर्तों में सुधार करने की आवश्यकता ।	,,
4	1265	श्री वेणी शंकर शर्मा :	चलते डिब्बों में चुड़नारों की उठाईगीरी को रोकने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
4	1266	श्री वेणी शंकर शर्मा :	यार्डों में, जहां गाड़ियां धुलाई तथा सफाई के लिए रात भर रखी जाती हैं, उठाईगीरी को रोकने के लिए विशेष रक्षक रखने की आवश्यकता ।	100 रुपये
4	1267	श्री वेणी शंकर शर्मा :	शाकाहारी तथा मांसाहारी भोजन व्यवस्था अलग कर उनके अलग प्रभारी ठेकेदार रखने की आवश्यकता ।	,,
4	1298	श्री वेणी शंकर शर्मा :	साहिबगंज (साहिबगंज चाप) और कटिहार के बीच रोजाना हजारों यात्रियों को आसानी से पहुँचने के लिए, जिन्हें 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में सात घंटे व्यतीत करने पड़ते हैं, एक पुल बनाने की आवश्यकता ।	,,
4	1269	श्री वेणी शंकर शर्मा :	साहिबगंज-चाप (लूप) पर चलने वाली गाड़ियों में बैटरियों को ठीक ढंग से चार्ज करने में असफलता जिसके फलस्वरूप पूर्ण अंधकार के समय चोरों तथा जेब कतरों को बहुत अच्छा अवसर मिलता है ।	,,
			(सांकेतिक)	
1	1284	श्री रामावतार शास्त्री :	रेल पथ निरीक्षकों के वेतन मानों 335 रुपये—485 रुपये और 450 रुपये—575 रुपये को अन्तरिम तौर पर निश्चित करने की आवश्यकता ।	,,
1	1285	श्री बिनोय कृष्ण दास चौधरी :	यद्यपि रेलवे बोर्ड यह बात पहले स्वीकार कर चुका है कि टी० टी० ई० (चल टिकट परीक्षक) को रेल-गाड़ियों के चालित कर्मचारी माना जाये और यह मामला रेल मंत्रालय द्वारा स्थापित एक सदस्यीय न्यायाधिकरण को भी सौंपा जाये, परन्तु ऐसा करने में विफलता ।	,,

1	2	3	4	5
6	1286	श्री बिनोय कृष्ण दास चौधरी :	स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के ड्यूटी के घंटों को सविराम ड्यूटी के बजाय निरन्तर ड्यूटी की सूची में घोषित करने की आवश्यकता ।	100 रु०
10	1287	श्री बिनोद कृष्ण दास चौधरी :	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में दो—टायर तथा तीन टायर शायिका गाड़ियों का प्रभार टी० टी० ई० के बजाय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को देकर टी० टी० ई० के पदोन्नति का मार्ग अवरुद्ध करना ।	,,
10	1288	श्री बिनोद कृष्ण दास चौधरी :	टी० टी० ई० के संवर्ग में अवरोध क्योंकि अन्य विभागों के ऐसे कर्मचारियों को भी, जिनके स्वास्थ्य का स्तर निम्न है, इन पदों पर नियुक्त कर दिया गया है और सेवारत टिकट जांच कर्मचारियों से ऊंची वरिष्ठता दी गई है ।	
10	1289	श्री बिनोद कृष्ण दास चौधरी :	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में हर चल टिकट परीक्षक को बाह्य करना कि वे अनिवार्य रूप से एक विशिष्ठ सीमा तक वे आय दें अन्यथा उन्हें दण्ड देने की अनावश्यक व्यवस्था।	,,
10	1290	श्री बिनोद दास कृष्ण चौधरी :	ड्यूटी पर होते हुए भी चल टिकट परीक्षकों को चालित कमरे का उपयोग करने की अनुमति न देकर परेशान करना ।	,,
10	1291	श्री बिनोद कृष्ण दास चौधरी :	चल टिकट परीक्षक 'ए' के कोटि बढ़ाये गये 7½ प्रतिशत पदों पर नियुक्त परीक्षकों का उपयोग परीक्षण कार्य के लिए करना और वर्तमान कार्य भार के साथ काम कर रहे टिकट जांच कर्मचारियों की संख्या को उक्त सीमा तक घटाना ।	,,

1	2	3	4	5
7	1292	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	कोयले के इन्जनों की जगह डीजल इंजिनों को अधिक संख्या में चालू करने में विफलता ।	100 रु०
7	1293	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	कोयले की जगह बिजली से चलने वाले इंजिनों को अधिक संख्या में चालू करने में अपेक्षित प्रगति लाने में विफलता ।	,,
7	1294	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	बड़ी लाइन से छोटी लाइन में तथा छोटी लाइन से बड़ी लाइन के बीच मालों के चढ़ाव उतराव में सामानों की पूरी सुरक्षा करने में विफलता ।	,,
7	1295	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	मालों के चढ़ाव उतराव में मालों के नुक्सान, गोलमाल आदि रोकने में विफलता ।	,,
7	1296	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	मालों के चढ़ाव उतराव में होने वाली गड़बड़ियों के कारण क्षतिपूर्ति में होने वाले रेलवे के अपार व्यय को कम करने में विफलता ।	,,
8	1297	श्री कमला मिश्र "मधुकर" :	क्षतिपूर्ति के मामलों की संख्या में होने वाली वृद्धि को रोकने में विफलता ।	,,
14	1298	श्री कमला मिश्र "मधुकर" :	पुर्वोत्तर रेलवे को नारकटियागंज से आगे सीधे गोरखपुर तक वाराणसी में पुल बना कर बढ़ाने में विफलता ।	,,
15	1299	श्री कमला मिश्र "मधुकर" :	तृतीय चतुर्थ एवं कैजुअल कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाओं की भयंकर कमी एवं उपेक्षा ।	,,
16	1300	श्री कमला तिश्र "मधुकर" :	सूखा, अकाल एवं बाढ़ग्रस्त इलाकों से आये रेल कर्मचारियों को विशिष्ट सुविधा देने में विफलता ।	,,
10	1031	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी एवं नैमित्तिक रेलवे कर्मचारियों के इलाज पर समुचित खर्च करने में विफलता ।	,,

1	2	3	4	5
10	1302	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	रेलवे के सफाई कर्मचारियों, पानी वाले कर्मचारियों एवं तृतीय श्रेणी के अन्य कर्मचारियों को समय पर समुचित वर्दी देने में विफलता ।	100 रु०
10	1303	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	प्वाइन्टमेनों, खलासियों, एवं निचली श्रेणी के अन्य कर्मचारियों, के लिए माननीय न्यूनतम सुविधाओं से विहीन आवासों को बदलने में विफलता ।	,,
10	1304	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	जंकशन स्टेशनों को छोड़ कर शेष रेलवे स्टेशनों पर रेल कर्मचारियों के आवासों में सुविधायें बढ़ाने में विफलता ।	,,
10	1305	श्री कमला मधुकर 'मिश्र' :	पूर्वोत्तर रेलवे के चकिया स्टेशन के कर्मचारियों के क्वार्टरों के निकटतम पानी के जमाव को रोकने में विफलता ।	,,
10	1306	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	पूर्वोत्तर रेलवे के चकिया स्टेशन के कर्मचारियों की वस्ती तक पक्की सड़क बनाने में विफलता ।	,,
10	1307	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	पूर्वोत्तर रेलवे के मुजफ्फर जंकशन के कर्मचारियों के बच्चों के लिए उच्च विद्यालय की स्थापना में विफलता ।	,,
10	1308	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	पूर्वोत्तर रेलवे के मुजफ्फरपुर जंकशन के कर्मचारियों को अस्पताल से मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं की कमी को दूर करने में विफलता ।	,,
10	1309	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	रेलवे कर्मचारियों की केन्टीन में भोजन सामग्रियों की किस्म में सुधार करने में विफलता ।	,,
11	1310	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	रेलवे कर्मचारियों के मिलने वाले पेन्शनों में घूसखोरी, विलम्ब एवं लालफीताशाही को रोकने में विफलता ।	,,

1	2	3	4	5
13	1311	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	पूर्वोत्तर रेलवे के मोतिहारी स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों के लिए वाचनालय, खेलकूद के मैदान आदि अनेक सुविधाओं की व्यवस्था करने में विफलता ।	100 रु०
13	1312	श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :	पूर्वोत्तर रेलवे के मोतीपुर, महवाल मेहसी, चकिया, पिपरा आदि स्टेशनों पर कर्मचारियों के निवास, रोशनी एवं सड़कों की मरम्मत आदि की ओर ध्यान नहीं दिया जाना ।	,,
1	1313	श्री जि० मो० विस्वास :	कार्यालयों में बिजली के संगणकों का अनावश्यक रूप के लगाना जिससे कार्यालय के कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है तथा भविष्य में होने वाले रोजगार की संभावना कम हो गई हैं ।	1 रु०
1	1314	श्री जि० मो० विस्वास :	मार्ग के रखरखाव सम्बन्धी स्वचालित मशीन का अनावश्यक रूप से लगाना जिससे बड़ी संख्या में गैंग के कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है तथा भविष्य में होने वाले रोजगार की सम्भावना कम हो गई है ।	,,
1	1315	श्री जि० मो० विस्वास :	रेलवे में लालफीताशाही का मुकाबला करने में असफलता ।	100 रु०
1	1316	श्री जि० मो० विस्वास :	रेलवे में स्वचालित यंत्रों की सम्भावना को रोकने की आवश्यकता ।	
1	1317	श्री जि० मो० विस्वास :	कालका हावड़ा डाक गाड़ी में डाइनिंग कार को मुगलसराय में अलग करने की बजाय हावड़ा तक लेजाने की आवश्यकता ।	

1	2	3	4	5
1	1318	श्री जि० मो० विस्वास :	रेलवे कर्मचारियों की रेलवे प्रादेशिक (टेरीटोरियल) सेना का रेलवे कर्मचारियों के वैध आन्दोलनों को दबाने में दुरुपयोग किया जाना ।	100 रु०
1	1319	श्री जि० मो० विस्वास :	एक ऐसा स्थाई समाधान निकालने में असफलता जिस से रेलों को रोकने में जनता द्वारा ड्यूटी पर तैनात रेलवे कर्मचारियों की मारपीट न की जाए ।	,,
1	1320	श्री जि० मो० विस्वास :	रेलवे कर्मचारियों की आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी देने में असफलता ।	,,
1	1321	श्री जि० मो० विस्वास :	अधिकांश कर्मचारियों द्वारा समर्थन प्राप्त एक क्षेत्र (जोन) में एक संघ तथा एक अखिल भारतीय संघ को मान्यता देने की आवश्यकता ।	,,
7	1322	श्री जि० मो० विस्वास :	गैर सरकारी खान मालिकों से घटिया कोयला लेने तथा उन्हें बढ़िया कोयले की कीमत देने के मामले में भ्रष्टाचार रोकने में असफलता ।	,,
14	1323	श्री जि० मो० विस्वास :	कलकत्ता के लिए वृताकार रेलवे परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्र करने में असफलता ।	,,
15	1324	श्री जि० मो० विस्वास :	दक्षिण पूर्व रेलवे में पुरुलिया से कोट शिला तक चौड़ी लाइन निकालने तथा सम्पूर्ण बी० डी० आर० को जिसे दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा गैर सरकारी पार्टी से अपने हाथ में ले लिया गया है, छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
1	1325	श्री जि० मो० विस्वास :	रेलवे के सभी विभागों में उच्च अधिकारियों की संख्या में भारी कटौती करने तथा तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या में फिर से वृद्धि करने की आवश्यकता ।	100 रु०
1	1326	श्री जि० मो० विस्वास :	गैंगमैनों की वर्दियों की नियमित सप्लाई करने में असफलता ।	,,
1	1327	श्री जि० मो० विस्वास :	रेलवे औषधालयों तथा अस्पतालों को उपयुक्त दवाइयों की व्यवस्था करने तथा रेलवे अस्पतालों में डाक्टरों की संख्या बढ़ाने में असफलता ।	,,
1	1328	श्री जि० मो० विस्वास :	रेलवे कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए अधिकतम आठ घण्टे तक की ड्यूटी नियत करने में असफलता ।	,,
1	1329	श्री जि० मो० विस्वास :	प्रशंसनीय सेवाओं के लिए रेलवे कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के लिए उन का चयन करने में निष्पक्षता बरतने में असफलता ।	,,
1	1330	श्री जि० मो० विस्वास :	रेलवे सेवाओं के लिए प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की भरती बन्द करने की आवश्यकता ।	,,
1	1331	श्री जि० मो० विस्वास :	"रनिंग स्टाफ" की ड्यूटी नियत करने में न्यायनिर्णायक के फैसले में संशोधन करने की आवश्यकता ।	,,
1	1332	श्री जि० मो० विस्वास :	रेलवे में 'मितव्ययता' आन्दोलन का नारा समाप्त करने में असफलता, जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों और उच्च-वेतनमान के पदों को समर्पित किया जाता है तथा बड़ी संख्या में कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा को खतरा होता है ।	,,
1	1333	श्री जि० मो० विस्वास :	रेलवे कर्मचारियों के लिए सरकारी कर्मचारियों के आचरण सम्बन्धी नियमों को समाप्त करने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
1	1334	श्री जि० मो० विस्वास :	गार्डों की श्रेणी में 'ग' वर्ग कपसमाप्त कर सभी 'ग' वर्ग को गार्डों की 'ख' वर्ग में पदोन्नति करने की आवश्यकता ।	100 रु०
1	1335	श्री जि० मो० विस्वास :	इंजनों का विद्युतीकरण अथवा डिजली-करण जैसी भी स्थिति हो, करने के बाद शेड और वाष्प इंजनों के सभी रनिंग स्टाफ को बिजली अथवा डीजल इंजनों के शेड और रनिंग स्टाफ के स्थान में नियुक्त करने की आवश्यकता ।	,,
1	1336	श्री जि० मो० विस्वास :	रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों तथा रेलवे विद्यालयों के शिक्षकों को मज़दूर संघ के पूर्ण अधिकार प्रदान करने में असफलता ।	,,
1	1337	श्री जि० मो० विस्वास :	रेलवे में न्यूनतम तथा अधिकतम वेतन के अन्तर को कम कर 1 और 10 के अनुपात में लाने की आवश्यकता ।	,,
1	1338	श्री जि० मो० विस्वास :	तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति, स्थानांतरण, वरिष्ठता आदि के निर्धारण में पक्षपात, भाई भतीजावाद तथा अन्य भ्रष्ट प्रथाओं का उन्मूलन करने की आवश्यकता ।	,,
1	1339	श्री जि० मो० विस्वास :	चतुर्थ श्रेणी की पदोन्नति सम्बन्धी समिति की सिफारिशों को पूरी तरह से क्रियान्वित करने में असफलता ।	,,
1	1340	श्री जि० मो० विस्वास :	मूल्य सूचकांकों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक रेलवे कर्मचारी को 60 रुपये अन्तरिम सहायता देने में असफलता ।	,,
1	1341	श्री जि० मो० विस्वास :	उन सभी कर्मचारियों को जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (ग) के अन्तर्गत हटाया गया था उन्हें वापस उनकी सेवाओं में बहाल करने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
1	1342	श्री जि० मो० विस्वास :	रेलवे कर्मचारियों को उनकी मजदूर संघ सम्बन्धी गतिविधियों के लिए खासतौर से 19 सितम्बर, 1968 के बाद स्थानांतरण के सभी आदेशों को रद्द करने की आवश्यकता ।	100 रु०
1	1343	श्री जि० मो० विस्वास :	उन रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध जिन्होंने 19 सितम्बर, 1968 को हड़ताल में भाग लिया, अदालती मामलों को वापस लेने में असफलता ।	,,
1	1344	श्री जि० मो० विस्वास :	19 सितम्बर, 1968 के हड़ताल के सिलसिले में जिन रेलवे कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया उन सबको बहाल करने की आवश्यकता ।	,,
1	1345	श्री जि० मो० विस्वास :	चल टिकट परीक्षकों को परिचालन कर्मचारियों के रूप में मानने में असफलता ।	,,
1	1346	श्री जि० मो० विस्वास :	डाइनिंग कारों तथा जलपान-गृहों में ठीक ढंग का खाना सप्लाई करने में असफलता ।	,,
1	1347	श्री जि० मो० विस्वास :	पुरूलिया बंकरा तथा मिदनापुर जिलों के मुख्यालयों के स्टेशनों से होकर टाटा अथवा चक्रधरपुर से हावड़ा तक और वापस एक एक्सप्रैस गाड़ी चलाने की आवश्यकता ।	,,
1	1348	श्री जि० मो० विस्वास :	अनारा में सड़क पर अप और डाउन दोनों यार्डों को मिलाने वाले एक ऊपरी पुल की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
1	1349	श्री जि० मो० विस्वास :	नैमित्तिक मजदूरों को पूरी तरह से नियमित करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
1	1350	श्री जि० मो० विस्वास :	नैमित्तिक मजदूरों को सेवा भंग सहित बिना भंग के 6 महीने की सेवा अथवा पूरी करने के बाद अधिकृत वेतनमान देने में असफलता ।	100 रु०
1	1364	श्री जि० मो० विस्वास :	दक्षिण-पूर्व रेलवे के आद्रा डिवीजन में कृषि प्रयोजन के लिए रेलवे भूमि के वितरण में कदाचारों को रोकने और वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाने की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
1	1365	श्री जि० मो० विस्वास :	दक्षिण-पूर्व रेलवे के आद्रा डिवीजन में रेलवे बाजारों में दुकानों के निर्माणार्थ रेलवे भूमि के वितरण में कदाचारों को रोकने की आवश्यकता ।	,,
1	1366	श्री जि० मो० विस्वास :	दक्षिण-पूर्व रेलवे के आद्रा-खड़गपुर खंड पर स्थित रामसागर स्टेशन को फ्लैग स्टेशन से 'ख' श्रेणी के स्टेशन में वर्गीकृत करने और उक्त स्टेशन के प्लेटफार्म पर रेलवे लाइनों के ऊपर से होकर उत्तर से दक्षिण तक एक ऊपरी पुल की व्यवस्था करके उसे नया रूप देने की आवश्यकता ।	,,
1	1367	श्री जि० मो० विस्वास :	दक्षिण-पूर्व रेलवे के आद्रा-खड़गपुर खंड पर स्थित सभी स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर बिजली लगाने की आवश्यकता ।	,,
1	1368	श्री जि० मो० विस्वास :	दक्षिण-पूर्व रेलवे के पुरूलिया और खड़गपुर के बीच स्थित सभी स्टेशनों पर यात्रियों को पेय जल की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
1	1369	श्री जि० मो० विस्वास :	दक्षिण-पूर्व रेलवे के पुरूलिया और खड़गपुर के बीच स्थित सभी स्टेशनों के तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालयों की हालत ठीक स्तर पर रखने और स्टेशनों में	

1	2	3	4	5
			स्थित प्रतीक्षालयों और शौचालयों की अच्छी तरह सफाई की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	100 रु०
1	1370	श्री जि० मो० विस्वास :	दक्षिण-पूर्व रेलवे के आद्रा डिवीजन पर स्थित विभिन्न स्टेशनों पर तैनात टोकन पोर्टरों, प्वइंट्समनों, कैबिन मैनों, लेविल-मैनों तथा अन्य परिचालन कर्मचारियों के लिए केवल आठ घण्टे की ड्यूटी रखने की आवश्यकता।	,,
1	1371	श्री जि० मो० विस्वास :	गार्डों और ड्राइवरों को अपनी ड्टी देते समय गड़बड़ करने वालों द्वारा दुर्व्यव-हार से पर्याप्त सुरक्षित रखने की व्यवस्था करने में विफलता।	,,
1	1375	श्री जि० मो० विश्वास :	डिवीजनल स्वास्थ्य अधिकारी दक्षिण-पूर्व रेलवे, आद्रा को सफाई कार्यों के लिए ट्रक सप्लाई करने का ठेका गैर-सरकारी ठेकेदारों के प्रभाव में आकर दक्षिण-पूर्व रेलवे बहुप्रयोजनी संविद श्रम सहकारी समिति लिमिटेड, आद्रा को देने में असफलता।	,,
1	1376	श्री जि० मो० विश्वास :	संविद-श्रम सहकारी समितियों को ठेका दिये जाने के मामलों में योजना आयोग की सिफारिश को क्रियान्वित करने में असफलता।	,,
1	1377	श्री जि० मो० विश्वास :	संविद-श्रम सहकारी समितियों से सम्बद्ध कार्यवाही के मामलों में भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने में असफलता।	,,
1	1378	श्री जि० मो० विश्वास :	आरक्षित पदों पर अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की पदोन्नति के मामलों में उत्तर रेलवे में फैली हुई भ्रष्ट प्रथाओं को बन्द करने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
1	1379	श्री जि० मो० विस्वास :	विभिन्न खातों में अर्थात् अप्रयुक्त टिकटों के लिए धन-वापसी, विशेष रेलगाड़ियों के लिए खर्चे का प्रत्यादेश के नाम में रेलवे विभाग के पास जमा राशि को वापस करने के लिए शीघ्र और निश्चित कदम उठाने में विफलता ।	100 रु०
1	1384	श्री भोगेन्द्र झा :	पूर्वोत्तर रेलवे पर दरभंगा और मुज्जफ्फरपुर जंकशनों को एक सीधी नयी रेलवे लाइन द्वारा मिलाने की आवश्यकता ।	
1	1385	श्री भोगेन्द्र झा :	पूर्वोत्तर रेलवे पर मधुबनी और निर्मली स्टेशनों को बरास्ता झांझथशी एक नयी रेलवे लाइन द्वारा मिलाने की आवश्यकता ।	,,
1	1386	श्री भोगेन्द्र झा :	पूर्वोत्तर रेलवे पर जय नगर और सीतामढ़ी स्टेशनों को एक सीधी नयी रेलवे लाइन द्वारा मिलाने की आवश्यकता ।	,,
1	1387	श्री भोगेन्द्र झा :	पूर्वोत्तर रेलवे पर सकरी और हसनपुर रोड स्टेशनों को एक सीधी नयी रेलवे लाइन द्वारा मिलाने की आवश्यकता ।	,,
1	1388	श्री भोगेन्द्र झा :	पूर्व रेलवे पर राजेन्द्रपुल हाल्ट को और आगे दक्षिण की ओर राजेन्द्र पुल के ठीक उत्तरी किनारे पर ले जाने की आवश्यकता ।	,,
1	1389	श्री भोगेन्द्र झा :	पूर्वोत्तर रेलवे पर निर्मली और सुपौल स्टेशनों को रेलवे लाइन का पुनर्निर्माण कर मिलाने की आवश्यकता ।	,,
1	1390	श्री भोगेन्द्र झा :	पूर्वोत्तर रेलवे पर कमतौल और जोगियारा स्टेशनों के बीच मुरेथा में एक रेलवे हाल्ट खोलने की आवश्यकता ।	,,
1	1391	श्री भोगेन्द्र झा :	पूर्वोत्तर रेलवे पर जयनगर और खजौली स्टेशनों के बीच कोराहिया में एक रेलवे हाल्ट खोलने की आवश्यकता ।	,,
1	1392	श्री भोगेन्द्र झा :	पूर्वोत्तर रेलवे पर दरभंगा जंकशन के उत्तर में रेलवे लाइन के पहले फाटक पर एक ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
1	1393	श्री भोगेन्द्र झा :	समस्तीपुर जंकशन के पश्चिम में रेलवे लाइन के पहले फाटक पर ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता ।	100 रु०
1	1394	श्री भोगेन्द्र झा :	पूर्वोत्तर रेलवे पर समस्तीपुर से रक्सौल तक दरभंगा होकर बड़ी लाइन का विस्तार करने की आवश्यकता ।	,,
1	1395	श्री भोगेन्द्र झा :	पूर्वोत्तर रेलवे पर बाराबंकी से कटिहार तक मुज्जफ्फरपुर होकर बड़ी लाइन का विस्तार करने की आवश्यकता ।	,,

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : 25 फ़रवरी 1970 को प्रस्तुत किये गये वर्ष 1970-71 के बजट में यात्री भाड़े तथा वस्तु भाड़े में वृद्धि करने के कुछ प्रस्ताव शामिल किये गये थे । उन्हें अब वापस ले लिया गया है और इसके फलस्वरूप रेलवे को 13 करोड़ रुपये कम आय होगी ।

[**श्री श्रीचन्द गोयल पीठासीन हुए ।**
Shri Shrichand Goyal *in the Chair.*]

उक्त कमी के फलस्वरूप विकास निधि के लिए पहले निर्धारित की गई 1874.59 लाख रुपये की राशि की बजाए अब केवल 574.59 लाख रुपये जुटाये जा सकेंगे । जैसा कि मैंने 10 मार्च, 1970 के अपने भाषण में कहा था कि रेलवे की आय बढ़ाने तथा खर्च कम करने के लिए सभी सम्भव कदम उठाये जायेंगे । विकास निधि में हुई कमी का रेलवे यात्रियों की सुविधाओं तथा कर्मचारी कल्याण कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस कमी की आय बढ़ा कर तथा सामान्य राजस्व में अधिक ऋण ले कर पूरा किया जायेगा ।

विकास निधि में कमी करने के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए ।

Shri George Fernandes (Bombay South) : In spite of the fact that notices for calling attention and short notice question were given by us, regarding the Railway accident at Perel workshop the hon. Minister has not made any statement thereon. Instead of linking up this matter with the demands for grants, it should be taken up separately so that we are able to put questions as well as give those facts which we have.

Shri Nanda : I assure the House that I will make a statement in regards the accident tomorrow and the information which I have already got or which I will be able to collect till tomorrow will be placed before the House.

श्री श्रद्धाकर सूपकार : भारत में परिवहन तथा संचार व्यवस्था की स्थिति शोचनीय होने के कारण, सभी रेल लाइन समाज के लिए उपयोगी हैं । केवल इस कारण से कि इनसे पर्याप्त आय नहीं हो रही है, कुछ लाइनों को बन्द करना उचित नीति अथवा उचित कार्यवाही नहीं है । यह हो सकता है कि बहुत सी लाइनों की काफी समय से मरम्मत न होने के कारण और उनके

पुरानी हो जाने के कारण ये अलाभप्रद हो गई हों। यह भी सम्भव है कि गाड़ियों की स्थिति खराब होने के कारण ये बहुत धीमी गति से चल रही हैं। अतः उनके जरिये पर्याप्त मात्रा में माल नहीं भेजा जा रहा है और यात्री भी कम सफर कर रहे हैं। इस समस्या को सुलझाने के लिए मेरे विचार से, जो छोटी लाइनें अलाभप्रद हैं उनको बड़ी लाइनों में परिवर्तित कर दिया जाय।

उड़ीसा के सभी सदस्यों ने तालचर-बिमलगढ़ लाइन के शीघ्र निर्माण करने पर अनेक बार काफी बल दिया है। इसके लिए हम लगभग 10 वर्ष से लड़ रहे हैं। मुझे याद है कि 1961 में जब तृतीय पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा था और श्री जगजीवन राम रेल मंत्री थे, हमने उनसे इस लाइन के निर्माण के लिए काफी अनुरोध किया था। रूरकेला से बरसुआ तक रेलवे लाइन होने के कारण रूरकेला तथा तालचर के बीच आधे से अधिक फासला तय किया जा चुका है, अब हमें रूरकेला तथा तालचर को मिलाने के लिए केवल 80 किलोमीटर लाइन की आवश्यकता है। यह न केवल रूरकेला के महत्वपूर्ण नगरों को मिलायेगी अपितु कलकत्ता-बम्बई और कलकत्ता मद्रास मुख्य लाइन को भी जोड़ेगी जो इस लाइन से कटक स्टेशन पर मिलती हैं। इसलिए इस लाइन के निर्माण कराने के लिए शीघ्र कदम उठाये जाये।

उड़ीसा के सदस्य दूसरी बात पर बल दे रहे हैं वह है पारादीप पत्तन का कलकत्ता और मद्रास के मध्य चलने वाली रेलवे लाइन से जोड़ना। इस लाइन के निर्माण में देरी होने के कारण पारादीप पत्तन का भीतरी प्रदेश से मिलाया जाना रुका पड़ा है। उड़ीसा से जापान को लोहे के निर्यात के उद्देश्य से इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही आवश्यक है।

जहाँ तक गाड़ियों के चलने का संबंध है, सलाहकार समिति को अनेक सुझाव दिये गये। उदाहरणार्थ सप्ताह में दो बार चलने वाली उत्कल एक्सप्रैस को प्रतिदिन चलाने की मांग की गई परन्तु इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमने इसकी गति बढ़ाने के विषय में भी परामर्श समिति में कहा था परन्तु यह अब भी उसी धीमी गति से चलाई जा रही हैं। इसकी गति एक्सप्रैस के नाम पर कलंक है।

कुछ दिशाओं में सुधारवादी कदम उठाये गये हैं, उदाहरण के लिए राजधानी एक्सप्रैस का चलाया जाना। इस एक्सप्रैस के सम्बन्ध में भी मुझे एक सुझाव देना है। जैसा कि ज्ञात है यह पूर्णतया एक वातानुकूलित गाड़ी है और इसमें कुर्सीमान का स्थान अधिक है। इसके संचालन समय में इस प्रकार का परिवर्तन किया जाय जिससे यात्रियों को रात्रि भर यात्रा न करनी पड़े। कलकत्ता से नई दिल्ली तक आने में इस गाड़ी को 17 घण्टे लगते हैं, अतः यह गाड़ी किसी भी स्थान से सुबह सबेरे छूटनी चाहिए और शाम तक पहुंच जानी चाहिए जिससे कि अधिकांश यात्रियों की गाड़ी के अन्दर नींद खराब न हो।

मेरा अनुरोध है कि उपरोक्त सुझावों पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : रेल आय-व्ययक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सामान्य आय-व्ययक के पश्चात इसी का स्थान है। अतः इस ओर, विशेषतया इसके आर्थिक पहलु की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

नई रेल लाइनों के निर्माण के विषय में यह परम्परा रही है कि इनका निर्माण, राष्ट्रीय

अर्थ व्यवस्था तथा किसी परियोजना को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाने की आवश्यकता पर ध्यान दिये बिना ही, इस प्रकार किया जाय कि प्रत्येक राज्य को एक लाइन मिले। मंत्रालय को इस सम्बन्ध में जांच करनी चाहिए कि जो लाइन निर्मित की जाती है वह अपनी लागत का भुगतान कर देगी।

इस सम्बन्ध में उदाहरण के लिए गुना-माक्षी लाइन तथा उदयपुर-हिम्मतनगर लाइन को लिया जा सकता है। ये बहुत अलाभप्रद लाइनें हैं। गुना-मीनीक्षी लाइन पर 6 करोड़ रुपया व्यय किया जा चुका है और 3.6 करोड़ रुपया और व्यय होगा तब इस लाइन पर यातायात आरम्भ हो सकेगा। इसके पश्चात भी इस लाइन से 0.25 प्रतिशत आय व्यय कम होने की आशा है। इस प्रकार की परियोजनाओं से कुल विनियोजन तथा वे भारतीय रेलवे का वार्षिक औसत व्यय दोनों ही बढ़े हैं।

कोंकण क्षेत्र में एक रेलवे लाइन की मांग की गई है। हमें इस बात का निरीक्षण करना है कि इस लाइन से लागत व्यय का भुगतान भी हो सकेगा या नहीं। इसके अतिरिक्त अन्य आर्थिक पहलुओं पर भी विचार करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए बिहार तथा उड़ीसा से मुगलसराय होती हुई गुजरात जाने वाली लगभग 6 गाड़ी हैं। गुजरात में तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तथा बिहार और उड़ीसा में कोयला। यदि पश्चिम रेलवे पर डीजल इंजन बढ़ा दिये जायें तो उड़ीसा और बिहार तथा गुजरात के मध्य कोयले का व्यर्थ में लाना ले जाना एक सकेगा।

गुजरात में कांडला पश्चिमी तट का महत्वपूर्ण पत्तन है। बम्बई पत्तन के पश्चात इसका स्थान है। परन्तु यह समृद्ध क्यों नहीं है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि राजस्थान तथा पंजाब से कांडला तक माल ले जाने में इतना व्यय पड़ता है जितना कि राजस्थान तथा पंजाब से बम्बई तक ले जाने में। अतः व्यापारी कांडला की अपेक्षा माल को बम्बई ले जाना अच्छा समझते हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और कांडला में सुविधायें देनी चाहिए जिससे बम्बई की अपेक्षा दरें सस्ती हो सकें।

अलाभप्रद छोटी लाइनों के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि सड़क परिवहन प्रतिस्पर्धा के कारण ऐसी लाइनों से लागत व्यय प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए रेलवे को छोटी लाइन समाप्त करके अथवा रेल मोटरकोच यातायात व्यवस्था का सूत्रपात करके सड़क परिवहन व्यवस्था की प्रतिस्पर्धा का उत्तर देना चाहिए।

नैरो गेज पर रेल इंजनों की कमी है। गोदरा-लूनावाडा रेलवे लाइन पर इंजनों के निरन्तर खराब होते रहने की शिकायत है। यदि हम अधिक मूल्य के कारण विदेशों से इंजन नहीं मंगा सकते तथा इनको अपने देश में नहीं बना सकते, तो हमें डीजल इंजन रखने चाहिए जो यात्रियों के हल्के भार वाले डब्बों को ले जाने में समर्थ हैं।

रेलवे को स्टीमर यातायात पर भी ध्यान देना चाहिए। बम्बई तथा सौराष्ट्र के मध्य अहमदाबाद होकर बहुत व्यापार होता है। रेलवे का यातायात भार को कम करने खम्बात की खाड़ी में दाहेज से भावनगर तक वैकल्पिक रूप में मागदतला से भावनगर तक नौका सेवा की व्यवस्था प्रारम्भ करनी चाहिए। इससे यात्रियों के समय में तथा भाड़े आदि में बचत हो सकेगी।

हवाई जहाज द्वारा निश्चय ही समय कम लगता है परन्तु रेलवे और स्टीमर द्वारा तो धन और समय दोनों की ही बचत होगी। अतः रेलवे को स्टीमर द्वारा परिवहन कार्य करने के लिए कुछ विचार करना चाहिये। आज रेलवे की स्पर्धा में सड़क परिवहन के साथ हवाई परिवहन भी है। लोगों की रूचि हवाई परिवहन में बढ़ रही है। अतः रेलवे को इस दिशा में कुछ नवीन प्रयोग करने की आवश्यकता है।

मैं राजधानी एक्प्रैस के नवीन प्रयोग का स्वागत करता हूं। यह अच्छा है कि उस के टिकट में गाड़ी में भोजन के दाम भी शामिल होते हैं। यह और भी अच्छा हो यदि हवाई यात्रा की तरह कुलियों का भाड़ा भी उसी में जोड़ दिया जाये।

रेलवे कुलियों को किसी प्रकार की कोई मानवीय सुविधा देने की ओर सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। यह लोग भी जीवन के 30-40 वर्ष राष्ट्र की सेवा करते हैं। अतः सरकार को इन की भविष्य निधि और डाक्टरी सहायता आदि के लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिये। उनके लिए सरकारी प्रणाली जुटायी जानी चहिये जिससे उन्हें भविष्य निधि में अशंदान करने की सुविधा हो।

इस बात पर सभी संसद सदस्य एक मत है कि तीसरे दर्जे के यात्रियों को जो सुविधायें दी हुई हैं। वे पर्याप्त नहीं हैं। यहां तक कि रेलवे मंत्री ने भी हाल ही में तीसरे दर्जे की यात्रा का कुछ अनुभव किया है। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि तीसरे दर्जे के यात्रियों की जो सुविधायें प्रदान की गई हैं वह पर्याप्त नहीं है। अतः तीसरे दर्जे के यात्रियों के आराम की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये क्योंकि रेलवे को अधिकांश आय इन्हीं लोगों से होती है। इस कार्य के लिए यदि रेल मन्त्री कुछ और मांगें भी पेश करें तो संसद सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं।

श्री जी० विश्वनाथन (वन्डीवाश) : चिंगलपट और चिन्ना के बीच एक लाइन बनाने को मांग की गई है, जिसका सर्वेक्षण कार्य किया जा चुका है। तामिलनाडु सरकार ने इस लाइन को प्राथमिकता प्रदान की है और केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह इस कार्य को आरम्भ करे क्योंकि यह लाइन वाडावासी, अरनी, कल्लाकुरिची जैसे अधिकांश स्थानों को जोड़ेगी। मन्त्री महोदय को शीघ्र ही इस लाइन पर प्राथमिकता से कार्य आरम्भ करवा देना चाहिये।

दूसरे वल्लाजाहयेर और तिन्डीनवम के बीच एक लाइन बनायी जानी चाहिये। यह लाइन मद्रास से बंगलौर और मद्राम से तिन्डीनवम दोनों को मिलायेगी। इस क्षेत्र में औद्योगीकरण की दृष्टि से यह पहला कदम होगा। सरकार द्वारा इस कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। इसके बाद मद्रास बंगलौर लाइन पर बिजली से चलने वाली गाड़िया चलाई जानी चाहिए। इस की योजना तो मन्त्रालय के विचाराधीन है।

मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह यह घोषणा कर दें कि इस बजट के पास होने से पूर्व ही मद्रास, बगलौर लाइन पर बिजली से गाड़ियां चलाने का कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

दक्षिण में वृन्दावन एक्सप्रैस गाड़ी काफी अच्छी गाड़ी है। यह केवल काटपाडि और जलारपेट दो ही स्थानों पर रुकती है। यह खेद का विषय है कि जलापरेट में केवल पांच टिकट ही जारी किये जाते हैं। मन्त्री महोदय को इस बारे में छानबीन करनी चाहिये और वहां पर जो टिकट बिकते है, उनकी संख्या में वृद्धि करनी चाहिये।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 26 मार्च, 1970/5 चैत्र, 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, March, 26, 1970/Chaitra 5, 1892 (Saka).

Printed at Akashdeep Printers, 20 Daryaganj, Delhi-6.